

प्रकाशक

मानिण्ड उपा याय, मंत्री

सम्मा साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

प्रकाश दिनांक १९८८

मूल्य

द्वारु रुपया

मद्रा

देवीप्रसाद शर्मा,

हिन्दुस्तान प्रेस, नई दिल्ली

समर्पण

कोई तीन साल की बात है, गांधीजी ने मुझसे और चलण पर एक ऐसी सरल पुस्तक लिखो जो समझ मके ।" उसी आज्ञा का फल यह पुस्तक है ।

सारी कहानी दो हिस्सों में सुनाई गई है । जब था तब तो सोचा था कि पूर्व भाग मीमांसा का होगा, १२ की हुडी का इतिहास होगा और सारा-का-सारा स्वयं मैं मीमांसा-भाग समाप्त करते-करते जब इतिहास-भाग के इकट्ठा करने लगा तब स्मरण आया कि "फंडेशन आफ आफ कामर्स ऐण्ड इंडस्ट्री" के तत्वावधान में श्रीपारसनाथ साल पहले, रुपए की हुण्डी का एक अच्छा इतिहास अंग्रेजी इसलिए उपयुक्त यही लगा कि मैं श्रीपारसनाथ जी से कह का इतिहास-भाग भी वही लिख दूं और उसमें यथासम्भव बातों का समावेश कर दूं ।

इस तरह मीमांसा-भाग मैंने लिखा और इतिहास-भाग नाथ जी ने ।

जिनकी आज्ञा से यह सब कुछ हुआ वे तो फाटक के भीतर उसलिए छपने के पहले इसे गांधीजी को दिखा देना अमम्भव था बिना दिखाए ही यह छापाखाने में जा रहा है ।

गांधीजी की आज्ञा थी कि इस जटिल विषय को सरल भाषा में जाय । हम दोनों ने कोशिश तो यही की है, पर कहा तक सफलता है यह तो पाठक ही बता सकेंगे ।

जिनकी आज्ञा से यह पुस्तक लिखी गई उन्हीं महापुरुष के चर यह समर्पित की जाती है ।

(पूर्व भाग) ।

मीमांसा

विषय-सूची

विषय

- १° ...सिक्के की आवश्यकता—अदला-बदली की व्यवस्था से
असुविधा—सिक्का राजा ने क्यों चलाया ?—सिक्का सोने-
चादी का क्यों ? १-
- २°नोट क्यों आया ?—चेक क्यों चला ?—नोट से लाभ—
नोट में हानि—राज-दुराजी में अरक्षितता ११-१
- ३°फुलावट और गिरावट—विस्तार और संकोच १९-२
- ४°द्रव्य-परिमाण-मत—द्रव्य की पगुता २६-३
- ५°वेहद फुलावट के नतीजे—फुलावट का कर्ज पर असर—
लाभ और हानि ३३-३८
- ६° ... प्रतीक की कीमत और विदेशी बाजार—विदेश में
कीमत कैसे बनती है ? ३९-४५
- ७° ... हुडी की दर और उद्योग-घघे—दर गिरने से लाभ
स्थायी या अस्थायी ?—फुलावट-नियन्त्रित और अनियन्त्रित ४६-५५
- ८° ... सूचक अंक—चलण की कीमत गिरती आई है ५६-६१
- ९° ... इस कर से वचना असंभव-सा है ६२-६५
- १०° ... उधार की फुलावट ६६-६८
- ११° ... गिरावट कब वाञ्छनीय है ? ६९-७१
- १२° ... दामो की साम्यावस्था—नियन्त्रण ७२-७५

में प्राण-प्रतिष्ठा के बाद विष्णु-तुल्य ही उमंगिए बन जाती है कि भक्ति-भाव से पूजने पर वह विष्णु की प्राप्ति करा देती है। कागज का टुकड़ा वैसे तो कागज ही है, पर नोट निकालनेवाली मस्या उसमें प्राणप्रतिष्ठा स्थापन करके उसे सजीव बना देती है—उसे कीमत का मपूर्ण प्रतिनिधित्व दे देती है।

पर शायद नोट की सपूर्ण उपमा हुण्टी में दी जा मके, क्योंकि नोट एक तरह की बेमीयादी हुण्टी है, जो चाहे जब नोट निकालनेवाली मस्या से सिकराई जा सकती है। उस मवध में यह बतना आवश्यक है कि रुपए की मुद्रा भी एक प्रकार का चादी पर छपा हुआ नोट-मात्र ही है। रुपए के भीतर जो चादी है उसकी कीमत पूरे एक रुपए की नहीं है। रुपए में पहले कुल १६५ ग्रेन अर्थात् $1\frac{1}{4}$ तोला चादी थी और उस चादी की कीमत, आज से कुछ समय पहले के भाव में (अर्थात् १०० तोले = ६२॥) कुल ०-९-२॥ पाई की होती थी। हाल में नया रुपया डाला गया है जिसमें चादी की मात्रा पहले में बहुत कम है अर्थात् १८० ग्रेन में कुल ९० ग्रेन। चादी का भाव इस समय प्राय १०० तोले = १२०) है। इस दर से भी नए रुपए की चादी की कीमत प्राय उतनी ही सी होती है। इसके माने यह हुए कि यदि रुपया चलाने-वाली सरकार की अवहेलना करके, रुपए की मुद्रा के भीतर भरी हुई चादी की कीमत के आधार पर ही, हम रुपए को बेचे, तो रुपए की कीमत हमें कुल प्राय ॥-१॥ मिले। इसलिए रुपए के चादी के सिक्के और नोट को हम स्वयंसिद्ध मुद्रा नहीं कह सकते।

पर वर्तमान समय में शायद ही ऐसा कोई मुल्क है जहा स्वयंसिद्ध मुद्रा कायम हो। १९३३ तक अमरीका का डॉलर स्वयंसिद्ध मुद्रा थी, पर वहा भी सिक्के के दामों में जब से सरकारी दस्तन्दाजी शुरू हुई और सिक्के के दाम गिराए गए तब से स्वयंसिद्ध मुद्रा, अर्थात् ऐसी मुद्रा जिसकी पूरी कीमत मुद्रा के भीतर ही हो, नहीं रही। जहा तक खयाल किया जाता है, आज सभी सुसभ्य देशों में नोटों का, अर्थात् प्रतीक-मुद्रा का ही चलण है।

इस प्रणाली अर्थात् नोटों के चलण के लाभ और हानिया अनेक हैं। इसका विश्लेषण आगे चल कर करेंगे।

नोट क्यों आया ?

पर स्वयसिद्ध मुद्रा के बाद प्रतीक-मुद्रा अर्थात् नोट का आविर्भाव कैसे हुआ, इसका विचार भी कर ले ।

जब ससार में लेन-देन बढा और लाखों का लेखा और करोड़ों पर कलम चलने लगी तब स्वभावतया जिस मुद्रा को हमने 'कम वजनी और घनमूल्यवाली' माना था वह भी अधिक वजनी मालूम देने लगी । एक गाहक के यहां मे हमें आज दस लाख रुपए का भुगतान मगाना है और दूसरे को उतना ही भेजना है, तो यदि सब-का-सब लेन-देन सुवर्ण-मुद्रा में ही हो, तो करीब २५,००० सुवर्ण मुद्राएँ—यदि एक सुवर्ण मुद्रा की कीमत ४० रुपए मान ले तो—हमें देनी और लेनी होगी । इन मुद्राओं का वजन भी करीब ८ मन होगा । २५ ००० सुवर्ण-मुद्रा के गिनने के लिए कितना समय चाहिए, और उम वजन को उठाने के लिए कितने आदमी चाहिए । उसमें समय की कितनी बरबादी होगी, इसकी कल्पना आसान है । इसके अलावा यदि सिक्कों द्वारा भुगतान हो तो सिक्कों की घिसाई और उसके द्वारा होनेवाली घन की छीजत का भी प्रश्न तो है ही । इन सब असुविधाओं और क्षतियों के बचाव के लिए नोट अर्थात् प्रतीक-मुद्रा ने प्रवेश किया । इसमें न गिनने का इतना झंझट, न इतना वजन । १०० नोट यदि १०-१० हजार के दे दिए तो दस लाख का भुगतान समाप्त हुआ ।

चेक क्यों चला ?

पर आगे चल कर व्यापार और लेन-देन ज्यादा बढा तब तो प्रतीक-मुद्रा भी असह्य मालूम होने लगी और सारा लेन-देन चेक-द्वारा ही होने लगा । चेक एक तरह का आज्ञा-पत्र है, जो आज्ञा देनेवाला अपनी बैंक के नाम लिखता है कि इतना रुपया अमुक सज्जन को दिया जाय । और उस आज्ञापत्र पानेवाले को उतनी रकम बैंक से मिल जाती है । स्वयसिद्ध मुद्रा का प्रतिनिधित्व प्रतीक-मुद्रा को मिला, और उसके बाद एक कदम आगे

चले तो प्रतीक मुद्रा का स्थान चेक को मिला । गिनते की प्रगति की यह कथा काफी दिलचस्प है ।

हमारे देश में तो बड़े शहरों को छोड़ कर चेक का चलण कहीं नहीं है । चेक तो वहीं चल सकता है जहां प्रथम तो बैंक हो, दूसरे जहां लेन-देन का काम भी ज्यादा हो और बड़ी-बड़ी रकमों का लेन-देन हो । चूँकि गावों में यह स्थिति नहीं है, इसलिए हमारे देश में तो, जैसा कि उपर कहा जा चुका है, चेक का चलण बड़े शहरों तक ही सीमित है, और नोटों का कस्बों और बड़े गावों तक । छोटे गावों में तो चादी और ताँबे के सिक्कों का ही चलण है । पर ये चादी-ताँबे के सिक्के भी तो, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, एक तरह के धातु पर छपे नोट—प्रतीक-मुद्रा ही हैं, क्योंकि उनकी स्वयंसिद्ध कीमत का उनकी निर्धारित कीमत से कोई मेल नहीं खाता ।

नोट से लाभ

प्रतीक मुद्रा-प्रणाली के लाभ तो स्पष्ट हैं । वजन कम होता है । लेन-देन में, गिनती करने में, समय की बचत होती है । मुद्रा हाथों में से रोज-रोज निकले, उससे धातु की जो छीजत होती है उसकी बचत होती है । पर एक और भी लाभ है । मान लीजिए, हमारे देश के लेन-देन के कारोबार के लिए १० करोड़ सुवर्ण-मुद्राओं की जरूरत है । यदि प्रति मुद्रा की ४० रुपए कीमत मान ले, तो इस हिसाब में ४०० करोड़ रुपए के सोने की, देश के लेन-देन की सहाय्यता के लिए जरूरत होगी । पर यदि नोटों का चलण है तो यही काम बहुत थोड़े सोने से चल जाता है । आखिर नोट का काम तो इतना ही है कि वह उतनी निर्धारित मुद्राओं का स्वामित्व नोट के स्वामी को सौंपता है ।

यह सही है कि आज ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहां नोट के बदले बैंक सुवर्ण-मुद्रा दे दे । पर इससे नित्य-प्रति के व्यवहार में कोई बाधा नहीं पहुँची है । यदि सुवर्ण-मुद्रा भी हमें नोटों के बदले में मिलती तो उस मुद्रा का उपयोग भी हम निम्न, सम्पत्ति या मनुष्य-श्रम

खरीदने में ही तो करते। और जब तक किसी मुल्क की मास सुरक्षित है तब तक सुवर्ण-मुद्रा प्रचलित न हो तो भी नोट गय-विनय में वही काम देता है, जो काम सुवर्ण-मुद्रा देती। इसलिए सुवर्ण-मुद्रा का अभाव किसीको नहीं खटकता। मास सुरक्षित है या नहीं, इसका पता भी तो, हमारे नोट की कीमत विदेशों में क्या है, इसीसे लगता है। इस प्रश्न का विवेचन तो आगे चल कर करेंगे, यहाँ तो मुद्रा के बजाय नोट-चलण में क्या-क्या क़िफ़ायत है उसका दिग्दर्शन कराना है।

बताना तो यह था कि नोट का क्षेत्र इतना ही है, कि वह उतनी निर्धारित मुद्राओं का स्वामित्व नोट के स्वामी को सौंपता है। मसलन, आपके पास दस सुवर्ण-मुद्रा का नोट है। (यह उदाहरण-मात्र है क्योंकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, आज किसी भी मुल्क में स्वयंसिद्ध मुद्रा का चलण नहीं है) तो आप चाहे जब नोट-प्रसार करनेवाली बैंक या संस्था के पास जाकर अपना नोट देकर उसके बदले में १० सुवर्ण-मुद्राएँ माग सकते हैं, जिसके कि आप अधिकारी हैं, और वह बैंक आपको १० सुवर्ण-मुद्राएँ दे देगी, जिसके लिए कि वह बाध्य है।

पर ऐसे किसी भी साधारण समय की कल्पना नहीं की जा सकती जबकि तमाम नोटवाले अपने नोट बैंक को पेश करके बैंक से नोटों के बदले में मुद्रा मांगेंगे। यदि देश के कारोबार के लिए १० करोड़ सुवर्ण-मुद्राओं के चलण की जरूरत है, और लोग अपनी सुविधा के कारण मुद्राओं में नहीं, पर प्रतीक मुद्रा अर्थात् नोटों से अपना काम चलाना चाहते हैं, तो यह स्पष्ट है कि जब तक नोट चलानेवाली बैंक की साख साबित है तब तक कोई समझदार व्यक्ति नोट को भुना कर मुद्रा मागने के क्षण में न पड़ेगा। इसलिए बैंक सावधानी के लिए १० करोड़ सुवर्ण-मुद्राओं के प्रतीकों के पीछे केवल ३ करोड़ सुवर्ण-मुद्रा अपने कोष में रखें तो भी पर्याप्त है।

इसके मानें यह हुए कि यदि हम अपना कारोबार केवल सुवर्ण-मुद्राओं से ही चलाना चाहते हैं तब जहाँ १० करोड़ सुवर्ण मुद्राओं के लिए ४०० करोड़ रुपए के सोने की जरूरत होगी वहाँ, यदि हम नोट-

प्रथा को अपना ले तो, कुल १२० करोड़ रुपए के सोने में ही काम चल जायगा—अर्थात् बैंक १२० करोड़ रुपए के मोन के आधार पर आमानी से ४०० करोड़ रुपए की कीमत की प्रतीक-मुद्राओं का प्रसार कर देगी। बैंक को सोने में रोकना पड़ा कुल १२० करोड़ रुपया। नोट-प्रसार किए कुल ४०० करोड़ रुपए की कीमत के। नोट-प्रसारणी ग्रंथ का तालपट ऐसी हालत में इस प्रकार होगा—

४०० करोड़—नोट चलण में	१२० करोड़—मोना सगैदा
डाले, उसकी कीमत आई	२८० करोड़—व्याज पर गेका

४०० करोड़

४०० करोड़

इस तरह २८० करोड़ रुपए का नाणा व्याज जो बैंक को मिल गया उसे लोगो को उधार देकर बैंक मुनाफा बना साएगी। देश के लिए यह कफायतसारी अवश्य ही ग्राह्य चीज है। इस तरह नोट ने अपने गुणों से समाज को मुग्ध करके अपना सिक्का जमा लिया।

नोट से हानि

पर "जड चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार।" नोटों में गुण हैं तो अवगुण भी हैं। एक अवगुण तो प्रत्यक्ष है। चूँकि स्वयंसिद्ध मुद्रा की कीमत तो इसके गर्भ में ही है और प्रतीक-मुद्रा (नोट) की कीमत तो, जब तक प्रतीक-मुद्रा का प्रसार करनेवाली बैंक सलामत है, तभी तक कायम है, इसलिए राज-दुराजी के जमाने में नोटों में लोग सहज ही विश्वास खो बैठते हैं और स्वयंसिद्ध सिक्को का सग्रह करके उन्हें दवाने लगते हैं।

इस महायुद्ध में पोलैण्ड, फ्रांस वगैरह मुल्को में जहा-जहा राज गिरने की सम्भावना हुई वहा लोग नोटों में विश्वास खो बैठे। पर चूँकि स्वयंसिद्ध मुद्रा का इन मुल्को में चलण नहीं था इसलिए लोग जवाइरात या सोना—ऐसी वस्तुओं का सग्रह करने लगे, या ऐसी वस्तुओं को लेकर देश के बाहर भागने लगे। यहा भी, जब फ्रांस की हार हुई, उस जमाने में लोगो ने

रुपयों का बुरी तरह मगह करना शुरू किया। यों तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है, रुपए का सिक्का भी एक तरह का नोट ही था, क्योंकि इसकी चादी की कीमत तो कुछ ९ आने २॥ पाई थी। पर रुपए के सिक्के के पक्ष में कुछ बातें थीं। आगिर इसकी स्वयंसिद्ध कीमत कागज के नोट की कीमत में तो ज्यादा ही थी। इसलिए लोगो ने घबड़ाहट में इसका मगह करना शुरू कर दिया।

यह मगह करने का मर्ज यहां तक बढ़ा कि छोटी रकमों के लेन-देन के लिए रुपए का सिक्का कुछ दिनों के लिए दुर्लभ-सा होने लगा था। सिक्कों की कोई कमी तो न थी, पर जब लोग भय से पागल-से हो जाते हैं उन समय बुद्धि से काम नहीं लिया जाता। इसलिए भयभीत लोगो ने चादी के रुपयों की धरोहर ध्वंसी करके सिक्के का अकाल-न्ना पैदा कर दिया और अन्त में इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार ने एक रुपए का नोट भी छपा और सिक्के दया बैठने के विरुद्ध कानून भी बनाया। इस बीच में लोगो में भी विश्वास का पुनः संचार होने लगा। पर भय के या अविश्वास के जमाने में स्वयंसिद्ध मुद्रा की या तो चादी के रुपए-जैसी अर्धस्वयंसिद्ध मुद्रा की साथ तो कैसे सुरक्षित रहती है और प्रतीक-मुद्रा की साथ कैसे नेल्सनाब्द होने लगती है, इसका आभास इस और पिछले महायुद्ध के इतिहास से मिल सकता है।

इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि स्वयंसिद्ध मुद्रा के मुकाबिले में प्रतीक-मुद्रा का सबसे बड़ा दोष तो यह है कि प्रतीक-मुद्रा की कीमती के स्थायित्व के बारे में या सुरक्षितता के बारे में घबड़ाहट के जमाने में पूरा यकीन तो कभी हो ही नहीं सकता। पर क्या इस सुरक्षितता के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी बाजिव होगी, कि स्वयंसिद्ध मुद्रा का ही चलण रख कर हम सुवर्ण-मुद्राओं के भार का वहन करे, उनके गिनने-समहालने के झंझट में समय खोवे और उनकी छीजत—जो मुल्क के धन की छीजत होगी—उसे बरदाश्त करे ? और इसके अलावा, जो काम १२० करोड़ रुपए के सोने से चल सकता है उसके लिए, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ४०० करोड़ रुपए की रकम को सोने में फसा के रखे ?

प्रथा को अपना ले तो, कुल १२० करोड़ रुपए के सोने से ही काम चल जायगा—अर्थात् बैंक १२० करोड़ रुपए के मोने के आधार पर आसानी से ४०० करोड़ रुपए की कीमत की प्रतीक-मुद्राओं का प्रसार कर देगी। बैंक को सोने में रोकना पड़ा कुल १२० करोड़ रुपया। नोट-प्रसार किए कुल ४०० करोड़ रुपए की कीमत के। नोट-प्रसारिणी बैंक का तल्पट ऐसी हालत में इस प्रकार होगा—

४०० करोड़—नोट चलण में	१२० करोड़—सोना खरीदा
डाले, उसकी कीमत आई	२८० करोड़—व्याज पर गेका

४०० करोड़

४०० करोड़

इस तरह २८० करोड़ रुपए का नाणा वेव्याज जो बैंक को मिल गया उसे लोगों को उधार देकर बैंक मुनाफा बना लाएगी। देश के लिए यह किफायतसारी अवश्य ही ग्राह्य चीज है। इस तरह नोट ने अपने गुणों से समाज को मुग्ध करके अपना सिक्का जमा लिया।

नोट से हानि

पर “जड चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार।” नोटों में गुण हैं तो अवगुण भी हैं। एक अवगुण तो प्रत्यक्ष है। चूँकि स्वयंसिद्ध मुद्रा की कीमत तो इसके गर्भ में ही है और प्रतीक-मुद्रा (नोट) की कीमत तो, जब तक प्रतीक-मुद्रा का प्रसार करनेवाली बैंक सलामत है, तभी तक कायम है, इसलिए राज-दुराजी के जमाने में नोटों में लोग सहज ही विश्वास खो बैठते हैं और स्वयंसिद्ध सिक्कों का सग्रह करके उन्हें दबाने लगते हैं।

इस महायुद्ध में पोलैण्ड, फ्रांस वगैरह मुल्कों में जहा-जहा राज गिरने की सम्भावना हुई वहा लोग नोटों में विश्वास खो बैठे। पर चूँकि स्वयंसिद्ध मुद्रा का इन मुल्कों में चलण नहीं था इसलिए लोग जवाइरात या सोना-ऐसी वस्तुओं का सग्रह करने लगे, या ऐसी वस्तुओं को लेकर देश के बाहर भागने लगे। यहा भी, जब फ्रांस की हार हुई, उस जमाने में लोगो ने

रुपयों का दुरी तरह संग्रह करना शुरू किया। यो तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है, रुपए का सिक्का भी एक तरह का नोट ही था, क्योंकि इसकी चांदी की कीमत तो कुल ९ आने २॥ पाई थी। पर रुपए के सिक्के के पक्ष में कुछ बातें थीं। आखिर इसकी स्वयंसिद्ध कीमत कागज के नोट की कीमत से तो ज्यादा ही थी। इसलिए लोगो ने घबड़ाहट में इसका संग्रह करना शुरू कर दिया।

यह संग्रह करने का मजं यहां तक बढ़ा कि छोटी रकमों के लेन-देन के लिए रुपए का सिक्का कुछ दिनों के लिए दुर्लभ-सा होने लगा था। सिक्कों की कोई कमी तो न थी, पर जब लोग भय से पागल-से हो जाते हैं उस समय बुद्धि से काम नहीं लिया जाता। इसलिए भयभीत लोगो ने चांदी के रुपयों की धरोहर छकट्टी करके सिक्के का अकाल-सा पैदा कर दिया और अन्त में इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार ने एक रुपए का नोट भी छपा और सिक्के दवा बैठने के विरुद्ध कानून भी बनाया। इस बीच में लोगो में भी विश्वास का पुनः संचार होने लगा। पर भय के या अविश्वास के जमाने में स्वयंसिद्ध मुद्रा की या तो चांदी के रुपए-जैसी अधर्म्यसिद्ध मुद्रा की साथ तो कैसे सुरक्षित रहती है और प्रतीक-मुद्रा की साथ कैसे नेस्तनाबूद होने लगती है, इसका आभास इस और पिछले महायुद्ध के इतिहास से मिल सकता है।

इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि स्वयंसिद्ध मुद्रा के मुकाबिले में प्रतीक-मुद्रा का सबसे बड़ा दोष तो यह है कि प्रतीक-मुद्रा की कीमती के स्थायित्व के बारे में या सुरक्षितता के बारे में घबड़ाहट के जमाने में पूरा यकीन तो कभी हो ही नहीं सकता। पर क्या इस सुरक्षितता के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी वाजिव होगी, कि स्वयंसिद्ध मुद्रा का ही चलण ररा कर हम सुवर्ण-मुद्राओं के भार का वहन करे, उनके गिनने-सम्हालने के क्षण में समय खोवे और उनकी छीजत—जो मुल्क के धन की छीजत होगी—उसे बरदाश्त करे ? और इसके अलावा, जो काम १२० करोड़ रुपए के सोने से चल सकता है उसके लिए, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ४०० करोड़ रुपए की रकम को सोने में फसा के रखे ?

राज-दुराजी में अरक्षितता

आज हमारे देश में नोटों का कुल चलण प्राय ८०० करोड़ रुपए की कीमत का होगा। पर कुछ समय पहले यह चलण २५० करोड़ रुपए का था। इसके माने यह है कि यदि रिजर्व बैंक, जो इन नोटों का प्रसार करनेवाली बैंक है, उसकी साख को ठेम पहुँचता तो इन २५० करोड़ के नोटों की कीमत को खतरा था।

पर ऐसी स्थिति की हम कल्पना करें तब तो यह जानना चाहिए कि इससे कहीं ज्यादा खतरा तो सरकारी प्रोमिसरी नोटों की रकम को हो सकता था और इन सरकारी प्रोमिसरी नोटों में तो प्रजा की कुल रकम लगभग १००० करोड़ के लगी हुई थी—अर्थात् नोटों की २५० करोड़ की कीमत से चौगुनी रकम तो प्रोमिसरी नोटों में लगी हुई थी। इससे पता लगेगा कि नोटों की सुरक्षितता की जब हम बात करते हैं तब हम भूल जाते हैं कि किसी भी राष्ट्र के पतन के कारण होनेवाली क्षति से बचने का तो कोई रामबाण उपाय है ही नहीं, और उस होनेवाली सारी क्षति में, नोटों की कीमत नेस्तनाबूद हो जाने के कारण होनेवाली क्षति का स्थान अपेक्षाकृत छोटा है।

नोट का स्वामी यह सहज ही कह सकता है कि सारी क्षति क्या होगी इससे गुझे क्या मतलब—मुझे तो अपने नोट की कीमत के नाश में होने वाली क्षति का ही दर्द है। पर इसका उत्तर तो यह है कि देश के सिक्के की नीति व्यक्ति की सुविधा के लिए नहीं, पर समाष्ट की सुविधा के लिए बनाई जाती है, और इस दृष्टि से स्वयसिद्ध मुद्रा से प्रत्येक मुद्रा की सुरक्षितता कम होने पर भी देश के लिए प्रतीक-मुद्राशैली का त्याग और केवल स्वयसिद्ध मुद्रा की नीति का ग्रहण বেশी खर्चीला होगा।

प्रतीक-मुद्राशैली में एक दोष और है—यदि उसे दोष कहा जाय तो—और उम दोष का वर्णन करने में पहले कुछ तत्सम्बन्धी बातों का विवेचन करना आवश्यक जान पड़ता है ।

हमने बताया है कि नोट-प्रसार करनेवाली संस्था यदि ४०० करोड़ रूपयों के पीछे १२० करोड़ रुपए का भी सोना रखे तो पर्याप्त होगा, क्योंकि जब तक बैंक की सख्त अक्षत है तब तक कौन नोट को भुना कर बदले में सुवर्ण-मुद्रा भागेगा ? इसलिए नोट की धाक अक्षत तो जो नोटों के पीछे सोना पड़ा है उस पर, बाकी नोट-प्रसारक बैंक की दक्षता, सावधानी और नेकनीयती पर है ।

मान लीजिए कि १२० करोड़ के सोने के मूँ ४०० करोड़ रुपए के नोटों के बजाय बैंक ने किसी भी कारणवश, अपनी मर्जी से या बाध्य होकर, ८०० करोड़ रुपए के नोट चलणमें डाल दिए, तो जो सोने की मिकदार पहले प्रतिशत नोटों के पीछे ३० की थी वह सिर्फ १५ की रह गई । ऐसी हालत में सहज ही नोटों की सख्त में लोगों को कुछ शक होने लगेगा । और, मान लीजिए कि यदि नोट-प्रसारक बैंक ने ८०० के बजाय उसी १२० करोड़ रुपए की कीमत के सोने की पूंजी के बल पर १६०० करोड़ के नोट चलण में डाल दिए, तब तो फिर नोटों की सख्त जोरो से डूबने लगेगी । और यदि १६०० करोड़ के बजाय ३२०० करोड़ के नोट चलण में डाल दिए तब तो लोगों में घबराहट फैल जायगी और लोग नोटों से दूर भागने लगेंगे, क्योंकि ३२०० करोड़ के पीछे यदि कुल १२० करोड़ का ही सोना हो तब तो प्रति सौ नोट के पीछे केवल ३॥ रुपए का ही सोना रहा, जो बैंक की देनदारी को देखते हुए अत्यन्त अल्प कहा जायगा ।

यह अनहोना-सा उदाहरण जानबूझ कर ही दिया है । कोई समझदार बैंक जानबूझ कर सुप्त-शांति के जमाने में ऐसी बेहूदी हद तक नहीं जाती ।

पर असाधारण समय में ऐसी घटनाएँ कई मुल्कों में हुई भी हैं। भारतवर्ष की ही बात लीजिए। इस समय जहाँ नोट प्रायः ८०० करोड़ रुपए के हैं वहाँ सोना कुल ४८ करोड़ रुपए का है।

नोटों का प्रसार करना आसान काम है। उसके लिए जटिल है वस कुछ कागज की। टेढ़े समय में या तो सरकार को कोई कर्ज देनेवाला नहीं मिलता, या मिलता भी है तो बहुत कड़े सूद पर। इसलिए कई बार ऐसा हुआ है कि सकटापन्न सरकार ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति न तो टैक्स लगा कर की, न कर्ज लेकर—उसने वस नोट छापनेवाली मशीनों को दिन-रात चला कर अपना मतलब पूरा किया। प्रायः ऐसा भी हुआ है कि जिस सरकार ने यह तरीका अस्तियार किया उससे औचित्य की सीमा का उल्लंघन हुए बिना न रह सका—और वह इतनी दूर आगे बढ़ गई कि उसका दिवाला निकल के ही रहा।

फ्रांस की इतिहासप्रसिद्ध क्रांति के समय वहाँ कुछ नोट जारी किए गए थे, जिन्हें assignat कहते थे। महन्त-मठाधीशों की जो जायदाद जब्त कर ली गई थी उसीकी पुष्टी या आधार पर ये नोट जारी किए गए थे। मगर उस जायदाद की कीमत से कहीं अधिक के नोट निकाल दिए गए, और इसका नतीजा यह हुआ कि इनकी कीमत बहुत नीचे गिर गई। कुछ काल बाद सरकार को मजबूर होकर इन नोटों को चलण से हटा लेना पड़ा।

२४ साल पहले रूस में, कम्यूनिस्ट क्रांति के समय भी ऐसी ही बात हुई। वहाँ चलण में जो सिक्का था उसका नाम रूबल (Rouble) था। क्रांति से पहले एक रूबल की कीमत प्रायः २ शिलिंग अर्थात् १½) थी। मगर बाद इसकी कीमत यहाँ तक गिर गई, कि कुछ समय तक रूस में आध सेर रोटी के २५० रूबल और आध सेर चीनी के ९०० रूबल लगते थे।

फुलावट और गिरावट

इस तरह थोड़े सोने की पूँजी पर बेहद परिमाण में नोट निकालने की नीति को अंग्रेजी में Inflationary policy कहते हैं। हम इस अंग्रेजी

परिभाषा के लिए "चलण की फुलावटी नीति"—इस मुहाविरा का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह किसी कारणवश नोट-प्रसारक बैंक यह भी कर सकती है कि १२० करोड़ की कीमत के सोने के मढ़े ४०० करोड़ रुपए की कीमत के नोट चलण में न रख कर केवल २०० करोड़ रुपए के नोट ही चलण में रखे, या तो और भी घटा कर १२० करोड़ के ही रखे। इस नीति को अंग्रेजी में Deflationary policy कहते हैं। हिन्दी में हम इसे "चलण की गिरावटी नीति" कह सकते हैं।

इस फुलावटी नीति या गिरावटी नीति का कबो प्रयोग किया जाता है, इसका विवेचन भी आवश्यक है। पर यह विवेचन करने के पहले, नोट कैसे अधिक परिमाण में चलण में डाल करके फुलावट पैदा की जाती है और कैसे नोट कम करके गिरावट की जाती है, इस प्रयोग को भी हम समझ लें।

कोई नोट-प्रसारक बैंक बिना सरकार की मर्जी के तो फुलावट या गिरावट ज्यादा हद तक कर ही नहीं सकती। इसलिए जब सरकारी मर्जी से यह काम होता है तो सरकारी सहयोग भी अपने-आप मिल जाता है। ऐसी हालत में यदि फुलावटी नीति का प्रयोग करना होता है तो एक तरीका तो यह है कि सरकार जितना खर्च करती है उससे कर कम उगाहती है—याने, मान लीजिए कि सरकार का खर्चा सालाना १००० करोड़ है, तो कर लगा कर सरकार ने उगाहा केवल ७५० करोड़, और बाकी जो २५० करोड़ का घाटा है उसको बैसा-का-बैसा रखा, अर्थात् कर वसूल करके उमकी पूर्ति नहीं की। नतीजा यह होता है कि कोष में आया ७५० करोड़, और कोष से निकला १००० करोड़। यह २५० करोड़ जो कोष से बेशी निकला वह सरकार ने कहा से निकाला? वस, सरकार ने सीधा-सा काम किया। उसने २५० करोड़ के नोट छापकर, या नो बैंक से नोट छपवाकर उसे उधार लेकर लोगो को चुका दिया, और इस तरह २५० करोड़ चलण में ज्यादा प्रवेश कर गया।

यह तरीका तो तभी काम में लाया जाता है जब कि सरकार आर्थिक कठिनाइयों में फसी हुई होती है, या तो दिवालिया बनने की

विस्तार और संकोच

स्वभाव से और उचित परिमाण से, आवश्यकतानुसार जो नोटो के चलण मे कमी या वेशी हो उसे स्वाभाविक संकोच या विस्तार कहना चाहिए ।

मान लीजिए, देश मे धन बढ़ा है, चीजों के दाम तेज हैं । विदेश के लोग हमारा माल धड़ाधड़ ले रहे हैं । हमने अपना माल बेच कर इस साल विदेशो से ५० करोड़ का सोना खरीदा । उसीके मद्दे १०० करोड़ के नोट चलण मे रखे, हाला कि नियम के हिसाब से १५० करोड़ के भी नए नोट निकाल सकते थे । नए नोट, बिना सोने का कोष बढ़ाए नहीं निकाले । इसके अलावा पहले जो सोना १२० करोड़ का और नोट ४०० करोड़ के थे, अब वह सोना १७० करोड़ का और नोट ५०० करोड़ के हो गए । इस तरह कुल सोना, जो पहले नोटो के अनुपात से ३० प्रतिशत था, वह अब ३४ प्रतिशत हो गया । दूसरे, यह सारा काम जरूरत के मुताबिक हुआ । देश की सम्पत्ति बढ़ रही थी, दाम बढ़ रहे थे, चलण मे ज्यादा नोटों की जरूरत भी थी । इसलिए जो हुआ, ठीक हुआ । यह स्वाभाविक विस्तार हुआ ।

इसी तरह मान लीजिए, देश मे भयकर अकाल पड़ा, भूमिकम्प हुआ या प्लेग-महामारी हुई । इसके कारण देश की सम्पत्ति इस साल कम हो गई । बाहर से माल मगाया ज्यादा, और भेजा कम । इसलिए हमें २५ करोड़ सोना कुल बाहर भेजना पड़ा । बैंक ने इस २५ करोड़ सोने के मद्दे ५० करोड़ के नोट चलण मे से निकाल लिए । इस हिसाब से अब नोटों का चलण ४०० करोड़ से घट कर ३५० करोड़ रह गया, और सोना रह गया १२० करोड़ से घट कर कुल ९५ करोड़, जो नोटों की कुल कीमत का २७ प्रतिशत हुआ । पर चूँकि यह सब सावधानी से, आवश्यकतानुसार हुआ, और सोने का परिमाण भी ३० से गिर कर २७ प्रतिशत रह गया, इसलिए इसे स्वाभाविक संकोच कह सकते हैं ।

अर्थशास्त्री आम तौर से फुलावट या गिरावट, इन दो ही परिभाषाओं का प्रयोग करते हैं। पर मेरा खयाल है कि यह यथार्थ नहीं है। सकोच और गिरावट में कुछ भेद तो है ही, और इन्हीं तरह विस्तार और फुलावट में भी भेद है। यह भेद अवश्य सूक्ष्म है, पर इस भेद को मान लेना ही शायद ज्यादा शान्धीय है, इसलिए मैंने यह भेद मान कर फुलावट—विस्तार, और गिरावट—सकोच, ऐसी अलग-अलग परिभाषाएँ रखी हैं। यह भेद इसलिए मान लिया है कि जहाँ फुलावट और गिरावट कृत्रिम रूपायों से की जाती हैं, और विशेष हेतु को लेकर की जाती हैं, सकोच और विस्तार आवश्यकतानुसार स्वभावतया ही होते हैं। तो भी यह सही है कि यह भेद सूक्ष्म-सा ही है।

चाँक फुलावट या गिरावट कृत्रिम उपायो से और विशेष हेतु के लिए की जाती है, इसलिए, यह क्यों की जाती है और इसका क्या फल होता है, यह समझना भी जरूरी है। पर इसी सिलसिले में एक और मत का उल्लेख आवश्यक है।

जिन्सों के दाम में घटा-बढ़ी के, मोटे तौर पर, दो कारण हो सकते हैं—एक तो उन जिन्सों से ही सम्बन्ध रखनेवाला, दूसरा उस द्रव्य से सम्बन्ध रखनेवाला जिसके द्वारा दाम सूचित किया जाता है, जैसे नोट या धातु का सिक्का। एक चीज की कीमत कल दो पैसे थी, आज तीन पैसे है। अर्थशास्त्री इसका कारण दो जगह ढूँढेगा। हो सकता है कि पैसे के परिमाण में कोई अन्तर नहीं पड़ा है, पर वह चीज घट चली है—कल जितनी उपलब्ध थी आज उतनी नहीं है—और इस घटी के अनुपात से उसका दाम बढ़ गया है। और हो सकता है कि चीज के परिमाण में कोई अन्तर नहीं पड़ा है, पर पैसे का परिमाण बढ़ गया है, और इस वृद्धि के अनुपात से उस चीज का दाम बढ़ चला है।

यहां जो सवाल पैदा होता है वह यो रखा जा सकता है, कि दाम बढ़ा वह चीज महंगी होने से या द्रव्य सस्ता होने से? अगर हम Value के अर्थ में मूल्य और Price के अर्थ में दाम शब्द व्यवहृत करें तो इसे यो रख सकते हैं कि उस वस्तु का अपना मूल्य चढ़ जाने के या द्रव्य का अपना मूल्य गिर जाने के कारण दाम बढ़ा?

वस्तुओं के मूल्य में घटा-बढ़ी के कारण ढूँढ निकालना कठिन प्रयास है। एक फमल मारी गई अनावृष्टि से, दूसरी बाढ़ या जल-बाहुल्य से, तीसरी टिड्डियों के आक्रमण से। तीनों चीजें कम हो गईं, उनकी मांग ज्यों-की-त्यों बनी रही, फलतः उनका मूल्य बढ़ गया—अर्थात् उनके दामों में तेजी आ गई। सम्भव नहीं कि कोई भी ऐसा मत प्रतिपादित किया जा सके

जो अनावृष्टि, बाढ़ और टिट्टियों का आक्रमण—जैसे विभिन्न, असम्बद्ध कारणों को अपने घेरे में लाकर तज्जनित जटिलता को किमी भी हद तक सरलता में परिणत कर सके। वास्तव में जहाँ तीन कारण दिए गए हैं वहाँ तीन सौ तो क्या, तीन हजार भी हो सकते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में इस कारण भी वृद्धि हो सकती है कि लन्दन के “टाइम्स” असवार ने एक खास तरह की राय जाहिर कर दी—या राष्ट्रपति रजवेल्ड ने किमी पत्रकार के तत्सम्बन्धी प्रश्न को मजाक में उड़ा दिया—या किसी करोड़-पति ने स्वप्न देखा कि वह उस वस्तु के टेर पर बेटा हुआ आसमान की ओर उठना जा रहा है। जहाँ दाम में घटा-बढ़ी किसी वस्तु के मूल्य में घटा-बढ़ी का प्रतिबिम्ब है वहाँ इस घटा-बढ़ी पर कोई सुनात्मक मत या नियम प्रकाश नहीं डाल सकता—जिज्ञासु को प्रत्येक कारण का अलग अन्वेषण और उसकी अलग व्याख्या करनी पड़ेगी।

द्रव्य-परिमाण-मत

द्रव्य अर्थात् रुपए-पैसे के मूल्य में घटा-बढ़ी के कारण न तो इतने अधिक हैं, न इतने विभिन्न। इसलिए इनके सम्बन्ध में Ricardo नामक अंग्रेज अर्थशास्त्री के समय से एक ऐसा उपयोगी मत चला आता है, और उसका नाम है “द्रव्य-परिमाण-मत” (Quantity Theory of Money)। जितने भी दाम होंगे, द्रव्य के ही रूप में होंगे। इसलिए द्रव्य के रूप में वृद्धि या ह्रास के जो भी कारण होंगे वे दामों के प्रसंग में सर्वत्र लागू होंगे।

इस मत का निचोड़ यह है —

द्रव्य के मूल्य में घटा-बढ़ी का दामों पर उल्टा असर होता है और वे उसी अनुपात से तेज या मन्दे हो जाते हैं। मान लीजिए कि किसी वस्तु का दाम होता है ४ ग्रेन सोना। अगर सोने का मूल्य घट कर आधा हो जाय, तो उस चीज का दाम ४ ग्रेन की जगह ८ ग्रेन सोना हो जायगा।

अब यह देखना है कि द्रव्य के मूल्य में घटा-बढ़ी होती क्यों है। इसके चार कारण हो सकते हैं —

(१) द्रव्य के परिमाण का घटना-बढ़ना। सोना या चादी खानों से

ज्यादा निकली तो उसका मूल्य कम हो गया—कम निकली तो उसका मूल्य बढ़ गया। अगर सिक्के सोना-चादी के हैं तो उनके मूल्य में भी ऐसी ही घटा-बढ़ी होगी और चीजों के दाम में —उसी हिसाब से—फर्क पड़ेगा। अगर चलण में सोना-चादी के सिक्कों की जगह कागजी नोट हैं और इनका परिमाण बढ़ता-घटता है, तो इनके मूल्य में भी उसी प्रकार अन्तर पड़ेगा और चीजों के दाम उसी प्रकार तेज या मन्दे होंगे।

(२) हो सकता है कि द्रव्य का परिमाण ज्यो-का-थ्यो बना हुआ है, पर उसके चलण या रफ्तार में कुछ खास कारण या कारणों से तेजी आ गई। इस तेजी का असर वही होगा जो उस द्रव्य का परिमाण बढ़ने का होता। कारण यह कि रफ्तार में तेजी के माने हैं उतने ही द्रव्य का ज्यादा चक्कर लगाना, अर्थात् द्रव्य के परिमाण का बढ़-सा जाना। अगर चलण या रफ्तार धीमी हो गई तो इसका असर उल्टा पड़ेगा, क्योंकि इसका अर्थ होगा द्रव्य के परिमाण का घट-सा जाना। जब कोई रुपए को अपने पास रखना नहीं चाहता तब दाम चढ़ते हैं, जब लोग रुपए को दबाकर बैठ जाते हैं तब दाम गिरते हैं।

(३) द्रव्य की माग, अवस्था-विशेष में, इस कारण कम हो जाती है कि लोग भुगतान के लिए चेक या हुण्टी-पुरजे का अधिकाधिक व्यवहार करने लगते हैं। ऐसी अवस्था में दाम गिरते नहीं, ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि द्रव्य की माग कम हो गई, द्रव्य का मूल्य गिर गया, चीजों के दामों में तेजी आ गई। चेक और हुण्टी भी तो आखिर द्रव्य के ही प्रतीक हैं। उनकी सख्या बढ़ गई तो एक प्रकार से वह द्रव्य ही बढ़ गया, क्योंकि यदि चेक-हुण्टी न होती तो उनके स्थान की पूर्ति नोटों को करनी पड़ती। इसलिए इस पहलू को यो भी बताया जा सकता है कि द्रव्य-परिमाण बढ़ गया, इसलिए द्रव्य के दाम गिर गए, और चीजों के दाम चढ़ गए।

(४) मगर इसके विपरीत यह भी हो सकता है कि वाणिज्य-व्यापार या लेन-देन की वृद्धि के कारण द्रव्य की माग बढ़ जाय। माग की पूर्ति न की जाय और चलण में द्रव्य न बढ़ाया जाय तो स्पष्ट है कि ऐसी अवस्था में द्रव्य का मूल्य बढ़ेगा—अर्थात् चीजों के दाम गिरेगे।

द्रव्य के मूल्य में घटा-बढ़ी के कारणों को समझाने के लिए ऊपर यह मान लिया है कि जहाँ एक बात बदलती है वहाँ और सब बातें समान बनी रहती हैं। पर प्रकृत जीवन में ऐसी अवस्था बहुत कम मिलती है। एक नहीं, अनेक बातें प्रायः साथ-ही-साथ बदलती रहती हैं और परस्पर-विरोधी शक्तियों की मुठभेड़-भी बनी रहती है। घटा-बढ़ी का जो अन्तिम कारण बताया गया है उस पर फिर एक नजर डालिए। लिखा है कि द्रव्य की माग बढ़ने से उसका मूल्य बढ़ेगा और चीजों के दाम गिरेगें। मगर सम्भव है कि जहाँ एक ओर द्रव्य की माग बढ़े वहाँ, दूसरी ओर, साथ-ही-साथ उसका परिमाण भी इतना बढ़ जाय कि उसके मूल्य में किसी प्रकार की वृद्धि न हो और दामों पर कोई असर न पड़े। वास्तव में वस्तु-स्थिति कभी-कभी इतनी जटिल होती है कि उसका पूरा विश्लेषण करना और यह जान लेना कि वह कौन-कौन से कारणों के फलस्वरूप बनी है, अत्यन्त कठिन कार्य हो जाना है। पर जटिल-से-जटिल अवस्था में भी द्रव्य के मूल्य में घटा-बढ़ी उपरोक्त कारणों से ही होती है—चाहे उनमें से एक मौजूद हो, चाहे एक से अधिक। माग बढ़ेगी या परिमाण कम होगा तो उसके मूल्य में वृद्धि होगी। माग घटेगी या परिमाण बढ़ेगा, तो मूल्य में ह्रास होगा। यह सरल या जटिल प्रत्येक अवस्था के लिए सत्य है।

उपरोक्त विश्लेषण को सामने रख कर ही हम “द्रव्य-परिमाण-मत” के शुद्ध स्वरूप को समझ सकते हैं, जो यह है कि सिक्का—चाहे वह स्वयं-सिद्ध मुद्रा हो चाहे प्रतीक मुद्रा—जब चलण में ज्यादा होता है तो जिन्सों के दाम—बढ़े चलण के अनुपात से—बढ़ जाते हैं; और सिक्का चलण में कम होता है तो, जितना कम होता है उसी अनुपात से, जिन्सों के दाम गिरते हैं।

यह बात सहज ही समझ में आ सकती है। मान लीजिए कि अचानक सोने की नई खाने निकल आई और सोने की पैदाइश बेहद बढ़ चली। उसके कारण सोने के दाम गिर गए, यहाँ तक कि सोने के दाम पहले से आधे हो गए—तो स्वभावतया ही, यदि हम विदेशों में खरीद से ज्यादा माल बेचते रहे हैं तो बदले में पहले जितना सोना खरीदते थे उसके बजाय

उतने ही माल के लिए दुगुना सोना हमें मिल सकेगा। सोना दुगुना मिलेगा, उस पर फिर नोट भी ज्यादा चलण में बढ़ेंगे। जैसे, पहले यदि १० करोड़ का नया मोना हम हर साल खरीदते थे और उसके मद्दे ३० करोड़ के नए नोट चलण में रखते थे, तो अब उतने ही माल के बदले में विदेशों में हमें १० करोड़ के बजाय (क्योंकि सोने के दाम आधे हो गए) २० करोड़ का सोना मिलेगा, जिसके मद्दे हम आसानी से ६० करोड़ के नए नोट चलण में रख सकेंगे। नए नोट चलण में आने से व्याज गिरेगा, नाणा मन्दा होगा और बहुतायत से उधार मिल सकेगा। कोई भी चीज कम होती है तो वह महगी हो जाती है, ज्यादा होती है तो सस्ती होती है। चूंकि नाणा ज्यादा हो गया, इसलिए नाणा सस्ता हो गया। नाणा सस्ती हो गया, इसके माने दूसरे शब्दों में यह हुआ कि चीजें महगी हो गईं। दर असल जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उस चीज का नाणे के साथ तब्रादला-मात्र होता है, याने नाणा हम बेचते हैं और चीज खरीदते हैं। जब नाणा सस्ता होता है तो सस्ते में विकेगा—अर्थात् जिन्सों के साथ नाणों की अदला-बदली में, यदि नाणा सस्ता है तो, हमें नाणा ज्यादा देना पड़ेगा। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह हुआ कि चीजों के दाम महंगे हो गए।

जब नोट चलण में बढ़ जाते हैं तो नाणा आसानी और सहूलियत से और बहुतायत से कम व्याज पर मिलने लगता है। ऐसी हालत में लोगों को अपना व्यवसाय बढ़ाने की फिक्र होती है। नए कारोबार में रुपया लगाने में किसीको हिचकिचाहट नहीं होती। नतीजा यह होता है कि व्यापार पनपता है, हर चीज के दाम बढ़ते हैं। पर इस मत के पूर्णतया सिद्ध होने की कई एक शर्तें हैं। एक शर्त तो यह है कि द्रव्य का चलण बढ़ा—चाहे नोटों का या सिक्कों का—उतना ही यदि व्यापार और लेन-देन भी बढ़ गया, तो फिर दाम नहीं बढ़ेंगे। दाम तो तभी बढ़ेंगे जब कि चलण अपेक्षाकृत बढ़ गया हो—अर्थात् यदि व्यापार बढ़ा है रुपए में एक आना, और चलण बढ़ गया रुपए में दो आना, तभी नाणा मन्दा है, ऐसा हम कहेंगे। ऐसी हालत में रुपए की छूट होगी और इसके कारण चीजों के दाम बढ़ेंगे।

इसके विपरीत यदि व्यापार या लेन-देन की जरूरत बड़ी रूपए में एक आना और चलण बढ़ा पीन आना हो, तो यह कहा जायगा कि अपेक्षा-कृत चलण में सकोच हुआ है, और इसलिए चीजों के दाम झुकाव की ओर होंगे। असल में तो इस मत की सिद्धि के लिए हमें यह शर्त लगानी होगी कि यदि दो तुलनात्मक स्थितियाँ और हर बात में बिल्कुल यक़ीन है, तो फिर यह नि सकोच कहा जा सकता है कि द्रव्य-परिमाण (नोट या सिक्कों का चलण) बढ़ने पर, जितना परिमाण बढ़ा उसी अनुपात में चीजों के दाम बढ़ेंगे और नाणा सस्ता होगा। और द्रव्य-परिमाण घटने पर, जितना परिमाण घटा उसी अनुपात से, चीजों के दाम गिरेगे।

द्रव्य की पंगुता

यहाँ, फुलावट और गिरावट के सम्बन्ध में, हमें एक बात कहनी है जो, जाहिरा तौर पर, अब तक जो कुछ कहा जा चुका है उसके विपरीत जान पड़ती है। हर हालत में फुलावट या गिरावट के नतीजे वही नहीं होते जो ऊपर बताया जा चके हैं। संभव है, फुलावट होते हुए भी दाम समान-से बने रहे, या उनमें तेजी भी आए तो नाममात्र की। और संभव है, गिरावट होते हुए भी जिन्मों के दाम चट जाय। आप कह सकते हैं कि “यह खूब रही। और अगर यह सच है, तो इससे तो ‘द्रव्य-परिमाण-मत’ का खोखलापन ही साबित हुआ। आप दोनों बातों का सामञ्जस्य कैसे करते हैं?”

फुलावट होते हुए भी, अगर लोगों के खर्च करने का वेग उस हिसाब से नहीं बढ़ता और द्रव्य या पैसा पंगु-सा होकर बैठा या पड़ा रहता है तब दामों में उतनी तेजी नहीं आ सकती, जितनी फुलावट को देखते हुए संभव जान पड़ती है। इस महासमर में इंग्लैंड की बात लीजिए। वहाँ फुलावट काफी हो चुकी है, पर उस अनुपात में दाम नहीं बढ़ पाए हैं। कारण यह है कि लोग मौजूदा हालत में मनोवाञ्छित रीति से जिन्स नहीं खरीद सकते। उनके पास पैसा अधिक है, उनकी शक्ति बढ़ गई है, पर वह पैसा तरह-तरह के नियानों के कारण, निष्क्रिय-सा पड़ा हुआ है। सरकार को लड़ाई के लिए हर तरह की जिन्स की जरूरत है—

और सख्त जरूरत है। अगर बाजार में उन जिन्सों को खरीदते समय सरकार को सर्वसाधारण की प्रतियोगिता का सामना करना पड़े, तो उसकी समस्या बड़ी जटिल हो जाय, और लड़ाई के लिए जैसी तैयारी होनी चाहिए, न हो सके। उस प्रतियोगिता को सरकार ने विभिन्न उपायों से बहुत कुछ रोक दिया है। इस कारण लोगों की क्रय-शक्ति अशक्त-सी हो गई है—उनके पास पैसा अधिकाधिक होते हुए भी वह उसे एक हृद से आगे खर्च करने में असमर्थ है। फिर दाम फुलावट के हिसाब में बढ़े तो कैसे ?

मान लीजिए कि लड़ाई बन्द होते ही सरकार की नीति फुलावट से गिरावट की हो गई, तो क्या दाम गिरने लगेंगे ? आज आय-वृद्धि होते हुए भी व्यय करने के मार्ग बन्द हैं, इसलिए उस पैसे का दामो पर जो असर पड़ सकता था वह नहीं पड़ रहा है। पर, कल अगर वह मार्ग खुल गए, और लोग मनमाना खर्च करने के लिए स्वतन्त्र हो गए तो गिरावट के बावजूद भी जिन्सों के दामो में बेहद तेजी आ सकती है।

सारांश यह कि दामो की दृष्टि से प्रधानता इस प्रश्न की है कि कितना पैसा खर्च हो रहा है—न कि इस प्रश्न की, कि कितना पैसा मौजूद है। साधारण समय में यह भेद कोई खास अर्थ नहीं रखता, क्योंकि लोग अपने पैसे को मनमानी रीति से खर्च करने के लिए स्वतन्त्र रहते हैं। पर इस महासमर-जैसे असाधारण समय में—जबकि पैसा होना एक बात है, उसे मनमानी रीति से खर्च करने की स्वतन्त्रता होना दूसरी बात—यह भेद विशेष महत्वपूर्ण है। फिर भी यह बात कोई ऐसी नहीं, जिसका “द्रव्य-परिमाण-मत” से मेल या सामञ्जस्य न हो सके। वास्तव में यह उसी मत के अन्तर्गत है, क्योंकि वह द्रव्य के परिमाण पर ही नहीं, उसके चलण या रफ्तार पर भी जोर देता है। हम अपने शब्दों को दोहराते हैं—“जब कोई रुपए को अपने पास रखना नहीं चाहता तब दाम चढ़ते हैं, जब लोग रुपए को दवा कर बैठ जाते हैं तब दाम गिरते हैं”। इस समय रुपया अधिक होते हुए भी दवा हुआ है, इसलिए दाम जितने ऊँचे हो सकते थे, नहीं हैं।

पर चलण के स्वाभाविक विस्तार और सकोच से जो असर चीजों के दामों पर पड़ता है उससे कहीं अधिक जोरदार असर चीजों के दामों पर चलण की फुलावट और गिरावट के कारण पड़ता है। चूँकि विस्तार या सकोच तो अपने-आप करीब-करीब स्वभाव से ही होता है, इसकी गति भी मन्द होती है और इसका असर भी सह्य और मृदु होता है।

पर चूँकि फुलावट और गिरावट जान-बूझ कर की जाती है, इसकी गति द्रुत होती है। इसलिए जिनकी ही कस कर फुलावट या गिरावट की नीति काम में लाई जाय, उतना ही अधिक तात्कालिक असर इस नीति का जिन्सों की कीमत पर होगा। और खास कर फुलावट की नीति में तो—यदि अत्यधिक, बेपरमाण, फुलावट की जाय तो—लोगों का नोटों से विश्वास इस कदर भाग जाता है कि वे नोटों को एक रात भी अपने पास रखना नापसन्द करते हैं और अपना पूँजी-पल्ला जिन्सों में ही रोकना पसन्द करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि चीजों के दाम अनाप-शनाप बढ़ जाते हैं। और व्याज की दर भी बढ़ने लगती है।

लड़ाई के बाद जर्मन मार्क और रूसी रूबल के चलण की फुलावट यहाँ तक बढ़ी कि साधारण समय में जितने नोट चलण में थे उससे कई लाख गुने नोट चलण में रख दिए गए। नतीजा यह हुआ कि नाणा कागज के टुकड़ों की तरह इतना सस्ता हो गया कि उनकी कोई कीमत ही नहीं रह गई और जर्मनी में जिस चीज के दाम साधारण समय में १-२ मार्क रहे होंगे उसके दाम लाखों मार्क तक हो गए। ज्यों-ज्यों मार्क छप-छप कर जोर से चलण में आने लगे, त्यों-त्यों बड़ी तेजी के साथ चीजों के दाम बढ़ने लगे—यहाँ तक कि हर मिनट दाम ऊँचे जाने लगे। कहा जाता है कि जब एक नानवाई अपने गाहक को रोटी बेचकर उसके मार्क पाता था तो उसे यह चिन्ता होती थी कि ताजा रोटी बनाने के लिए आटा खरीदते-खरीदते

कहीं आटे के दाम बढ़ न जाय । इसलिए वह रोटी बेचते ही मार्क लेकर बेतहाशा दौड़ कर आटेवाले की दूकान पर पहुँच कर आटा ले लेता था और मार्क से पिण्ड छूटने पर ही शान्ति से सास लेता था ।

बेहद फुलावट के नतीजे

उस जमाने की इससे भी ज्यादा मजेदार कई सच्ची कहानियाँ प्रचलित हैं । जब मार्क की कीमत कौड़ी से भी कम होने जा रही थी, तब तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी के लोगो का विश्वास इस बुरी तरह डुल गया कि कई लोगो ने तो अपनी कफन-काठी भी मरने के पहले खरीद कर रख दी ताकि बाद में कहीं दाम बेगुमार ज्यादा न बढ़ जायें ।

एक प्रतिष्ठित भारतीय कोठी का कुछ मार्क एक जर्मन व्यापारी से पावना था । वह मार्क हजारों की तादाद में था, जिसकी साधारण समय में हजारों रुपए कीमत थी । भारतीय कोठी ने जब जर्मन व्यापारी से रुपया मागा और लिखा कि आप हमारे मार्क भेज दीजिए, तो जर्मन व्यापारी ने जवाब लिखा कि “महाशय, आपके २५,००० मार्क पावने थे, पर मैं जो यह खत आपको लिख रहा हूँ उसके टिकिट और, लिफाफे के दाम ही तो ढाई लाख मार्क हो जाएंगे । इस हिमाव से यदि मैं हिसाब लगाऊँ तो उल्टा मेरा ही आप से पावना निकलेगा ।”

कहते हैं, ऑस्ट्रिया में दो भाई थे, जिनमें से एक के पास २०-३० हजार क्राउन थे, जिसके कारण वह सम्पन्न माना जाता था । और दूसरा शराबी था, जो नित्य जितना कमाता था उसका एक बड़ा हिस्सा शराब में खर्च कर देता था और शराब की बोलतले घर में जमा रखता था । जब क्राउन की फुलावट हुई तब, जो भाई सम्पन्न था उसके क्राउन तो कौड़ी के हो गए, पर जो शराबी था उसकी खाली बोतलों की कीमत लाखों क्राउन हो गई । नाणे की फुलावट क्या-क्या करामात दिखाती है, इसका यह एक मजेदार उदाहरण है । अस्तु ।

मान लीजिए कि हमारे यहाँ २५० करोड़ रुपए के नोटों का चलण

है, उसे बढ़ा कर २५,००० करोड़ के नोटों का कुल चलण कर दिया जाय—अर्थात् मौगुना चलण बढ़ा दिया जाय, तो स्वभावतया रुपए की साथ सौआ हिम्सा रह जायगी। और जो मेथी की सब्जी आज दो पैसे सेर मिलती है उसके दाम २०० पैसे सेर, अर्थात् एक सेर मेथी की कीमत करीब-करीब ३ रुपए हो जायगी।

ऊपर हमने बताया है कि नाणा चलण में ज्यादा होता है तो चीजों के दाम पनपने लगते हैं और सस्ते व्याज में उधार मिलने लगता है। पर यह सस्ते व्याज की बात केवल नियंत्रित विस्तार तक ही सीमित है—अर्थात् व्यापार को पनपाने के लिए या केवल मौमिमी टान को मेटने के लिए ही जब हम चलण में मिक्का ज्यादा डालते हैं, और मो भी नियंत्रण के साथ स्वल्प मात्रा में, तभी तक व्याज मंदा रहता है। पर जहां फुलावट की नीति जोर में शुरू की और चलण में लोगों का विश्वास कपित हुआ कि व्याज की दर जोर से बढ़ने लगती है।

जर्मनी में फुलावट के जमाने में चीजों के दाम कैसे बढ़ गए, इसका उदाहरण हमने ऊपर दिया है। उस जमाने में व्याज की दर भी यहाँ तक बढ़ी थी कि एक जमाने में व्याज १२०० प्रतिशत—अर्थात् १०० सिक्के का व्याज एक साल का १२०० रुपया हो गया। आपने यदि कुल १०० सिक्के उधार दिए तो एक साल के बाद आपको अपने देनदार से १२०० सिक्के व्याज के मिल गए। ऐसी विषम स्थिति हो गई थी।

यह कुछ अनहोनी-सी बात लगती है कि इतनी ऊँची व्याज की दर हो सकती है—और सो भी एक सुसभ्य देश में। काबुली व्याज कड़ा होता है। पठान लोग गरीबों को अत्यंत ऊँचे व्याज पर उधार देते हैं। पर यह १२०० प्रतिशत का व्याज तो काबुलियों से भी बाजी मारता है। पर उस समय की परिस्थिति को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

जैसा कि हमने पहले बताया है, जब फुलावट नीति जोर से शुरू होती है तो चलण का मूल्य घड़ाघड़ गिरने लगता है। मान लीजिए, जिस चलण का मूल्य आज एक माना है उसका मूल्य एक साल में शतांश रह

गया, और भय यह हो कि शायद महीने-बीस दिन के बाद ₹१ रह जाय या इससे भी कम हो जाय, तो फिर चलण अपने पास कोई नहीं रखेगा। इसलिए जिस नानवाई का हमने उदाहरण दिया है वह बेतहाशा दौड़ कर मार्क का आटा खरीद कर ही दम लेता था। ऐसी जहा हालत हो वहा फिर चलण को अपने पास कौन रखे ? जिसने उधार दिया वह तो मारा गया, क्योंकि साल भर के लिए यदि किसी ने १०० मार्क उधार दिए और मार्क के दाम गिर कर साल भर में ₹१ रह जाय, तो जो मार्क उसे वापिस मिलेंगे वे सौ के बजाय आधे मार्क का सा काम देंगे। इसके माने यह हुए कि यद्यपि उसे वापिस १०० मूल रकम और १२०० व्याज के, कुल १३०० मार्क मिले, पर १३०० की कीमत ₹१ के हिसाब से $\frac{1}{100} \times 1300 = ₹13$ मार्क ही कुल रह गई। इतना व्याज पाने पर भी कर्ज देनेवाला घाटे में ही रहा। यही कारण है कि इस तरह की फुलावट की नीति के जमाने में नाणा प्रचुर मात्रा में होते हुए भी व्याज की दर बेहद बढ़ जाती है, क्योंकि उधार देनेवाले को बड़ी जोखिम उठानी पड़ती है।

फुलावट का कर्ज पर असर

फुलावट में प्रतीक की साख में ठेस पहुँच गई और प्रतीक की मिकदार चलण में ज्यादा हो गई। इसलिए, जैसा कि पहले बता चुके हैं, जिन्सों के दाम भी बढ़ गए। पर किसी कर्जदार को एक मौ का देना था और पावनेदार का उतना ही पावना था तो—यद्यपि जब दोनों का लेन-देन हुआ था तब प्रतीक स्वयसिद्ध मुद्रा का मन्चा प्रतिनिधि रहा हो—आज प्रतीक स्वयसिद्ध मुद्रा का प्रतिनिधित्व खो बैठा, तब भी पावनेदार को वही सौ मिलेंगे, और देनेवाले को वही मौ देने पड़ेंगे। फुलावटके कारण प्रतीक की करामात कम हो गई, इसमें लेन-देन की निर्वाहित रकम पर कोई अमर नहीं पड़ेगा।

पहले जो एक रुपया दस मेर गेहूँ खरीद सकता था, अब फुलावट के कारण रुपए की माँग गिर गई और जिन्सों के दाम बढ़ गए, इसलिए चाहे दस मेर गेहूँ के बदले ८ मेर ही खरीद सके, पर पावनेदार देनदार में

यह नहीं कह सकता, "भारि साहब—मैंने जब आपको उधार दिया तब रुपए की सारा सोलह कला सपूर्ण थी। प्रतीक के स्वामी को बैकवाले आठो पहर छट मे स्वयसिद्ध मुद्रा देते थे। अब वह बात नहीं रही। फुला-वट की नीति के कारण प्रतीक हतथ्री हो गया। इसकी कलाए घट गई। १० सेर गेहू के बजाय अब इसके बदले में ८ सेर गेहू ही मिल सकते हैं। इसलिए मेरा रुपया जो पहले सोलह कलावाला था उसीको लौटाने की आपकी जिम्मेवारी है। इसलिए आप या तो मुझे स्वयसिद्ध मुद्रा का प्रतीक लौटाइए, और यदि आप मुझे घटे दाम का रुपया लौटाना चाहते हैं तो सौ के ऋण के बजाय आपको सवा सां देना होगा।" यदि पावनेदार ऐसी बात कहे तो देनदार अवश्य ही कहेगा, "तुम कहा आकाश-पाताल की वाते कर रहे हो? मालूम होता है तुम्हारे दिमाग की कोई कील गिर भागी है, इसलिए बेहतर है कि तुम अपनी चिकित्सा कराओ।"

लाभ और हानि

पर बावजूद इस प्रश्नोत्तरी के यह नो मानना ही पड़ेगा कि इस फुला-वट की नीति के कारण पावनेदार को घाटा हुआ, और देनदार को लाभ, क्योंकि पावनेदार का जो पावना था, वह था पूर्णकला रुपया या सुवर्ण-मुद्रा, और अब वापिस मिल रहा है उसे घटी कीमत का प्रतीक, जो पुराने रुपए की अपेक्षा कम जिन्स खरीद सकता है। पर चूंकि कानून का यह तकाजा है कि फुलावट या गिरावट के कारण प्रतीक की कीमत में चाहे जो घटा-बढ़ी हो (उस घटा-बढ़ी को निश्चित रूपेण मापने का कोई साधन नहीं है, और यदि हो भी तो वह सरकार को मान्य नहीं है) उससे पावनेदार या देनदार के पावने देने की रकम पर कोई असर नहीं होगा—अर्थात् यदि स्वयसिद्ध मुद्रा के चलण के समय का १०० का पावना देना है, तो वह फुलावट-नीति के समय भी १०० का ही पावना देना माना जायगा।

करोड़ों का देना-पावना हर मुल्क में होता है और उस देने-पावने की रकम ज्यों-की-त्यों बनी रहती है, इसलिए सर्वसाधारण को प्रतीक की कीमत गिर गई है या बढ़ गई है, इसका थोड़ी घटा-बढ़ी में कोई पता भी नहीं

चलता। पर पता न भी रहे तो भी उसके असर से लोग वंचित नहीं रहते। यदि दाम चढ़ते हैं तो सभी को उसका फल भुगतना पड़ता है, और गिरते हैं तब भी यह सभी को लागू पड़ता है।

एक सावधान और सम्पन्न व्यक्ति ऑस्ट्रिया में कैमे दरिद्र हो गया और उसका भाई, जो शराबी था, कैसे धनिक बन गया, इसका उदाहरण हम पहले दे आए हैं। यद्यपि फुलावट के कारण प्रतीक-मुद्रा की दर कितनी गिर गई है, इसकी माप-तौल का सर्वसाधारण को पूरा पता नहीं चलता, पर जाननेवाले तो जानते ही हैं कि फुलावट के कारण प्रतीक की कीमत कम हो जाती है और इसके फलस्वरूप पावनेदार को, नकद रुपया रखनेवाले को, जिन्सों की खपत करनेवाले को, मजदूरपेशा लोगों को, और जिनकी आय निर्धारित है उनको (जैसे जमींदार, पेन्शनयाप्ता लोग, नौकरीपेशा लोग, कर वसूल करनेवाली संस्थाएँ—जैसे सरकार, म्युनिसिपैलिटी, कॉलेज, स्कूल इत्यादि) हानि होती है, और कर्जदार लोग, कारखानेवाले, माल पैदा करनेवाले, (जैसे किसान, जुलाहा, बढई, लोहार, चमार आदि) इन लोगों को लाभ होता है।

गिरावट की नीति में, जिन्हे फुलावट में लाभ होता है, उनको हानि है, और फुलावट में जिन्हे नुकसान है, उनको लाभ है।

इस फुलावट या गिरावट के कारण हमारी मुद्रा की कीमत पर विदेशों में क्या अमर होता है, इसका भी जरा विवेचन कर दें ।

हमने पहले बताया है कि प्रतीक-मुद्रा तो स्वयमिद्ध मुद्रा की प्रतिनिधि-मात्र है—अर्थात् एक सुवर्ण-मुद्रा की कीमत का प्रतीक हम नोट-प्रसारक बैंक के पास पेश करे, तो हम एक सुवर्ण-मुद्रा पाने के अधिकारी होंगे और बैंक एक सुवर्ण-मुद्रा देने के लिए बाध्य होगी । पर यह अधिकार और जिम्मेवारी, दोनों-के-दोनों फुलावट-नीति के प्रवेश करने ही समाप्त हो जाते हैं, और गिरावट-नीति के आने पर दोनों और भी सुरक्षित बन जाते हैं ।

कारण स्पष्ट है । थोड़े में सोने की पूंजी पर एक तरफ तो अत्यधिक और बेपरमाण प्रतीक चलण में डाल दिए जाय, और दूसरी तरफ प्रतीक के स्वामी का प्रतीक के बदले में स्वयसिद्ध मुद्रा पाने का अधिकार अक्षुण्ण बना रहे और बैंक प्रतीक-मुद्रा के बदले में सुवर्ण-मुद्रा देने के लिए बाध्य हो—ये दोनों बातें असंगत हैं, क्योंकि १२० करोड़ की कीमत के सोने के आधार पर यदि ३२०० करोड़ के नोट चलण में डाल दिए जाय और उनमें से यदि २०० करोड़ की कीमत के नोटवाले भी अपने अधिकार का उपयोग करे और बैंक से नोट भुना कर सुवर्ण-मुद्रा मागे, तो बैंक को अपना दरवाजा बन्द करने के सिवा कोई चारा न होगा । कुल पूंजी ही यदि १२० करोड़ है, तो फिर २०० करोड़ के नोटों का भुगतान बैंक चुका ही कैसे सकती है ? ज्यादा से ज्यादा—३२०० करोड़ के नोटों में से—कुल १२० करोड़ ही तो चुका सकती है । बाकी के नोटों के पीछे जब कोष में सोना ही नहीं रहता, तो फिर नोटों की पुष्टी ही नेस्तनाबूद हो जाती है, और इसलिए नोटों की साख शून्यवत् रह जाती है । इसलिए जहां फुलावट-नीति के प्रयोग का विचार हुआ कि प्रतीक मुद्रा के स्वामी का सुवर्ण-मुद्रा पाने का अधिकार समाप्त हुआ ।

गिरावट की नीति में, इसके विपरीत, यह अधिकार और भी ठोस बन जाता है, क्योंकि चलण के नोटों के परिमाण के मुकाबिले में बैंक के क्रोष में स्थित सोने का परिमाण और भी बढ़ जाता है। इसलिए स्वभावतया प्रतीक-मुद्रा की साख बढ़ जाती है। पर फुलावट-नीति में तो प्रतीक नाममात्र का प्रतीक रहता है। पहले प्रतीक की कीमत जो एक सुवर्ण-मुद्रा थी, फुलावट होने पर अब उसकी कोई निश्चित कीमत नहीं रही। अब प्रतीक की कीमत उसकी साख की घटा-बढ़ी के अनुसार घटती और बढ़ती रहती है। और वह साख फुलावट के परिमाण के पीछे कमी-बेश होती रहती है। यदि फुलावट ज्यादा होती है तो, जैसा कि ऊपर बताया है, प्रतीक की कीमत ज्यादा गिर जाती है, और यदि फुलावट अपेक्षाकृत कम होती है तो प्रतीक की कीमत कम गिरती है।

जब तक प्रतीक और स्वयंसिद्ध मुद्रा का कानूनन सम्बन्ध था, दोनों गँठजोड़े-से बंधे थे, तब तक तो प्रतीक की निर्धारित कीमत कायम थी। पर जहाँ प्रतीक और स्वयंसिद्ध मुद्रा का तलाक हुआ कि कीमत की स्थिरता गायब हुई। यद्यपि कहने के लिए तो प्रतीक फिर भी एक सुवर्ण-मुद्रा का नोट ही होगा, जैसा कि इंग्लैण्ड में एक पाउण्ड का नोट आज भी एक पाउण्ड का नोट ही कहलाता है, पर उसके माने यह नहीं कि उसके पीछे एक पाउण्ड की सुवर्ण-मुद्रा पड़ी है, जिसे हम चाहे जब बैंक ऑफ इंग्लैण्ड से माग लेंगे और वह हमें दे देगी। इस तलाक के बाद असल में तो प्रतीक की कीमत कटी पतंग की तरह हो जाती है, और जैसे हवा के झोको के बल पर पतंग गिरती है या उठती है, उसी तरह प्रतीक की कीमत भी चलण की फुलावट की कमी-बेशी के आधार पर झिलोरे खाती रहती है।

प्रतीक की कीमत और विदेशी बाजार

यह सही है कि सर्वमाधारण को फुलावट या गिरावट के कारण प्रतीक की दर में क्या घटा-बढ़ी हुई, इसका कोई पता नहीं चलता, क्योंकि उनकी नजरों के सामने तो मिवाय जिन्सों की कीमत की घटा-बढ़ी के और कोई ऐसे लक्षण नहीं आते जिनसे उन्हें प्रतीक की नई कीमत का

प्रत्यक्ष ज्ञान हो। उनके सामने रुपए की वही पहलेवाली शक्ति है, वही देनदार-पावनेदार की रकम है, वही रुपए का नाम है।

पर विदेश में लोग हमारे प्रतीक की कीमत के सम्यन्ध में इतने अन्धकार में नहीं रहते। उन्हें हमारे प्रतीक की कीमत का और उसमें रोज होनेवाली घटा-बढ़ी की करीब-करीब सही माप-तौल मिल जाता है, और इसलिए, जैसे मनुष्य अपने चेहरे को स्वयं नहीं देख सकता किन्तु दर्पण की सहायता से अपने मुँह की बदसूरती या सुन्दरता की सही माप-तौल कर सकता है, उसी तरह हमारे प्रतीक का विदेशी लोग क्या दर-दाम करते हैं, इससे उसकी कीमत का अधिक सही ज्ञान हमें हो सकता है। विदेशी बाजार एक तरह दर्पण का काम देते हैं, क्योंकि उन्हींके द्वारा हम अपने प्रतीक की सही कीमत का पता लगता हैं।

पर विदेशी बाजार हमारे दर्पण क्यों बन जाते हैं ? यदि विदेशों से हम माल न तो खरीदें और न उन्हें बेचें, तब तो किसको फुर्सत है कि हमारे चलण की क्या कीमत होनी चाहिए, इसपर कोई विदेशी बहस करने बैठेगा। पर चूँकि हम विदेशों में जितना मोल लेते हैं और बेचते हैं, इसलिए हमारे चलणी प्रतीक की कीमत को हर समय कूतते रहना उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। यह क्यों ?

मान लीजिए, आप लन्दन के बाजार में कुछ चीजें मोल लेते हैं, तो उनका दाम आप यदि भारतीय नोटों में चुकाना चाहेंगे तो कोई दूकानदार आपको माल न बेचेगा, इसलिए आपको वह दाम अंग्रेजी नोटों में चुकाना पड़ता है। अंग्रेजी नोट आप कहाँ से लाते हैं ? आपके घरवाले हिन्दुस्तान में किसी विदेशी बैंक को रुपया देते हैं और उसकी कीमत का अंग्रेजी द्रव्य खरीद कर आपको उसी बैंक की मार्फत भेज देते हैं, जो आपको अंग्रेजी नोट या सिक्कों की शकल में मिल जाता है। पर इसी तरह यदि सब लोग यहाँ से इंग्लैण्ड भेजनेवाले ही होंगे, और मगानेवाला कोई न रहेगा, तब तो कारो-बार अपने-आप कुछ दिन के बाद बन्द हो जायगा। पर चूँकि जैसे भेजने-वाले हैं वैसे ही लन्दन से द्रव्य मगानेवाले भी हैं, इसीलिए यह दुर्तफा

कारोबार चलता रहता है, और जब हम रुपए से अंग्रेजी पाउण्ड खरीदते हैं (लन्दन धन भेजने के लिए) या तो पाउण्ड बेच कर रुपया खरीदते हैं (लन्दन से धन मगाने के लिए) तब ज़िम् कीमत में या तो हम रुपया बेच कर पाउण्ड खरीदते हैं, या पाउण्ड बेच कर रुपया खरीदते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि हमारे प्रतीक (चलण) की विदेश में क्या कीमत है।

विदेश में कीमत कैसे बनती है ?

प्रश्न का उत्तर यह है कि हर चीज़ की कीमत लेने और बेचनेवालों की गरज पर अवलम्बित है। वैसे ही इस विषय में भी होता है।

पर इसे ज्यादा स्पष्टतया समझ लेना आवश्यक है। यदि हम विदेशों में माल ज्यादा लेते हैं और कम बेचते हैं, जैसे कि हमने १०० का माल तो लिया और ६० का बेचा, तो हमें विदेशों को ४० चुकाना बाकी रहा। यह ४० हम कैसे चुकाएँगे ?

इसके तीन तरीके हो सकते हैं।

एक तरीका तो है पावनेदार को मोना भेज कर। सोने के सभी ग्राहक होते हैं, और तमाम मुल्कों ने करीब-करीब सोने की एक निर्धारित कीमत कायम कर रखी है, उस निर्धारित कीमत पर, हर मुल्क की नोट-प्रसारक बैंक प्रायः सोना खरीदने को तैयार रहती हैं। इसलिए पावनेदार को सोना भेज कर हमारा कर्ज चुकाने में तो कोई कठिनाई है ही नहीं। पर हर माल मोना भेज कर तो वही मुल्क माल खरीद सकता है जिसके पास मोने की बड़ी-बड़ी खानें हों और जहाँ सोने की बड़ी मिकदार में पैदाइश भी हो। इसलिए मोना भेज कर दाम चुकाने का यह तरीका चाहे १-२ माल के लिए भले ही चले, पर हर मुल्क के लिए निरन्तर इस तरीके का चलाना व्यावहारिक नहीं हो सकता।

दूसरा तरीका है—जहाँ माल खरीदा वही लोगों में धन उधार लेकर माल का दाम चुकाया। यह तरीका भी विशेष समय के लिए चाहे उपयुक्त हो, पर निरन्तर नहीं चल सकता। निरन्तर उधार कौन देता जायगा ?

आखिर कभी तो वापिस चुकाना ही होगा। इसलिए यह तरीका भी निरन्तर नहीं चल सकता।

अब एक तीसरा तरीका है, जो दाम चुकाने के लिए सर्वदा व्यावहारिक होता है। यह तरीका यह है कि अपने यहाँ बनी चीजों को या अपनी सेवा या श्रम को विदेश में बेचकर उससे जो द्रव्य मिले, हम उसीसे अपना विदेशी देन चुकावे।

उपरोक्त तीन तरीकों में से प्रथम दो तरीके तो सर्वदा और बड़े परिमाण में चल ही नहीं सकते। तीसरा ही एकमात्र तरीका है, जो हमें विदेश के भुगतान चुकाने में हमारा सहायक हो सकता है। हर मुल्क के लिए यह लाजिमी है कि या तो वह विदेशी व्यापार में मह मोटे या विदेश में माल लेने और बेचने की कीमत को एक हद तक समतल पर रखे—अर्थात् जितना-सा ले उतना-सा ही बेचे।

इसके कुछ अपवाद हैं सही। मान लीजिए कि हमारे पास ऐसी चीजें हैं जिनके बिना दुनिया का काम ही नहीं चल सकता है, तो विदेश-वाले हमसे हमारी जिन्से खरीदते जाएँगे और बदले में हमें मोना भेजते जाएँगे। या तो ऐसा भी हो सकता है, जैसा कि इंग्लैण्ड के सम्बन्ध में था। इंग्लैण्ड ने तमाम दुनिया को कर्जदार बना रखा था, इसलिए यद्यपि इंग्लैण्ड बेचता था कम, खरीदता था दुनिया में ज्यादा—उस ज्यादा खरीदे हुए माल की कीमत—अपने कर्जदारों से व्याज-बमूली का जो धन आता था, उसीसे चुका देता था। पर ऐसे अपवादों को छोड़ कर यह मानना होगा कि विदेशी खरीद और बिक्री की कीमत को समतल पर लाना हमारे लिए आवश्यक है।

पर जब तक हम इस लेवा-बेची को समतल पर नहीं लाते तब तक यदि विदेशों में हम जितना बेचते हैं उससे हम ज्यादा खरीदते हैं, तो उसकी कीमत चुकाने के लिए हमें हर समय अपने द्रव्य याने मुद्रा को बेच कर विदेशी द्रव्य याने विदेशी मुद्रा खरीदने की जरूरत बनी रहती है। इसके कारण हमारे प्रतीक का दाम विदेशों में झुकाव की ओर—अर्थात् गिरने की ओर होगा। और यदि हम विदेशों में जितना लेते हैं उससे वहाँ ज्यादा बेचते हैं, तो उस बेचाव की कीमत को स्वदेश लाने के लिए या तो हमें वहाँ सोना मिल

जायगा, अन्यथा हम हर समय विदेशी द्रव्य-प्रतीक के ठेचवाल और अपने चलण-प्रतीक के लेवाल रहेंगे। नतीजा यह होगा कि हमारे प्रतीक की कीमत विदेशों में चढ़ाव की ओर होगी।

जब फुलावट की नीति होती है तब, हमने बताया है कि, हमारे प्रतीक की कीमत कम हो जाती है। पर किम समय कितनी कीमत गिरी, उसका सही अन्दाज भी, जैसा कि ऊपर बताया है, विदेशी बाजारों से ही लगता है। विदेशों में हमारे द्रव्य की कीमत कैसे भिन्न-भिन्न, पर तमाम सजोगों के कारण, कायम होती है, इसकी कुछ कल्पना उपरोक्त चित्रण से ही की जा सकती है। इन तमाम सजोगों में कई सजोग ऐसे होंगे जो विदेशों में हमारे चलण की कीमत को चढ़ानेवाले होंगे, और कई ऐसे सजोग होंगे जो हमारे चलण की कीमत को गिरानेवाले होंगे। इन सब सजोगों के जोड़-बाकी के बाद शेष जो सजोग कीमत बढ़ाने या घटाने के पक्ष का रह जाता है उसीका फिर एकपक्षीय असर होता है।

जब फुलावट की नीति हमारे यहाँ बरतती है तो हमारी जिन्सों के दाम हमारे देश में तो बढ़ते हैं, पर चूँकि विदेशों में तो न फुलावट है, न गिरावट, स्पष्ट है कि वहाँ दाम साधारणतया स्थिर रहेंगे—अर्थात् न चढ़ेंगे, न गिरेंगे। “साधारणतया”—पाठकों का ध्यान इस त्रिया-विशेषण की ओर आकृष्ट किया जाता है। अवस्था-विशेष में—जैसा कि आगे चल कर बताया गया है—एक देश में दाम गिरने में हमारे देश या देशों में भी मन्दी आ सकती है।

अच्छा, तो हमने कहा कि फुलावट की नीति के कारण अपने देश में हमारी जिन्सों के दाम बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि हमने फुलावट-नीति धारण की, उस समय हमारे यहाँ गेहूँ का दाम १ रुपए का १० सेर था। और यह भी मान लीजिए कि उसी जमाने में हमारे १ रुपए के मिक्के की कीमत किसी एक विदेशी मुल्क में १ मार्क जितनी थी। इसके माने हुए कि हमारे यहाँ और वहाँ, दोनों जगह १ मार्क में १० सेर गेहूँ मिल सकने थे। (१ रुपया=१ मार्क। १ रुपया=१० सेर गेहूँ। इसलिए १ मार्क=१० सेर गेहूँ।) अब हमारे यहाँ तो फुलावट की

नीति जारी हो गई, उसके कारण गेहूँ के दाम अन्य जिनसों के दामों के साथ चढ़ गए और अब एक रुपए में केवल ८ सेर ही गेहूँ मिलता है। पर उस विदेश में तो आज भी वही भाव है जो पहले था, याने १ मार्क का भाव १० सेर गेहूँ ही है। (इस उदाहरण में हमने यह मान लिया कि और तमाम स्थिति दोनों मुल्कों में एकसा है, इसलिए जिनसों के दाम भी, यदि हमारे यहाँ फुलावट न हो तो एकसा रहते।)

अब मान लीजिए कि हमने उस विदेश में एक मार्क की कोई चीज खरीदी, उसकी कीमत चुकाने के लिए बदले में हमने वहाँ गेहूँ बेचा। अब गेहूँ यहाँ मिलता है १ रुपए का ८ सेर। वहाँ भाव है १ मार्क का १० सेर गेहूँ। हमें १ मार्क वहाँ भेजना चाहिए, क्योंकि हमने १ मार्क की वस्तु ली है। तो हमको एक मार्क चुकाने के लिए वहाँ दस सेर गेहूँ बेचना पड़ा, जिसका कि हमें यहाँ स्वदेश में १½ रुपया देना पड़ा। इसके माने यह हुए कि पहले जहाँ १ रुपए की कीमत १ मार्क थी, अब १½ रुपए की कीमत १ मार्क हुई। दूसरे शब्दों में हमारे रुपए की दर १ मार्क से गिर कर ८० मार्क रह गई। $\frac{१ \text{ मार्क}}{१\frac{१}{२} \text{ रुपया}} = .८० \text{ मार्क}$ । अर्थात् २० प्रतिशत कीमत गिर गई।

विदेशी मुल्कों में हमारे द्रव्य की कीमत को शास्त्रीय भाषा में हुण्डी की दर कहते हैं। जब हमारे चलण की कीमत विदेशों में बढ़ती है तो हम कहेंगे कि हमारी हुण्डी की दर तेज है। हमारे चलण की कीमत गिरी, तो कहेंगे कि हुण्डी की दर मन्दी है।

१०	घिसाई
५	व्याज
१०	मुनाफा

 १००

अब मान लीजिए फुलावट-नीति के कारण जिन्सो के दाम बढ़े और जिस माल का कारखानेदार को पहले १०० रुपया मिलता था उसका अब १२५ रुपया मिलेगा। इसके साथ-साथ, मान लीजिए, कच्चे माल का दाम भी बढ़ा और मजदूरी भी उसी अनुपात से बढ़ी, तो फिर मुनाफे पर क्या असर होगा ? नीचे के तालपट से इसका स्पष्ट अन्दाज लग जायगा।

पुरानी कीमत नई कीमत

रुपया

रुपया

कच्चा माल	५०	६२½
मजदूरी	२५	३१
घिसाई	१०	१०
व्याज	५	५
मुनाफा	१०	१६
	<hr/>	<hr/>
	१००	१२५

उपरोक्त तफसील से पता लगेगा कि जहा कच्चे माल और मजदूरी का दाम २५ रुपया प्रतिशतक बढ़ा वहा घिसाई और व्याज में पुराने और नए खर्च में कोई फर्क नहीं पडा। कारण प्रत्यक्ष है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, फुलावट और गिरावट के कारण लेन-देन की रकम पर कोई प्रभाव नहीं पडता। १०० रुपए हमने कर्ज ले रखा था तो आज भी हमें १०० रुपया ही चुकाना है। इसलिए व्याज पर कोई असर नहीं पडता। और घिसाई पर भी क्या असर पड़ेगा ? इसलिए मुनाफा जो पहले १० रुपए एक अदद पर था, वह अब १६ हो गया। या तो यो भी हो सकता है कि कारखानेदार की आज यह शक्ति है कि पहले जहा

बाहर की चीज का पड़ना १०० रुपए का था और कारखानेदार मुनाफे को अक्षुण्ण रखते हुए १०० रुपए में कम में नहीं बेच सकता था, आज वह विदेशी माल का पड़ता १२५ रुपया होने पर भी १० रुपए का ही मुनाफा रखे तो ११८ रुपया १२ आने में बेच सकता है।

इस हिमाय से यह सही है कि कारखानेदार का मुनाफा बढ़ गया, और यदि वह अपने दाम नहीं घटाता तो मुनाफा १० के बजाय १६ हो गया, याने ६२॥ प्रतिशत बढ़ गया। पर साथ ही यह भी जानना चाहिए कि जिनस्तो के दाम बढ़ने के कारण उस मुनाफे की ताकत ६२॥ प्रतिशत नहीं बढ़ी। यदि जिनस्तो के दाम औसतन सवाए हो गए हैं, जैसा कि हमने हिसाब लगाया है, तो फिर दाम बढ़ने के पहले जो करामात १३ रुपए में थी वही आज १६ में है। मान लीजिए कि पहले १३ रुपए में १ मन पाट मिलता था और अब पाट के दाम बढ़ कर सवाए हो गए—अर्थात् १६ हो गए, तो पहले के १३ और अबके १६ रुपए की क्रय-शक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ा। खैर।

तो अब इस परिस्थिति के दो असर साथ-साथ हुए। एक तो स्वदेशी उद्योग-धंधों पर, और दूसरा विदेशी आयात पर और निर्यात पर। स्वदेशी उद्योग-धंधों पर अच्छा असर हुआ। विदेशी आयात मुरझाने लगा, और निर्यात पतपने लगा।

सबसे पहले स्वदेशी उद्योग-धंधों को लीजिए।

यह स्वाभाविक है कि जब मुनाफा बढ़ता है तो कारखानेदार या माल उपजानेवाले को ज्यादा माल पैदा करने की चाह होती है। ऊपर के हिसाब में हमने मान लिया है कि मजदूरी भी अन्य जिनस्तो के दामों के साथ-साथ बढ़ने लगती है। पर व्यवहार में ऐसा होता नहीं। जब जिनस्तो के दाम बढ़ते हैं तो मजदूरी भी जब तक उसी अनुपात से नहीं बढ़ती तब तक कारखानेदार को हमारी कूत में भी मुनाफा अधिक रहता है। इसके फलस्वरूप कारखानेदार माल ज्यादा पैदा करने लगता है, कारखाना बढ़ाने भी लगता है। नए-नए कारखाने भी खुलने लगते हैं। अधिक लोगो को मजदूरी मिलने लगती है।

१०	घिसाई
५	व्याज
१०	मुनाफा
<hr/>	
१००	

अब मान लीजिए फुलावट-नीति के कारण जिन्सो के दाम बढ़े और जिस माल का कारखानेदार को पहले १०० रुपया मिलता था उसका अब १२५ रुपया मिलेगा। इसके साथ-साथ, मान लीजिए, कच्चे माल का दाम भी बढ़ा और मजदूरी भी उसी अनुपात में बढ़ी, तो फिर मुनाफे पर क्या असर होगा ? नीचे के तलपट से इसका स्पष्ट अन्दाज लग जायगा।

	पुरानी कीमत रुपया	नई कीमत रुपया
कच्चा माल	५०	६२½
मजदूरी	२५	३१
घिसाई	१०	१०
व्याज	५	५
मुनाफा	१०	१६
	<hr/>	<hr/>
	१००	१२५

उपरोक्त तफसील से पता लगेगा कि जहाँ कच्चे माल और मजदूरी का दाम २५ रुपया प्रतिशतक बढ़ा वहाँ घिसाई और व्याज में पुराने और नए खर्च में कोई फर्क नहीं पड़ा। कारण प्रत्यक्ष है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, फुलावट और गिरावट के कारण लेन-देन की रकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। १०० रुपए हमने कर्ज ले रखा था तो आज भी हमें १०० रुपया ही चुकाना है। इसलिए व्याज पर कोई असर नहीं पड़ता। और घिसाई पर भी क्या असर पड़ेगा ? इसलिए मुनाफा जो पहले १० रुपए एक अदद पर था, वह अब १६ हो गया। या तो यो भी हो सकता है कि कारखानेदार की आज यह शक्ति है कि पहले जहाँ

बाहर की चीज का पड़ता १०० रुपए का था और कारखानेदार मुनाफे को अधुण्ण रखते हुए १०० रुपए से कम में नहीं बेच सकता था, आज वह विदेशी माल का पड़ता १२५ रुपया होने पर भी १० रुपए का ही मुनाफा रखे तो ११८ रुपया १२ आने में बेच सकता है।

इस हिसाब से यह सही है कि कारखानेदार का मुनाफा बढ़ गया, और यदि वह अपने दाम नहीं घटाता तो मुनाफा १० के बजाय १६ हो गया, याने ६२॥ प्रतिशत बढ़ गया। पर साथ ही यह भी जानना चाहिए कि जिन्सों के दाम बढ़ने के कारण उस मुनाफे की ताकत ६२॥ प्रतिशत नहीं बढ़ी। यदि जिन्सों के दाम ओसतन सवाए हो गए हैं, जैसा कि हमने हिसाब लगाया है, तो फिर दाम बढ़ने के पहले जो करामात १३ रुपए में थी वही आज १६ में है। मान लीजिए कि पहले १३ रुपए में १ मन पाट मिलता था और अब पाट के दाम बढ़ कर सवाए हो गए—अर्थात् १६ हो गए, तो पहले के १३ और अबके १६ रुपए की श्रम-शक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ा। खैर।

तो अब इस परिस्थिति के दो असर साथ-साथ हुए। एक तो स्वदेशी उद्योग-धंधों पर, और दूसरा विदेशी आयात पर और निर्यात पर। स्वदेशी उद्योग-धंधों पर अच्छा असर हुआ। विदेशी आयात मुरझाने लगा, और निर्यात पनपने लगा।

सबसे पहले स्वदेशी उद्योग-धंधों को लीजिए।

यह स्वाभाविक है कि जब मुनाफा बढ़ता है तो कारखानेदार या माल उपजानेवाले को ज्यादा माल पैदा करने की चाह होती है। ऊपर के हिसाब में हमने मान लिया है कि मजदूरी भी अन्य जिन्सों के दामों के साथ-साथ बढ़ने लगती है। पर व्यवहार में ऐसा होता नहीं। जब जिन्सों के दाम बढ़ते हैं तो मजदूरी भी जब तक उसी अनुपात से नहीं बढ़ती तब तक कारखानेदार को हमारी कूत में भी मुनाफा अधिक रहता है। इसके फलस्वरूप कारखानेदार माल ज्यादा पैदा करने लगता है, कारखाना बढ़ाने भी लगता है। नए-नए कारखाने भी खुलने लगते हैं। अधिक लोगों को मजदूरी मिलने लगती है।

इसका प्रभाव बाहर से आनेवाली चीजों पर भी पड़ता है। चूँकि कारखानेदार का मुनाफा बढ़ा है, इसलिए उसमें यह ताकत आ जाती है कि वह मुनाफे को थोड़ा कम करके भी विदेशी चीजों के मुकाबिले में अपना माल सस्ता बेच सके। विदेशी चीजों का ऐसी प्रतिद्वंद्विता में टिकना मुश्किल हो जाता है। विदेशी आयात पर इससे बुरा असर पड़ता है।

इसके विपरीत, निर्यात पर अच्छा असर होता है, क्योंकि जब ऊँचे पड़ता की वजह से यहाँ दाम ऊँचा हो गया पर विदेशों में हमारी चीज का दाम वही पुराना है, तब यहाँ के उपजानेवाले थोड़ा सा यहाँ भाव मदा कर दे तो विदेश में भाव पुराने दामों से भी सस्ता हो जायगा। और इस तरह विदेशों में हमारे माल की बिक्री बढ़ेगी। सारांश यह कि अपनी मुद्रा की कीमत गिरा देने से हमारे कल-कारखाने, उद्योग-धंधे सब पनप उठते हैं, विदेशी आयात पर प्रहार होने लगता है; विदेशी निर्यात जागने लगता है। इस तरह देश की समृद्धि बढ़ने लगती है।

दर गिरने से लाभ स्थायी या अस्थायी ?

यह प्रश्न हो सकता है कि जरा हुण्डी के हेरफेर से या मुद्रा की कीमत कम कर देने से समृद्धि बढ़ने का क्या वास्ता? वास्ता है। वह इस तरह से।

एक आलसी मनुष्य है, वह न खेत बोना है, न मेहनत करता है। इसलिए दारिद्र्य ने उसके घर पर प्रभाव जमा रखा है। अब किमीने उसमें कहा कि हम तुम्हें रोजमर्रा कुछ मिठाई खिराएंगे, कुछ तमाशे दिसाएंगे और कुछ अच्छे कपड़े भी देंगे, बशर्ते कि तुम अपने खेत को मेहनत के साथ जोतो और उसमें जो फमल हो उसका आधा हिस्सा हमें दे दो। वह आलसी मिठाई और अच्छे कपड़ों के प्रलोभन में आकर काम करने लगता है, और अन्त में अच्छी फमल तैयार कर लेता है। फसल के आधे हिस्से की आमदनी वह प्रलोभन देनेवाले सज्जन को सौंप देता है। इस सज्जन को तो, उसने जितना मिठाई इत्यादि पर खर्च किया था उसकी पूरी कीमत उस फमल के आधे हिस्से में से बमूल हो जाती है, और उस आलसी को अच्छा खाने-पहनने को मिला, और आधी फसल मिली जिससे उसकी

समृद्धि बढ़ गई। इसके अलावा उसकी आदत भी तो बदली। काम करते-करते वह आलसी कर्मशील बन गया। प्रलोभन देनेवाले सज्जन का कुछ व्यय नहीं हुआ, और आलसी कर्मण्य बन गया।

अब कोई कहे कि हुण्डी की दर गिरने और समृद्धि से क्या वास्ता? तो यह भी कहा जा सकता है कि आलसी के मिष्टान्न-भोजन से उसकी समृद्धि का क्या वास्ता? पर बात यह है कि गिरती हुई हुण्डी की दर, या दूसरे शब्दों में, गिरती हुई मुद्रा की कीमत माल उपजानेवालों के दिलों में एक तरह का उत्साह और तृष्णा पैदा करती है, जो उन्हें ज्यादा काम करने के लिए खदेड़ती है, और इस तरह देश की समृद्धि पर इसका अच्छा असर होता है।

ठीक इसका विपरीत असर गिरावट की नीति का होता है।

हमने यह बताया है कि यह अच्छा असर मुद्रा की गिरती हुई कीमत का होता है। पर एक दफ़ा कीमत गिरा दी गई, फिर भी क्या उसका असर होता है?

होता है, पर आशिक। हमने पप का पहिया घुमाया और पानी कुएँ में से निकलने लगा। जब पहिया घुमाना बन्द कर दिया तब पानी भी निकलना बन्द हो गया। इसी तरह जब हुण्डी की दर गिरती ही रहती है तब तो चीजों के दाम भी बढ़ते ही चले जाते हैं और उससे पैदा होनेवाले नतीजे—जैसे उद्योग-धंधों की उन्नति, अधिक माल की पैदाइश, बेकारों को रोजगार, विदेशी आयात को ठेस, निर्यात की पुष्टि इत्यादि अपना प्रभुत्व जमाए रखते हैं। उसी तरह हुण्डी की गिरी हुई दर भी एक जगह आकर जब स्थिर हो जाती है और लोगों को उसकी स्थिरता में विश्वास आ जाता है, तब गिरती हुई हुण्डी से जो नतीजे पैदा हुए थे वे धीरे-धीरे करके रफ़ा होने लगते हैं—अर्थात् पप में से पानी निकलना धीरे-धीरे बन्द हो जाता है।

पर इसके माने यह नहीं कि हुण्डी गिरा कर फिर स्थिर कर दी तो उसका कोई असर ही नहीं हुआ। जो पानी कुएँ से निकल आया उसकी भी तो कोई कीमत है। उस निकले हुए पानी से हमने सिंचाई की,

धान पैदा किया, उससे हम पुष्ट वने। पुष्ट बन कर हमने मेहनत ज्यादा की। उस मेहनत से फिर नई सम्पत्ति पैदा की, और इस तरह से समृद्धि-चक्र जो चला तो फिर चलता ही गया। इस दृष्टि से गिराई हुई मुद्रा की दर का लाभ भी एक दृष्टि में स्थायी-सा हो गया।

पर यह भी कोई कह सकता है कि फिर हुण्डी की दर गिरने में इस तरह लाभ होता है तो हम दर को गिराते ही क्यों न जायें ? स्थिर करे ही क्यों ? इस रामबाण औपधि से अघाना ही क्यों ? अफसोस ! मकर-ध्वज के सेवन में शरीर की चपलता अवश्य बढ़ती है, पर वह स्वयं मनुष्य की क्षुधा को नहीं भेटता। और ज्यादा भोजन से तो शरीर का अन्त भी हो सकता है। फिर यदि हम मुद्रा की दर को गिराते ही चले जायें तो एक समय ऐसा आ सकता है कि जब मुद्रा की साख में किसीको श्रद्धा ही न रहे और मुद्रा स्वयं नेस्तनाबूद हो जाय। और फिर तज्जनित हानि-लाभ भी कहा रहे ? जब शरीर ही नहीं तो प्राण कहा ? मुद्रा ही मर मिटे, तो उससे होनेवाले हानि-लाभ कहा रहे ? और यदि मुद्रा की कीमत गिरा देना ही एक जादू का डबा हो, जो एक पल में समृद्धि पैदा कर दे, तो फिर हर मुल्क ही इसका प्रयोग क्यों न करे ? और यदि हर मुल्क इसका प्रयोग करने लग जाय तो दो देशों के बीच जो हुण्डी की घटा-बढ़ी से हानि-लाभ होता है वह होने ही नहीं पाए। दो लकीर पाम-पास में हो, और एक बड़ी हो, तो दूसरी छोटी कहलायगी। पर यदि बड़ी को काट कर छोटी कर दी जाय तो, जो पहले छोटी थी वह अब बड़ी कहलायगी।

हुण्डी गिरने के माने भी तो यही है कि हमने अपनी मुद्रा की दर गिरा दी, अन्य मुल्कवालों ने नहीं गिराई। ऐसी हालत में अपेक्षाकृत हमारी मुद्रा मस्ती हो गई। पर यदि दूसरे देशवालों ने भी गिरा दी, तो फिर हमारी हुण्डी की दर दूसरे देशों के मुकाबिले में नीची नहीं रही। और ऐसी हालत में विदेशी आयात-निर्यात पर कोई अच्छा-बुरा असर नहीं हुआ। बताना तो यह है कि हुण्डी गिरने का असर पूर्णतया स्थायी नहीं है, एक अंश में स्थायी है। मकरध्वज-भोजन का कुछ तो लाभ शरीर को मिलता ही है। हुण्डी गिराने में समाज की आर्थिक स्थिति को जो एक मर्तवा लाभ मिलता

है उसका स्थायी असर भी रह ही जाता है। ठीक इसके विपरीत, गिरावट-नीति द्वारा मुद्रा की दर चढ़ा कर समाज की आर्थिक स्थिति को हानि पहुँच जाती है, वह भी स्थायी नुकसान कर बैठती है। छाती में जो मेल लगा उसका घाव तो रुझ गया, पर उसका दाग तो रह ही गया, और वह जगह भी सदा के लिए नाजुक बन गई।

कभी-कभी तो ऐसा देखा गया है कि ससार की बड़ी-बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं की तरह में एक छोटी-सी घटना हुई है, जिसको इतिहास लिखने-वालों ने कम महत्त्व दिया। प्रशिया के फ्रेडरिक दी ग्रेट को महान बनने का मौका यो मिला कि ऑस्ट्रिया का शाहन्शाह मर गया। पर ऑस्ट्रिया का शाहन्शाह भी तो इसलिए मरा कि वह एक रोज कुतुरम्ते की तरकारी बहद परिमाण म खा गया। 'विधि का लिखा को मेटनहारा' यह उक्ति सही है। पर विधि भी जब कोई बड़ी होनहार को घटने बैठता है तब शुरुआत एक नगण्य चीज से करता है। ऑस्ट्रिया के शाहजादों के खून ने यूरोप में खून की नदिया बहा दी। दुर्योधन और अर्जुन, जब दोनों श्रीकृष्ण के पाम महाभारत-युद्ध के लिए सहायता मागने गए तब यदि दुर्योधन श्रीकृष्ण के सिरहाने न बैठ कर पैताने बैठता, या तो श्रीकृष्ण की सेना न लेकर स्वयं श्रीकृष्ण को अपने पक्ष में लेता, तो महाभारत-युद्ध का अन्त क्या होता, यह बताना कठिन है।

पर कोलम्बस ने अमेरिका का आविष्कार किया, और नई दुनिया से व्यापार-रोजगार चमक उठा। उसके कारण यूरोप भर में सरसब्जी फैल गई, ऐसा यूरोप के आर्थिक इतिहासज्ञ मानते हैं। अमेरिका की भूमि क्या मिली, यूरोप के लिए तो गड़ा सोना मिल गया। और केलीफोरनिया में तो सचमुच सोने की खानें मिल गई जिन्होंने यूरोप की समृद्धि को खूब वृद्धि की। इन सबका यूरोप पर कितनी मात्रा में असर हुआ, यह चाहे न मापा जा सके, पर जो जाहोजलाली की बाढ़ यूरोप में आ गई उसने उसको सदा के लिए सम्पन्न कर दिया, इसमें कोई शक नहीं।

इसलिए, हृष्टी गिरने का असर चाहे अस्थायी हो, पर एक मर्तवा

मिला हुआ, सहारा कमजोर शरीर के पनपने में काफी सहायता पहुँचा देता है ।

फुलावट—नियंत्रित और अनियंत्रित

फुलावट-नीति के शुभ परिणामों का भी हमने जिक्र किया और अति मात्रा में उसके बुरे नतीजों का भी वर्णन किया । यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि जहाँ फुलावट-नीति केवल व्यापार-रोजगार को चमकाने के लिए, उद्योग-धंधों को पनपाने के लिए काम में लाई जाती है, वहाँ फुलावट स्वल्प मात्रा में, और नियन्त्रण के साथ, उपयोग में लाई जाती है ।

हम बता चुके हैं कि जब फुलावट द्रुत गति से अनियन्त्रित होकर चलती है तब व्याज सस्ता नहीं, महंगा—अत्यन्त महंगा हो जाता है । महंगा व्याज भी रोजगार-व्यापार के लिए घातक है । इसलिए स्वेच्छा से जब फुलावट-शस्त्र का प्रयोग होता है तब सारी नीति पर इस हिसाब से नियन्त्रण रखा जाना है कि जिसमें सिक्के की साख में से लोगों की श्रद्धा न टूटे, लोगों में इसके सम्बन्ध में भय या भवराहट का संचार न हो, व्याज की दर साधारणतया ठीक हो और दामों में तेजी इतनी ही आवे जितनी कि संचालक चाहते हों । इसके माने यह हुए कि ऐसी नीति तो स्वेच्छा में ही काम में लाई जाती है, और उसी हालत में काम में लाई जा सकती है जबकि देशकी सरकार प्रजा का विश्वासभाजन हो, बलिष्ठ हो और देश और परदेश में उस सरकार और उस देश की पूरी धाक हो । और चूँकि यह मारा-का-सारा रोल अपने देश में उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन देने के लिए और लोगों में नई आर्थिक जागृति पैदा करने के लिए खेला जाता है इसलिए यह फुलावट भी स्वल्प मात्रा में ही होती है ।

पर इसके विपरीत, जहाँ फुलावट अनियन्त्रित होती है—जैसा कि रूस, जर्मनी वगैरह के सम्बन्ध में हम ऊपर बता चुके हैं—तब इसका परिणाम दूसरी तरह का होता है । यह सही है कि उस फुलावट में भी कल-कारगाने बेहद पनपते दिग्गडें देते हैं, पर मुद्रा की शक्ति का इस जोर में ह्रास होता चला जाता है कि वह करोड़ों का मुनाफा हजारों के मुकाबिले में भी बलहीन

होता है । और दूसरी तरफ सरकार और देश की साख में इतने जोर का धक्का पहुँचता है, कि जिनके पास पूजा होती है वे तबाह हो जाते हैं । लोग अपना माल-मत्ता, सम्पत्ति आदि बाहर भेजने लगते हैं । परस्पर की साख में भी विश्वास हट जाता है । अन्तरराष्ट्रों में देश की साख कौड़ी की रह जाती है । सारा आर्थिक तन्त्र छिन्न-भिन्न हो जाता है ।

ऐसी स्थिति अवश्य ही अवाछनीय है, और यह स्पष्ट है कि जान-बूझ कर ऐसी स्थिति को कोई निमन्त्रण नहीं देता । यह तो मजदूरी से ही आती है । देश का दिवाला निकलने का दूसरा नाम यह उग्र फुलावट है, जिसे राज-दुराजी के जमाने में ही सरकार बलात् बाध्य होकर अपनाती है । सरकार को जब राजतन्त्र चलाने के लिए कर-संग्रह में भी कटिनाई आने लगती है तब कागज, स्याही और प्रेस की शरण लेकर इस जोर से नोट छापना शुरू करती है कि इस ताण्डव नृत्य को देख कर एक छिन के लिए भी कोई अपने पास नोट रखने की हिम्मत नहीं करता ।

हम बता चुके हैं कि चलण का मूल्य स्थिर नहीं, पर घटता-बढ़ता है। तो भी जन-समाज के मन पर एक ऐसी थोथी और बेबुनियाद छाप पड़ी हुई है कि चलण का मूल्य स्थायी है। यदि ऐसा नहीं होता तो जिम निर्भयता के साथ लोग रुपया उधार देते हैं और सरकारी कागजों में लगाते हैं वैसा कभी नहीं होता। पर मनुष्य तो प्रायः वर्तमान का पूजारी होता है, और पुरानी स्मृति कटु भी हो तो उसे भूल जाता है। इसलिए जब तक कोई भयकर युद्ध, विप्लव या आकस्मिक घटना के कारण चलण की कीमत बुरी तरह नहीं गिरने लग जाती तब तक साधारण मनुष्य को तो पता भी नहीं चलता कि चलण की कीमत गिरी है क्या। साधारण फुलावट यदि नियन्त्रित हो तब तो आम जनता को पता भी नहीं चलता कि पर्दे के पीछे क्या नाटक खेला जा रहा है। तो भी जिन्सों के दामों के आकड़ों का हम सूक्ष्म अध्ययन करें तो हमें सहज ही पता लग जायगा कि पिछले सौ सालों में चलण के मूल्य में घटा-बढ़ी होती ही रही है।

जिन्सों के दामों के आकड़े कैसे तैयार होते हैं इसका संक्षिप्त विवरण भी जान लेना चाहिए। मान लीजिए कि हमारे देश के गरीब किसान अधिकतर गेहूँ, बाजरा, मोट, चना, धी, तेल, दियासलाई, कपड़ा, गुड़, इत्यादि—४० या ५० चीजों का उपयोग करते हैं। तो आकड़े तैयार करने वाले विशेषज्ञ उन सब जिन्सों के दामों का एक गड-पडता निकाल लेते हैं। वह गड-पडता साधारण तरह से यो निकाला जाता है कि जिस साल को हम बुनियादी साल मानते हैं उसके गड-पडता का अंक मी मान लिया जाता है। मान लीजिए, मन् १९१४ को हमने बुनियादी साल माना। उस साल में

गेहूँ का भाव था

५ रुपया मन

जौ का भाव था

४ रुपया मन

तेल का भाव था	२० रुपया मन
घी का भाव था	४० रुपया मन
गड का भाव था	५ रुपया मन
कपडे का भाव था	४ आने गज

(यह महज उदाहरण है, इसीलिए ४०-५० चीजों के दाम न देकर सिर्फ ६ जिन्सों के दाम दिए हैं।)

तो हमने उस माल की जिन्सों की कीमत १०० के अंक पर कायम कर दी। अब १९४१ में मान लीजिए—

गेंहूँ का भाव था	६१ रुपया मन (याने २५ प्रतिशत बढ़ा)
जौ का भाव था	५ रुपया मन (याने २५ प्रतिशत बढ़ा)
तेल का भाव था	१५ रुपया मन (याने २५ प्रतिशत घटा)
घी का भाव था	८० रुपया मन (याने १०० प्रतिशत बढ़ा)
गुड़ का भाव था	२११ रुपया मन (याने ५० प्रतिशत घटा)
कपडे का भाव था	६ आने गज (याने ५० प्रतिशत बढ़ा)

तो—

१ वस्तु में	२५ प्रतिशत बढ़ा
१ "	२५ " बढ़ा
१ "	२५ " घटा
१ "	१०० ' बढ़ा
१ '	५० " घटा
१ "	५० " बढ़ा

तो १२५ प्रतिशत कुल बढ़ा, और ६ जिन्सों द्वारा १२५ प्रतिशत को विभाजित किया तो फल यह निकला कि एक जिन्स पर २० $\frac{१}{५}$ प्रतिशत वृद्धि हुई (१ $\frac{३}{५}$ = २० $\frac{१}{५}$ प्रतिशत) — अर्थात् जिन्सों की दर १०० में बढ़ कर १२० $\frac{१}{५}$ हो गई। तात्पर्य यह हुआ कि जिस चलण की ऋण-शक्ति १९१४ में १०० थी वह १९४१ में २० $\frac{१}{५}$ प्रतिशत कम हो गई। दूसरे शब्दों में, चलण का दाम २० $\frac{१}{५}$ प्रतिशत गिर गया।

सूचक अंक

इस तरह जिन्सों की दर के जो अंक तैयार किए जाते हैं उन्हें हम "सूचक अंक" के नाम से पुकार सकते हैं। अब १९१५ से १९४० तक के सूचक अंक नीचे की तालिका में देते हैं। इससे पता लगेगा कि चलण की क्रय-शक्ति में कितनी घटा-बढ़ी हुई है, अर्थात् चलण की कीमत किस कदर घटती या बढ़ती रही है।

कलकत्ते में कुछ खास चीजों के थोक दाम

१९१४ = १००

१९१५	औसत	११२	१९२८	औसत	१४५
१९१६	"	१२८	१९२९	"	१४१
१९१७	"	१४५	१९३०	"	११६
१९१८	"	१७८	१९३१	"	९६
१९१९	"	१९६	१९३२	"	९१
१९२०	"	२०१	१९३३	"	८७
१९२१	"	१७८	१९३४	"	८९
१९२२	"	१७६	१९३५	"	९१
१९२३	"	१७२	१९३६	"	९२
१९२४	"	१७३	१९३७	"	१०२
१९२५	"	१५९	१९३८	"	९६
१९२६	"	१४८	१९३९	"	१०८
१९२७	"	१४८	१९४०	"	१२०

पर यह भी सही है कि चलण की कीमत के म्याथिन्व में जितनी श्रद्धा यूरोपवासियों की रही उतनी उस देश के लोगों की न रही। हमारे पिछले इतिहास में समय-समय पर इनके राज्य बदलते रहे हैं, इनके दंगे-फसाद होते रहे हैं कि इसके कारण भारतवासियों को स्वभाव में ही सोते-चांदी में मोह ज्यादा रहा। इसके विपरीत उगिल्स्तान में, बाहर के आक्रमणों में

मुक्त रहने की वजह, वहाँ के लोगों में काफी अमन-चैन रहा। नतीजा यह हुआ कि स्वभाव से ही चारों ओर शान्ति और व्यवस्था दिखाई देती रही, और इसलिए उन्हें अपनी सरकार की साख में श्रद्धा भी ज्यादा रही। लंदन नाणे का एक वृत्त बाजार बन गया और अंग्रेजों की देखा-देखी हमने भी सरकारी कागजों में और तरह-तरह के शेयरों में रुपया लगाना सीख लिया।

चलण की कीमत गिरती आई है

पर वताना तो यह था कि चलण की कीमत स्थायी नहीं रही, और दूसरी बात यह वतानी थी कि चलण की कीमत गिरा कर अपना उल्लू सीधा करने का तरीका इतिहास में हर सल्तनत ने—जब वह विपद्यस्त हुई तब—बिना किसी हिचकिचाहट के अस्तियार किया है। रोम की प्राचीन सरकार ने हजारों साल पहले अपने चलण को अशत खोटा करके अपना खजाना भरा, तभी से हर सल्तनत ने यह पाठ सीख लिया। और चलण के दाम गिरा कर प्रजा की बिना जानकारी के कर-वसूली का यह अद्भुत तरीका मौके-मौके पर हर सरकार ने विपद् के समय अपने लाभ के लिए कामयाबी के साथ आजमाया।

बात यह है कि सिक्का जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, उसके चलण का संपूर्ण अधिकार तो हर देश की सरकार के पास रहता है। और इस अधिकार का दुरुपयोग करके भी यदि कोई सल्तनत अपना दिवाला दवा सके और राज्यच्युत होने से अपने-आपको बचा सके तो कौन ऐसी सयमी सल्तनत हो सकती है जो इस अधिकार का दुरुपयोग करने के लोभ का सवरण कर सके? इसलिए जहाँ किसी सल्तनत पर आपत्त आई, कोई बड़ा बलवा होने को है या कोई बड़ा युद्ध छिड़ गया और धन की बड़ी राशि की जरूरत आ पड़ी और प्रजा सीधी तरह से देने की तैयार नहीं, यदि जबरन लिया जाय तो क्रांति की आग धधक उठती है, लोगों की रहीं-सही सहानुभूति भी गायब हो जाती है, तो ऐसे विकट समय में सबसे सीधा और सहज मार्ग कर-वसूली का यही रह जाता है कि नोट छापे जाओ,

और उसीसे अपना खर्च चलाए जाओ। धन की जरूरत पड़ी और सीधी अगुली से धीन निकला तो फिर चलण के दाम गिरा कर टेढ़ी अगुली से—चाहे वह फिर अधिकार का दुष्योग ही न्योन हो—धीन निकाला।

पर एक बात और है। चलण के दाम गिराने में ऐसी विपद्ग्रस्त सरकार का तो स्वार्थ रहता ही है, पर प्रजा के एक दल-विशेष की भी सहानुभूति रहती है। हमने पहले बताया है कि चलण के दाम गिरने से कर्जदार और बंधी मालगुजारी देनेवाले और अन्य ऐसे लोग, जिनका दायित्व बंधी हुई रकम में हो, उन्हें लाभ होता है। इसलिए ऐसे सब लोग चलण के दाम गिरने के स्वभाव से ही पक्षपाती होते हैं, और विपद्ग्रस्त सरकार को तमाम ऐसे लोगों की सहानुभूति अपने आप मिल जाती है। प्रख्यात अर्थ-शास्त्री श्री केयन्स ने सच कहा है—

“चलण का मूल्य जब गिरता है तब उसका लाभ केवल सरकार तक ही सीमित नहीं रहता। किसान, कर्जदार और अन्य लोग, जिन्हें अपने-अपने क्षेत्र में एक निर्धारित रकम देनी पड़ती है—मसलन व्याज या मालगुजारी इत्यादि—वे सब-के-सब उस लाभ में शरीक हो जाते हैं। जैसे आर्थिक क्षेत्र में आजकल व्यापारी लोग समाज के एक रचनात्मक और श्रियात्मक अंग माने जाते हैं, वैसे ही प्राचीन समय में किसान इत्यादि एक विशिष्ट अंग माने जाते थे, और सततनत पर इनका प्रभाव तो पड़ता ही रहता था। कोई भी मासार्थिक परिवर्तन, जो द्रव्य के मूल्य को ठेस पहुँचाता था, वह नए आदमियों के लिए एक रसायन का काम कर जाता था। यह परिस्थिति पुराने लोगों की दौलत का नाश करके नए लोगों के पास दौलत ला देती थी। जिन्होंने धन संग्रह करके रखा था उनका सातमा करके व्यवसायशील लोगों को यह परिस्थिति सहायक हो जाती थी। कुदरत का यह खेल ऐसा लगता है मानो संग्रह और श्रिया के बीच के संग्राम में द्रव्य के मूल्य का गिरना श्रिया का पक्ष लेता रहा हो। द्रव्य के मूल्य के गिरने की प्रवृत्ति ने बपीनी धन और उस पर चक्रवृत्ति व्याज खानेवाले इन्मान की सामर्थ्य पर काफी आक्रमण किया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि बपीनी शक्ति को अवमंथ्य होकर भोगने की वृत्ति को उसने जबरदस्त धक्का मारा।

उस परिक्रिया ने हर पीढ़ी को वर्षाती सम्पत्तिके उत्तराधिकार से एक तरह से वंचित-ना कर दिया । जो हो, विपद्ग्रस्त सरकार की जहरते और कर्जदार वर्ग की आवश्यकताएँ, इन दो प्रभावों ने मिल कर, कभी एक तो कभी दूसरी शक्ति ने, द्रव्य के मूल्य का लगातार घटाना जारी रखा है । यह क्रिया ईसा के ६०० साल पहले, जब पहले-पहल सिक्का चला, तभी से न्यूनाधिक रूप से चलती आ रही है ।”

फुलावट का यह एक दिलचस्प पहलू है । किन तरह समाज की भिन्न-भिन्न श्रेणियों का स्वार्थ सिक्के के मूल्य के साथ बढ़ा है, किस तरह जान-बूझ कर समाज की कुछ श्रेणियाँ चलण के मूल्य को गिरा देने के पक्ष में रहती हैं और असाधारण समय में लुटकनी हुई सन्तान के लिए भी चलण का मूल्य गिराना कितना उपयोगी शस्त्र है, यह ऊपर के कथन से जाहिर होता है ।

फूलावट एक तरह का कर—प्रच्छन्न कर है, यह कम लोग जानते हैं। पर यह ध्रुवसत्य है कि एक कमजोर सरकार भी, जिसके कर लगाने के अन्य सब साधन सूख गए हों, और जिसके लिए कोई भी कर उगाहना असभव-सा हो गया हो, इस अन्तिम शस्त्र का उपयोग करके प्रच्छन्न कर उपाजन कर सकती है। इस प्रच्छन्न कर का यह मजा है कि कोई कितना ही सरकार का विरोधी क्यों न हो, वह भी इस कर से बच नहीं सकता। इस पहलू को कुछ और विश्लेषण के साथ समझाने की जरूरत है।

जहाँ हमने “द्रव्य परिमाण मत” का जिक्र किया है वहाँ यह बतला दिया है कि अन्य सब स्थिति समान रूप से वर्तती हो तो जितना ही चलन में हम द्रव्य का अधिक प्रवेश करावेगे उसी अनुपात से द्रव्य का मूल्य गिरेगा और जिनमो के दाम चढ़ेंगे। इसका फिर एक उदाहरण दे देना अच्छा होगा।

मान लीजिए कि सामान्य अवस्था में हमारे यहाँ २५० करोड़ रुपए के नोट चलन में हैं, जिनकी सोने की कीमत १० करोड़ तोला सोना है। (एक तोला सोने की कीमत=२५ रुपए। इसलिए १० करोड़ तोला सोना $\times २५ = २५०$ करोड़ रुपए) तो यदि हमने चलन में २५० करोड़ रुपए के नोट और छाप कर डाल दिए, तो भी सोने की कीमत तो वही १० करोड़ तोले की रहेगी। पर चूंकि चलन में नोट अब ५०० करोड़ के हो गए, इसलिए जहाँ पहले २५० करोड़ रुपए के नोटों की कीमत १० करोड़ तोला सोना थी, अब ५०० करोड़ रुपए के नोटों की कीमत १० करोड़ तोला सोना रही—अर्थात् नोटों की सोने की माप में जो कीमत पहले थी उससे आधी हो गई। इसके माने यह भी हुए की जिनसो की कीमत दुगुनी हो गई—अर्थात् नोटों का चलन दुगुना हुआ, उसके अनुपात में नोटों का मूल्य तो आधा रह गया, पर जिनसो का मूल्य दुगुना हो गया।

अब सरकार को जो नए २५० करोड रुपए नए नोट छापने के कारण हासिल हुए वह सारा-का-सारा धन उन लोगो की जेब से निकला, जिनके पास चलण की धरोहर थी—अर्थात् ऐसे लोगो की जेब से निकला जो रुपया उधार देने का काम करते थे—जैसे बैंक, साहूकार इत्यादि, या तो जिन्हे जेब-खर्च के लिए भी अपनी जेब में कुछ नोट रखने पड़ते थे। इस २५० करोड की क्रय-शक्ति अवश्य ही पहले के मुकाबिले में घट गई, क्योंकि जिन्सो के दाम जो चढ़ गए। पर जब फुलावट-नीति पहले-पहल शुरू होती है तब लोगो के अज्ञान के कारण जिन्सो के दाम अचानक नहीं घट जाते, और इसलिए नए २५० करोड की क्रय-शक्ति भी शुरू-शुरू में पहले से बिल्कुल आधी शायद न होगी। अब सरकार इस तरह से यदि २५० करोड का कर उगाहती तो सैकड़ों अमेले होते, पचासो तरह का विरोध होता, कर-कानून बनाना पड़ता। इसके विपरीत, इस तरह से चुपचाप नोट छाप कर चलण में प्रवेश करा देने से सरकार ने चुपचाप अपना काम बना लिया।

इस कर से बचना असंभव-सा है

कोई कह सकता है कि क्या इस कर से कोई बच भी सकता है? हा, कल्पना में बच सकता है, पर व्यवहार में शायद ही। आखिर यह कर उसी की जेब से निकलता है, जिसके पास द्रव्य की धरोहर हो। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, यह कर एक तो इस तरह के लोगो की पाकेट से निकलता है जो उधार रुपया देते हैं; दूसरे, ऐसे लोग जिन्हे क्रय-विक्रय के लिए रोजगार-वधे के लिए कुछ-न-कुछ रुपया तो सिलक में रखना ही पड़ता है, उनकी जेब से भी यह कर निकलता है।

अब ये दोनों तरह के लोग कर से इस तरह बच सकते हैं कि उधार देनेवाले तो उधार देना बन्द कर दें, घर में जवाहरात इत्यादि रख छोड़ें, और क्रय-विक्रयवाले नोट का व्यवहार तक करना छोड़ दें। पर यह नाममकिन है। सूद पर उधार देनेवाले शायद उधार देना बन्द करके अपना धन जिन्सो में रोक दें, पर नित्य की खरीद-फरोस्त के लिए रुपए

का व्यवहार बन्द करना, यह दवा मर्ज से भी कहीं ज्यादा कष्टप्रद है। हम गहरे उतरने पर देखेंगे कि रोजमर्रा की खरीद-फरोख्त के लिए जो रुपया हम उपयोग में लाते हैं उसके कारण हर व्यक्ति पर यह नई तरह का कर इतनी कम भिन्नता में पड़ता है कि वजाय इसके कि वह रुपए का व्यवहार बन्द कर दे, एक नागरिक इस कर को अदा करना अधिक पसन्द करेगा।

हम एक अन्तिम सीमा का उदाहरण ले लें। मान लीजिए सरकार चलण में इतना द्रव्य प्रविष्ट करती है कि जिसके कारण हर महीने द्रव्य का मूल्य करीब आधा ही रह जाता है। अब यदि रोजमर्रा के व्यवहार के लिए हर मनुष्य दो दिन में ज्यादा फरोख्त किए हुए माल का रुपया अपने पास नहीं रखता, तो इसके माने यह हुए कि रुपए की एक महीने में १५ बार पट्टाई हुई—अर्थात् १५ बार भिन्न-भिन्न कामों के लिए उसी रुपए का उपयोग हुआ। द्रव्य का मूल्य गिरा एक महीने में ५० प्रतिशत। रुपए की पट्टाई हुई एक महीने में १५ बार। तो $५० - १५ = ३३$ । अर्थात् हर सौदे की लेवा-बेची पर ३३ प्रतिशत कर पड़ा। याने, १०० रुपए में जिस सौदे को खरीदते उसके $१०० + ३३$, अर्थात् १३३ रुपए असल में आपको देने पड़े। यह कर असाधारण जमाने के लिए इतना कम है कि केवल इससे बचने के लिए ही कौन रुपए का व्यवहार बन्द करेगा?

इसलिए, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इस कर से अत्यन्त विरोधी भी बच नहीं सकता, और निकम्मी-मे-निकम्मी सरकार भी यह कर उगाह सकती है। अमल में तो इस शस्त्र का उपयोग भी वही सरकार करती है, जिसका दिवाला निकलने जा रहा हो। हा, अन्य माथा में, और नियंत्रण के माथे, तो उद्योग-धंधों को पनपाने के लिए, जैसा कि पहले बताया चुके हैं, हर अच्छी सरकार भी फुलावट-नीति को समय-समय पर काम में लाती है।

पर यह भी मही है कि जिस तरह हर चीज की सीमा होती है वैसे ही इस शस्त्र की कामगार के बारे में भी कहा जा सकता है। जब माथे में रोगों की कोई श्रद्धा नहीं रहती तब लोग महज खरीद-बिक्री के लिए, और

मो भी अत्यन्त कम समय के लिए ही, अपने पास नोट रखते हैं। नतीजा यह होता है कि चलण को व्यवहार में लानेवाले इतने कम हो जाते हैं कि फिर हजारों मन नोट छाप कर चलण में प्रविष्ट करने पर भी कोई लम्बी रकम सरकार को हासिल नहीं होती। इसलिए इस शास्त्र की धार भी अंत में करीब-करीब भूठी-सी पड़ जाती है।

ऐसी भयंकर फ्लावट का एक परिणाम और होता है। सरकार का कर्ज तो अपने-आप चूक जाता है। जब द्रव्य का मूल्य इतना गिर जाय कि रुपया एक कौड़ी का भी न रहे तो, फिर हजारों-अरबों का देना-पावना भी केवल हिसाब-बहियों की शोभा की चीज रह जाता है, और इस तरह सरकार का कर्ज अपने-आप रफा हो जाता है। चूँकि सारा-का-सारा यह कर द्रव्य के धरोहरघानी की जेब से निकला, इसलिए इसे हम यदि पूजा-कर की भी उपमा दें तो यह अनुपयुक्त उपमा न होगी। पर यह पूजा-कर घुमाके नाक पकड़ने-जैसी चीज है। सीधे रास्ते से पूजा-कर लगाने में मनुष्य शास्त्रीय विधि का उपयोग कर सकता है। पर लुढ़कती हुई सलत-नत में सीधा मार्ग अस्तित्व करने की हिम्मत कहाँ? इसलिए यह अशास्त्रीय और भ्रष्ट मार्ग ऐसी विपद्ग्रस्त सरकार के लिए ज्यादा आसान होता है।

हमने अबतक फुलावट-नोति की चर्चा की। उससे पाठक के दिल पर यही असर होगा—और वह स्वाभाविक है, क्योंकि सारे विवेचन में ध्वनि भी वही निकलती है—कि फुलावट या गिरावट की क्रिया का संचालन केवल सरकार या नोट-प्रसारक बैंक के हाथ में ही रहता है। किन्तु यह बात अशत ही सही है। हृदय-दरजे की भयंकर फुलावट या गिरावट का संचालन तो अवश्य ही या तो सरकार कर सकती है या उसके इशारे से नोट-प्रसारक बैंक। पर, एक सीमा के भीतर, फुलावट या गिरावट अन्य बैंक या अन्य साहूकार भी पैदा कर सकते हैं।

हमने बतलाया है कि धन का प्रतीक मुद्रा, मुद्रा का प्रतीक नोट और नोट का या मुद्रा का प्रतीक चेक या हुडी हो जाती है। जिस आमासी की माख अच्छी है उसकी हुडी भी धन ही है। फुलावट या गिरावट नोटों के अधिक विस्तार या सकोच से पैदा होती है, क्योंकि नोट धन के प्रतीक है। तो उमी तरह चेको और हुडियो-द्वारा भी तो धन का प्रसार या सकोच किया जा सकता है, क्योंकि यह भी तो धन के प्रतीक है। वह इस तरह होता है—

मान लीजिए एक बैंक है या एक साहूकार है। उसके पास रुपया मिलकर में नकद पड़ा है, अथवा, सरकारी कागजों में, कम व्याज में रखा पड़ा है। न तो वह अक्रिय रकम किसी तरह के वाणिज्य-व्यवसाय में लगती है, न लेन-देन में काम आती है। उधार लेनेवालों की कमी नहीं, पर उन्हें बैंक या साहूकार की उस अक्रिय पूँजी से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अब व्यापार को पनपते देगकर पूँजी के स्वामी उस बैंक या साहूकार की रुपया उधार देने की इच्छा होती है। वह व्यापारियों एवं अन्य उधार लेनेवालों को रुपया देना शुरू करना है और इस तरह उस धन का उपयोग होने लगता है। अक्रिय रकम अब सक्रिय बन जाती है और जितनी ही रकम सक्रिय बनती जाती है, उतनी ही बाजार में नाणे की बहुतायत होती जाती है।

उधार की फुलावट

इस बहुतायत का वही असर होता है जो नोट-प्रसार के कारण होता है, वल्कि नोट-प्रसार से पैदा हुई फुलावट की अपेक्षा, उधार-द्वारा की गई फुलावट कभी-कभी ज्यादा शक्तिशाली भी होती है। एक करोड़ रुपए का नया नोट हम चलण में डालते हैं और सौ करोड़ का नोट पहिले से चलण में है, तो साधारणतया यह कहा जा सकता है कि एक प्रतिशतक फुलावट हुई और उसका साधारणतया (यदि और कोई नया मसला उलट-फेर का मौजूद न हो तो) उसी परिमाण में दामों पर भी असर होना चाहिए। पर उधार-द्वारा एक करोड़ की पूजी यदि नाणों के बाजार में प्रवेश करती है तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसका दामों पर असर, एक करोड़ की फुलावट के अनुपात से ही होगा।

हम कल्पना कर सकते हैं कि किसी आसामी के पास एक लाख का गल्ला पड़ा है जिसपर उस आसामी की रकम लगती है। उसे रुपया उधार न मिलने की वजह से उसका हाथ रुका पड़ा है। उसे अचानक बैंक से रुपए उधार मिल जाते हैं। अब उसका हाथ खुला हो जाता है। एक लाख रुपए से वह एक तेल का कारखाना खोलता है। उसे अब सरसों की जरूरत पड़ती है। सरसों बेचनेवाले आसामी के पास मुद्दत से सरसों पड़ी थी, वह बिक नहीं रही थी। उसे बेच कर सरसोंवाला आसामी एक बर्तन बनाने का कारखाना खोल लेता है। उसके लिए तावा खरीदता है। तावेवाले आसामी के पास मुद्दत से तावा पड़ा था जो बिक नहीं रहा था। तावा बिकते ही वह नया माल खरीदने लगता है। नया माल खरीदने से खानवाला काम बढ़ाता है। चारों तरफ से मजदूरों की माग होने से ठलुए मजदूरों को काम मिलता है। वे फिर ज्यादा कपड़ा खरीदने लगते हैं, तो कपड़े की पैदाइश बढ़ती है। उसके माने हैं—ज्यादा मजदूरों की माग, ज्यादा रुई की जरूरत। वस, इस तरह से बाजार की रोशनी जो फीकी हो चली थी, फिर चमकती है। उस चमक का दूसरी चीजों पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह उत्पन्न हुई आशावादिता चारों ओर प्रकाश डालती है और थोड़ी-सी रकम से, बड़ी-सी फुलावट भी आ सकती है।

हमने यह उदाहरण इसपर काफी रग चढाकर पेश किया है। ऐसा ही होता है सो नहीं, पर ऐसा हो सकता है, इतना ही बताना है। गरज यह है कि उधार से पैदा हुई फुलावट कभी-कभी अपने अनुपात से ज्यादा काम कर जाती है, क्योंकि उसके पीछे एक भावना रहती है, जो लोगों में आशा का संचार करके कभी-कभी आवश्यकता से अधिक सरगर्मी ला देती है। इसी तरह जब बैंक अपना उधार सिमेटती है तो आवश्यकता में ज्यादा मुर्दनी भी पैदा कर देती है।

अब हम देख सकते हैं कि उधार-द्वारा भी धन का विस्तार और सकोच और तज्जनित फुलावट या गिरावट पैदा की जा सकती है।

नोटों के प्रसार और सकोच से जो काम होता है, एक तरह से उधार के विस्तार और सकोच से भी वही काम होता है। दोनों चीजें एक तरह में तो एक ही हैं, क्योंकि दोनों के द्वारा धन का सकोच या विस्तार हो सकता है। पर बैंको या साहूकारों-द्वारा धन का विस्तार अर्थात् धन का चलण में प्रवेश तभी होता है जब कि व्यापार चलता हो या तो अच्छे चलने की आशा हो, कारखानेवाले कमाते हों, भविष्य उज्ज्वल दिखता हो। रुपया उधार देने में किसी तरह का खतरा न लगता हो, तभी उधार का विस्तार होता है। साख एक नाजुक चीज है जो लाजवती पौधे की तरह सतरे की आशका होते ही अपने डाल-पात को समेट लेती है। जहाँ ममय अच्छा आया, व्यापार 'पनपने लगा, कि पूँजीवाले उधार देने में बहादुरी दिखाने लगते हैं, और जहाँ सतरे की घटी बजी कि वे अपना बोरिया-बघना उठाने लगते हैं। इस तरह से उधार देनेवाले भी फुलावट और गिरावट के कर्ता बन जाते हैं। इस फुलावट या गिरावट को साख की फुलावट या गिरावट भी कह सकते हैं।

पर यह उधार की फुलावट या गिरावट सीमा के भीतर ही रहती है। किर्मी पूँजीवाले के पास अग्नित धन तो होता नहीं, मर्यादबद्ध धन ही होता है। इसलिए बैंक या साहूकार-द्वारा की गई फुलावट या गिरावट भी सीमा के भीतर बद्ध रहती है।

फुलावट-नीति का हमने विस्तार के साथ जिफ किया । गिरावट का हमने ज्यादा जिफ नहीं किया है । पर शायद यह समझाने की जरूरत नहीं कि गिरावट का परिणाम हर बात में फुलावट से उल्टा होता है ।

विपद्ग्रस्त सरकार धन उगाहने के लिए—चारों तरफ से उसकी चाल रुक जाती है तब—फुलावट-नीति का आसरा लेती है, या तो स्वल्प और नियंत्रित मात्रा में फुलावट उद्योग-धर्मों को पनपाने के लिए भी काम में लाई जाती है ।

तो फिर यह प्रश्न हो सकता है कि गिरावट-नीति का दौरदौरा कब होता है ?

गिरावट-नीति आम तौर में ऐसी दशा में प्रयोग में लाई जाती है जब कि सरकार तो व्यवस्थित है और व्यवस्था के साथ विशेष हेतु के लिए उस सरकार ने फुलावट-नीति का प्रयोग किया है, पर मात्रा से कुछ ज्यादा फुलावट हो गई है, और इसलिए, फुलावट का जोश ठंडा करने के लिए व्यवस्था के साथ अब कुछ गिरावट-नीति के प्रयोग की आवश्यकता है । ऐसी आवश्यकता पडने पर गिरावट-नीति का उग्र प्रयोग किया जाता है ।

पर जैसे फुलावट वेवसी की चीज है, वैसे ही गिरावट इस बात की धोतक है कि सरकार सहीसलामत है, उसकी ताकत या व्यवस्था में कोई कमजोरी नहीं है । गिरावट में तो चलण की साम्ब बढानी पडती है । इसलिए यह काम एक व्यवस्थित सरकार ही, और सो भी विशेष हेतु के लिए ही, कर सकती है । यह इसलिए स्वाभाविक है कि जिस तरह फुलावट असीमित हो सकती है, वैसे गिरावट सीमा के बाहर नहीं जा सकती ।

पर गिरावट-नीति के प्रयोग के उदाहरण ससार के आर्थिक इतिहास में कम मिलते हैं। ज्यादातर लोगो ने विवश होकर, या तो देश के उद्योग-धंधो की उन्नति के लिए, फुलावट-नीति का ही प्रयोग किया है। इसलिए फुलावट-नीति के गुण-दोषो का हम अच्छी तरह विवेचन कर लें नो काफी है, क्योंकि जो हानि-लाभ फुलावट के हैं उसको ठीक तरह समझने के बाद गिरावट के गुण-दोष अपने-आप समझ में आ जायगे।

जब गिरावट-नीति का प्रयोग होता है तब फुलावट-नीति से ठीक उल्टे नियमो को काम में लाया जाता है—अर्थात् किसी भी बहाने नोटो को चलण में से निकाल कर नोटो की एक बनावटी तंगी पैदा की जाती है। सरकारी खर्च के लिए, मान लीजिए, आवश्यकता है एक सौ करोड़ की और कर-वसूली की गई सवा सौ करोड़ की, तो जनता के पास से पचीस करोड़ का धन र्पंच लिया गया। और इसी परिमाण में जनता की क्रय-शक्ति कम हो गई, या तो व्याज ऊँचा देकर बिना किसी हेतु के सरकार ने पचीस करोड़ का ऋण ले लिया और उसे खर्चने के बजाय कोष में ही रख छोड़ा। तो इसका भी वही असर पड़ा—अर्थात् जनता की क्रय-शक्ति कम हो गई।

गिरावट कब वांछनीय है ?

जनता की क्रय-शक्ति को कम करने की यह नीति एक तरह से तो दम घोटने की नीति—जैसी लगती है। इसलिए ऐसी नीति को काम में लाना तभी वांछनीय हो सकता है जब कि सत्तनत को यह लगे कि जनता समृद्ध है और समृद्धि के नशे में वित्त-शाठ्य करने जा रही है—अर्थात् धूँत के बाहर खर्च करने की या व्यवसाय करने की जन-साधारण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसका आगे जाकर परिणाम भयानक हो सकता है। जब सरकार को ऐसी विपत्ति की आशका होती है तभी, जैसे दूध के उफान को ठाँ करने के लिए पानी में छोट दिया जाता है उसी तरह समृद्धि के उफान को—समृद्धि को नहीं, क्योंकि समृद्धि तो ठोस अमली चीज़ है, उफान धोखा है—आवश्यकानुसार गिरावट

का प्रयोग करके शान्त करना प्रजाप्रिय सरकार का कर्तव्य बन जाता है।

सरकार ने कर-वसूली से या ऋण-द्वारा जो धन जनता से खँचा उसका आखिर तो व्यय ही करना है। और वह व्यय उस समय किया जाता है जब कि उफ़ान के बाद की सुस्ती के मारे जनता भयभीत होकर अपनी सारी प्रगतियों को वन्द कर देती है, व्यय में आवश्यकता से ज्यादा कजूमि करने लगती है, व्यापारी मदी से भयभीत होकर अपने हाथ-पाव सिमेट लेते हैं, बेकारी बढ़ने लगती और जिन्सों के दाम गिरने लगते हैं। ऐसे समय में जनता को फिर प्रोत्साहन देने के लिए, अतिशय भाई हुई नदी को शान्त करने के लिए, ठंडे खून में फिर से गर्मी लाने के लिए, जनता से खँचा हुआ धन सरकार खर्चने लगती है। और जहाँ खर्च शुरू हुआ कि फिर ताजगी आने लगती है।

इसके यह माने नहीं कि हिन्दुस्तान में सरकार ने जो गिरावट का प्रयोग किया वह इसी सिद्धान्त पर किया और जब मदी ने तबाही शुरू की तब उसको रोकने के लिए फिर फुलावट का प्रयोग किया। यहाँ की कथा तो निराली है।

इस देश में गिरावट-नीति अनसर इसलिए काम में लाई गई है कि द्रव्य के परिमाण में कमी करके उसका मूल्य ऊँचा कर दिया जाय।

आगे जब हम भारतवर्ष की हुण्डी का विवेचन करेंगे तब गिरावट-नीति से इस देश की जिन्सों के दामों पर, कल-कारखानों पर, समृद्धि पर और आयात-निर्यात पर क्या असर हुआ, गिरावट की नीति को सफल बनाने के लिए कैसे करोड़ों रुपए बरबाद किए गए, इन सब बातों का विवेचन करने के लिए हमें काफी मौका मिलेगा।

फुलावट में दामों में तेजी, गिरावट में मन्दी, यह हमने बतलाया है। और फुलावट या गिरावट मुख्यतया सल्तनत की मर्जी की चीज है। कम-से-कम सरकार सहीसलामत रहे तो बेवसी की फुलावट को तो हम अनहोनी चीज करार दे सकते हैं। इसलिए सीमावद्ध फुलावट या गिरावट सरकार की मन्शा पर अवलम्बित रह जाती है। तो फिर यदि फुलावट में तेजी और गिरावट से मन्दी होनी है तो दाम करीब-करीब स्थिर रखने के लिए भी कभी फुलावट तो कभी गिरावट की चाभी घुमाई जा सकती है। दूसरे शब्दों में, दाम स्थिर रखने के लिए भी इन दोनों तरकीबों का उपयोग किया जा सकता है। और दाम स्थिर रहना, यह भी तो समाज के लिए एक बड़ा लाभ है।

हम पहिले बता चुके हैं कि दामों की तेजी में माल उपजानेवालों को लाभ और बड़ी आय वालों को नुकसान है, दामों की मन्दी में इससे उल्टा। पर इस तेजी-मन्दी के उलट-फेर में कभी किसीको लाभ और कभी हानि से सामाजिक असन्तोष फैलता है सो बुराई तो है ही, पर इस असन्तोष के साथ-साथ पैदाइश पर भी बुरा असर पड़ता रहता है। धीरे-धीरे लगा-तार तेजी चलती है तो पैदाइश बढ़ती रहती है पर फिर, जब दामों में मुड़की आनी है और दाम गिरते हैं तो कारखानों को ताला लगाने लगता है, बेकारी बढ़ती है और इसमें समाज में गरीबी आने लगती है। उससे असन्तोष बढ़ता है। सम्भव है दाम स्थिर हो—कम-से-कम एक परिधि के भीतर—तो शायद इस परिस्थिति में पैदाइश की वृद्धि भी हो और समाज के विभिन्न फिरफों में दामों की घटा-बढ़ी में पैदा हुआ असन्तोष भी न होने पाए। इस भावना में प्रेरित होकर कई अर्थशास्त्री दामों की साम्यावस्था की पृष्टि करते हैं।

दामों की साम्यावस्था

दामों की साम्यावस्था से इतना ही प्रयोजन है कि दामों के सूचक अंक (Index Figure) की साम्यावस्था। यह तो नामुमकिन चीज है कि हम सब जिनसों के अलग-अलग दामों की घटा-बढ़ी को रोक सकें। मान लीजिए, एक साल गेहूँ की फसल बहुत बढ़िया बैठी, और सरसों की फसल मारी गई। तो गेहूँ की बहुतायत से गेहूँ की मन्दी और सरसों की कमी के कारण सरसों की तेजी अवश्यम्भावी है। इसे कोई नहीं रोक सकता। पर अलग-अलग चीजों की तेजी या मन्दी एक बात है, और सम्मिलित दामों की तेजी या मन्दी दूसरी बात। जब सम्मिलित दामों की तेजी या मन्दी आती है तभी समाज के एक अंग को लाभ और दूसरे को हानि होती है। इस सम्मिलित दामों की तेजी या मन्दी को गिरावट या फुलावट की नीति-द्वारा काफी दर्जे तक रोका जा सकता है। वह इस तरह —

सत्तनत दामों के सूचक-अंकों का अध्ययन करती रहती है और जहाँ दाम कुछ बढ़े कि नोट-प्रसारक बैंक चलण में से नोटों को निकाल कर धन का सकोच शुरू कर देती है, जहाँ दाम गिरे कि नोटों का चलण बढ़ाकर विस्तार कर देती है। इस तरह के सकोच-विस्तार-द्वारा दामों को यथासाध्य साम्यावस्था में रखने की कोशिश की जाती है। और उसमें उसे साधारणतया सफलता भी मिलती है। इस सारी क्रिया को विस्तार से समझाने में छोटी-मोटी अन्य कई क्रियाओं का भी जल्लेख करना पड़ेगा। चूँकि पाठकों के सामने एक मोटी-सी रूप-रेखा देना ही इस पुस्तक का ध्येय है इसलिए ज्यादा व्योरे में उतरना आवश्यक नहीं है। बतलाना इतना ही है कि फुलावट-गिरावट की नीति से दामों में तेजी, मन्दी और साम्यावस्था तीनों चीजें लाई जा सकती हैं।

पर दामों को साम्यावस्था में रखने के और भी तरीके हैं। एक तरीका तो खास करके इसी महायुद्ध में बहुतायत से काम में लाया गया है। यह तरीका नया नहीं है, पर इतने विस्तार से इसी युद्ध में काम में

लाया गया है, इसलिए इसे नया तरीका भी कह सकते हैं। यह तरीका है मालकी उपज, खपत और दामो का नियंत्रण करना।

जब हम नोट-प्रसार अधिकता से करके दामो की तेजी को प्रोत्साहन देते हैं या तो कम करके दामो की मदी को आह्वान करते हैं तो एक तरह से हम दामो की तेजी या मदी पर सीधा हल्ला न बोलकर ऐसे टेढ़े-मेढ़े उपायो का प्रयोग करते हैं कि जिससे जनता की क्रय-शक्ति कमोवेश होकर चीजों की उपज और खपत पर अपने-आप अच्छा या बुरा असर पड़ता रहे।

जनता के पास क्रय-शक्ति है और वह उसका उपयोग करके दामो को तेज करना चाहती है। उस क्रय-शक्ति को हमने कर-द्वारा या उधार लेकर अपने कब्जे में कर लिया। फलस्वरूप अब जनता बाजार से हट जाती है और दाम गिर जाते हैं। या तो जनता की क्रय-शक्ति का ह्रास हो गया और इसलिए बाजार में सन्नाटा छा गया। सत्तनत ने नए-नए खर्च करना शुरू करके जनता की क्रय-शक्ति बढ़ा दी और जनता फिर बाजार में खरीदने के लिए आ घमकी और इस तरह बाजार में फिर जान आ गई। यह गिरावट या फुलावट का एक तरीका है दामों को घटाने और बढ़ाने का।

पर मान लीजिए कि आपके पास असह्य दौलत पड़ी है। उसको किमीने नहीं छीना। पर आप पर यह दफा लगा दी कि आप अमुक परिमाण से ज्यादा किसी भी हालत में किसी भी वस्तु को खरीदने नहीं पावेंगे, और न दूकानदार बिना सरकारी इजाजत के आपको कोई चीज बेचेगा। तो फिर इसका परिणाम भी वही होता जाता है जो चलण की कमी-बेची से पैदा किया जाना है; क्योंकि आपके पास धन होने हुए भी आप खरीद के हकदार नहीं रहे। यदि सरकार इस तरह की सारी हल्चलो का नियंत्रण कर टाले कि अमुक चीज की छत्ती पैदाइश होगी, हर मनुष्य अमुक मिकदार ही अमुक चीज की खरीद और सपत कर सकेगा, बेचनेवाले और लेनेवाले अमुक बंधे हुए दाम पर ही खरीद और फरोख्त कर सकेंगे और जो कोई सरकारी दुस्मउदूकी करेगा उसे

सजा भुगतनी पड़ेगी, तो फिर चाहे किसी के पास असह्य धन क्यों न पड़ा हो वह धन बेकार-सा बन जाता है और उसकी नियंत्रित क्रिया के कारण दामो की घटा-बढ़ी भी नियंत्रित हो जाती है। अवश्य ही यह दूसरा तरीका, दामो की साम्यावस्था लाने का, ज्यादा सीधा है—आडा-टेढा नहीं है—पर इसके यह माने नहीं कि यह ज्यादा वाछनीय है।

नियंत्रण

इस तरीके में योजना और संचालन के लिए अफसरो और कारिन्दों की एक बृहत् सेना को रोकना पड़ता है जो रात-दिन इसी ताक-झाक में रहती है कि किमीने इस नियम का भंग तो नहीं किया। इतने नागरिकों को केवल योजना और संचालन के लिए रोक रखना, यह भी देश की समृद्धि के लिए एक हानिकर चीज है। आखिर जब तक हर आदमी कुछ पैदाइश करता रहता है तभी तक देश की समृद्धि बढ़ती है। यदि सब लोग संचालन में, वाद-विवाद में, सैन्य और पुलिस में और ऐसे अन्य बेउपजाऊ घघों में ही लगे रहे, तो फिर समृद्धि कहा ? इस दृष्टि से वही तरीका अच्छा है जिसमें कम-से-कम आदमियों की शक्ति का ह्रास हो। पर दुद्ध-काल में इन सब नियमों की अवहेलना करनी पड़ती है। ऐसे विकट समय में ध्येय की अपेक्षा साधन गौण बन जाता है। इसलिए ऐसे नियंत्रणों का उपयोग विकट काल में ही वाछनीय माना जाना चाहिए। यद्यपि रूस में शांति-समय में भी नियंत्रण का उपयोग किया गया है पर रूस के सम्बन्ध में तो यह भी कहा जा सकता है कि वहा शांति का समय आया ही नहीं—विकट समय का ही दौर-दौरा रहा, और इसलिए वहा नियंत्रण-नीति अभीष्ट ही थी। जो हो, दामो की साम्यावस्था नियंत्रण से भी लाई जा सकती है, यह अब पाठक समझ सकेंगे।

×

×

×

×

अब पाठको से विदा लेता हूँ।

(उत्तर भाग)

इतिहास

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ
१ अनेक की जगह एक	...	८१-
२ चादी का परित्याग	...	९४-
३ सोने का ग्रहण	...	११७
४ आड से शिकार	..	१३७
५. लेने के देने	...	१६२
६ १८ पैसे का रुपया	...	१८२
७ इतिहास की पुनरावृत्ति	...	१९७-
८ मन्दी की मार	...	२१०
९ स्टर्लिंग से गैठबन्धन	...	२२४
१०. गैठबन्धन के बाद	...	२३८
११. रिजर्व बैंक की स्थापना	...	२५१
१२ साहूकार की समस्या	..	२६४
१३ सिंहावलोकन	...	२८४
परिशिष्ट	.	२९३०

अनेक की जगह एक

मुद्रा का अर्थ चिह्न है। बहुत काल पहले जब सिक्को के लिए चादी या सोने के टुकड़ों का व्यवहार बड़ा तब यह आवश्यक हो गया कि वे टुकड़े ठीक तौल के हों और प्रमाणस्वरूप उनपर कोई चिह्न बना दिया जाय। इस प्रकार सिक्को का नाम मुद्रा हो चला।

प्रश्न उठता है कि मुद्रासम्बन्धी कला इस देश की अपनी उपज थी या वह कहीं बाहर से आई ?

यहां के सिक्को की तौल और बनावट दोनों ही निराले ढंग के हैं, और धीरे-धीरे इस मत की पुष्टि होती जा रही है कि भारत ने इस विषय में न तो किसीकी नकल की, न किसीको अपना गुरु माना। “नागरी प्रचारिणी पत्रिका” (वैशाख १९९७) में प्रकाशित स्व० दुर्गाप्रसाद जी का लेख इस सम्बन्ध में पढ़ने लायक है। आप लिखते हैं— “मुझे जहां तक मोज करने का अवसर मिला है, इसका प्रमाण मिला है कि भारत में गौतम बुद्ध से पहले सिक्को का चलन था। उस समय के सिक्को मुझे प्राप्त भी हुए हैं।” आपके लेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध के समय में चादी के सिक्को की तौल ४० और २५ रत्ती होती थी। पण, कार्पापण—ये चादी के तत्कालीन सिक्को के नाम थे। सिक्को पर पहले किमी राजा की मूर्ति या उपाधि अंकित करने की प्रथा नहीं थी, केवल कुछ चिह्न—जैसे हाथी, कुत्ता या वृक्ष—ठप्पो से अंकित कर दिए जाते थे। ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दी से अक्षरो का प्रयोग होने लगा। कुछ समय तक प्राकृत का बोलवाला रहा। फिर देवनागरी या हिन्दी का प्रयोग होने लगा। चादी का रुपया चलानेवाला शेरशाह था। उसके सिक्को पर कूफी के साथ हिन्दी को भी स्थान प्राप्त था। उसके

बेटे इस्लामशाह के समय में भी यही बात रही। श्रीयुत दुर्गाप्रसाद जी लिखते हैं — “इनके समय तक तो मुद्राओं पर हिन्दी को बराबर स्थान मिला, पर जब मुगल बादशाह बाबर, हुमायूँ और अकबर ने अपने अधिकार जमाए और सिक्के चलाए तो उन्होंने पहले कूफी अक्षरों में अपने नाम सिक्कों पर लिखे। हुमायूँ ने पहलेपहल फारसी अक्षरों का प्रचार भारत में किया। उसके पहले फारसी अक्षरों को, जिसमें उर्दू लिखी जाती है, यहाँ कोई नहीं जानता था। .

अकबर और उसके बाद जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब इत्यादि सभी बादशाहों ने फारसी का प्रचार किया। राजकार्य सब फारसी में होते रहे। सिक्कों पर भी फारसी अक्षरों को जगह दी गई और हिन्दी देवनागरी को हटा दिया गया।”

भारत में सोने के सिक्कों का प्रचार भी अत्यन्त प्राचीन काल में है। उन्हें निष्क, पाद आदि कहते थे। कुछ विद्वानों का मत है कि समार में पहलेपहल सिक्कों के लिए सोने का ही प्रयोग होता था, क्योंकि सोना सुलभ था, और चादी दुर्लभ। सोना जहाँ मिलता था वहाँ सोने के ही रूप में, उसे अलग करने के लिए कोई विशेष परिश्रम या प्रयास नहीं करना पड़ता था, पर चादी की बात और थी, वह दूसरे मनिज द्रव्यों के साथ इस प्रकार मिश्रित थी कि उसे निकालना या हासिल करना जग टेढ़ा काम था। कहते हैं कि उस युग में सोने में चादी का मूल्य कहीं अधिक था। तब चादी निकालने के ज्ञान या विज्ञान की उन्नति होती गई और चादी की दुर्लभता मिटती गई। कुछ काल बाद स्थिति बिलकुल बदल गई। चादी सुलभ हो चली, और सोना दुर्लभ। मालूम नहीं, हम देश में इनका क्या प्रयोग होता है। पर इतना निश्चित-सा ज्ञान पड़ता है कि प्राचीन काल में यहाँ सोना, चादी की तुलना में, मस्ता था। फोल्डर कमेटी के नाम पर बयान देने हुए अगरेज अर्थशास्त्री मि० मैकल्लियट ने कहा था —

“अति प्राचीन काल में भाग्यवर्ष गुप्त था, और पाश्चात्य देश भ्रमण या वंदन। उस समय भाग्यवर्ष को विदेशी चम्पुओं की कोई नाम जम्पन नहीं था और वह बिना सोना या चादी पाए, अपना मातृ देश को लेकर न था। पर भाग्यवर्ष में सोना और देशों की अपेक्षा मस्ता

धा—ईरान में १३ भाग चादी एक भाग सोने के बराबर होती थी, और भारतवर्ष में ८ भाग चादी एक भाग सोने के, लेहाजा भारत में बाहर ने चादी बहुत बड़े परिमाण में आया करती, जिसके बदले में वहां से या तो सोना बाहर जाता या दूसरा माल ।”

सोने-चादी के इतिहास में अमेरिका का पता चलना (१४९३) एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है । यूरोपवालों को मानो बुवेर की निधि हाथ लग गई । जहां सोने या चादी का—पर विशेषतः चादी का—एक साधारण सोता-सा बहता था वहां, समुद्र नहीं तो एक जबर्दस्त दरिया लहरें मारने लगा । थोड़े ही समय में यूरोप की भूमि इनसे परिप्लावित हो चली और वहां के आधिक क्षेत्र में पूरा इनकिलाब नजर आने लगा । ‘पानी फलक पर खेत में दाना बदल गया ।’

१४९३ और १८०० के बीच सोने और चादी के उत्पादन का तखमीना यह है —

सोना (लाख औंस)	चादी (लाख औंस)
१४९३-१६०० २३०	७,४७०
१६०१-१७०० २९०	१२,७२०
१७०१-१८०० ६१०	१८,३३०
१,१३०	३८,५२०

उत्पादन की दृष्टि से १६वीं सदी में सोने और चादी का पारस्परिक अनुपात १ : ३२ था—अर्थात् जितना सोना निकला उससे ३२ गुना अधिक चादी निकली । १७वीं सदी में यह अनुपात १ : ४४ हो चला । पारस्परिक मूल्य का अनुपात पहले १ : ११ था— अर्थात् एक भाग सोना प्रायः ११ भाग चादी के बराबर होता था । पर यह अब प्रायः १ : १५ हो चला, और प्रायः दो सौ साल तक— अर्थात् १९वीं सदी के पिछले भाग तक— यही कायम रहा ।

इस देश में यूरोप से चादी का आयात अब और भी अधिक हो चला । विदेशी कम्पनियों—मुख्यतः ईस्ट इंडिया कम्पनी—का इस व्यापार पर

एकाधिपत्य-सा था। उधर बगाल-विहार में—और अशत अन्यत्र भी—आर्थिक क्षेत्र के अधिपति थे मुर्शिदाबाद के जगत्सेठ। नवाब ने इन्हे टकसाल का इजारा दे रखा था। लेहाजा चादी के सबसे बड़े खरीदार यही थे। ईस्ट इंडिया कम्पनी और जगत्सेठ के घराने के बीच के लेन-देन के सन्ध पर, और तत्कालीन व्यापारिक अवस्था पर, यह अवतरण अच्छा प्रकाश डालता है—

“(१७४६) अवतूबर में विलायत से कुछ चादी आई। कौंसिल के आग्रह करने पर (जगत्सेठ) महताबराय ने उसे खरीद लिया। इससे कम्पनी को कई लाख रुपए तत्काल मिल गए और कुछ दिनों तक उसे कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ी। पर नया साल शुरू होते ही अवस्था फिर बदली और ढाका के कर्मचारियों ने कौंसिल में रुपया मांगा। इसी समय कुछ चादी आ पहुंची। कौंसिल ने उसे कासिमबाजार भेज दिया। वहां वह महताबराय को बेच दी गई और उसके पेटे कम्पनी को ढेढ़ लाख रुपया मिल गया। पर यह रुपया कासिमबाजार की कोठी को न मिला, इसकी वहावालो ने शिकायत की और कौंसिल को लिखा—‘ऐसे समय में, जब कि हमपर कर्ज का इतना भारी बोझ है और कम्पनी की साख इतनी कम रह गई है, आपने यह रुपया भगाकर अच्छा काम नहीं किया। महाजन पहले में ही अवीर हो रहे थे, मालूम नहीं, अब वे क्या कर बैठेंगे।’ कौंसिल ने उन्हें लिखा कि हम और चादी शीघ्र ही भेजनेवाले हैं। चादी कासिमबाजार भेजी गई, पर महताबराय ने उसे उमी दम लेने में इनकार कर दिया।” ईस्ट इंडिया कम्पनी के पुराने कागजात में जाहिर होता है कि रुपए की टान उस समय काफी थी और जगत्सेठ न चादी का दाम घटा दिया था। वह १७४७ के उत्तरार्द्ध में २४० सिक्के रुपए भर चादी के लिए २०१ रुपए में अधिक देने को तैयार न थे। कम्पनी अपनी चादी उनके हाथ बेचनी जानी और बराबर दाम बढ़ाने के लिए आग्रह करनी जानी।

पटना की लड़ाई में विजय पाकर ईस्ट इंडिया कम्पनी बगाल-विहार का और धीरे-धीरे मारे भाग्यवर्ष ना, भाग्यविधाना बन बैठी। जगत्सेठों ने उस राज्यशक्ति को सफर बनाने में प्रमुख भाग लिया था और

कम्पनी की तन-मन-धन से सहायता की थी, पर उन्हें अन्त में लेने के देने पड़ गए, और कहना चाहिए कि पलासी के मैदान की रचना कराकर उन्होंने अपने ही विनाश के बीज बोए। आर्थिक और राजनैतिक, दोनों ही क्षेत्रों में सर्वोपरि ईस्ट इंडिया कम्पनी बन बैठी और जगत्सेठ उपाधि उस घराने की विपुल सम्पदा और प्रभुता का स्मारक-मात्र रह गई।

पर चादी के सिक्कों का प्रचार विशेषतः उत्तर भारत में ही था। दक्षिण में प्रधानता सोने के सिक्कों की थी।

संस्कृत में चादी को रुप्य या रौप्य कहते हैं। अष्टाध्यायी में एक विशेष प्रकार की मुद्रा के लिए "आहत रुप्य" शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसी रुप्य या रौप्य का अपभ्रंश रुपया है। १८३५ से पहले इस देश में तरह-तरह के रुपए प्रचलित थे। इनमें बुद्ध के नाम-धाम इस प्रकार थे—

१—पुराने सिक्के (१७९३-१८१७)

२—नए सिक्के (१८१८-१८३२)

३—पुराने और नए फर्खावादी रुपए, जो फर्खावाद, बनारस और सागर की टकसालों में ढले थे।

४—फर्खावादी रुपए, जो कलकत्ते की टकसाल* में ढले थे।

५—मद्रासी रुपए।

सोने के सिक्कों का भी यही हाल था। इस बहुतायत और विभिन्नता ने बड़ी अड़चन पैदा होती थी—लेन-देन, व्यापार के मामले में यह अनेकता प्रबल बाधक का काम करती थी। ईस्ट इंडिया कम्पनी की ओर से जो कलक्टर नियुक्त होते थे उन्हें चादी के कम-से-कम ६० और सोने के कम-से-कम ७२ सिक्के माल या लगान के रूप में, लोगों से लेने पड़ते थे। बंगाल का यह हाल था कि एक जिले में जो रुपया चलता वह दूसरे जिले में नहीं। यह भी नहीं कि एक जिले के अन्दर एक ही प्रकार के सिक्के का बोलबाला हो। अलग-अलग चीजों के लिए अलग-अलग सिक्के

*कम्पनी की टकसालों में रुपए की ढलाई कल-द्वारा होती थी, इस-लिए उसका नाम कलदार पड़ा।

थे । और घिसाई की मात्रा न्यूनाधिक होने के कारण सिक्को पर वट्टे का हिसाब भी अलग-अलग था । चादी और सोने का पारस्परिक सम्बन्ध सदा एक-सा नहीं रहता था—कभी सोना सस्ता हो जाता, कभी चादी । इनमें जो चीज सस्ती होती वह तो चलन में रह जाती, और जो महंगी होती वह निकल जाती । इन सारी अड़चनों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा-सम्बन्धी सुधार आवश्यक था और वह सुधार था अनेकता की जगह एकता का स्थापन । भारतवर्ष का अधिकांश एक राजछत्र की छाया में आ चुका था , इसलिए वह सुधार अब उतना कठिन भी नहीं रह गया था । कहना चाहिए कि शासन-सम्बन्धी एकता के बाद मुद्रा-सम्बन्धी एकता आने ही वाली थी ।

कम्पनी के डाइरेक्टरो ने इस विषय में अपना मत प्रकट करते हुए १८०६ में मद्रास-सरकार को लिखा कि भारतवर्ष का प्रधान सिक्का चादी का होना चाहिए, जिसका वजन १८० ग्रेन (एक तोला) हो और जिसमें १६५ ग्रेन खालिस चादी हो । उनकी राय थी कि प्रधानता चादी के सिक्के की रहे, पर सोने का चलन भी बन्द न हो । माय ही, वे इन दोनों के बीच कानूनन कोई सम्बन्ध स्थापित करना नहीं चाहते थे । उनका प्रस्ताव था कि सोने का मूल्य उसके परिमाण और उसकी माग पर अवलम्बित हो ।

पर प्रायः ३० साल तक मुद्रा-सम्बन्धी एकीकरण का प्रस्ताव प्रस्ताव ही रहा । उसको विधान का रूप मिला १८३५ में, जिसमें दो साल पहले बंगाल के गवर्नर-जनरल सारे देश के गवर्नर-जनरल बनाए जा चुके थे और शासनमन्त्रा पुरी तरह केन्द्रीभूत हो चुकी थी । उस साल २७ मई को सरकार की ओर से यह घोषित किया गया कि भारतवर्ष का जितना भाग ब्रिटिश छत्रच्छाया में आ चुका है उसमें अब एकही प्रकार के रूप का चलन होगा और हर धान में यह रूपया आजकल के फर्मावादी रूप के समान होगा । इस घोषणा के अनुसार जो विधान बना उसे भारत के मुद्रा-सम्बन्धी इतिहास में बड़े ही गौरव का स्थान प्राप्त है । उसका माराग यह था—

(१) १ली मिनम्बर १८३५ में कम्पनी की टक्कालों में एक ही प्रकार

के रुपए की ढलाई होगी। इन रुपए का वजन १८० ग्रैन होगा, जिसमें खालिस चादी १६५ ग्रैन होगी। अठसियों और चवसियों में भी इसी हिसाब में चादी रहेगी।

(२) कुछ खान तरह के सोने के सिक्के भी टाले जायें, पर कोई भी आदमी कम्पनी के राज्य में सोने का सिक्का देने या लेने को बाध्य न होगा।

इन विधान की बदौलत १६५ ग्रैन खालिस चादीवाला रुपया मुद्रा-सिंहासन पर जा बैठा। देने-लेने के लिए सब लोग इसीका व्यवहार करने को बाध्य थे, इसलिए अपने क्षेत्र में धीरे-धीरे इसका एकछत्र राज्य-सा स्थापित हो गया। भारतवर्ष में हर प्रकार के मूल्य का मापदण्ड चादी बन गई।

पर साथ-साथ एक हद तक सोने का चलन भी बना रहा। कम्पनी की टकनाल में सोने का जो प्रधान सिक्का टालना उसका वजन भी १८० ग्रैन था, जिसमें खालिस सोना १६५ ग्रैन था। इसका मूल्य था १५), और १८४१ का सरकारी आदेश था कि जब तक दूसरा हुक्म जारी नहीं किया जाता तब तक उनकी ओर से ये सिक्के इसी दर से मंजूर किए जायें। पर यह अवस्था चिरस्थायी न हो सकी। कुछ ही वर्ष बाद ऑस्ट्रेलिया और कैलीफोर्निया में नई खानों के खुलने से सोने का उत्पादन बहुत बढ़ चला और चादी की तुलना में वह सस्ता हो चला। नतीजा यह होने लगा कि लोग अपना लगान या कर रुपयों में न चुका कर मोहरों में चुकाने लगे। बाजार में एक मोहर के १५) से कम मिलते, क्योंकि सोना सस्ता हो रहा था— पर सरकारी खजाने में वह अब भी उसी दर से ली जाती, इसलिए मोहरों की बहा भरमार होने लगी। और सरकार किसीको भी १५) में मोहर लेने को बाध्य नहीं कर सकती थी। सरकार चाहती तो चादी की जगह उसी समय सोने को दे देती और सोने को ही मूल्य का मापदण्ड बना देती। पर ऐसा न करके सरकार ने १८४१ के आदेश को ही उठा लिया और १ली जनवरी १८५३ से मुद्रा के रुप में सोने का चलन विलकुल बन्द हो गया।

सन् सत्तावन के गदर के कारण भारत-सरकार की आर्थिक कठिनाइया

वेहद बढ़ गई और स्थिति सुधारने के लिए मि० जेम्स विल्सन नामक विशेषज्ञ इंग्लैण्ड से लाए गए। यह भारत-सरकार के प्रथम अर्थ-सदस्य थे और इन्हींके समय में करेन्सी नोट जारी किए गए। यह १८६१ की बात है। उससे पहले नोट जारी करने का अधिकार कुछ खास बैंकों को प्राप्त था, पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के बाहर नोटों का प्रचार नहीं के बराबर था। उस समय कोई भी आदमी नोट देने या लेने को कानूनन बाध्य न था। विल्सन ने नोटों का प्रचार बढ़ाने की दृष्टि से अपनी योजना भारत-सचिव के सामने रखी। उस समय भारत-सचिव सर चार्ल्स उड थे, और उनका इस विषय में विल्सन से मतभेद था। विल्सन इस मत के अनुयायी थे कि नोटों की पुष्टी के लिए जो कोप या रिजर्व कायम किया जाय उसमें एक हद तक सोना-चादी रखकर बाकी हिस्सा सरकारी कागज के रूप में रखा जाय। सर चार्ल्स का सिद्धान्त था कि कम-से-कम नोटों की पुष्टी ऐसे कागज में होनी चाहिए, और रिजर्व का बाकी सारा हिस्सा सोने या चादी का होना चाहिए।

अन्त में हुआ वही जो भारत-सचिव को मजूर था। सन् १८६१ में नोट-मवधी जो विधान बना उसने करेन्सी रिजर्व में सरकारी कागज की हद चार करोड़ पर बाध दी—अर्थात् यहाँ तक तो नोटों की पुष्टी सरकारी कागज या मिन्सूरिटीज में की जा सकती थी, पर यहाँ पहुँच जाने के बाद जो नोट निकाले जाते वे रिजर्व में सोना-चादी रखकर ही। आरम्भ में रिजर्व में चादी ही चादी रहती थी, १८६५ में कुछ सोना भी जमा हुआ, पर उसकी मात्रा कम होती गई, और १८७५ में वह बिलकुल गायब हो गया। फिर १८९८ के बाद करेन्सी रिजर्व में सोना टकट्ठा होने लगा। आरम्भ में दम, बीम, मौ और एक हजार के नोट जारी किए गए थे। पांच रूपए का नोट १८७१ में जारी किया गया, और दम हजार का नोट उसके भी बाद। १८६१ के विधान ने मारे देश को कुछ हफ्तों में बाट दिया, जो 'मॉर्गल' कहलाते थे—जैसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और रंगून। एक मॉर्गल का जारी किया हुआ नोट दूसरे मॉर्गल में कोई लेने को बाध्य न था, पर सरकारी देना किसी भी मॉर्गल के नोटों में अदा किया जा सकता था। नोटों की

लोकप्रियता बढ़ाने के लिए और भी सुभीते कर दिए गए थे। पर नोटों का विशेष प्रचार वर्तमान गताब्दी में ही हुआ है। समय-समय पर नोट-सम्बन्धी विधान में संशोधन होते रहे हैं। इस गताब्दी के पहले ग्यारह साल के भीतर, पांच से लेकर सौ रुपए तक के नोट 'अखिल भारतीय' कर दिए गए—अर्थात् वे चाहे किसी भी मर्कल के हों, लोग उन्हें सर्वत्र लेने को कानूनन बाध्य हो गए। इनसे नोटों का प्रचार और भी स्वच्छन्दता में होने लगा। नोटों की कागजी पुष्टी की हद भी १८६१ और १९४३ के बीच कहीं-से-कहीं जा पहुंची है।

जिस समय नोट-सम्बन्धी विधान पहलेपहल बना उस समय यहाँ रुपए की बड़ी टान थी। इसके कुछ खास कारण थे। अमेरिका में उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच जो भीषण संग्राम हुआ उसका एक नतीजा यह हुआ कि दक्षिण में रुई का निर्यात (एक्सपोर्ट) कुछ समय के लिए बन्द हो गया और यह व्यापार भारतवर्ष को मिल गया। यहाँ से निर्यात काफी होने लगा और देश का पावना चुकाने के लिए दूसरे देशों के लिए अधिकाधिक चादी भेजना आवश्यक हो गया। पर भारतवर्ष इस समय बाहर कर्ज भी काफी ले रहा था। १८५५-५६ और १८६९-७० के बीच उसने प्रायः ९६ करोड़ रुपए कर्ज लिए। इन दोनों कारणों से चादी का आयात कहीं-से-कहीं बट गया। १८५७-५८ और १८६२-६३ के बीच ससार भर में जितनी चादी निकली उससे अधिक चादी अकेले भारतवर्ष ने ली। फिर भी यहाँ रुपए की टान बनी ही रही। ऐसी अवस्था में लोगों का ध्यान मोने की ओर जाना स्वाभाविक था। १८६४ में यहाँ के वाणिज्य-व्यापार से सम्बन्ध रखनेवाली कुछ सभाओं या चेम्बरो ने प्रस्ताव किया कि मूल्य का मान या स्टैंडर्ड सोना कर दिया जाय, और सोने के सिक्के चलन में लाए जाय। इस सम्बन्ध में कुछ अवतरण उस आवेदनपत्र से दिए जाते हैं, जो वेम्बर्ग के चेम्बर की ओर से बड़े लाट के पास भेजा गया था—

“भारतवर्ष का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, वह आर्थिक और औद्योगिक उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है, पर चादी इस समय उस व्यापार और उस उन्नति में सहायक न होकर बाधक हो रही है।

“जिस समय चादी को अपनाया गया था उस समय उसका उत्पादन सोने से प्रायः दूना था। इसलिए कहा जा सकता है कि उसे अपनाना वृद्धि-मत्ता का काम था। पर वह बात अब नहीं रही। इधर चादी के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। पर भारतवर्ष की माग बेहद बढ़ गई है, इसलिए चादी से काम चलाना असम्भव-सा हो गया है।

“ससार में हर साल प्रायः एक करोड़ पौंड (स्टर्लिंग) की चादी निकलती है। पर पिछले छ साल में एक भारतवर्ष ने ही हर साल एक करोड़ पन्द्रह लाख पौंड की चादी ली है। पिछले साल तो उसने १ करोड़ ४५ लाख पौंड की ली।

“ऐसी अवस्था में चादी के मूल्य में बहुत बड़ी वृद्धि अनिवार्य है—जिसका अर्थ है भारतवर्ष जैसे देश में द्रव्य की कमी और दामों का गिरना।

“उधर सोने का यह हाल है कि उसका उत्पादन बहुत बढ़ गया है और ससार में जितनी चादी निकलती है उससे कम-से-कम १५० प्रतिशत अधिक सोना निकलता है।

“भारतवर्ष के लिए, और बाकी दुनिया के लिए, चादी काफी नहीं है, पर मय के लिए सोने की बहुतायत है; इसलिए हमें चाहिए कि हम चादी जैसी कीमती और भारी चीज को छोड़कर सोना जैसी सस्ती और हल्की चीज को अपनावें।

“उसमें कई लाभ होंगे—चादी का मूल्य अपनी मुनामिव जगह पर बना रहेगा और इस देश के वाणिज्य-व्यवसाय का विस्तार अप्रतिहत गति में होता रहेगा।

“सोने का उस समय जो बहिष्कार है वह न तो मभ्योचित है, न युक्ति-मग्न है, न स्वाभाविक है। सोना उस समय भी यहाँ काफी आता है, पर वह मित्रों के रूप में नहीं चल सकता। सरकार को चाहिए कि यह शीघ्र-मे-शीघ्र चादी की गद्दी सोने को दे दे, जिसमें सोने के मित्रों का चलन हो जाय, और उसमें तो अनेक लाभ हो सकते हैं उनमें यह देश बचि न रहे।”

इस विषय पर सार्फी दिग्गज-बादी हुई, पर कोई गति नबीजा न निकल।

भारत-सचिव अन्त में यहाँ तक जाने को राजी हुए कि साँवरेन या गिनी (१०) की दर से सरकारी खजानों में ले ली जायगी। बाद यह दर (१०१) कर दी गई। १८६६ में इस विषय के अनसन्धान के लिए एक कमीशन भी बैठा। भारत-सरकार के तत्कालीन अर्थ-सदस्य सोने के सिक्के के पक्ष में थे। कमीशन ने भी अपनी राय उसके पक्ष में दी। पर यह गव निष्पल रहा। १८७२ और १८७३ में अर्थ-सदस्य ने फिर इस सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव भारत-सरकार के सामने रखे। पर सरकार को प्रस्तावित सुधार स्वीकार न हुआ। १८७४ की ७ वी मई को उसने अपना निर्णय इन शब्दों में प्रकाशित कर दिया कि—

“सोने के सिक्के को चलन में लाने की वाञ्छनीयता पर विचार कर सरकार इस नतीजे पर पहुँची है कि फिलहाल सोने को मूल्य का मान बनाने के लिए कोई भी कार्रवाई न की जाय।”

फलत यहाँ चादी के रुपए का ही बोलबाला बना रहा।

अब और देशों की मुनिए। फ्रांस में सोना और चादी दोनों के ही सिक्के चलते थे। पर १८५० से पहले वहाँ प्रधानता चादी की ही थी। कानूनन एक भाग सोना १५॥ भाग चादी के बराबर था, पर १८०३ और १८५० के बीच बाजार-दर के अनुसार चादी इससे प्रायः मस्ती पड़ती थी; १५॥ के बजाय प्रायः १६ भाग चादी एक भाग सोने के बराबर होती थी। जहाँ दो प्रकार के सिक्के चलते हैं वहाँ सस्ता या घटिया सिक्का तो चलन में रहता है, और महंगा या बढ़िया बाहर निकल जाता है। इनको अर्थशास्त्र में ‘ग्रेणम नियम’ कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसपर प्रकाश डालनेवाले सर टॉमस ग्रेणम नामक अंगरेज अर्थ-सचिव थे। फ्रांस की ही बात लीजिए। सोने के सिक्के में कोई भ्रूणतान करता तो वह निर्फ १५॥ भाग चादी पाने का हकदार होता, पर उसी सिक्के को गलाकर वह बाजार में बेच देता तो उसे १६ भाग चादी मिल जाती। ऐसी अवस्था में यह स्वाभाविक था कि चलन में सोने के सिक्के निकल जायें और उसमें चादी के सिक्को की भरमार हो जाय। पर १८५० के बाद गंगा उलटी बहने लगी— अर्थात् चादी महंगी और सोना सस्ता हो चला। जो अनुपान कानूनन

१ १५॥ या वह अब कुछ समय के लिए प्राय १ १५ हो चला। सिक्के के रूप में १५॥ भाग चादी एक भाग मोने के बराबर होती, पर बाजार में अपने असली रूप में विकने पर १५ भाग का ही एक भाग सोना हो जाता। उस परिवर्तित अवस्था में चलन से चादी निकलने लगी, और उसकी जगह सोना भरने लगा। फ्रांस में अब यह प्रश्न उठा कि दोनों डाल पकड़ने की—दो नावों पर पैर रखने की क्या जरूरत? कुछ लोग कहने लगे कि इंग्लैण्ड की तरह फ्रांस सिक्के मोने को अपना ले, कुछ इसका विरोध करते हुए उसकी जगह चादी की सिफारिश करने लगे। पर फ्रांस के कर्त्ताधर्त्ता न मोने का परित्याग करना चाहते थे, न चादी का। वे कुछ संशोधन के माध्य परम्परा को कायम रखना चाहते थे। चलन में चादी के सिक्के निकले जा रहे थे, इसको रोकने के लिए उन्होंने कुछ सिक्कों में चादी की मात्रा कम कर दी। फिर १८६५ में फ्रांस, बेल्जियम, स्विटजरलैण्ड और इटली की एक गमा इस बात पर विचार करने के लिए हुई, कि इन देशों की मुद्रा-नीति क्या होनी चाहिए। इसके फलस्वरूप लैटिन-मुद्रा-मन्त्र की स्थापना हुई और आपस में यह तय पाया कि मध्य पन्द्रह साल तक कायम रहे, और जो देश इसके सदस्य हो वे सब-के-सब अपनी मुद्रा-नीति एक करें। नीति यह ठहरी कि सोना और चादी, दोनों में ही मुद्रा का काम दिया जाय और गौण सिक्कों में चादी की मात्रा कम कर दी जाय ताकि निर्माण के लिए, उन्हें गलाकर बेचना लाभदायक न हो। मोने और चादी के बीच का अनुपात वही १ १५॥ रखा गया और उस बात की व्यवस्था की गई कि सब के भीतर एक देश के सिक्के दूसरे देशों में भी चल सकें।

मन्त्र को कुछ हद तक सफलता जरूर मिली, पर यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी स्थापना में मुद्रा-सम्बन्धी प्रश्न का कोई स्थायी हल हो गया। उदाहरणार्थ जून १८६७ में, फ्रांस के आग्रह में उस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। उसमें बीस देश सम्मिलित हुए थे, जिनमें केवल दो—इंग्लैण्ड और पोर्टुगाल—मोने के अद्वैतवादी उपागम थे। बाकी सब-के-सब या तो द्वैतवादी थे, जो सोना और चादी दोनों में ही मुद्रा का काम लेते थे, या जो केवल चादी के उपागम थे।

सम्मेलन में हॉलैण्ड को छोड़कर सभी देशों का झुकाव सोने की ओर था, और यह निश्चित हुआ कि धीरे-धीरे सब-के-सब चादी को छोड़ सोने को अपना लें और सर्वत्र एक ही प्रकार के सिक्कों का चलन हो। यहाँ तक तो डगलैण्ड सबके साथ रहा, पर अब उसके प्रतिनिधि कहने लगे कि हमने जो कुछ कहा है उससे हमारी सरकार पाबन्द नहीं है और वह अपनी मुद्रा-प्रणाली में तब तक कोई भी हेर-फेर न करेगी जब तक उसे विश्वास न हो जाय कि यह सब प्रकार से वाछनीय है। उनका यह नया सुर सुनकर लोगों का उत्साह ठंडा पड़ गया और आगे जो कार्रवाई हुई उसमें उतनी एकता नजर नहीं आई। सम्मेलन की सिफारिशों का तत्काल कोई नतीजा नहीं निकला, पर इसमें सन्देह नहीं कि उसने सोने का जो गुण-गान किया उसका, निकट भविष्य में, कितने ही देशों की मुद्रा-नीति पर खासा असर पड़ा। १८७० में फ्रांस और प्रशिया (जर्मनी) के बीच मगाम छिड़ा। इसमें फ्रांस की हार से उसका प्रभाव जाता रहा, और मुद्रा-सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय एकता के प्रश्न को आगे बढ़ानेवाला अब कोई दूसरा राष्ट्र न रह गया। मूल्य के मान के रूप में तो सोने को कई देशों ने ग्रहण कर लिया, पर अन्तर्राष्ट्रीय सिक्के की बात जहाँ थी वहीं रही।

चांदी का परित्याग

लन्दन में चांदी स्टैंडर्ड ओंस के हिस्सा में विकती है। वहां का स्टैंडर्ड है १००० भाग में ९२५ भाग खालिस चांदी। जिस समय का वृत्तान्त यहां दिया जाता है उस समय इंगलैण्ड की मुद्रा मोने की थी, इसलिए कुल दाम मोने में ही समझे जाने चाहिए।

१८७३ में पहले कई माल तक लन्दन में चांदी का दाम ६० पेंस के करीब था। इधर चांदी में कुछ तेजी जरूर आ गई थी, मगर वह इतनी अधिक नहीं थी कि उसे विशेष महत्वपूर्ण कहा जा सके। लोगों को थोड़े समय के लिए कुछ चिन्ता जरूर हुई, मगर वे शीघ्र ही निश्चिन्त हो गए और उनका यह विश्वास फिर दृढ़ हो चला कि चांदी और मोने के बीच का सम्बन्ध स्थिर या स्थायी बना रहेगा।

वास्तव में १८७३ चांदी के इतिहास में एक नए युग का प्रारम्भिक वर्ष था। यह युग मुद्रा-जगत् में भूचाल-गा लानेवाला और कई महान् समस्याओं का उपस्थित करनेवाला था। उस भूचाल में चांदी और मोने का पुराना सम्बन्ध छिन्नभिन्न-गा हो गया, और इसका एक नतीजा यह हुआ कि कई देशों ने चांदी में ध्वस्त कर मोने का पत्ता पकड़ लिया।

चांदी अब अधोमुख हो चली—उसका दाम क्रमशः गिरने लगा। यों तो यह गिरना पहले ही शुरू हो गया था, पर १८७३ में जब दाम ५७½ पेंस हो गया तब समाज का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित हुआ और उस सम्बन्ध में तरह-तरह के प्रश्न किए जाने लगे। चांदी बराबर गिरती ही गई। हर पांच साठ का औसत ले तो १८७६ और १८९० के बीच उसका दाम यह रहा—

१८७६—८०

५२½ पेंस

१८८१—८५

५०½ पेंस

१८८५—९०

४४½ पेंस

दाम गिरते-गिरते १८९३ में ३७½ पेंस तक आ गया था ।

चादी के यो अधोमुख होने का कारण क्या था ?

इस सम्बन्ध में प्रधान कारण यह बताया जाता है कि फ्रांस पर विजय पाने के बाद जर्मनी ने सोने को अपनाकर चादी को वहिष्कृत कर दिया । यह भारी चादी जब बाजार में बिकने लगी तब दाम का गिरना अनिवार्य हो गया ।

जर्मनी को फ्रांस में जो हर्जाना मिला वह काफी बड़ी रकम थी । इसलिए चादी की जगह सोने का चलन करना उसके लिए आसान हो गया । उधर उसकी महत्वाकांक्षा बढी-चढी थी ही । शायद उसका यह भी खयाल था कि सोना वडप्पन का चिह्न है, और कोई भी राष्ट्र तब तक बटों की श्रेणी में नहीं आ सकता जब तक वह इस विषय में इंग्लैण्ड की बराबरी नहीं करता । १८७१ में ही उसने इस ओर कदम बढ़ाया और १८७३ में उसकी स्वाहिश पूरी हो गई । सोना सिंहासन पर आरुढ़ हो गया और चादी जहा-तहा जाकर सरीदार ढूँटने लगी । १८७३ और १८७९ के बीच जर्मनी की ओर से जो चादी ससार में बेची गई वह ११ करोड़ औंस से ऊपर थी ।

पर कुछ विद्वानों का मत है कि अगर भारतवर्ष पर हुडी करके भारत-सचिव कंग्रेडो रपा, हर साल वित्तगत न खेचते रहते तो जर्मनी की चादी इस तरह बिकने पर भी बाजार इतना खराब न होता । इस मत के प्रति-पादकों में मि० मार्टिन उड थे, जो कभी बम्बई के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के सम्पादक रह चुके थे । १८९३ में हर्शल कमेटी को उन्होंने इस विषय पर अपना लिखित वक्तव्य दिया था । उनका कहना था कि जब लन्दन की ओर से इस प्रकार की हुडी की जाती है तब लन्दन के लिए यह जरूरी नहीं रह जाता कि वह चादी भेज कर भुगतान करे—और उतने करोड़ रुपए की चादी बिकने और भारतवर्ष जाने से रह जाती है । अगर भारतवर्ष

पर इंग्लैण्ड का राजनैतिक प्रभुत्व न होता और इंग्लैण्ड इतने करोड़ रूपए इस देश से हर साल न लेता जाता तो चादी की यह हालत न होती।

चादी का दाम गिरता गया और, जैसा कि ऊपर कह चुके हैं, वह दाम सोने में था। यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि चादी सस्ती हो गई या सोना महंगा हो गया? वास्तव में दोनों ही बान हुई। सोने का उत्पादन इधर कम हो चला था, और चादी का उत्पादन बहुत बढ़ गया था। अमेरिका में पहले चादी कम—बहुत कम—निकलती थी पर, १८५९ के बाद वहाँ इसकी पैदावार उतनी बढ़ी कि ससार आश्चर्य-चकित हो गया और चादी की समस्या सयत्त राज्यों की राजनीति का एक प्रधान अंग बन गई। १८५६ से १८६० तक वहाँ कुल चादी ३०९,४०० औंस निकली थी। दूसरे पाँच वर्षों में निकली २८,१८०,६०० औंस। पर बाद की पैदावार को देखते हुए यह भी बहुत कम था। अकेले १८७४ में वहाँ २८,८६८,२०० औंस चादी निकली, और १८९२ में ६३,५००,००० औंस।

अमेरिका में उस समय मुद्रा^{*} सोने की थी, और सोना महंगा होने के कारण दाम गिरते जा रहे थे। इसलिए वहाँ यह आन्दोलन उठा कि मुद्रा-गिहागन पर चादी को भी बँटने का अवसर दिया जाय। इस आन्दोलन के समर्थक चादी के उत्पादक और कृषक थे। यह आन्दोलन तो सफल न हो सका, पर इसके फलस्वरूप अमेरिका की सरकार बाजार में चादी की बहुत बड़ी गरीदार बन गई। यहाँ दो विभागों का उल्लेख आवश्यक है—एक तो ब्रिग्ड-ग्रेन्मीन ऐक्ट, और दूसरा चार्मन ऐक्ट। पहला १८७९ में पास हुआ और उसके अनुसार सरकार हर साल कम-से-कम २०,६२५,००० औंस और अधिक-से-अधिक ४१,२५०,००० औंस चादी गरीदने को बाध्य हुई। बारह साल तक सरकार चादी गरीदती गई, पर दाम का

^{*} प्रायः ऐसे प्रसंग में मुद्रा का व्यवहार स्वयंसिद्ध मुद्रा के अर्थ में किया गया है।

प्रतीक-मुद्रा चादी या ताँबे के अलावा कागज की भी हो सकती थी और हर जगह था भी।

गिरना रका नहीं । १८७८ में जो दाम ५२, १/४ पेंस था वह १८९० में ४३ १/४ पेंस हो गया । इस माल विधान-द्वारा अमेरिका की सरकार प्रतिवर्ष कम-से-कम ५४,०००,००० आंस सरीदने को बाध्य की गई । चांदी के बाजार में उससे थोड़े समय के लिए तेजी आई और दाम ५४ १/२ पेंस हो गया, पर उगे फिर अधोमुख होते देर न लगी और, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, दाम गिरते-गिरते १८९३ में ३७ १/४ पेंस पर आ गया ।

रुपए में ग्वालिस चांदी थी १६५ ग्रेन, और जब चांदी का दाम ६० पेंस था तब एक रुपया प्रायः दो शिलिंग* के बराबर होता था । यह रुपए का विनिमय-मूल्य था । ज्यों-ज्यों चांदी गिरती गई, वह विनिमय-मूल्य या एक्सचेंज भी गिरता गया । उदाहरणार्थ —

चांदी का औसत दाम		औसत एक्सचेंज
	पेंस	पेंस
१८७७—७३	५९ १/४	२२ ३५१
१८७४—७५	५८ १/४	२२ २२१
१८७५—७६	५६ १/२	२१ ६४५
१८७६—७७	५२ १/४	२० ४९१

एक्सचेंज गिरने से समाज के एक अंग की हानि थी, और दूसरे का लाभ था ।

जब एक रुपए में दो शिलिंग अर्थात् २४ पेंस होते थे तब दस रुपए की ममता एक पाँड में होती थी । उस समय किसीका एक पाँड विलायत में होता तो वह बैंक को देकर उसके बदले यहाँ १०) पा सकता था, या किसीको एक पाँड वहाँ देना होता तो वह १०) यहाँ देकर बदले में एक पाँड वहाँ पा सकता था । जब एक्सचेंज गिरते-गिरते यहाँ तक आ गया कि

* १२ पेंस = १ शिलिंग, और २० शिलिंग = १ पाँड स्टर्लिंग ।

रुपए का वजन था १८० ग्रेन (३ औंस), जिसमें ग्वालिस चांदी थी १६५ ग्रेन । चांदी के दाम से रुपए का विनिमय-मूल्य निकालना साधारण अकगणित का काम था ।

एक रुपया सोलह पेस के बराबर होने लगा, तब १५) की समता एक पौंड से होने लगी। अब अगर विलायत में एक पौंड जमा हो तो उसके बदले १५) यहाँ ले लीजिए, और अगर विलायत में एक पौंड चुकाना हो तो उसके लिए यहाँ १५) दाखिल कीजिए।

एक्सचेंज गिरने से इस देश के उत्पादकों का—विशेषकर कृषक-समाज का—लाभ था। उनका जो माल विदेश में बिकता उसका दाम पौंड-शिलिंग-पेस में मिलता। फिर इनका रुपए से विनिमय करना पड़ता। अब अगर रुपए का विनिमय-मूल्य गिर गया, तो पौंड के उतने ही अधिक रुपए हुए, जिससे यहाँ के उत्पादक या किसान विशेष लाभ में रहे।

हा, जिन्हें रुपया विलायत भेजना था उनकी बात और थी। एक्सचेंज ज्यों-ज्यों गिरता, उन्हें अधिकाधिक रुपए देकर पौंड लेने पड़ते। इस श्रेणी में थे ब्रिटिश कर्मचारी, जिन्हें अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए विलायत पैसा भेजने पड़ते थे, ऐसे व्यापारी या व्यवसायी जिनका कारोबार यहाँ था पर जो अपने मुनाफे या अपनी पूँजी को यहाँ से उठाकर वहाँ ले जाना चाहते थे, और भारत-सरकार, जिसे भारत-सचिव की माँग पूरी करने के लिए हर साल कई करोड़ रुपए जुटाने पड़ते थे। विलायत में माल मगानेवाले भी इसी श्रेणी में थे। मान लीजिए, उन्होंने एक पौंड का माल मगाया और हिसाब लगाया कि १३।८) में उन्हें वैंक से एक पौंड मिल जायगा, इसी बीच एक्सचेंज गिर जाने में पौंड के पन्द्रह रुपए लगने लगे। लेहाजा उन्हें उम पौंड के लिए १॥३) अधिक देना पड़ा।

भारतवर्ष के अधिकांश निवासी किसान हैं, और ऐसे विषय में देश के हानि-लाभ का निर्णय उन्हींके हित की दृष्टि में होना उचित है। पर निमान न तो निश्चित है, और न गगणित। इसलिए, जहाँ उनकी गहरी हानि होती है वहाँ भी उनमें कुछ करते-धरने नहीं बनता, और ऐसी दशा में उनके हित की उपाय होना बिल्कुल स्वाभाविक है। उधर सरकार या अंग्रेज कर्मचारी या व्यवसायी गुणिशुद्ध, गृहगठित और सदा मातृधान रहनेवाले हैं। उनकी जहाँ थोड़ी भी हानि होती है, वे रोने-चिल्लाने लगते

हैं और ऐसा आन्दोलन खड़ा कर देते हैं कि उनके हित की उपेक्षा असम्भव-सी हो जाती है। रुपए के एक्सचेंज के इतिहास में बार-बार ऐसा ही हुआ है।

जब चादी की दर के साथ रुपए की विनिमय-दर गिरने लगी, तो विलायत पैसे भेजनेवालों को यह स्थिति बहुत अखरने लगी, और उन्होंने इसके खिलाफ हो-हल्ला मचाना शुरू कर दिया। किसान तो बेजवान थे, और उनकी ओर से बोलनेवाले दूसरे लोग भी आज की अपेक्षा बहुत कम थे।

१८७५ में पार्लमेण्ट की ओर से एक कमेटी इस विषय के अनुसन्धान के लिए बैठी कि चादी के दाम गिरने के क्या कारण हैं, और भारत तथा इंग्लैण्ड के बीच के एक्सचेंज पर इसका क्या असर पड़ा है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में विषय-विवेचना तो की, पर भारतवर्ष की ओर से किसी कार्रवाई की सिफारिश नहीं की।

उसी साल अगरेज व्यापारियों की ओर से भारत-सरकार के पास आवेदन-पत्र भेजे गए कि कुछ काल के लिए चादी की टकसाल सर्वसाधारण के लिए बन्द कर दी जाय। पर सरकार को यह मजूर न हुआ।

तीन साल बाद स्वयं सरकार ने यह प्रस्ताव किया कि भारतवर्ष चादी की जगह सोने को अपना ले और सर्वसाधारण को अपनी चादी टकसाल में ले जाकर उसके सिक्के ढलवा लेने का जो अधिकार प्राप्त है वह उससे ले लिया जाय—अर्थात् मुद्रा सोने की हो और रुपया उसके प्रतीक का काम करे। “दोनों के बीच की दर समय-समय पर सरकार निश्चित करती रहे और जब उसमें यथेष्ट स्थिरता आ जाय तब वह दर बराबर के लिए दो शिलिंग कर दी जाय।” उस समय बाजार में एक्सचेंज की दर १ शिलिंग ७ पैसे थी। दो शिलिंगवाले दिन इस समुदाय को अभी तक भूले नहीं थे।

भारत-सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए लन्दन में एक कमेटी बैठी, जिसके सदस्यों में भारत-सचिव की कौंसिल और ब्रिटिश सरकार, दोनों के ही प्रतिनिधि थे। इस कमेटी ने एकमत हो अपनी राय उस प्रस्ताव के विरुद्ध दी। ब्रिटिश सरकार के अर्थ-विभाग की ओर से

इस प्रस्ताव पर जो टिप्पणी की गई थी (नवम्बर २४ १८७९) उसका कुछ अंश उद्धृत करने लायक है —

“भारत-सरकार का प्रस्ताव है कि चांदी के रुपए को इस समय जो स्थान प्राप्त है वह उससे छीन लिया जाय और उसे प्रतीक-मुद्रा बनाकर उसके और सोने की मुद्रा के बीच एक स्थायी सम्बन्ध सरकारी आदेश से स्थापित कर दिया जाय ।

“पर यह व्यवस्था स्वाभाविक न होकर कृत्रिम होगी और उसी सफलता के लिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य होगा । उस प्रकार के हस्तक्षेप से बहुत कुछ बुराई होने का डर है ।

“हो सकता है कि इस प्रकार रुपए की दर बाध देने से भारत-सरकार, अंगरेज कर्मचारी और अंगरेज व्यवसायी अपनी-अपनी चिन्ता से मुक्त हो जाय और फायदे में रहें, पर आगिर उसका दाम चुकाना पड़ेगा भारत के किसानों को, जिनके कर्ज का तोड़ा (गल्ले इत्यादि का दाम गिर जाने के कारण) और भी भारी हो जायगा और जिन्हें लगान या कर चुकाने के लिए (उपज के रूप में) आज जितना देना पड़ता है उसमें कहीं अधिक देना पड़ेगा ।”

भारत-मन्त्रि ने दिसम्बर १८७९ में भारत-सरकार को लिखा कि उस परिवर्तन की मजूरी नहीं दी जा सकती ।

लैटिन-मुद्रा-मण्डल के सदस्य-देशों को अपनी हितरक्षा के लिए अंगरेजों की प्रणाली की कार्यवाही करनी पड़ी । चलन में मोना निकाला जा रहा था, और उसकी जगह सस्ती चांदी भरती जा रही थी । चूंकि उनके यहां चलन में चांदी के सिक्कों का अनुपात बहुत बड़ा हुआ था, वे अपनी मुद्रा-प्रणाली में चांदी का पूर्ण बहिष्कार करने में असमर्थ थे । पर आगे के दिनों उन्होंने चांदी की टकमाल या दरवाजा सर्वसाधारण के लिए बन्द कर दिया । १८८० तक यूरोप में कोई भी देश ऐसा न रह गया था जहां सर्वसाधारण को यह अधिकार हो कि चांदी टकमाल में ले जाकर उगें सिक्के द्रव्य में । मध्य के मान के सिद्धान्त पर सिक्के चीन और भारत-वर्ष में चांदी रह गई थी ।

कमेटी-कान्फ्रेस-कमीशन, इनका मिलमिला बना ही रहा । दो अन्त-राष्ट्रीय सम्मेलन फिर पेरिस में हुए, और दोनों का उद्देश्य यही था कि चादी में स्थिरता लाने के लिए सब देशों की ओर से कुछ किया जाय । पर सब एकमत न हो सके, इस कारण परिस्थिति में कोई अन्तर न पड़ा ।

१८७८-७९ से १८८४-८५ तक चादी ५१ पैसे के आसपास बनी रही और फलन एक्सचेंज भी स्थिर रहा —

चादी का औसत दाम		औसत एक्सचेंज
	पैसे	पैसे
१८७८—७९	५२½	१९७६१
१८७९—८०	५१½	१९९६१
१८८०—८१	५१½	१९९५६
१८८१—८२	५१½	१९८९५
१८८२—८३	५१½	१९५२५
१८८३—८४	५०½	१९५३६
१८८४—८५	५०½	१९३०८

पर १८८६ में चादी फिर नीचे गिनी और भारत-सरकार ने फिर अपनी कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए एक्सचेंज बाधने के उद्देश्य से एक स्कीम ऊपरवालों के सामने रखी । पर इस बार भी उसका प्रयत्न निष्फल रहा, ऊपरवालों ने उसके प्रस्ताव को नामजूर कर दिया । उन्होंने भारत-सरकार के प्रस्ताव की आलोचना करते हुए लिखा —

“इसमें मन्देह नहीं कि अंगरेज कर्मचारी-जैसे लोगों को इससे कुछ लाभ पहुँचेगा, पर साथ ही, इसमें भारतीय किसान या करदाता की बड़ी हानि होगी । चादी का दाम गिरने से डेढ़र भारतवर्ष के वाणिज्य-व्यवसाय की बड़ी उन्नति हुई है, और ऐसा जान पड़ता है कि जनता को हानि की अपेक्षा लाभ अधिक हुआ है । ऐसी हालत में भारत-सरकार का हस्तक्षेप करके रुपए को कृत्रिम मूल्य देना बहुत आपत्तिजनक है । हम इस प्रश्न पर केवल सरकार या उसके अंगरेज कर्मचारियों के हित या सुविधा की दृष्टि से विचार नहीं कर सकते, हमें सब में अधिक तो यह देखना

और विचारना होगा कि चादी के गिरने का भारतीय जनता पर—उसकी व्यापारिक और औद्योगिक अवस्था पर—क्या असर पड़ा है ।”

१८८६ में एक शाही कमीशन, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड हर्शल थे, चादी और सोने के सम्बन्ध की आलोचना के लिए बैठा । इस कमीशन के १२ सदस्यों में एक सर डेविड वॉर्वर थे, जो भारत-सरकार के प्रतिनिधि कहे जा सकते थे । पर यह कमीशन भी एकमत न हो सका । छ सदस्यों ने द्वैत मुद्रा-प्रणाली के पक्ष में राय दी, पर बाकी छ की राय यह ठहरी कि अद्वैत (सोना या चादी) की जगह द्वैत (सोना और चादी दोनों) को ग्रहण करना अन्धकार में कूदने के समान खतरनाक होगा । इस मत-भेद के कारण कुछ भी न हो सका । भारत-सरकार ने आशा की थी कि अन्तर्गष्ट्रीय समझौते से द्वैत प्रणाली की स्थापना और चादी के प्रश्न का हल हो जायगा, पर वह आशा निराशा में परिणत हो गई ।

उधर चादी नीचे गिरती ही गई और उसके साथ-साथ हमारी हण्डी की दर भी —

चादी का औसत दाम		औसत एक्मनैज
	पेस	पेस
१८८५—८६	४८ $\frac{५}{८}$	१९ २५४
१८८६—८७	४५ $\frac{३}{४}$	१७ ४४१
१८८७—८८	४४ $\frac{३}{४}$	१६ ८९८
१८८८—८९	४२ $\frac{३}{४}$	१६ ३७९
१८८९—९०	४२ $\frac{१}{४}$	१६ ५६६
१८९०—९१	४७ $\frac{१}{४}$	१८ ०८०
१८९१—९२	४५ $\frac{१}{४}$	१६ ७३३
१८९२—९३	३९ $\frac{१}{४}$	१४.९८५
१८९३—९४	३५ $\frac{१}{४}$	१४ ५४७

१८९१ में मुम्बई में आया कि अमेरिका चादी की समस्या पर चिन्ता करने के लिए एक अन्तर्गष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है । भारत-वर्ष में किसीने इस सम्मेलन में विशेष आशा नहीं की । पर सरकार और

अगरेज व्यवसायी यह सोचने-विचारने लगे कि अगर यह सम्मेलन भी पहले सम्मेलनों की तरह असफल रहा तो हमारा कर्नव्य क्या होगा। भारत-सरकार ने इस सम्बन्ध में भारत-सचिव को लिखा (जून २१, १८९२) कि —

“अगर यह स्पष्ट हो गया कि इस सम्मेलन में कोई सन्तोषजनक व्यवस्था होनेवाली नहीं है, और यह भी स्पष्ट हो गया कि भारतवर्ष और अमेरिका के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता, तो हमारा प्रस्ताव है कि सर्वसाधारण के लिए चादी की टकसाल का दरवाजा बन्द कर दिया जाय और चादी की जगह सोने की गद्दीनशी करने की तैयारी की जाय।”

सोने और चादी के बीच का सम्बन्ध क्या हो, इस विषय में अपनी राय जाहिर करते हुए भारत-सरकार ने लिखा कि एक्सचेंज को हम उसी रेट या दर के आस-पास रखना चाहते हैं जो नई व्यवस्था करते समय बाजार में हो।

२१ जून को लिखते हुए भारत-सरकार ने भारत-सचिव को विश्वास दिलाया कि लोकमत चादी के परित्याग और सोने के अंगीकार के सर्वथा अनुकूल है और व्यापारीवर्ग से हमें इस काम में हर प्रकार की उचित सहायता मिल सकती है।

वास्तव में यह अत्यन्त और असत्य था। भारतवासियों के जो सच्चे प्रतिनिधि हो सकते थे वे चादी के परित्याग के घोर विरोधी थे, क्योंकि वे जानते थे कि सोने की आड़ में उसके पक्षपाती एक्सचेंज को ऊँचा करना चाहते थे। ब्रिटिश व्यवसायी भी दो दलों में विभक्त थे। एक दल सरकार के साथ था, और उसके नेता थे मैकीनन मैकजी कम्पनी के मि० जेम्स मैके, जो बाद में लॉर्ड इचकेप के नाम से मशहूर हुए। इसकी ओर से ‘इण्डियन करेन्सी एसोसियेशन’ नाम से एक संस्था सड़ी की गई, और पार्लमेण्ट के पास भेजने के लिए एक आवेदनपत्र पर येनकेनप्रकारेण लोगों के दस्तखत कराए जाने लगे। दूसरा दल चादी के परित्याग के प्रस्ताव का विरोधी था, और इसमें राली ब्रदर्स, ग्राहम, जॉर्ज हेडर्सन, ऐण्ड्रू यूल, शा वेल्लेस-जैसे प्रतिष्ठित फर्म सम्मिलित थे। इन लोगों की

ओर से ९ फरवरी १८९३ को गवर्नर-जनरल के पास एक आवेदनपत्र भेजा गया। उसमें कहा गया था—

“हम लोग कलकत्ते के व्यवसाय के बहुत बड़े अंश के प्रतिनिधि हैं और प्रान्त भर के उत्पादक और दूसरे व्यवसायी इस विषय में हमारे साथ हैं।

“हम लोगों का मत है कि करेन्सी एसोसियेशन रुपए का विनिमय-मूल्य ऊँचा कराने और ठहराने के लिए जो प्रस्ताव कर रहा है वह हानि-कारक है, जिससे सरकार की अपनी सार्व और इस देश के वाणिज्य-व्यवसाय को खतरा है।

“हम लोग इस बात के पक्षपाती नहीं कि रुपए का मूल्य डाब-डोल बना रहे या वह बराबर नीचे गिरता जाय, पर हमारे विचार में उसमें भी कहीं अधिक आपत्तिजनक है उसको पाँड-शिलिंग-पेस में कृत्रिम मूल्य प्रदान करना। हम यह कहें बिना नहीं रह सकते कि करेन्सी एसोसियेशन का बताया हुआ इलाज किया गया तो बीमारी और भी बढ़ जायगी और तरह-तरह के उपद्रव होने लगेंगे।

“हम लोग अनुभवी व्यापारी होने का दावा कर सकते हैं, और इस हैसियत में हम करेन्सी एसोसियेशन के अध्यक्ष के इस कथन का गूँठ फगना चाहते हैं, कि चांदी के गिरने में इस देश के व्यापार को बड़ा धक्का लगा है और यहाँ ऐसी मन्दी आ गई है जैसी पहले कभी नहीं थी। वाम्ना में जो मन्दी है उसके कारण और ही है।

‘हम जानते हैं कि सरकार की आर्थिक स्थिति चांदी या एमनेज के गिरने में चिन्ताजनक हो गई है—और उसके जिन कर्मचारियों को उसमें नुकसान पहुँचा है उनमें हमारी पूरी सहानुभूति भी है। पर स्थिति का मुताबिके के लिए न तो यह आवश्यक है, न वांछनीय, कि हम अपनी मदद-प्रार्थना को ही—जो हमारे वाणिज्य-व्यवसाय का आधार है और जिसमें इस देश की धन-सम्पदा उतनी बड़ी है—बिनाकुल बर्बाद दें।’

उपर जिन फर्मा के नाम लिख गए हैं उनके अलावा उस आवेदनपत्र पर रिचर्ड ब्रन्नी, टांगरान प्रसाद बोरिंग वाणिज्य, न्याय मार्गद,

आक्टोवियन स्टील, ग्रामर लॉरी, जेम्स डफ्स, डेविड मैमून ऐंड कम्पनी आदि के भी हस्ताधार थे ।

भारतीय मन्त्रियों की ओर से भी टकसाल वन्द करने के प्रस्ताव का विरोध किया गया । कांग्रेस के मत का उल्लेख हम पीछे करेंगे, यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं कि कलकत्ते की इण्डियन एसोसियेशन और पश्चिम भारत की प्रमुख मन्त्रिणी इण्डस्ट्रियल एसोसियेशन ने भी उस प्रस्ताव का घोर विरोध किया । इण्डियन एसोसियेशन ने अपने वक्तव्य में ठीक ही कहा —

“भारत-सरकार की जो आर्थिक स्थिति हो रही है उसे सुधारने का सही तरीका है फौजी खर्च में कमी करना, जो रकम इंग्लैण्ड में रार्ब की जाती है उसको घटाना, अंगरेज कर्मचारियों की मन्त्र्या कम करके उनकी जगह भारतवासियों को भरती करना, और—आवश्यक हो तो—ऐसी विदेशी वस्तुओं पर हलका-सा कर लगा देना, जो यहाँ न तो जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आती है, न इस देश के उद्योग-धन्धों की तरस्की के लिए ।”

वास्तव में सरकारी कर्मचारी करेन्सी एसोसियेशन से शिखण्टी का काम ले रहे थे । पर वे उतने में ही सन्तुष्ट न हुए । उनकी ओर से, और भी जितने उपायों से आन्दोलन किया जा सकता था, किया गया । ३१ जनवरी १८९३ को एक डेपुटेशन बड़े लाट (लॉर्ड लैन्सडाउन) से भी मिला । उनके साथ सरकार की हमदर्दी जाहिर करते हुए बड़े लाट ने यह सूचित किया कि यद्यपि सारा विषय उस समय विचाराधीन था तथापि भारत सचिव के आज्ञानुसार यह निश्चित हो चुका था कि फिलहाल जो कर्मचारी छुट्टी लेकर विलायत जायेंगे उनको वेतन और भत्ता १६½ पेंस की रेट में मिलेगा । बाजार-दर उस समय १४½ पेंस थी ।

सरकार की हमदर्दी और भी आगे गई । टकसाल वन्द हो जाने के बाद उसने गोरे और अधगोरे कर्मचारियों को एक खास तरह का भत्ता देना मजूर किया, जो एक्सचेंज गिरने के कारण होनेवाली क्षति की पूर्ति के लिए था । यह भत्ता कई साल तक मिलता रहा । बाजार में वास्त-

विक एक्सचेंज रेट और १८ पेंस के बीच जो फर्क होता वह उन्हें सरकार की ओर से मिल जाता, जिससे वे साल में १००० पौंड तक विलायत भेज सके। जिन्हें इतना न भेजना पड़ता वे भी भत्ता पाने के हकदार होते। हर साल इसमें सरकार का एक करोड़ रुपए से अधिक खर्च होता रहा। कांग्रेस बराबर इस भत्ते का विरोध करती रही।

१ सितम्बर १८९२ को भारत-सरकार के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक करेन्सी-कमेटी की नियुक्ति हुई। इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड हर्शल, (जो उस समय लॉर्ड चान्सेलर थे) और इसके बाकी सदस्यों में मि० कर्टनी, सर आर्थर गाटले, जनरल स्ट्राची आदि थे।

इसी बीच वह अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी बेल्जियम की राजधानी में बैठा। पर जिस राह और सम्मेलन जा चुके थे उसी राह यह सम्मेलन भी गया। इसकी असफलता का एक नतीजा यह हुआ कि चांदी की टक्क-साल बन्द करानेवालों के आन्दोलन में और भी बल आ गया।

उधर हर्शल कमेटी की बैठकें लन्दन में होती रहीं और गवाहिया गुजरती रहीं। उन गवाहों में एकमात्र भारतवासी प्रात स्मरणीय दादाभाई नौरोजी थे, और उन्होंने भारत-सरकार के प्रस्ताव का विरोध ही किया। पर उनका साथ देनेवाले कई अगरेज गवाह भी थे, जिनमें गल्ली ब्रदर्स के मि० गल्ली, मि० राबर्ट ग्रिफिन (जो वर्षों बोर्ड आफ ट्रेड में बड़े कर्मचारी रह चुके थे), यूनियन बैंक आव स्कॉटलैण्ड के जनरल मैनेजर मि० चार्म गेडनर, मि० विलियम फौलर, सर फ्रांक फार्न्स गेडम आदि मुख्य थे।

कमेटी की रिपोर्ट मई १८९३ के अन्त में तैयार हुई। उसका निचोड़ यही था कि भारतवर्ष चांदी का परित्याग कर दे—सर्वसाधारण के लिए टक्का का दरवाजा बन्द कर दिया जाय और टुण्टी की दर फिलहाल १६ पेंस कर दी जाय।

गर्ज यह कि भारत-सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। कमेटी ने उसमें टैक्सेस किया ता इतना ही, कि टुण्टी की दर १८ पेंस न बन्दे (यह हद सरकार की ओर से मुद्राई गई थी) उगने फिलहाल १६ पेंस कर देने की सिफारिश की। भारत-सरकार ने कहा था, और कमेटी

ने भी इनको दोहराया कि चादी का परिचयाग, मोने के ग्रहण के उद्देश से ही किया जा रहा था ।

२० जून को भारत-सचिव ने तार-द्वारा भारत-सरकार को एकसाल बन्द करने और नई व्यवस्था जारी करने के लिए मुनासिब कार्रवाई करने की इजाजत दी ।

२६ जून को बड़े लाट की विधान-सभा में इस विषय से सम्बन्ध रखने वाला कानून पार हुआ और उसी दम चादी सिंहासनच्युत कर दी गई । सर्वसाधारण के लिए अब एकसाल का दरवाजा खुला न रहा—वहा चादी के सिक्के टलवाने का अधिकार अब केवल सरकार को रह गया । साथ ही साथ इस बान की भी व्यवस्था की गई कि एकसाल में जो कोई १६ पैसे अर्थात् ७ ५३३४४ ग्रेन तालिस सोना दाखिल करे उसे बदले में एक रुपया मिल जाय ।

हर्शल कमेटी ने जिस व्यवस्था की सिफारिश की थी, और जो अब कानूनन जारी की गई, वह थोड़े समय के लिए थी । विचार यह था कि इसका अनुभव हो जाने पर स्थायी व्यवस्था की जाय । एक्सचेंज अर्थात् हुण्डी की दर के सम्बन्ध में यह बात खास तौर से नोट कर लेनी चाहिए । हर्शल कमेटी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर परिस्थिति अनुकूल हो तो यह दर बढ़ाई जा सकती है । सरकार की ओर से विधान-सभा में कहा गया कि चादी के रुपए और सोने के बीच जो सम्बन्ध स्थापित किया जा रहा है उसको अन्तिम निर्णय नहीं समझना चाहिए ।

कांग्रेस ने प्रस्ताव-द्वारा इस बात पर जोर दिया था कि हर्शल कमेटी की जो सिफारिशें हो वे सर्वसाधारण के सामने रखी जाय और किसी भी प्रकार की कार्रवाई में पहले उसपर पूरी तरह से विचार हो ले । पर हमारी सरकार उतने समय के लिए भी ठहरनेवाली न थी ।

अब पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनिए —

बार-बार सरकार की ओर से यह रोना रोया जाता था कि चादी गिरने से हुण्डी की दर गिरती है और इसका नतीजा यह होता है कि जो रकम हमें विलायत भेजनी होती है उसके लिए यहा अधिकाधिक रुपए

सरहदी लडाओ म पेमा पानी की तरह बहाया गया, फौजी ताकत बढ़ाने में अन्धाधुन्ध खर्च किया गया। पर जब आर्थिक कठिनाई उपस्थित हुई तब इसके लिए दोषी ठहराई गई गरीब चादी और रुपए का गिरा हुआ विनिमय-मूल्य।

घड़ी भर के लिए यह मान भी लिया जाय कि बिना कर-वृद्धि किए सरकार की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती थी, तो भी कहना पड़ेगा कि सरकार को जो करना चाहिए था उसे करने को वह तैयार न थी। विदेशी वस्तुओं पर उस समय जो कर या ड्यूटी थी वह नहीं के बराबर थी। १८७५ में यह ड्यूटी ५ प्रतिशत कर दी गई थी। कपड़े के लिए खास रियायत थी। १८८२ में नमक और शराब को छोड़, बाकी चीजों पर मे ड्यूटी उठा ली गई और इसके बाद कई साल तक विदेशी वस्तुएं यहाँ बिना किसी प्रकार का कर दिए आती रही। इनमें प्रधानता कपड़े की थी। हर्शल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि "आय बढ़ाने के लिए अगर विदेशी वस्तुओं पर फिर मे ड्यूटी लगा दी जाय तो इसका बहुत कम विरोध होगा—कहा तो यह जाता है कि यह काम लोकप्रिय होगा। पर कठिनाई यह है कि अभी हाल में ही कपड़े पर मे ड्यूटी उठा ली गई है, और अगर वह फिर मे लगा दी गई तो इंग्लैण्ड में इसका घोर विरोध होगा।" इंग्लैण्ड का विरोध स्वार्थमूलक था। उसका उद्देश था मंचेस्टर की मिलों को अधिक-से-अधिक सम्पन्न करना। बार-बार उनकी मालाई की वेदी पर भारत के हित का बलिदान किया गया। अगर भारत स्वतन्त्र होना, और चादी के गिरने में सचमुच उसे कोई कठिनाई होनी, तो वह इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा कर बड़ी ही आसानी से उस समस्या का हल कर सकता था।

यह बड़े सरकार के मास्ट की बात। अब अंगरेज कमचारियों की कठिनाइयों को नज़िज़।

वहने की आवश्यकता नहीं कि उन्हें मगार में ऊँचे-ऊँचे बैठा और ऊँचे-ऊँचे बने मिलने थे। 'कैपिटल' नामक पत्र ने अपने १० जुलाई, १८९० के अंक में बहुत ठीक लिखा था कि "अगर एक चादी कमी-

शन यहा आकर जाच करे, तो यह बात-की-बात में स्पष्ट हो जायगा कि जो अफंसर या कर्मचारी सबसे ज्यादा शोर जरूर मचा रहे हैं वे इमदाद पाने के सबसे कम हकदार हैं। यहा तो जरूरत इस बात की है कि वेतन और भत्ते नए सिरे से मुकरंर किए जाय, क्योंकि कुछ तो बहुत ही कम पाते हैं, और कुछ बहुत ही ज्यादा। ससार में और कोई देश नहीं, जहा वेतन इतने उंचे हों, और चीजें इतनी सस्ती।” यह ध्यान में रखने की बात है कि यूरोप में १८७३ और १८९३ के बीच, मोना महंगा होने के कारण, दाम काफी नीचे गिर गए थे। स्वेज की नहर के खुलने से यूरोप का रास्ता पहले से छोटा हो गया था और आने-जाने में खर्च कम पड़ता था। इधर भारतवर्ष में रेलों का जाल फैलता जा रहा था और व्यापारिक प्रतियोगिता बढ़ती जा रही थी। ये सारे कारण विदेशी वस्तुओं के दामों को यहा नीचे गिरानेवाले थे। एक्सचेंज गिरने का असर उलटा जरूर पड़ता था, पर फिर भी बाहर से आनेवाली चीजें १८९३ में १८७३ की अपेक्षा सस्ती थीं। लन्दन के ‘स्टेटिस्ट’ नामक पत्र ने इन कर्मचारियों की मांग पर टीका करते हुए लिखा था —

“इनका कहना है कि वेतन का जो हिस्सा हमें यूरोप से आनेवाली चीजों पर खर्च करना पड़ता है उसमें सैकड़े ३८ की वृद्धि हुई है। शायद इनका खयाल है कि यूरोप में रहनेवाले भारत की बातों से विलकुल अनभिज्ञ हैं। यह खयाल न होता तो ये ऐसी बात कहने की धृष्टता न करते। असलियत तो यह है कि यह वृद्धि नहीं के बराबर हुई है।

फिर इनका कहना है कि वेतन का जो हिस्सा हमें विलायत भेजना पड़ता है उसमें भी नुकसान उठाना पड़ता है। पर अगर नुकसान हो भी तो भारत-सरकार का इसमें क्या दोष? वह तो कहेगी और बहुत ठीक कहेगी, कि हमने तुम लोगों को जो कुछ देने का वादा किया था वह दे दिया। उसके जितने कर्मचारी हैं उनके वेतन वह रुपये में चुका देती है। चादी के गिरने से रुपए की एक्सचेंज-दर [गिरती है तो वह क्या करे? उसके लिए न वह जिम्मेवार है, न वह उसके रोके रुक सकती है।”

चादी के विगड़ आन्दोलन करनेवालों का कहना था कि मौजूदा हालत में एमचेज अस्थिर, टावाटोल रहता है और यह व्यापार के मार्ग में बाधक का काम करता है। पर हर्शल कमेटी के सामने कई ऐसे उदाहरण पेश किए गए जो और ही बात साबित करनेवाले थे। दक्षिण अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रिया आदि देशों के साथ—एमचेज में अस्थिरता होती हुए भी—एंग्लैण्ड बड़े पैमाने पर व्यापार कर चुका था, और जिन्होंने यह उदाहरण पेश किए, उनका पूछना था कि जब एमचेज की घटावही वहां बाधक नहीं हुई तब क्या कारण है कि गिरफा भार्गवर्ष में होगी? रास्ली ब्रदर्स नामक जगद्विग्यान कम्पनी के मालिक मि० स्टैफेन रास्ली ने कमेटी ने पूछा कि ऊपर रुपए की दर में जो घटावही हुई है, उसमें आपको अपने व्यापार में कोई दिक्कत उठानी पड़ी है या नहीं? मि० रास्ली ने जवाब दिया कि नहीं, कोई भी नहीं। उन्होंने यह तरीका भी बताया जो, व्यापारी लॉग जॉयिंग में बचने के लिए काम में लाने थे और आज भी लात हैं। मान लीजिए, हमें दो महीने बाद कुछ डॉलरों की जरूरत पड़ेगी। एमचेज अस्थिर होने के कारण कोई नहीं कह सकता कि उस समय उन डॉलरों के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे। पर हम उस विषय में निश्चिन्त हो जाना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में हम 'फारवर्ड' अर्थात् आगे मिलनेवाले डॉलर आज ही बैंक में गरीद लगे और समय आने पर उन्हें देकर भुगतान कर देंगे। अगर बैंक ने आगे के डॉलर मिलने में दिक्कत हुई, तो हम सम्भवतः यदा कुछ मात्र गरीद कर अमेरिका में बेच देंगे, जिसमें हमें वही समय पर डॉलर मिल जाय।

यदि पूछा जाय तो मुद्रा या विनिमय का प्रश्न सरकार या उर्मा कर्मचारियों या व्यापारियों का प्रश्न न होकर हम देश की जनता का—यदा के कगटों त्रिमानों का—प्रश्न था। हमें कमाने की कमीटी यही थी कि चादी या एमचेज के गिरने में उस जनता का—उन कगटों त्रिमानों का—लाभ हुआ है या हानि? अगर त्रिमान-जैसे उत्पादक उसमें लाभान्वित हुए थे, तो हमने यह सिद्ध था कि चादी हमारे देश के लिए हितकर थी, और हमारे सामने यह बात तोट मरुतब पाने लायक नहीं थी कि अगले

कर्मचारी या व्यापारी उससे थोड़ी-बहुत हानि उठा चुके थे और उससे असन्तुष्ट थे ।

ऊपर कहा जा चुका है कि यूरोप में दाम गिरते आ रहे थे । सोना महंगा हो रहा था, इसलिए जो दाम सोने में दिए जाते थे वे कम हो रहे थे । भारतवर्ष में चादी न होती और चादी का बाजार इस तरह न गिरता तो यहाँ भी दामों की यही गति होती । इसमें किसान या दूसरे उत्पादक बड़े घाटे में रहते । किसान को लगान या कर या सूद के रूप में जो कुछ देना पड़ता है वह एक निश्चित रकम होती है । यह रकम वह देता है अपने गाँव पसीने की कमाई से—अपने खेत का अन्न या गल्ला बेचकर । इसका दाम जितना ही अधिक मिले, उसके हक में उतना ही अच्छा । मान लीजिए कि जिस समय यूरोप में दाम गिर रहे थे उस समय हमारे रुपए के विनिमय-मूल्य में स्थिरता थी, तो उस हालत में हमारे यहाँ भी दाम उसी हिसाब से गिरते और हमारे किसान बड़े सकट में पड़ जाते । पर हुआ यह कि चादी सस्ती हो चली—रुपए का विनिमय-मूल्य भी गिरता गया—और द्रव्य सस्ता होने का अर्थ है दामों का उठना, इसलिए दाम (सोने में गिरने पर भी) यहाँ ऊपर उठे रहे । सोना महंगा होकर हमारे किसानों पर आघात करने जा रहा था, पर चादी ने सस्ती होकर, और बीच में पड़कर, उनको बचा लिया । इंग्लैण्ड में जिन्सों का दाम जहाँ १८६३ में १०० था वहाँ गिरते-गिरते १८९३ में ६१ रह गया था । भारत में गल्ले का दाम जहाँ १८६३ में १०० था वहाँ १८९३ में १२९ था । अगर यहाँ चादी का रुपया न होता और इसका मूल्य न गिरता, तो यहाँ भी दाम ऊपर जाने के बजाय इंग्लैण्ड की तरह नीचे गिरते ।

विदेशी व्यापार के आकड़े भी यही सिद्ध करते हैं कि चादी से हमारा लाभ ही हुआ ।

१८७३—७४

निर्यात (एक्सपोर्ट)	५४,९६,०७,८६० रु०
आयात (इम्पोर्ट)	३१,६२,८४,९७० रु०
आयात से निर्यात अधिक	२३,३३,२२,८९० रु०

१८९२—९३

निर्यात (एक्सपोर्ट) १०६,५१,५१,९३० रु०

आयात (इम्पोर्ट) ६२,६१,८३,८३० रु०

आयात से निर्यात अधिक ४३,८९,६८,१०० रु०

भारतवर्ष में इम्पोर्ट (आयात) एक्सपोर्ट (निर्यात) पर निर्भर करता है। जब किसान अपना गन्ना बेचकर ज्यादा रुपए पाते हैं तब वे विदेशी वस्तुओं पर भी ज्यादा खर्च करते हैं। एक्सचेंज गिरते रहने में इम्पोर्ट बहुत कम हो जाना चाहिए था, पर असलियत में यह प्रायः दूना हो गया। फिर भी करंसी ऐसोसियेशनवाले सन्तुष्ट नहीं थे, और यही कहते जाते थे कि व्यापार चौपट हो गया।

नीचा एक्सचेंज भारतवर्ष के लिए लाभदायक है या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कलकत्ते की मजदूर कम्पनी ऐण्ड यूल् के मालिक मि० जार्ज यूल् ने (जो इण्डियन नेशनल कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के प्रेसिडेंट हुए थे) कहा था कि—

“हा, यह अवश्य लाभदायक है। मैं यह उत्तर गहरी समीक्षा-परीक्षा के बाद दे रहा हूँ।”

मि० यूल् का कहना था कि ब्रिटिश पूँजीपति यहाँ के उद्योग-मालों का गन्ना घोट देना चाहते थे और उमी उद्देश में, भारत-सरकार के अगरेज कर्मचारियों को आगे मझा करके, मारा आन्दोलन चला गये थे। इसमें गाम हाथ लंकाशायरवालों का था, जो यहाँ की काटन-मिलों को नष्ट कर डारना चाहते थे। चादी के गिरने में इन मिलों को पायदा पटुचा था और उनकी तरफ़ी हुई थी। १८७६-७७ में जहाँ ४७ काटन-मिलें थी वहाँ १८९१-९२ में १०५ हो चली थी। इस बीच में ग्लिण्डल (तुल्य) १,१००,११० में ३,०७०,९८८ और लूम (करघे) ९,१३९ में २४,६७० हो चले थे। यहाँ की काटन-मिलें चीन के बाजार में भी मँचंगर में प्रतिस्पर्धिता करने लगी थी और इसके व्यापार का काफी बड़ा हिस्सा उनके हाथ में आ गया था। नीचे के आंकड़ों की रेजिष्ट्र —

इंग्लैण्ड से सूता चीन गया—

	कीमत पीड मे
१८९०	१,७९७,०००
१८९१	१,५०७,०००

भारतवर्ष से सूता चीन गया—

	कीमत पीड मे
१८९०	१७,५०७,०००
१८९१	१९,३९७,०००

१८७६-७७ में भारतवर्ष में जहा ७,९२७,००० पीड सूता और १५,५४४,००० गज कपडा चीन गए थे वहा १८९१-९२ में क्रमश १६१,०५३,००० पीड और ७३,३८४,००० गज गए ।

जापान भी उस समय यहा की मिलो के सूते का बडा खरीदार था । यह मब मैचेस्टर के लिए असह्य था, इसलिए उसकी ओर से इस बात की भरपूर कोशिश हुई कि भारतवर्ष से चादी की मुद्रा उठा ली जाय और रुपए की एक्सचेंज-दर उस समय जो ऊंची-मे-ऊंची हो सकती थी, कर दी जाय । इस प्रकार एक्सचेंज को उचा करने से चीन में भारतवर्ष की क्या क्षति होनेवाली थी, यह बताते हुए अघाई की चीन-एसोसियेशन नामक सम्या ने हर्गल कमेटी को लिखा था —

“उस समय भारतवर्ष की मिल जब २३,००० रुपए का सूता यहा बेचती है तब उसके १०,००० डॉलर होते हैं । चीनवाले १०,००० डॉलर इसलिए देते हैं कि वे इससे कम म वैमा सूता स्वय तैयार नहीं कर सकते, पर अगर एक्सचेंज की दर १८ पेस कर दी गई तो भारतवर्ष की मिल को तो पहले की ही तरह २३,००० रुपए मिलेंगे, पर चीन के खरीदार को इसके लिए यहा १२,००० डॉलर देना पड़ेगा । बहुत सम्भव है कि सूता इतना महंगा हो जाने पर चीनवाले अपनी ही मिले खोल ले और भारतवर्ष के लिए स्थिति यह हो जाय कि या तो वह अपना दाम नीचा करे, या इस व्यापार से हाथ धो बैठे ।”

झाघाई के अलावा और स्थानों ने भी—जैसे हागकाग और सीलोन ने—
 इस प्रस्ताव का विरोध किया कि भारतवर्ष से चादी की मुद्रा उठा ली जाय।
 उन देशों में भी यहाँ का रुपया चलता था, और इसका मूल्य कृत्रिम हो जाने
 से वहाँ के उत्पादकों की भी हानि थी। पर उनका आवेदन-निवेदन भी
 अरुण्यरोदन ही रहा।

सोने का ग्रहण

मूल्य मापने के लिए पहले चादी का रुपया काम में लाया जाता था। स्वयसिद्ध मुद्रा होने के कारण, १६५ ग्रेन चादी की सोने में जो कीमत होती, वही रुपए की कीमत थी। पर अब रुपए का वह स्वरूप न रहा। रुपया अब प्रतीक-मुद्रा कर दिया गया। वह सोने का प्रतिनिधित्व करने लगा। १६५ ग्रेन चादी की कीमत सोने में चाहे जितनी कम हो, पर वह १६ पैसे अर्थात् ७ ५३३४४ ग्रेन सोने का द्योतक हो गई।

“हर्ज क्या रुपया जो कागज का चला? गम न खा—रोटी तो गेहूँ की रही।” पर सच पूछिए तो चादी का रुपया भी अब एक प्रकार का नोट ही था। साधारण नोट से उसमें फर्क था तो इतना ही कि यह नोट कागज का न होकर चादी का था। मूल्य अब दोनों का ही कृत्रिम था।

चादी की टकसाल बन्द हो जाने पर स्थिति यह थी —

(१) चाँदी अब स्वयसिद्ध मुद्रा या मूल्य-मापक नहीं रही।

(२) सरकार अपने को बचनबद्ध कर चुकी थी कि यह स्थान सोने को प्रदान किया जायगा।

(३) इस देश में चलन सिर्फ प्रतीक-मुद्राओं का रह गया, जिनमें कागजी नोटों के साथ चादी के भी नोट थे।

(४) साधारणतः चादी की ऐसी प्रतीक-मुद्रा कानूनन एक हद तक ही लेने-देने के काम में लाई जा सकती है। उदाहरणार्थ, इंग्लैंड में शिलिंग का सिक्का प्रतीक-मुद्रा का काम करता था, पर शिलिंग में एक पौड से ज्यादा देने-लेने को कोई भी कानूनन बाध्य नहीं था। पर यहाँ भारतवर्ष में रुपए पर ऐसी कोई कैद नहीं लगाई गई—चाहे जितना देना-भावना हो, रुपए में दिया-लिया जा सकता था।

(५) अभी तक चरुन में प्रत्यक्ष रुप में मोना नहीं आया था। एक-साल में या सरकार की खजाने में नाँवरेन १६ पैस की दर में लिए जा सकते थे। पर उन्हें देने-लेने को जनता कानूनन बाध्य नहीं थी।

(६) सरकार इस दर में (अर्थात् ७५३३८८ ग्रेन मोना = १ रुपया) मोने के बदले रुपए देने को तैयार थी, पर रुपए के बदले सोना देने को नहीं। रुपए का विनिमय-मूल्य १६ पैस बाध्य दिया गया था, इसलिए वह उसमें ऊपर नहीं जा सकता था। जब ७५३३८८ ग्रेन मोना सरकार को देकर इसमें एक रुपया लिया जा सकता था, तब कोई दूसरे को एक रुपए के लिए उसमें अधिक मोना क्योंकर देता? पर चूँकि सरकार ने रुपए के बदले मोना देने की कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी, उसका विनिमय-मूल्य १६ पैस में नीचे गिर सकता था।

(७) विनिमय-मूल्य या एक्सचेंज १६ पैस कर दिया गया था, पर स्यासी रुप में नहीं। हमारे सामक देवना यह चाहते थे कि ऊठ किम कर-वट बैठना है। परिस्थिति अनुकूल हुई तो उनका उगदा उमराँ और भी उचा कर देने का था। मूल्य के मान के लिए अंगरेजी में 'स्टैंडर्ड' शब्द व्यवहृत होता है। मोना स्टैंडर्ड कर देने का अर्थ है इस बात की व्यवस्था करना कि लेन-देन के भुगतान के लिए लोगों को माना मित्र मों। पर इस समय वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उधर चादी भी स्टैंडर्ड की गणत नहीं रह गई थी। फिर यहाँ का स्टैंडर्ड क्या था? वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं था। सर जन लवक नामक एक प्रसिद्ध वैदक थे, जो १८८६ वाले माना-चादी वर्गीकरण के मेम्बर थे। उन्होंने इस विषय में अपनी राय जाहिर की थी।

नकारात्मक स्टैंडर्ड 'एक्सचेंज स्टैंडर्ड' था

समझ में, इस स्टैण्डर्ड को इससे अच्छा और कोई नाम न मिल सकने के कारण—‘एक्सचेंज स्टैण्डर्ड’ कहना चाहिए।”

सर जॉन लवक इस प्रकार के स्टैण्डर्ड के विरोधी थे। उनकी खास आपत्ति यह थी कि इस प्रकार की व्यवस्था में करेसी का घटना या बढ़ना प्राकृतिक रूप में न होकर सरकार की मर्जी के मुताबिक हुआ करेगा, जो बड़ी भयंकर वस्तु होगी।

चांदी के पक्षपाती बराबर यह कहते आ रहे थे कि जो लोग सोना-सोना चिल्ला रहे हैं वे कपटी हैं और उनका उद्देश्य भारतवर्ष को सोना देना नहीं, बल्कि हुडी की दर को ऊंचा करके रुपए को ही बराबर चलन में रखना है। मिस्टर राली ने अपने मत का स्पष्टीकरण करते हुए कहा था कि “मेरा विश्वास है कि सोने के स्टैण्डर्ड के प्रश्न की आड़ या तह में एक्सचेंज का प्रश्न है। अगर भारतवर्ष में सोने का स्टैण्डर्ड हो चले तथा सोने और रुपए के बीच की एक्सचेंज-दर काफी नीची हो, तो मैं हर्गिज उस स्टैण्डर्ड का विरोध न करूंगा।” अब धीरे-धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि सचमुच हमारे साथ एक तरह की चाल चली गई थी—हमको सोने का स्टैण्डर्ड देने का वादा मचाई के साथ नहीं किया गया था। जो हर्शल कमेटी के मेम्बर रह चुके थे उनका भी सोने के सम्बन्ध में अपना-अपना विचार था। १८९८ में बयान देते हुए लॉर्ड फारर ने तो यह कहा कि “अगर मेरा विश्वास यह न होता कि हर्शल कमेटी की रिपोर्ट भारतवर्ष को सोने का स्टैण्डर्ड दिलायेगी तो मैं उस पर कभी दस्तखत न करता।” उनका कहना था कि यहाँ अभी तक सोने का स्टैण्डर्ड स्थापित नहीं हुआ है। उधर मि० कर्टनी ने जो लॉर्ड फारर की तरह हर्शल कमेटी के मेम्बर रह चुके थे, फर्माया कि—नहीं, जब सरकार सर्वसाधारण से लगान या कर के भुगतान में सोना लेने को तैयार है और रुपए की एक्सचेंज-दर १६ पैसे हो चुकी है तब समझना चाहिए कि सोने का स्टैण्डर्ड स्थापित हो चुका। शुरू से ही यहाँ की मुद्रा-प्रणाली को ऐसा रूप दिया गया कि वास्तविकता आसानी से किसीकी समझ में न आ सके और उसकी जटिलता की आड़ में हमारे कर्ताधर्ता जो दस्तन्दाजी चाहें, कर सकें। जिस रोज हर्शल कमेटी की रिपोर्ट तैयार

(५) अभी तक चलन में प्रत्यक्ष रुप से सोना नहीं आया था। टक-साठ में या सरकारी राजाने में साँवरेन १६ पेस की दर में लिए जा सकते थे। पर उन्हें देने-लेने को जनता कानूनन बाध्य नहीं थी।

(६) सरकार इस दर में (अर्थात् ७५३३४४ ग्रेन सोना = १ रुपया) सोने के बदले रुपए देने को तैयार थी, पर रुपए के बदले सोना देने को नहीं। रुपए का विनिमय-मूल्य १६ पेस बाध दिया गया था, इसलिए वह उममें ऊपर नहीं जा सकता था। जब ७५३३४४ ग्रेन सोना सरकार को देकर इसमें एक रुपया लिया जा सकता था, तब कोई दूसरे को एक रुपए के लिए उममें अधिक सोना क्योंकर देता ? पर चूँकि सरकार ने रुपए के बदले सोना देने की कोई जिम्मेवारी नहीं ली थी, उमका विनिमय-मूल्य १६ पेस में नीचे गिर सकता था।

(७) विनिमय-मूल्य या एक्सचेंज १६ पेस कर दिया गया था, पर स्थायी रूप में नहीं। हमारे जागतिक देयता यह चाहते थे कि उठ किंग कर-वट बैठता है। परिस्थिति अनुकूल हुई तो उनका इरादा उमको और भी ऊँचा कर देने का था। मूल्य के मान के लिए अंगरेजी में 'स्टैंडर्ड' शब्द व्यवहृत होता है। सोना 'स्टैंडर्ड' कर देने का अर्थ है इस बात की व्यवस्था करना कि लेन-देन के भुगतान के लिए लोगों को सोना मिल सके। पर हम समय यह ऐसी बात व्यवस्था नहीं की। उधर चांदी भी 'स्टैंडर्ड' की जगह नहीं रह गई थी। फिर यहाँ का 'स्टैंडर्ड' क्या था ? वास्तव में उम प्रदान का उत्तर देना आसान नहीं था। सर जान लवक नामक एक प्रसिद्ध बैंकर थे, जो १८८६ बाई सोना-चांदी कमीशन के मेम्बर रह चुके थे। उन्होंने उम समय में अपनी राय जाहिर करने हुए कहा था कि यहाँ का नकारात्मक 'स्टैंडर्ड' 'एक्सचेंज स्टैंडर्ड' था। हमकी व्याख्या उन्होंने इस शब्दों में की थी —

“जब हमें कोई सरकार ऐसे नोट (वे चाहे राज के २१, चाहे रुपए की तरह चांदी के) जारी करती है जो कानूनन सोने में बदले नहीं जा सकते, और उमकी सीपन टूटने की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेती है, तो, मेरी

समझ में, इस स्टैंडर्ड को इससे अच्छा और कोई नाम न मिल सकने के कारण—‘एक्सचेंज स्टैंडर्ड’ कहना चाहिए।”

सर जॉन लवक इस प्रकार के स्टैंडर्ड के विरोधी थे। उनकी खास आपत्ति यह थी कि इस प्रकार की व्यवस्था में करेसी का घटना या बढ़ना प्राकृतिक रूप में न होकर सरकार की मर्जी के मुताबिक हुआ करेगा, जो बड़ी भयंकर वस्तु होगी।

चांदी के पक्षपाती बराबर यह कहते आ रहे थे कि जो लोग सोना-सोना चिल्ला रहे हैं वे कपटी हैं और उनका उद्देश्य भारतवर्ष को सोना देना नहीं, बल्कि हुडी की दर को ऊंचा करके रुपए को ही बराबर चलन में रखना है। मिस्टर राली ने अपने मत का स्पष्टीकरण करते हुए कहा था कि “मेरा विश्वास है कि सोने के स्टैंडर्ड के प्रश्न की आड़ या तह में एक्सचेंज का प्रश्न है। अगर भारतवर्ष में सोने का स्टैंडर्ड हो चले तथा सोने और रुपए के बीच की एक्सचेंज-दर काफी नीची हो, तो मैं हर्गिज उस स्टैंडर्ड का विरोध न करूंगा।” अब धीरे-धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि सचमुच हमारे साथ एक तरह की चाल चली गई थी—हमको सोने का स्टैंडर्ड देने का वादा सचाई के साथ नहीं किया गया था। जो हर्शल कमेटी के मेम्बर रह चुके थे उनका भी सोने के सम्बन्ध में अपना-अपना विचार था। १८९८ में बयान देते हुए लॉर्ड फारर ने तो यह कहा कि “अगर मेरा विश्वास यह न होता कि हर्शल कमेटी की रिपोर्ट भारतवर्ष को सोने का स्टैंडर्ड दिलायेगी तो मैं उस पर कभी दस्तखत न करता।” उनका कहना था कि यहाँ अभी तक सोने का स्टैंडर्ड स्थापित नहीं हुआ है। उधर मि० कर्टनी ने जो लॉर्ड फारर की तरह हर्शल कमेटी के मेम्बर रह चुके थे, फर्माया कि—नहीं, जब सरकार सर्वसाधारण से लगान या कर के भुगतान में सोना लेने को तैयार है और रुपए की एक्सचेंज-दर १६ पैसे हो चुकी है तब समझना चाहिए कि सोने का स्टैंडर्ड स्थापित हो चुका। शुरू से ही यहाँ की मुद्रा-प्रणाली को ऐसा रूप दिया गया कि वास्तविकता आसानी से किसीकी समझ में न आ सके और उसकी जटिलता की आड़ में हमारे कर्ताधर्ता जो दस्तन्दाजी चाहे, कर सकें। जिस रोज हर्शल कमेटी की रिपोर्ट तैयार

हई थी उस रोज एक्सचेंज की दर १४ ६२५ पेस थी। रिपोर्ट निकल जाने पर २७ जून को यह दर एक दिन के लिए १६ पेस हो गई, पर वहा ठहर न सकी। १८९३-९४ में औसत दर १४ ५४४ पेस रही। यह दर बाजार की हालत पर निर्भर करती है। ऐसा न होता तो सरकार विधान-मात्र से दर को और भी ऊंचा कर सकती थी। सरकार ने कानून पास कर दिया कि वह दो शिलिंग देनेवाले को एक रुपया देगी, पर बाजार की हालत ऐसी नहीं कि किसीको रुपए के लिए सरकार के पास जाना पड़े; और दो शिलिंग से कम में ही रुपया मिल जाता है तो सरकार का कानून कानून ही रहेगा, वह दर चल न सकेगी। यह जरूर है कि सरकार अपनी नीति-नीति में परिवर्तन कर बाजार की हालत बदल सकती है और बाजार को अपने पास आने के लिए मजबूर कर सकती है। पर यह अवस्था भी एक हद तक ही पैदा की जा सकती है।

दिसम्बर १८९३ में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ और उसमें यह प्रस्ताव पास हुआ कि—“भारत-सरकार ने आनन-फानन कानून पास करके सर्वसाधारण के लिए चादी की टकराल का दरवाजा बन्द कर दिया। इसलिए यह कांग्रेस अत्यन्त गेद प्रकट करती है; कारण कि रुपए का मूल्य कृत्रिम और ऊंचा करके जनता पर परोक्ष रूप में एक नया कर लगा दिया गया है और इस कार्रवाई में हमारे व्यापार और उद्योग-धन्यों को—गायकर कपड़े की मिलों को—बड़ी हानि पहुँची है।”

टकराल बन्द हो जाने के बाद चादी के दाम और एक्सचेंज की दर यह रही —

	चादी का औसत दाम पेंस	औसत एक्सचेंज पेंस
१८९१-९२	२८ १/२	१३ १०१
१८९२-९३	२९ ३	१३ ६३८
१८९३-९४	३० १	१८ ८५१
१८९४-९५	२७ १/४	१५ ३५४
१८९५-९६	२६ १/२	१५ ९३८

आरम्भ में कई साल तक एक्सचेंज १६ पेंस से बहुत नीचे रहा— अर्थात् सरकार चाहती थी कि रुपए को लोग १६ पेंस देकर ले, मगर रुपया इससे सस्ता बना रहा। अपनी नीति को असफल होते देख सरकार ने रुपए का अभाव या कमी करना शुरू कर दिया। रुपया ढालना न ढालना अब सरकार के बस की बात थी। उसने नए सिक्कों की ढलाई बन्द कर दी, जिससे बाजार में रुपए की टान बढ़ती गई। एकसाल बन्द होने से पहले नई करेन्सी के रूप में हमें प्रायः सात से नौ करोड़ रुपए की हर साल जरूरत पड़ती थी। सिक्कों तो इससे भी ज्यादा ढलते थे, पर उनमें से कुछ गला दिए जाते थे और उनके जेवर इत्यादि बच जाते थे। जो सिक्के चलन में रह जाते उनकी तादाद इतनी थी। हमारी जन-संख्या, हमारा वाणिज्य-व्यापार, हमारी तरह-तरह की आवश्यकताएं बढ़ रही थी, और इसलिए यह आवश्यक था कि करेन्सी भी उन्हींके अनुसार बढ़ती रहे। अगर स्वाभाविक रीति से वह बढ़ती तो १८९४ से १८९८—इन पांच वर्षों में कम से कम ४० करोड़ और रुपए, नए सिक्कों के रूप में, चलन में आ जाते। पर वास्तव में हुआ कुछ और ही। इतने समय में कुल पांच करोड़ रुपए के लगभग चलन में बढ़ पाए। सरकार प्रायः नए सिक्के ढालती ही नहीं थी, इसलिए पुराने सिक्कों से ही सबको काम चलाना पड़ता था। १८९३ में चलते-फिरते रहनेवाले रुपयों की सरया १३८ करोड़ कूती गई थी। अगर यह संख्या ज्यों-की-त्यों बनी रहती तो भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपर्याप्त होती। पर स्वाभाविक कारण—जैसे गलाकर और काम में ले आना, जमीन में गाड़ देना, इस देश से बाहर भेज देना—उस संख्या में ह्रास ही करने-वाले थे, इसलिए १८९७ की कूत के अनुसार वह केवल १२० करोड़ ठहरी थी। ऐसे समय में, जब कि रुपयों की आवश्यकता दिन-दिन बढ़ रही थी, सरकार ने उनकी ढलाई बन्द कर और उनकी तादाद कम कर, उनका मूल्य बढ़ा दिया और एक्सचेंज अन्त में १६ पेंस हो गया। पर पांच साल से कम में यह काम पूरा न हो सका।

यहां यह प्रश्न किया जा सकता है कि सर्वसाधारण के लिए एकसाल

जरूर बन्द थी, पर लोग सरकार को सोना देकर तो रुपया ले ही सकते थे, फिर वे ऐसा क्यों नहीं करते थे ? उत्तर यह है कि सोना लोग सरकार के पास तभी ले जाते जब और जगह बेचने में अधिक लाभ न होता। जब तक एक्मनेंज १६ पेंस न हुआ, सोना बाजार में सरकारी दर में महंगा बिकता रहा। सरकार तो ७५३३४४ ग्रेन सोने के बदले एक रुपया देती, पर इतने सोने का मूल्य बाजार में एक रुपए से अधिक था। उपर कहा जा चुका है कि उगलैण्ड में स्टैंडर्ड सोने का था और पौड-शिलिंग-पेंस उस समय सोने के द्योतक थे। फिर, जब बाजार में एक्मनेंज १६ पेंस होता तो उसका अर्थ यही था कि उतने सोने का मूल्य एक रुपया हुआ। अवश्य ही जब किसीको १४ पेंस (सोना) बेच देने से ही एक रुपया मिल जाना है तब वह १६ पेंस (सोना) देकर एक रुपया लेने को तैयार न होगा। यही कारण है कि उतने माल तक कोई अपना सोना ले जाकर सरकार से रुपए मागने न गया। इसी बात को दूसरी तरह यों कह सकते हैं कि इतने समय तक एक्मनेंज-नीति सफल न हो सकी।

चादी की कहानी पूरी करने के लिए यहा अमेरिका की भी कुछ घटनाओं का उल्लेख आवश्यक है।

जब १८०३ में भारत-सरकार ने अपनी टकमाल बन्द करके चादी की मुद्रा यहा से उठा ली तब अमेरिका ने शर्मन-बिधान को मन्सूरा करके बाजार में चादी गरीदना बन्द कर दिया। इससे चादी और भी नीचे गिरी। दामों का यह हाल रहा —

पेंस—

१८०३	३५ ^३ / _४
१८०४	२८ ^१ / _४
१८०५	२० ^१ / _२
१८०६	३० ^१ / _४
१८०७	२३ ^१ / _४
१८०८	२६ ^१ / _४
१८०९	२३ ^१ / _४

१८९६ में चादी अमेरिका में एक बार फिर राजनैतिक आन्दोलन का मुख्य विषय बन बैठी। वहाँ के रिपब्लिकन चाहते थे कि इस विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय समझौते की फिर चेष्टा की जाय। पर डिमॉक्रेट इसके विरोधी थे। उनकी भाग थी कि अमेरिकन सरकार बिना औरो से किसी प्रकार का समझौता किए द्वैत मुद्रा-प्रणाली ग्रहण कर ले और सोने तथा चादी के बीच १ : १६ का सम्बन्ध स्थापित कर दे। पेंसिलेनिया के चुनाव में जीत रिपब्लिकन पार्टी की रही और नए राष्ट्रपति ने दोनों धातुओं के बीच सम्बन्ध निश्चित करने के उद्देश्य से इंग्लैण्ड और फ्रांस के साथ पत्र-व्यवहार शुरू कर दिया। फ्रांस की राय थी कि यह सम्बन्ध या अनुपात १ : १५ $\frac{1}{2}$ हो, पर यहाँ भारत-सरकार को यह मजूर न था। बाजार में उस समय (१८९७) यह अनुपात १ : ३४२० था—अर्थात् प्रायः ३४ भाग चादी एक भाग सोने की बराबरी करती थी। फ्रांस की बात म्वीकार करने का अर्थ होता चादी का मूल्य इतना अधिक कर देना कि १५ $\frac{1}{2}$ भाग चादी ही एक भाग सोने की बराबरी कर सके। साथ ही, इसका अर्थ होता रुपए के एक्सचेंज को अत्यधिक ऊँचा कर देना—जो भारत-सरकार की भी दृष्टि में सर्वथा अनुचित था। अमेरिकन राष्ट्रपति के पत्रव्यवहार का कोई नतीजा नहीं निकला। इधर सोने के उत्पादन में बड़ी वृद्धि होने लगी थी और सोना सस्ता होने लगा था। लोग थोड़े ही समय में चादी को भूल-मे गए।

१८९८ में भारत-सरकार ने एक प्रस्ताव भारत-सचिव के सामने रखा, जिसका उद्देश्य था कर्ज लेकर इंग्लैण्ड में सोने का एक रिजर्व कायम करना और रुपए गला-गला कर चादी के रूप में बेच देना। सरकार का कहना था कि चलन में रुपया आवश्यकता से अधिक है और एक्सचेंज को १६ पैसे तक उठाने और वहाँ टिकाने के लिए इस आधिक्य या बाहुल्य को मिटा देना जरूरी है।

२९ अप्रैल को भारत-सचिव ने एक नई करेसी कमेटी नियुक्त करके उसे आदेश दिया कि वह सरकार के प्रस्ताव पर विचार करे। इस कमेटी के अध्यक्ष सर हेनरी फौलर थे, जो स्वयं भारत-सचिव रह चुके थे। उसके दूसरे सदस्यों में सर जॉन म्यूर, सर डेविड बार्बर, लॉर्ड बैलफोर, मि०

कैम्पबेल आदि थे। अनुसन्धान के लिए जो क्षेत्र कमेटी को दिया गया था वह भारत-सरकार के प्रस्ताव तक ही परिमित नहीं था। भारत-सचिव के आदेशानुसार यह भारतीय मुद्रा-प्रणाली से सम्बन्ध रखनेवाली हर बात का अनुसन्धान कर सकती थी और उसपर अपनी राय दे सकती थी।

कमेटी के सामने मुख्य प्रश्न दो थे —

(१) यहाँ का मान या स्टैण्डर्ड सोना हो या चादी ?

(२) चादी और सोने के बीच सम्बन्ध क्या हो ?

बहुतेरे गवाहों ने इस बात पर जोर दिया कि १८९३ में जो भूल हुई उसके गुधार के लिए यह आवश्यक है कि चादी अपनी पुरानी जगह पर फिर से स्थापित कर दी जाय। कुछ गवाह ऐसे भी थे, जो चादी को उगी हालत में फिर से उमकी पुरानी जगह पर लाने के पक्षपाती थे, जब कि अन्तर्राष्ट्रीय समझौता होकर दोनों धातुओं का सम्बन्ध सदा के लिए निश्चित हो जाय।

यह हुई चादी के पक्षपातियों की बात। सोने के पक्षपाती भी दो दलों में विभक्त थे। एक दल चाहता था कि सोने का मान तो हो ही, साथ-साथ सोने के मिक्के भी चलन में हों। दूसरा दल कहता था कि मान तो सोने का रहे पर यहाँ उसके मिक्के न चलाए जाय।

गवाहों में इस बार दो भाग्यवागी थे—श्रीयुक्त रमेशचन्द्र दत्त, (बांग्ला के भार्वा प्रेमिडेंट) और बम्बई के पारसी व्यापारी मि० मेरधानजी रमनजी। दोनों न ही सरकार की नीति की कड़ी आलोचना की।

चादी के पक्षपातियों की दलील यह थी कि "उमंगे भाग्यवर्षों की बाफ़ी लाभ हुआ था, और ऐसी वस्तु का परिचालन हीन न करना चाहिए था। १८९३ में परिस्थिति और भी उपायों में काबू में लाई जा सकती थी। उसके लिए मुद्रा-प्रणाली में ऐसे उद्धरणों की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस बीच में यह अनुभव हो गया था कि इस क्षेत्र में सरकार की दम्नताओं में क्या-क्या अनर्थ हो सकते हैं। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार करी (मुद्रा) की मात्रा स्वतः

घटती-बढ़ती रहे। पर यह प्रबन्ध जब सरकार अपने हाथ में ले लेती है तब यह घटना-बढ़ना उसके इच्छानुकूल होने लगता है। फिर तो यह हो सकता है—जैसा कि यहाँ हो चुका था—कि रुपए की सरत जरूरत है, और सरकार उसे देने में इनकार कर देती है, देश में रुपए-पैसे का दुर्भिक्ष है, और सरकार कहती है कि नहीं, रुपए का बाहुल्य है, हम सिक्कों को चलन से निकाल कर गलाने जा रहे हैं। पर करेसी का स्वतः घटना-बढ़ना तभी हो सकता है जब टकसाल का दरवाजा सबके लिए खुला रहे, जिसको मूद्रा की आवश्यकता हुई, अपना सोना या चादी टकसाल में ले गया और उसके सिक्के करा लिए। यहाँ भारतवर्ष में सोने की ढलाई की आशा कम थी, इसलिए यह और भी आवश्यक था कि चादी की टकसाल फिर से खोल दी जाय। इससे सारी कृत्रिमता और तज्जनित दोष दूर हो जायगे।”

उस समय चादी का दाम २७ और २८ पैसे के बीच था, पर चादी के पक्षपातियों का कहना था कि अगर टकसाल खोल दी गई और यहाँ चादी के सिक्के पूर्ववत् ढलने लगे तो बाजार शीघ्र ही ३० पैसे हो चलेगा। इसका अर्थ होगा १२ पैसे का रुपया। पर विपक्षी यह कहते कि इस बात की गारण्टी ही क्या है कि चादी या एक्सचेंज इससे भी नीचे न गिरेगा? मि० राली ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि “ससार में सभी कुछ सम्भव है, पर हम व्यापारी अनुभव से जानते हैं कि क्या सम्भव है, और क्या असम्भव। जहाँ व्यावहारिक बातों की चर्चा हो वहाँ ऐसे प्रश्न उठाने से क्या लाभ?” मि० डकन नामक दूसरे गवाह से भी यही प्रश्न किया गया और उनका उत्तर इस प्रकार था—“हमारे स्कॉटलैण्ड में जब कभी कोई ऐसा सवाल करता है तब इसका जवाब एक लोकोक्ति के रूप में दिया जाता है। वह लोकोक्ति यह है कि अगर आसमान गिर पड़े तो गानेवाले पक्षियों के दम घुट जायेंगे। पर वावजूद इसके, वे पक्षी गाते ही जाते हैं।”

लॉर्ड एलेडनहम इंग्लैंड के प्रसिद्ध बैंकर थे, और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके थे। इन्होंने अपने वयान में भारत-सरकार की कार्रवाई

की तीव्र आलोचना की और उसे 'जुर्म' तक बताया । लॉर्ड ऐन्डनहम द्वैत मुद्रा-प्रणाली के पक्षपाती थे और सोने-चादी का सम्बन्ध निश्चित करने के लिए चाहते थे कि फिर से अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के लिए प्रयत्न किया जाय ।

मि० राबर्ट बार्कले नामक व्यवसायी भी ऐसा समझौता चाहते थे । उन्होंने अपने इजहार में कहा —

"मेरा विश्वास है कि भारत में चादी की टकराल का दरवाजा फिर से खोल देने का निश्चय होते ही कुछ ऐसी शक्तियाँ काम करने लगेंगी जो चादी के मूल्य को बढ़ाये बिना न रहेंगी । भारतीय टकराल बन्द होने से पहले, चादी का दाम ३८ पैसे में कभी नीचे नहीं गिरा था, और ऐसे निश्चयमात्र में ही उस दाम में तेजी आ जायगी । चीन और अफ्रीका में भी चादी के उपयोग के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है ।"

सोने के पक्षपाती नहीं कहते जाने थे जो टकराल बन्द होने से पहले बार-बार कह चुके थे—“चादी काफी चलत, डावाडोल, अस्थिर, अव्यवस्थित साबित हो चुकी है । एमचेंज को अपने साथ नीचे गिरा कर दगने उन सबको नुकसान पहुँचाया है—और उनमें भारत-सरकार का नाम सबसे पहले लेने लायक है—जिन्हें स्पष्ट बिलायत भेजना पड़ता है ।” पर हमें आग माने के सब पक्षपाती मान जाने को तैयार न थे । कोई हम सोना किसी रूप में देना चाहता था, कोई किसी रूप में । कुछ तो सोना नाममात्र का ही देने पाते थे ।

उन सबको मानने पड़ा सबकुछ यह था कि जो रूपए चलन में थे और जो प्रतीक-मुद्रा बना दिए गए थे उनके बदले, जन्मा की माग होने पर, सरकार सोना देने को तैयार रहेगी या नहीं ? सर जॉन लबक का कहना था कि जब तक सरकार बदले में सोना देने को तैयार नहीं रहती तब तक सोने का मान या स्टैण्डर्ड मायक हो ही नहीं सकता । पर माने के पक्षपातियों में एक बार में यही कहा कि अगर माने के स्टैण्डर्ड की प्रतीक्षा के लिए यह आखिरका हो तब तो 'न रोमा बांग न बजेगी वागुगी' । दूसरे के अन्दर सरकार सोना देने को बाध्य न हो—उसी आशय पर सर

अपनी-अपनी स्कीम पेय की। हा, अगर किसी साल भारत की देनदारी ज्यादा हुई और उसके लिए भुगतान में सोना बाहर भेजना आवश्यक हो गया तो इन स्कीमों में इस बात की प्राय व्यवस्था थी कि सरकार रुपए लेकर उस काम के लिए सोना दे।

आपस का मतभेद विशेषतः इस बात पर था कि देश के भीतर चलन में सोने के सिक्के रहे या नहीं। मि० मैकलियड, लॉर्ड नॉर्थमुक, सर मैथ्युअल माण्टेग्यू, सर एडगर विन्स्टेन—जैसे लोग इस बात के पक्ष में थे। उनका कहना था कि जब तक सोने के सिक्के चलन में न होंगे, यहाँ की मुद्रा-प्रणाली पूर्णतः स्वस्थ न हो सकेगी। सर एडगर विन्स्टेन मित्र-सरकार के सलाहकार रह चुके थे। उनका कहना था कि “सिद्धान्ततः यह सम्भव है कि सोने का मान या स्टैण्डर्ड बिना सोने के सिक्कों के चलन के हो, पर यह अपवादस्वरूप है, और जिन मुद्रा-प्रणाली में ऐसी व्यवस्था हो वह कभी उत्तम नहीं कही जा सकती। सोने के मान या स्टैण्डर्ड का आधार ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें आवश्यकतानुसार सोना देश में बाहर बेरोक-टोक जा-आ सके और देश के भीतर भुगतान के लिए सोने के सिक्कों का म्वच्छन्द व्यवहार हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था उस व्यवस्था में अधिक प्रचलित और हितकर है, जिसमें लेन-देन के लिए केवल प्रतीक-मुद्रा काम में लाई जाती हो। यह भी कहा जा सकता है कि जहाँ सोने का मान या स्टैण्डर्ड है, पर चलन में सोना नहीं है, वहाँ सरकार द्वारा दस्त-न्दाजी विरोध रूप से होगी। पर इस प्रकार की दस्तन्दाजी बहुत ही बुरी चीज है। जो भी मुद्रा-प्रणाली हो, वह स्वतः काम करनेवाली होनी चाहिए और सरकार द्वारा हस्तक्षेप कुछ खास परिस्थितियों में ही—और वहाँ भी कम-से-कम—होना चाहिए।” सोने के सिक्के के विरोधी यह कहा करते कि चलन में सोना अधिक काल तक नहीं ठहर सकता—लोग उसे दबाकर बैठ जायेंगे। इसके उत्तर में मि० मैकलियड का कहना था कि सोना इस देश के लिए कोई नई चीज नहीं थी। सोने के सिक्के यहाँ सदियों तक चल चुके थे। १८५३ से पहले जो सोने के सिक्के यहाँ चलन में थे उनका तखमीना था बारह करोड़ पौड। ‘नहीं, भारतवर्ष को सोने के

सिक्को का ऐसा लोभ या मोह नहीं है कि वह उन्हें चलन में रहने ही न दे।"

गोने के सिक्के के विरोधियों में बंगाल-बैंक के कर्मचारी मि० लिण्डसे का नाम विशेष उल्लेखनीय है। यह इस विषय पर वर्षों से लिखते आ रहे थे और जब फौलर कमेटी बँठी तब उसके सामने उन्होंने एक स्कीम रखी, जो इनके नाम से मशहूर है। इनकी स्कीम सक्षेप में यह थी —

"सोना मान या स्टैंडर्ड कर दिया जाय, पर चलन में गोने के सिक्के न हों। देश के भीतर रुपए और नोट करेन्सी का काम करे। लन्दन में एक करोड़ पौंड कर्ज लेकर एक रिजर्व (कोष) कायम किया जाय, जिसका नाम 'गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व' हो। रुपए की एक्स्चेंज-दर, ऊपर और नीचे, दोनों ओर बाध दी जाय। जब किसीको रुपयों की जरूरत हो तब वह लन्दन में सरकार को स्टर्लिंग दे और १६½ पेंस की दर से यहाँ उगमे रुपए ले ले। इसके विपरीत, जब किसीको विलयत में स्टर्लिंग की जरूरत हो तब वह यहाँ रुपए देकर १५½ पेंस की दर से वहाँ सरकार से स्टर्लिंग ले ले। १५,००० से कम किसीको रुपए न मिले और १,००० से कम किसीको स्टर्लिंग न मिले। अगर किसी समय स्टर्लिंग की मांग उतनी अधिक हो कि रिजर्व गाली हो जाने का डर हो, तो उस हालत में सरकार भारतवर्ष में मिलनेवाले रुपयों का कुछ हद तक गला ग्राह और चांदी को लन्दन भेज कर बेच दे और उगमा स्टर्लिंग कर ले।"

इस स्कीम का नाम उद्देश या भारतवर्ष में करेन्सी के लिए गोने का व्यवहार न होने देना, और उसमें इस बात पर बहुत जोर दिया गया था कि गोने का जो रिजर्व हो वह लन्दन में ही रहे। मि० लिण्डसे का कहना था कि लन्दन में सोना रहने से ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक केन्द्र की मजबूती बनी रहेगी, और वह रिजर्व को भारतवर्ष में रखने के बहुत विरोधी थे।

पर उस समय भारत-सरकार का मत और ही था। उसके अर्थ-मन्त्री सर जेम्स बेन्टिन्क ने इस स्कीम की आलोचना करते हुए कहा कि "भारतवर्ष में नई मुद्रा-प्रणाली की मजबूती के लिए वह अव्यक्त आवश्यक है कि

सर्वसाधारण को उसपर पूरा विश्वास हो। और उस विश्वास-सम्पादन के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि सोने का रिजर्व इसी देश में रखा जाय। अगर रिजर्व लन्दन में रखा गया, और लोगो का यह खयाल हो चला कि भारत-मन्त्रि या व्यापारियो की माग पूरी करने में यह कभी भी गायब हो सकता है तो विश्वास हर्गिज न जम सकेगा।" सर जेम्स वेस्टलैण्ड की एक टिप्पणी यह थी कि रिजर्व ६,००० मील दूर न रखकर भारतवर्ष में रखा जाय तो उसकी मिकदार चाहे जो हो, वह हर हालत में ज्यादा मुफीद साबित हो सकता है।

और लोगो ने भी इस स्कीम को आपत्तिजनक बताया और इसकी कड़ी आलोचना की। इसका सबसे बड़ा दोष यह बताया गया कि इसमें सरलता और स्वाभाविकता को तिलाजलि दे दी गई थी और सारी व्यवस्था जटिल-से-जटिल और कृत्रिम-से-कृत्रिम बना दी गई थी। प्रायः सब कुछ सरकार के हाथ में या उनकी मर्जी पर छोड़ दिया गया था, और विशेष ध्यान इस बात का रखा गया था कि सोना यथासम्भव लन्दन में ही केन्द्री-भूत रहे।

यद्यपि फौलर कमेटी ने यह स्कीम स्वीकार नहीं की तथापि हमारे शासको की कारसाजी से देश में जो मुद्रा-प्रणाली प्रचलित हुई वह बहुत कुछ इसी स्कीम के अनुसार थी। इसीलिए इस विषय के इतिहास में लिण्डसे-स्कीम को विशेष महत्व प्राप्त है।

कमेटी ने अपना निर्णय देते हुए पहले तो भारत-सरकार के प्रस्ताव को यह कह कर अस्वीकार्य बताया, कि इस बीच में परिस्थिति बहुत कुछ बदल चुकी थी—एक्स्चेंज १६ पैसे तक पहुँच गया था और स्थिर हो रहा था—अब वह समस्या नहीं रह गई थी—अगर रुपए चलन से निकाल लिए गए तो यहाँ मुद्रा-सम्बन्धी स्थिति भयंकर हो जायगी और अगर उन रुपयों को गला कर बेच दिया गया तो चादी और भी नीचे गिर जायगी, जिससे चीन-जैसे चादी की मुद्रावाले देश और भारतवर्ष के बीच के एक्स्चेंज में हलचल-सी उपस्थित हो जायगी।

चादी और सोने के बीच के प्रश्न पर कमेटी ने अपना फैसला चादी के

गिलाफ दिया और भारतवर्ष के लिए सोने को ही श्रेयस्कर बताया। “भारतवर्ष में मूल्य का मान या मापक सोना ही होना चाहिए—चाहे वह सोने के गिनाले के साथ हो, चाहे सोने के रिजर्व या कोष के।”

पर कमेटी ने उन सब स्कीमों को त्याज्य ठहराया जिनमें बिना सोने के गिनालों के सोने का मान या स्टैण्डर्ड चलाने की बात थी। ऐसे सिक्के हम देश में बहुत समय तक चल चुके थे, और इतिहास में इस आशका की पुष्टि नहीं होती थी कि जैसे छलनी से पानी बाहर निकल जाता है वैसे ही हम देश में चलन में सोने के गिनाले निकल जायेंगे। कमेटी की सिफारिश यह थी —

“हम लोग हम बात के पक्ष में हैं कि ब्रिटिश गांवरेन या गिनी का भारत-वर्ष में भी चलन होने लगे और लोग उसे देने-लेने को बाध्य कर दिए जाय। साथ ही, ब्रिटिश टकमाल की अमेरिलिया में जो तीन शाखाएँ हैं उन्हें जिन बातों पर सोने के गिनाले (गांवरेन) ढालने का अधिकार प्राप्त है उन्हीं बातों पर भारतवर्ष की टकमालों को भी ऐसे गिनाले अवाधिन रूप से ढालने दिया जाय। इसका फल यह होगा कि सब गांवरेन समान होंगे और उनका चलन ग्रेट-ब्रिटेन में तथा भारतवर्ष में, दोनों जगह, होने लगेगा।”

रूपयों के बारे में कमेटी ने लिखा कि “स्वयमिद्ध मुद्रा गांवरेन होगा, और रूपए प्रतीक-मुद्रा का काम करेंगे। पर देने-देन में रूपयों का व्यवहार परिमित या नियन्त्रित करना समभव नहीं—इसलिए हम विषय में प्रतीक-मुद्रा स्वयमिद्ध मुद्रा के ही समान होगी।” कमेटी ने अमेरिका के संयुक्त राज्य और फ्रांस, इन दो देशों के उदाहरण देकर यह दिखाया कि क्या सोने का मान या स्टैण्डर्ड या, फिर भी चाहे जितना हद तक हो, लोग चाहे कि गिनाले देने-लेने को बाध्य थे। कमेटी की राय में आवश्यकता केवल हम बात की थी कि रूपया की नाशद जगहन में ज्यादा न बढ़ाई जाय; और इसी सिफारिश थी कि जब तक चलन में सोने का परिमाण अल्पविक नहीं हो जाता तब तक और रूपए न ढाले जाय।

रूपया के बढ़ते भारत-सरकार सोना देने को बाध्य हो—ऐसी कोई सिफारिश कमेटी ने नहीं की।

एक्स्चेंज की स्थायी दर के सम्बन्ध में कमेटी ने अपना निर्णय १६ पेंस के ही पक्ष में दिया । उसकी खास दलील यह थी कि मौजूदा दर यही है और यह प्रायः डेढ़ साल से कायम है । इसको वेदखल करके किसी भी दूसरी दर को इसकी जगह बिठाना—वने को बिगाड़ना, वसे को उजाड़ना और अनगिनत आदमियों के साथ अन्याय करना होगा ।

एकसाल बन्द करके जो परिस्थिति पैदा कर दी गई थी उसमें सरकार १६ पेंस ही बयो, जो दर चाहती, कायम कर सकती और ठिका सकती थी । सिक्को की ढलाई अब उसके हाथ की बात थी—उनकी तादाद या सरया कम करके वह उनका मूल्य चाहे जितना ऊँचा कर सकती थी । सवाल सिर्फ यही था कि लोगो को अपनी यन्त्रणा के रूप में इसका क्या दाम चुकाना पड़ेगा और इसमें कितना समय लगेगा ? कृत्रिम उपाय से किसी दर को कायम कर देना और फिर उसी दर की दुहाई देना—यह नीति-रीति हमारी सरकार और उसके तरफदारो को ही शोभा दे सकती थी । फौलर-कमेटी की नियुक्ति अप्रैल १८९८ में हुई थी । उसने अपना काम इतनी ढिलाई से किया कि उसकी रिपोर्ट निकली जुलाई १८९९ में । तब तक १६ पेंस दर कायम हुए प्रायः १८ महीने हो चुके थे । क्या इसमें भी सन्देह हो सकता है कि जानबूझ कर यह निर्णय इतने समय बाद किया गया, ताकि उस दर के पक्ष में और कुछ नहीं तो इतना तो कहा जा सके, कि यह पीछा डेढ़ साल का हो चुका है, अब इसको उखाड़ कर इसकी जगह दूसरा पीछा लगाना जोखिम और खतरे का काम है ?

उपर कहा जा चुका है कि नए सिक्को की ढलाई बन्द करके और रुपए की कहतमाली पैदा करके ही सरकार ने उसकी कीमत १६ पेंस तक पहुँचाई । कमेटी को इस सम्बन्ध में जो साक्ष्य मिला वह 'उस भयंकर स्थिति का सूचक था, जिसे सरकार की नीति ने यहाँ कुछ काल पहले पैदा कर दिया था ।

बैंक-रेट १३ प्रतिशत तक पहुँच गई थी, पर व्यापारियों को २४ प्रतिशत पर भी रुपया उधार मिलना मुश्किल था । रुपए की ऐसी तंगी लोगोके लिए त्रिलकुल नई बात थी । कलकत्ते की किलवर्न कम्पनी

के प्रतिनिधि ने अपने वयान में कहा था — “इस समय किसी भी उद्योग-धंधे के लिए रुपया उठाना असम्भव हो रहा है। सरकारी कागज पर कर्ज लेना चाहे तो मिलने का नहीं, क्योंकि सराफ उस पर रुपा देने को तैयार नहीं है। अच्छी-से अच्छी कम्पनी के शेयर बेचना चाहे, तो शेयर बिकने के नहीं। जो कम्पनिया डिविडेंड देती आ रही हैं उनके भी शेयर बाजार में बिक नहीं सकते। हम लोगों की एक स्टोम-ट्रोट कम्पनी है, जो कई साल से आठ प्रतिशत मुनाफा देती आ रही है। पर अगर हम उसके ५०० शेयर भी बेचना चाहे तो नहीं बेच सकते। बाजार में महीनों में रुपए की ऐसी तंगी है कि कोई ऐसे शेयर या डिबेंचर का भी रागीदार नहीं निकलता।”

रुपया इतना महंगा हो जाने से चीजों के दाम गिरे थे और व्यापार मंदा हो रहा था। श्रीयुत रमेशचन्द्रदत्त ने इस सम्बन्ध में कमेटी का ध्यान अपने एक नोट की ओर आकर्षित करते हुए कहा था — “टकमाल बन्द हो जाने के बाद भारतवर्ष के प्रायः प्रत्येक प्रान्त में — पंजाब, रायपुर प्रान्त, बंगाल, बम्बई, मद्रास, आसाम, और मध्य प्रान्त में — गन्ने का दाम नीचे गिरना शुरू हुआ। मैंने १८९३-९४ और १८९४-९५ को एक साथ लिया है, और मैं देगता हूँ कि प्रायः सर्वत्र दाम गिर गए थे। मैं इसका कारण यही बता सकता हूँ कि टकमाल बन्द हो जाने के बाद रुपया महंगा हो गया। १८९२, १८९४ और १८९५ में मैं मध्य बंगाल में था (१८९३ में मैं बाहर था) और मैं निजी अनुभव से कह सकता हूँ कि १८९४-९५ में दाम गिरने का और कोई कारण नहीं हो सकता था। उस समय मधुसूत प्रान्त में आनाडवा, दमलियागन्धे का दाम उँचा रहना चाहिए था। पर आप देखेंगे कि प्रायः हर जगह दाम नीचे हो रहे हैं।”

इसी तरह नींद और प्रायः के दाम नीचे गिर गए थे और इसी कारण की दरवाही खल गई थी। बम्बई की रॉडन-मिडो की आख्या प्रसिद्ध हो रही थी। ६ अगस्त १८९८ के अहम ‘टाइम्स आफ इण्डिया’ ने लिखा था — “जर्मनी-बर्लिन मुद्रा के बजाय प्रिण्टनी जा रही है। ऐसा

वुरा समय तो न कभी देखा गया, न सुना गया। अधिकांश मिले घाटे से चल रही हैं—कुछ किसी तरह अपनी आय से अपना व्ययमात्र पूरा कर लेती हैं, बहुत कम मिले ऐसी हैं जो कुछ मुनाफे के साथ चल रही हों। मालूम नहीं, ऐसे दुष्काल का अन्त कब होनेवाला है।” वाणिज्य-व्यापार में दारुण मन्दी छाई हुई थी और बड़े-बड़े व्यवसायियों को टाट उलट देना पड़ा था।

विदेशी व्यापार का हाल यह था कि जितना निर्यात (एक्सपोर्ट) होना चाहिए था, नहीं हो रहा था, और जो आयात (इम्पोर्ट) न होना चाहिए था, होने लगा था। एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट घटा देने पर जो बाकी बचता है वह एक्सपोर्ट-सरप्लस (निर्यात का आधिक्य) कहा जाता है। एक्सचेंज की दर का इस सरप्लस पर क्या असर पड़ता है वह नीचे के अंकों से स्पष्ट हो जायगा —

निर्यात का आधिक्य

साल	करोड़ रुपए	एक्सचेंज की रेट (पेस)
१८९३-९४	१५	१४.५४
१८९४-९५	३४	१३ १०
१८९५-९६	३२	१३ ६४
१८९६-९७	२०	१४.४५
१८९७-९८	११	१५ ४०

दर जितनी ही ऊँची, सरप्लस उतना ही नीचा—अर्थात् एक्सपोर्ट उतना ही कम। अवश्य ही एक्सपोर्ट कम होने के कुछ और भी कारण थे—अकाल, भूकम्प, महामारी, सरहद्दी लड़ाई इत्यादि—पर सबमें प्रधान कारण एक्सचेंज ही था। जब यहाँ दाम ऊँचे होते हैं तब एक्सपोर्ट को विदेश में एक हद तक दाम घटा कर माल बेचने की गुंजाइश रहती है। पर जब यहाँ दाम नीचे होते हैं तब यह गुंजाइश नहीं के बराबर रह जाती है। चीन के व्यापार से भारतवर्ष को क्रमशः हाथ धोना पड़ा। जब यहाँ का सूत वहाँ महँगा पड़ने लगा तब चीन में ही काँटन-मिले स्थापित होने लगी, और अन्त में वह बाजार हमारे हाथ से निकल गया। उधर इम्पोर्ट को

एक्स्चेज बढ़ने से प्रोत्साहन मिला और यहाँ के उत्पादकों की कठिनाई इससे और भी बढ़ गई। जर्मनी और ऑस्ट्रिया-हंगरी से उन दिनों चुकन्दर की चीनी की बाजार में बाढ़-सी आ गई और देशी चीनी या गुड़ बनाने-वालों को उससे काफी नुकसान पहुँचा। जो दूरदर्शी थे वे जानते थे कि इम्पोर्ट स्थायी रूप से तभी बढ़ सकती है, जब एक्स्पोर्ट की यथेष्ट उन्नति होती रहे। यही कारण है कि राली ग्रदर्स और ग्राहम कम्पनी—जैसे इम्पोर्टर भी नीचे एक्स्चेज के पक्ष में थे। मि० राली ने कहा था—“ग्राहम और हमारी फर्म बड़े-मे-बड़े इम्पोर्टर हैं—बल्कि ग्राहम तो केवल इम्पोर्टर हैं—फिर भी वे चादी की टकमाल को गोल देने और एक्स्चेज को नीचा रखने के पक्ष में हैं।” मि० ग्राहम ने इसका समर्थन करते हुए कहा था—“चादी के और एक्स्चेज के गिरने में स्वयं मुझे नुकसान पहुँचा है। पर मेरा विश्वास है कि यह नुकसान थोड़े समय के लिए है। लोग मुझसे पूछते हैं कि ‘आप तपड़े के इम्पोर्टर होने हुए चादी की टकमाल गोल देने के पक्ष में कैसे हैं?’ मैं उत्तर देता हूँ कि यह प्रश्न एक्स्पोर्ट या इम्पोर्ट का नहीं, यह तो देश की मलाई का प्रश्न है। देश की उत्पादन-शक्ति बढ़ जाय तो एक्स्पोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही फायदे में रहेंगे। फल इतना ही है कि एक्स्पोर्ट फोरन फायदा उठा लेगा और इम्पोर्टर का—अर्थात् मुझे कुछ देर ठहरना पड़ेगा।”

१८९८ बाटे तारिख के अविवेक्षण में एक प्रस्ताव पाम हुआ, जिसमें कहा गया कि “एक्स्चेज के गिरने में होनेवाली हानि का मूल कारण है इम्पोर्ट में भारत-सरकार के राजों की उत्तरोत्तर वृद्धि।” और यह कि “अगर उस नुकसान को पूरा करने के लिए एक्स्चेज का कृत्रिम ढंग से ऊँचा लिया जाता है या चन्दन में करों की समीप कर दी जाती है तो इससे भारत में भी अर्थिक बहिर्गति बढ़ेगी और उसकी व्यापारिक क्षति हुए बिना नहीं रह सकती।”

एक्स्चेज के प्रश्न पर क्वेन्टी गवर्नमेंन्ट ने १६ पक्ष के पक्ष में निर्णय न दे सके। उससे दो मेश्वर सर जॉन स्मूर और मि० कैम्पबेल ने १० देर की निर्णय की, और मि० स्टार्ट की राय यह ठहरी कि इस प्रश्न का अन्तिम निर्णय अभी न लिया जाय।

सर जॉन म्यूर और मि० कैम्बेल ने १६ पेस का विरोध करते हुए यह दिखाया कि यह दर कृत्रिम टग से कायम की गई थी और इस देश के लिए हानिकर थी, इसने किमानों का बड़ा नुकसान था।

“यह सच है कि दर जितनी ऊँची होगी, भारत-सरकार के लिए स्टैलिंग उतना ही सस्ता होगा। पर पूछा जा सकता है कि सरकार को जो फायदा हुआ वह आखिर आया कहा से? इस प्रश्न का उत्तर देना आसान काम है। सरकार को जो लाभ होता है वह वास्तव में उस किसान की हानि है जिसे अब कम दाम में ही अपना माल बेच देना पड़ता है।”

रुपए की असली कीमत तो १५ पेस से भी बहुत कम थी, इसलिए यह आक्षेप करना जा नहीं था कि उसकी सिफारिश करनेवाले रुपए की कीमत घटाकर उसे ‘घटिया’ कर देना चाहते थे। प्रत्युत १६ पेस कीमत बहुत ज्यादा थी, और उसके विरुद्ध बहुत कुछ कहा जा सकता था। कृत्रिम और ऊँची दर की भयकरता को कम करने के उद्देश से इन दोनों मेम्बरो ने यह सिफारिश करना मुनासिब समझा कि वह १६ के बजाय १५ पेस कर दी जाय।

इधर चांदी के पक्ष-विपक्ष की बातें हो रही थी, उधर सोने का उत्पादन वेग से बढ़ रहा था और सोने में चीजों के दाम भी ऊँचे होने लगे थे। १८९८-९९ में दाम ऊँचे होने के कारण इस देश के माल की मांग अच्छी रही और एक्सपोर्ट की उन्नति हुई। सोने के उत्पादन में इस वृद्धि के कारण ससार के मुद्रासम्बन्धी इतिहास में एक नए अध्याय का आरम्भ हो चुका था या होनेवाला था। भारतवर्ष में भी अब दाम बढ़ने लगे और कुछ समय बाद लोग १६ पेस के दोषों को भूल से गए और उसीको स्वाभाविक समझने लगे।

यहां भारत-सरकार के आय-व्यय के विषय में कुछ कह देना आवश्यक है। लॉर्ड रिपन के जाने के बाद इस देश में कई नए टैक्स लगाए गए, जिससे करदाता का बोझ बेहद भारी हो गया। १८८२-८५ में सरकार प्रतिवर्ष कर के रूप में जो कुछ ले चुकी थी उसको आधार मानकर स्वर्गीय गोखले ने अपनी एक स्पीच में दिखाया था कि १८८५-९८ इन

१४ सालों में सरकार ने जनता से १२० करोड़ अधिक लिया था। इसमें से ८० करोड़ तो फौजी खर्च में चला गया था, और बाकी दूसरी मदों में। शिक्षा के लिए इसमें से कुल एक करोड़ ही प्राप्त हुआ था।

पहले सरकार की ओर से कहा जाता कि एक्सचेंज गिरने से जो हानि होती है वह उसे टेंगसा घटाने के प्रश्न पर विचार भी करने नहीं देनी। जब एक्सचेंज १६ पैसे कर दिया गया और सरकार की वह गहन समस्या हल हो गई, तब लोगों को आशा होने लगी कि हमारा बोझ अब हलका कर दिया जाएगा। पर उनका बोझ ज्यों-का-त्यों बना रहा और उनकी आशा निराशा में परिणत हो गई। रुपए की कीमत जब १२ और १३ पैसे के बीच थी तब सरकार को जितना खर्च पड़ता था उसमें—रुपए की कीमत १६ पैसे होजाने पर—चार और पांच करोड़ के बीच की बचत होने लगी, पर इस बचत का कई साल तक जनता को कोई लाभ न पहुंचा। अब सरकार की नीति यह हो चली कि आय से व्यय पूरा होना ही पर्याप्त नहीं कहा जा सकता—आय इतनी होनी चाहिए कि प्रतिवर्ष व्यय पूरा करने के बाद गांभी बचत रहे। १९०१-०२ में समाप्त होनेवाले पांच वर्षों में यह बचत १२ २६ करोड़ रुपए रही। श्रीयुत गोखले का कहना था कि अगर युद्ध और अकाल के कारण व्यय में वृद्धि न होती तो सरकार की आय उगही आवश्यकता में प्रतिवर्ष प्रायः ६॥॥ करोड़ रुपए अधिक होती।

इस विषय पर दूसरे अध्याय में और भी प्रकाश डाला गया है।

थाड़ से शिकार

फोर्लर-कमेटी ने बहुमत से जो मिफारिशें की थीं उन सबको भारत-सचिव ने मंजूर कर लिया। उन्होंने अपने बक्तव्य में कहा कि—“इस रिपोर्ट के महत्व के अनुसार हम पर ब्रिटिश सरकार ने ध्यानपूर्वक विचार किया है। और इसमें जो तथ्य और जो युक्तियां पेश की गई हैं उन्हें सार-गर्भित मानती हुई वह इस नतीजे पर पहुंची हैं कि इसके उसूल मान लिए जाय और वे अमल में लाए जाय।” पर इतना कह कर भारत-सचिव और उनके सलाहकारों ने रिपोर्ट को ताक पर रख दिया और उन उसूलों के ही खिलाफ काम करना शुरू कर दिया।

उन्होंने नई मुद्रा-प्रणाली के संगठन या रचना में कानून से कम—बहुत कम—काम लिया और अपनी निरकुशता प्रायः अक्षुण्ण रखी। जो कुछ करते रहे, हुषनामों या फरमानों के जरिए, जो उनके सुविधानुसार बदले जा सकते थे।

इस समय में कब कौन-सी घटना घटी, इसका एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है—

१८९९—एक ऐक्ट पास हुआ, जिससे लोग साँवरेन या गिनी लेने-देने को बाध्य हो गए। दर रही १६ पेस = एक रुपया।

१८९९-१९०३—भारतीय टकसालों में साँवरेन ढालने के सम्बन्ध में समझौते का जो प्रयत्न हो रहा था वह छोट दिया गया।

१९००—रूपयों की ढलाई से जो मुनाफा होता उससे लन्दन में गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व-सुवर्णनिधि या सुवर्ण-कोष-की रचना की गई।

१९०४—भारत-सचिव की ओर से ऐलान किया गया कि १६६ पेस की दर से वह चाहे जितने की हुई भारत-सरकार पर बेचने को तैयार रहेगे।

१९०५—नोटो की पुस्तकी के लिए जो करेन्सी रिजर्व था उसकी ओर से कुछ सोना बैंक आव इगलैण्ड में रखा गया, और यह विधान भी बना कि उस रिजर्व का एक हिस्सा लन्दन में कर्ज या उधार दिया जा सकेगा ।

१९०६—पहले यह व्यवस्था थी कि भारतवर्ष में सोना देनेवाले को सरकार रुपए दे देती । अब यह व्यवस्था कर दी गई कि सिर्फ सोने के ब्रिटिश सिक्के देनेवाले रुपए पा सकेंगे ।

१९०७—गोल्ड स्टैण्डर्ड रिजर्व की एक शाखा इस देश में खोली गई, जिसमें रुपए रक्के जा सकते थे ।

१९०८—कलकत्ते में लन्दन पर १५३६ पैस की दर से हुजिया बेनी गई और लन्दन में गोल्ड स्टैण्डर्ड रिजर्व में उनका भुगतान किया गया ।

१९१०—दस और पचास रुपए के नोट अगिल भारतीय कर दिए गए और यह विधान बना कि सोने के ब्रिटिश सिक्कों के बदले नोट मिल सकेंगे ।

१९११—तीन रुपए के नोट भी अगिल भारतीय कर दिए गए ।

१९१३—भारतीय मद्रा-प्रणाली की जाच के लिए एक शाही कमीशन नियुक्त हुआ ।

अब फौलर-कमेटी की सिफारिशों को लेकर हम यह सिक्का चाहते हैं कि सरकार द्वारा स्वीकृत हो जाने पर भी वे कहा तक अमल में लाई गईं । सबसे पहले सोने के सिक्के की बात ली जाए ।

कमेटी ने सिफारिश की थी कि ब्रिटिश मार्केट देने-देने को लोग वास्तव कर दिए जाय । १८०९ में एक्ट के द्वारा यह विधान कर दिया गया । कमेटी की दूसरी सिफारिश यह थी कि जिन धनों पर ब्रिटिश शासक सरकार आधिकारिक रूप से मार्केट देने देती है उन्हीं धनों पर यह भी होने दे । ब्रिटिश सरकार ही और मे या उसके अंग-विभाग की शक्ति से ऐसा किया जाता है कि यह सिफारिश सिफारिश हो गई । यद्यपि मैं यह सिक्का जरूरत और पर नहीं दिया गया । पर यह सिक्का की जा आधिकारिक पेश की गई उनमें उनके अमली भाव के सम्बन्ध में उन्हीं मन्त्रियों ने यह मन्ता था ।

पहले तो शाही टकसाल ने यहाँ ढलाई की व्यवस्थादि के विषय में अडचने डाली, पर जब इनसे भी काम बनते न देखा तब अन्त में ब्रिटिश अर्थ-विभाग ने यह कहना शुरू किया कि आगिर भारतवर्ष में साँवरेन ढालने की ऐसी जरूरत ही कौन सी है ? १८९९ से १९०३ तक पत्र-व्यवहार ही चलता रहा और अन्त में भारत-सरकार ने हार मानकर यह प्रयत्न ही छोड़ दिया। हा, उसकी ओर ने यह बराबर कहा जाना रहा कि हमारा लक्ष्य ज्यो-का-स्यो बना हुआ है और हम आगा करते हैं कि हम किसी-न-किसी दिन सोने का सिक्का यहाँ ढाल सकेंगे। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश शाही टकसाल को हमारे मार्ग में रोड़े अटकाने का अवसर इसलिए मिल गया कि हम ब्रिटिश साँवरेन की ढलाई की इजाजत मागते थे। अगर हम अपना ही कोई सिक्का—जैसे मोहर या अशरफी—ढालने की बात करते, तो हमारे मार्ग में वह कठिनाई उपस्थित न होती।

१९१२ में सर विट्ठलदास ठाकरसी ने बड़ी व्यवस्थापिका सभा में इस आशय का एक प्रस्ताव पेश किया कि भारतीय टकसालों में सोने के भारतीय सिक्के ढालने की व्यवस्था की जाय। उन्होंने अपने भाषण में कहा—

“इस विषय में कभी कोई सन्देह नहीं रहा है कि हमारी मुद्रा नीति का लक्ष्य है सोने के सिक्के के साथ सोने का मान या स्टैंडर्ड। . . . पर आज तक सोने के सिक्के की व्यवस्था न हो सकी। विलम्ब से इस देश की बड़ी हानि हो रही है और इस विषय की कठिनाई भी बढ़ती जा रही है। कहा जाता है कि इस देश के लोग इतने गरीब हैं कि यहाँ सोने के सिक्के चलाना बुद्धिमत्ता का काम नहीं। पर यह दलील लचर है। सोने के स्टैंडर्ड के लिए जब यहाँ के लोग गरीब नहीं तब, सोने के सिक्के के लिए बचोकर हो सकते हैं ? इस समय तो यह अवस्था है कि हमारी सोने से जो भलाई हो सकती है, नहीं हो रही, पर जो बुराई हो सकती है वह हो रही है।”

श्रीयुत गोखले ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि मुद्रा-

प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसका संचालन प्राकृतिक रीति से होना रहे—जिममें सरकार का हस्तक्षेप या दखल नहीं के बराबर हो, और वह प्रणाली तभी हो सकती है जब फील्ड-कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार उसका आधार मोना कर दिया जाय।

सरकार की ओर से कहा गया कि अवश्य ही सारे प्रश्न पर फिर से विचार करने की जरूरत है और हम इसे भारत-सचिव के सामने राने जा रहे हैं। इसपर सर ब्रिट्टल दास ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया।

भारत-सरकार ने भारत-सचिव को लिखा, और भारत-सचिव को फिर ब्रिटिश सरकार के अर्थ-विभाग का दरवाजा खटखटाना पड़ा। पर हमकी मनोवृत्ति या भाव में कोई अन्तर नहीं पड़ा था। फिर वही किस्सा शुरू हुआ। कहा गया कि भारत-सरकार हम क्षमते में क्यों पड़ना चाहती है? सावरेन ढालने के लिए हमारी देखरेख जरूरी है। अगर भारत-सरकार की टकताई का प्रयत्न हमने हाथ में ले लिया तो यह अगुविधाजनक होगा, और अगर सावरेन ढालने के लिए हमने अपनी शायदा कहा गोल दी तो हमारे गर्व बहुत ज्यादा पड़ेगा। भारत-सचिव की अपनी राय मोने के माफि के पक्ष में नहीं थी पर भारत सरकार का आग्रह देखकर उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश अर्थ-विभाग की बातें आपका मजबूत न हो तो मैं यह इजाजत देने की तैयारी हूँ कि आप दस रुपए की अपनी मोहर ढालना शुरू कर दें। भारत-सरकार हम पर राजी हो गई। पर भारत-सचिव ने लिखा कि कुछ भी करने में पहले सर्वसाधारण की राय दर्शाया कर लेना जरूरी है। भारत-सरकार ने यह बुराया लगा और उमन जवाब दिया कि व्यवस्थापिका मना में और उमन बाहर, हम विषय की चिन्ता हो बार आलोचना हो चुकी है और वह स्पष्ट हो चुका है कि यही का लाकमन जाग म हम प्रभाव का समर्थन करता है, यदि यह ना यह पड़ा जाता है कि ना इजाजत मनाई और अस्वीकृत हो मिला नहीं है वह भारत का क्या नहीं मिला रहे? १८ फरवरी १९३२ का भारत-सचिव ने मना किया कि ना जारी बर्तमान दिग्दर्शन में जा रहा है वह हम विषय का भी अनुमतिमान करेगा। भारत-सरकार अब और कर ले कम मन्नों की? फील्ड-कमेटी की ना गिराविल

भारत-सचिव द्वारा स्वीकृत हो चुकी थी उसपर १४ साल बाद अब दूसरा कमीशन अपनी राय देने जा रहा था कि उसे अमल में लाना कहा तक ठीक होगा ।

रुपए का वजन, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, १८० ग्रेन (१/२ औंस) होता है, जिसमें खालिस चादी इस समय १६५ ग्रेन थी । रुपए की नकली कीमत १६ पेंस थी, और असली कीमत इससे बहुत कम । जब चादी का दाम लन्दन के बाजार में २४ पेंस होता तब सरकार को एक रुपया ढालने में प्रायः ९ १८१ पेंस खर्च पड़ता । जब चादी का दाम ३२ पेंस होता तब यह खर्च १२ २४१ पेंस बैठता । असली और नकली कीमतों के बीच जो फर्क था उसे सरकार अपना मुनाफा समझती थी ।

फौलर-कमेटी की सिफारिश थी —

“रुपयों की ढलाई से जो मुनाफा हो वह सरकार की साधारण आय में शामिल न किया जाय । सोने में उसका एक खास रिजर्व रखा जाय और यह रिजर्व पेपर करेंसी रिजर्व या सरकारी रोकड़ से विलकुल अलग हो ।”

कमेटी की मन्शा यह थी कि यह रिजर्व सोने के रूप में रखा जाय, और भारतवर्ष में ही रखा जाय । पर भारत-सचिव के सलाहकारों ने सोने में ऐसे कागज को भी शरीक बताया जिसका तबादला सोने से हो सकता था । भारत-सरकार के तत्कालीन अर्थ-सदस्य सर एडवर्ड लॉ भी इसी मत के थे । हा, लॉर्ड कर्जन स्वयं अर्थ की ऐसी खेचातानी के विरुद्ध थे, और उन्होंने भारत-सचिव को लिखा भी कि हमें कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे किसी प्रकार की गलतफहमी फैले या लोगों का विश्वास उठ जाय । पर भारत-सचिव ने उनकी एक न सुनी, और सरकार को आदेश दिया कि रुपयों की ढलाई से जो मुनाफा हो वह आप नियमित रूप से हमारे पास भेज दिया करे । इस प्रकार गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व की स्थापना लन्दन में हुई । और उसमें सोने के अलावा स्टर्लिंग कागज भी रहने लगे ।

१९१३ वाले शाही कमीशन ने कई गवाहों से इस विषय पर प्रश्न किए, और यह जानना चाहा कि सोने से फौलर-कमेटी का सचमुच अभिप्राय

गया था। ऐसे गवाही में मि० मार्चेण्ट, मि० कोल और मि० रास के नाम उल्लेखनीय हैं। मि० मार्चेण्ट स्वयं फौलर-कमेटी के सदस्य रह चुके थे। उन्होंने कहा कि "अब इस विषय में लोगों के विचार बदल गए हैं और मैं स्वयं सोने की जगह स्टर्लिंग के व्यवहार का समर्थन करूंगा। पर जिस समय की यह बात है उस समय तो सोने से अभिप्राय वास्तविक सोने से ही था।" मि० कोल बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके थे। उन्होंने भी कहा कि प्रारम्भ में यही विचार था कि सारा-का-मारा रिजर्व सोने में रखा जाय। मि० रास बंगाल चेम्बर के प्रतिनिधि-स्वरूप गवाही देने गए थे। उनका वाक्य यह था—

"फौलर-कमेटी की रिपोर्ट की भाषा बहुत स्पष्ट है। उसकी सिफारिश थी कि यह रिजर्व पेपर करेंसी रिजर्व या सरकारी रोकड़ से बिल्कुल अलग रखा जाय। उसका अर्थ यही हो सकता है कि रिजर्व उसी देश में रहने-वाला था। इंग्लैंड में रहने की गन्ना होनी तो यह क्यों लिखा जाना कि 'पेपर करेंसी रिजर्व और सरकारी रोकड़ से बिल्कुल अलग?' वहाँ तो यहाँ यह रिजर्व अलग रहता। रिजर्व में माली मोना रहे या नहीं, उस सम्बन्ध में मैं कमेटी की उस सिफारिश को निर्णयात्मक समझता हूँ— 'एसम्बेज का रंग गिरने की आश तो तो सरकार अपने पास के सोने का कुछ हिस्सा बिल्लायन भेज दे।' मैं तो इसका अर्थ यही लगा सकता हूँ कि जब सरकार के पास उस देश में मोना हो तब वह उसे बिल्लायन जाने दे। फिर कमेटी की दूसरी सिफारिश यह थी कि जब सरकार के पास रिजर्व में काफी मोना हो जाय और उसके गजाने में भी मोना हो, तब वह भारत-वर्ष में अपनी देनदारी माने में चुका सकती है।"

अर्थ का अर्थ कर—मन्य और न्याय की हत्या कर—भारत-वर्ष ने उस देश का मोना बिल्लायन भेजना और उसका मनमाना उपयोग करना शुरू कर दिया। उस धोखाधड़ी ने भारत-सरकार का भी हानि कर दिया।

१९०३ में लॉर्ड डर्बिच की अध्यक्षता में एक कमेटी उस देश में गयी थी जिसने दो दिनों तक मुद्रा के प्रश्न पर विचार करने के लिए बैठी।

इसकी सिफारिश हुई कि उस साल रुपये की ढलाई के मुनाफे* का डेढ़ करोड़ रुपया रेलो के सुधार में लगा दिया जाय । पर भारत-सचिव इससे भी दो कदम आगे गए और उन्होंने निश्चय किया कि जब तक गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व ३० करोड़ रुपए का नहीं हो जाता तब तक हर साल मुनाफे की आधी रकम रेलो में लगती रहे । उनका विचार शायद यह था कि रिजर्व ३० करोड़ हो जाने पर सारी रकम उस काम में लगा दी जाय । भारतवर्ष में उनके इस निर्णय से बड़ा असन्तोष फैला और इसका काफी विरोध किया गया ।

भारत-सरकार ने भी २४ जून १९०७ को तार-द्वारा निवेदन किया कि रिजर्व का सोना अभी ऐसे काम में न लगाया जाय, पर भारत-सचिव ने उसपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और डेढ़ करोड़ से ऊपर रुपया रेलो में लगा ही दिया । साथ ही यह कहा कि जो निर्णय हो चुका है उसीके अनुसार आगे भी उपयोग होता रहेगा ।

भारत-सरकार ने एक्स्चेंज के गिरने की आशका प्रकट करते हुए कहा था कि रिजर्व को ऐसी परिस्थिति के लिए अक्षुण्ण रखा जाय । इसके उत्तर में भारत-सचिव ने लिखा था कि "डरने की कोई बात नहीं, व्यापार की वर्तमान अवस्था और अपने पास के साधनों को देखते हुए मैं इस आशका को निर्मूल समझता हूँ ।"

पर जो आसमान इतना साफ नजर आता था उसीमें घनघोर घटा को उमड़ते देर न लगी । १९०७ में यहा अनावृष्टि रही । कुछ महीने बाद अमेरिका में एक भीषण आर्थिक सकट उपस्थित हो गया । यहा से एक्स्पोर्ट बहुत कम हुआ । माग इस समय रुपए की नहीं, स्टर्लिंग की थी, क्योंकि

* दर असल यह कोई मुनाफा नहीं था । जैसे कागज के नोटो की पुश्ती के लिए फरेन्सी रिजर्व था, वैसे ही चांदी के नोटो की पुश्ती के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व । रुपया अपनी नकली कीमत का कुछ हिस्सा अपने साथ लिए चलता था, पर बाकी कीमत की पुश्ती के लिए रिजर्व में सोना रखना जरूरी था ।

भारत-सचिव के निर्णय के आगे भारत-सरकार ने सिर झुकाया, पर इतना कहे बिना उससे न रहा गया कि "आपका यह निर्णय हम गेद के साथ स्वीकार करते हैं।" भारत-सचिव ने केवल १,०००,००० पौंड सोने के रूप में रगना मजूर किया था।

१९०६ में गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व की एक शारा इस देश में रोती गई जिगम छ करोड रुपए रखने की व्यवस्था की गई। यह कुछ ऊटपटांग-सी बात थी कि जिसका नाम 'स्वर्णनिधि' हो उसमें रुपए रखे जाय। पर भारत-सचिव गहा भी एक चाल चल रहे थे। करेन्सी रिजर्व में यह कानूनी व्यवस्था थी कि लन्दन में एक हद से ज्यादा रकम सोने में ही रखी जा सकती थी। मान लीजिए कि रुपयो की माग हुई और लन्दन में भारत-सचिव को सोना मिला। अगर ये रुपए करेन्सी रिजर्व से दिए गए तो वह सोना उगी रिजर्व की सम्पत्ति हुई, और भारत-सचिव को उस सोने के साथ मनमानी करन का अधिकार नहीं था। पर गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व में कानून का कोई ऐसा नियन्त्रण नहीं था, भारत-सचिव जो चाहते, कर सकते थे। इसलिए इस रिजर्व की यह शारा उनके सुभीते के लिए गोली गई। छ करोड रुपए तक इस शारा में यहा दिए जा सकते थे, और उनके बरके विनायक में जो सोना मिलता उगता भारत-सचिव जिस प्रकार चाहो, उपयोग कर सकते थे।

३१ मार्च १९१३ को गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व इस रूप में था—

पौंड

मिक्स्टीज या कागज (बाजार दर में)	१५,०५५,६६९
रुपए, जो थोड़े समय के लिए उधार दी गई थी	१,००५,६६६
	<hr/> १६,०६१,३३५
बैंक अथवा इन्वेंट में रखा हुआ सोना	१,६००,०००
	<hr/> १७,६६१,३३५
भारतीय शासन में छ करोड रुपए, १० पैसों की दर में	१,०००,०००
	<hr/> २०,६६१,३३५ पौंड

उस समय गोल्ड स्टैण्डर्ड रिजर्व-सम्बन्धी नीति यह थी कि जब यह २५,०००,००० पाँड हो जाय तब इस विषय पर फिर से विचार हो कि रुपयो की ढलाई का मुनाफा और सूद से होनेवाली आमदनी सब-की-सब इस रिजर्व में जमा की जाय या नहीं।

३१ मार्च १९१३ को पेपर करेन्सी रिजर्व का यह हाल था कि चलन में कुल नोट ६८.९७ करोड रुपए के थे। इनकी पुष्टी के लिए रिजर्व में ये चीजे थी —

भारतवर्ष में रुपए	१६४५ करोड रुपए
" सोना	२९३७ " "
लन्दन में सोना	९१५ " "
लन्दन में सिव्यूरिटीज	४०० " "
भारतवर्ष में ,,	१०.०० " "

६८९७ करोड रुपए

१८६२ में चलन में कुल नोट ३६९ करोड थे। १८९० में यह तादाद १५७७ करोड हो चली थी। नोटों के प्रचार में विशेष वृद्धि चादी की टकसाल बन्द हो जाने के बाद हुई। इधर उनकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न किया गया और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले विधान में कई संशोधन हुए।

१८७५ से पहले रिजर्व में कुछ सोना रहता था, पर चादी के मुकाबले जब सोना महंगा हो चला तब उसका रिजर्व में आना बन्द हो गया। १८९३ में सोने और रुपए के बीच की दर बाधी गई और सरकार सोने के बदले रुपए देने को तैयार हुई। पर चूँकि सोने की कीमत बाजार में ज्यादा थी, कोई रुपए लेने के लिए सरकार के पास अपना सोना न ले जाता था। १८९८ में जब एक्सचेंज १६ पेंस हो गया तब लोग सरकार को सोना देकर उससे रुपए लेने लगे। करेन्सी रिजर्व में इस प्रकार सोना इकट्ठा होने लगा। १९०० के आरम्भ में प्रायः ७॥ करोड रुपए का सोना वहाँ इकट्ठा हो चुका था।

सोने को चलन में लाने के लिए कुछ प्रयत्न किया गया, पर वह विशेष सफल न हो सका। उस समय भारतवर्ष के कुछ हिस्सों में अकाल पड़ा हुआ था और आर्थिक अवस्था सोने के चलन के अनुकूल नहीं थी। पर जब सोना चलन में लौट कर सरकारी गजाने में आने लगा तब भारतवर्ष में उसने चलन के विरोधी इसका यह अर्थ लगाने लगे कि यहाँ के लोग गरीब होने के कारण सोने का व्यवहार नहीं कर सकते, उनके लिए रुपया ही विशेष उपयुक्त है, इत्यादि। वास्तव में उस साल यहाँ की अवस्था सोने के चलन के प्रतिकूल थी। इसके बाद फिर कभी सरकार की ओर से सोने को चलन में लाने के लिए कोई काम उद्योग नहीं किया गया।

आरम्भ में क्रेन्गी रिजर्व का मारा सोना इसी देश में रहता था। १८९८ में अस्थायी रूप से कुछ सोना लन्दन में रखा गया। पर यह व्यवस्था कुछ ही समय बाद स्थायी कर दी गई। कारण यह माना गया कि यहाँ चाँदी गरीब होने के लिए सोना रखना जरूरी था। बाद में यह विधान बना कि क्रेन्गी रिजर्व का सोना सरकार, लन्दन में या उस देश में, जहाँ चाँदे, रख सकती थी। भारत-राज्य उस रिजर्व का भी काफी सोना लन्दन में रखने लगे।

१९०५ के विधानद्वारा सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह क्रेन्गी रिजर्व का एक निश्चित भाग स्टैंडिंग मिनिस्ट्रीज में रख सकती है। पहले इसकी छह दो करोड़ रुपए थी। १९११ में यह चार करोड़ कर दी गई। मारा रिजर्व, जो मिनिस्ट्रीज में यहाँ और लन्दन में रखा जा सकता था, १८ करोड़ था।

मारा स्टैंडिंग रिजर्व और क्रेन्गी रिजर्व के अलावा भी सरकार के हथ में कुछ रुपए रहते थे, जिसे सरकारी गारंटी कहते थे। यह गारंटी भारतवर्ष और लन्दन, दोनों जगह रखी जाती थी।

उदाहरण यह थी कि लन्दन में कम-से-कम ४,०००,००० पाँउ रहते और भारतवर्ष में कम-से-कम ८,०००,००० पाँउ। नए साल के आरम्भ में सरकार में प्रायः १२,०००,००० पाँउ रखना पड़ता था, अर्थात् मारा

मिला कर १६,०००,००० पौण्ड । वास्तव में कब कहा कितनी रोकड थी, यह नीचे की तालिका से स्पष्ट होगा —

३१ मार्च	लन्दन में पौड	भारतवर्ष में पौड	कुल जोड पौड
१९०८	४,६०७,२६६	१२,८५१,४१३	१७,४५८,६७९
१९०९	७,९८३,८९८	१०,२३५,४८३	१८,२१९,३८१
१९१०	१२,७९९,०९४	१२,२९५,४२८	२५,०७४,५२२
१९११	१६,६९६,९९०	१३,५६६,९२२	३०,२६३,९१२
१९१२	१८,३९०,०१३	१२,२७९,६८९	३०,६६९,७०२

स्पष्ट है कि रोकड वाकी जितनी होनी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा थी, और इसका कारण यह था कि लन्दन का हिस्सा बड़ने-बड़ने प्रायः तिगुना होने लगा था । जहा ४,०००,००० पौड पर्याप्त था वहा १८,०००,००० पौड से भी अधिक जमा रहता था ।

आखिर इतना रुपया आता कहा से था ? इसका उत्तर है—बजट की वचत से । हर साल व्यय से आय अधिक होती, और जो वचत होती वह लन्दन मगा ली जाती ।

१८९८-९९ से वचत होना शुरू हुआ था, और प्रथम महासमर के आरम्भ तक होता ही गया । पहले दस वर्षों में जो वचत हुई वह ३७½ करोड रुपए थी । १९१० और १९१४ के बीच २० करोड की और वचत रही । यह भारत-सरकार के बजट की बात है । प्रांतीय सरकारों की वचत इसमें शामिल नहीं है ।

श्रीमंत गोखले के बजट-सम्बन्धी भाषणों में सरकार की इसलिए काफी निन्दा मिलती है कि वह हर साल टैक्स के रूप में जरूरत से ज्यादा लोगों से वसूल करती, और अन्धाधुन्ध खर्च करने के बाद जो कुछ बच रहता उसे शिक्षा और स्वास्थ्य-सम्बन्धी कामों में न लगा कर और कामों में लगा देती । बजट बनाते समय आय का तखमीना जानबूझ कर कम किया जाता । खर्च पर किसी प्रकार का नियंत्रण था ही नहीं । यूरोपियन कर्मचारियों की सरया बढ़ती ही जाती थी, पर यह सब होने पर भी जब वचत होती और सरकार से उसका कुछ हिस्सा शिक्षा-प्रचार या स्वास्थ्य-सुधार जैसे

का विभाग) का रुपया-पैसा जमा रखने के अलावा भी उसका कुछ काम कर दिया करती—इमके लिए इसे जो कमीशन या पुरस्कार मिलता वह साल में ६६,००० पौंड होता था। सब मिला कर इस बैंक को इंडिया ऑफिस से साल में प्राय ८६,००० पौंड अर्थात् १२,९०,००० रुपए का लाभ था। चेम्बरलेन-कमीशन के सामने इंडिया ऑफिस की ओर से आने वाले गवाहों ने भी स्वीकार किया कि यह रकम बहुत बड़ी थी और भारतवर्ष को यह सौदा बेहद महंगा पड़ रहा था। पर उनका कहना था कि इंडिया ऑफिस लाचार है। कानूनन वह दूसरी बैंक से अपना काम करा नहीं सकता, और जब बैंक आव् इंगलैण्ड से अनुनय-विनय करता है कि कमीशन घटाइए तब बैंक साफ इनकार कर देती है। वास्तव में बैंक आव् इंगलैण्ड इंडिया ऑफिस की बेवसी का नाजायज फायदा उठा रही थी।

इंडिया ऑफिस लन्दन में रुपया उधार देने का काम करता था। कहा जाता है कि इस विषय में वह ईस्ट इंडिया कम्पनी की बताई हुई राह पर चल रहा था।

इंडिया ऑफिस की ओर से एक खास दलाल लेन-देन के इस काम को देखता था। ऐसे लोगो की एक लिस्ट रखी जाती, जिन्हें रुपया उधार देने में कोई जोखिम नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति या फर्म अपना नाम इस लिस्ट पर चढाना चाहता तो उसे दररवास्त करनी पडती। यह दरग्व्वास्त इंडिया ऑफिस की फाइनेस-कमेटी की सिफारिश हो जाने पर भजुरी के लिए भारत-सचिव के पास जाती। जिनकी साख ऊंची होती वे ही इस लिस्ट पर आ सकते थे।

जिस फाइनेस-कमेटी का यहा जिक्र किया गया है उसके चेयरमैन या अध्यक्ष इधर कुछ वर्षों से लन्दन के लॉर्ड इचकेप या सर फेलिक्स शुम्टर जैसे बड़े व्यापारी होते आ रहे थे। लेन-देन के काम में इस चेयरमैन का बहुत बड़ा हाथ रहता, और भारत-सचिव प्राय इन्ही के कहने के अनुसार चलते थे।

कर्ज सिक्यूरिटीज पर दिया जाता था, पर कुछ खास बैंको को बिना जमानत के ही दे दिया जाता। बैंक आव् इंगलैण्ड की ओर से गवाही देने

वाले मि० कोल ने चेम्बरलेन-कमीशन से कहा था कि उनके यहाँ यह प्रथा नहीं थी, और बड़ी-से-बड़ी बैंक को भी सिक्कूरिटीज देने पर ही रुपया उधार मिल सकता था। कर्ज लेनेवालों में दो बड़ी बैंके ऐसी थी, जिनसे लॉर्ड इंचेप और सर फेलिक्स शुस्टर स्वयं सम्बद्ध थे। उस समय ऐसे समालोचनों की कमी नहीं थी, जिन्होंने इन दोनों पर पक्षपात का दोषारोपण करते हुए यह कहा कि इनका एक हाथ कर्ज देता था, और दूसरा लेता था। पर लॉर्ड इंचेप ने अपनी और सर फेलिक्स शुस्टर की सफाई में कहा कि उन्होंने उन बैंकों के साथ जरा भी गिआयत नहीं की थी।

इण्डिया ऑफिस के दलाल मि० होरेस स्काट थे। उनमें पहले उनके पिता एक पद पर रह चुके थे। ब्याज से जो आमदनी होती उसपर पाँच प्रतिशत के हिस्से से मि० स्काट को दलाली मिलती थी। १९१०-११ में उनकी दलाली १६,००० पौंड अर्थात् २,४०,००० रुपए हुई थी। इस पर टिप्पणी करते हुए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री केन्स ने लिखा था—“जब पढ़े-पढ़त यह मादूम हुआ कि बड़े लाट को छोड़, भारत-भरकार की ओर से हममें अधिक धनन या पुरस्कार पानेवाला इण्डिया ऑफिस का यह दलाल है तब तब आश्चर्य-चकित हो गए। मजा यह कि इस दलाल को अपना पूरा समय इण्डिया ऑफिस के काम के लिए नहीं लगाना पड़ता, उगता अपना भी व्यवसाय है, और वह उसे भी देगता-भालता है।”

आन्दोलन उठने पर मि० स्काट की दलाली घटा दी गई। फिर भी हमें उनकी आय आठ हजार पौंड अर्थात् १,२०,००० रुपए के लगभग थी। भारत-भरकार की ओर से स्ट्राफ़ (कागज) की तरीद-बित्री करने में मि० स्काट १,५०० पौंड अर्द्ध मिलता था। समालोचनों का कहना था—और बहुत ही सच कहना था कि घटा देने पर भी इण्डिया ऑफिस के दलाल की दरगो बरत जायगी। उन-देन करों का होना था, और न्याय की दर भारत की राज्य पर निर्भर करनी थी। दलाल की कार्य-प्रणाली से राज्य की मदद ज्यादा कम नहीं पड़ सकती थी कि उसे हम पैसों पर पुरस्कार दिया जाय। पर इण्डिया ऑफिस परी कलाह पर क्या किया देना था वह ?

भारतवर्ष का जो रुपया लन्दन के व्यापारियों को इस प्रकार उधार दिया जाता वह कभी-कभी २७ करोड़ के करीब पहुँच जाता था। व्याज की दर कभी-कभी इतनी नीची होती कि बैंक ऑफ इंग्लैंड भी हैरान हो जाती। इस बात को सब स्वीकार करते थे कि लन्दन का सराफा और लन्दन का व्यापार, दोनों को इण्डिया ऑफिस की इस महाजनी से बहुत लाभ था।

पर भारतवर्ष का रुपया भारतवर्ष के काम न आ सकता था। यहाँ सरकार की नीति इतनी सकीर्ण थी कि बड़ी-से-बड़ी बैंक के लिए भी उधार लेना लाभप्रद नहीं था। १८९९ और १९०६ के बीच कुल छ बार बैंको ने सरकार से बर्ज लिए—प्रत्येक बार २० से ४० लाख रुपए के बीच। १९०६ और १९१३ के बीच लेन-देन का काम हुआ ही नहीं। व्यापारियों को यहाँ प्रायः ऊँचे व्याज पर रुपया मिलता। ८ प्रतिशत यहाँ के लिए साधारण दर थी। जब कभी लोग सरकार से कहते कि रुपया सस्ता करके वाणिज्य-व्यापार और उद्योग-धंधों की उन्नति में सहायता पहुँचाइए तब उन्हें उत्तर मिलता कि “यह सहायता पहुँचाना हमारा काम नहीं। बाजार को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, और भारतीय पूँजी ऐसे कामों में लग सके, इसका प्रवन्ध करना चाहिए।” भारतवर्ष का धन लन्दन के लिए था, भारतवर्ष के लिए नहीं।

भारत-सचिव भारत-सरकार पर जो हुण्डी किया करते वह ‘कौंसिल बिल’ कहलाती थी। भारतवर्ष में आयात (इम्पोर्ट) की अपेक्षा यहाँ से निर्यात (एक्सपोर्ट) अधिक होने के कारण स्टॉलिंग की अपेक्षा रुपए की माग प्रायः अधिक रहती थी। रुपए चाहनेवाले लोग विलायत में भारत-सचिव को सोना या स्टॉलिंग देकर उससे भारत-सरकार के नाम हुण्डी ले सकते थे और हुण्डी भुना कर उसके रुपए कर सकते थे। इसके लिए कायदा यह था कि रुपए चाहनेवालों को टेण्डर देना पड़ता—अर्थात् यह बताना पड़ता कि वे किस दर से उसे खरीदने को तैयार हैं। फिर भारत-सरकार की ओर से यह सूचित किया जाना कि किसकी दर मंजूर हुई है और किसको कितने की हुण्डी मिलेगी। तार-द्वारा जो हुण्डी की जाती उसके लिए

वाले मि० कोल ने चेम्बरलेन-कमीशन से कहा था कि उनके यहां यह प्रथा नहीं थी, और बड़ी-से-बड़ी बैंक को भी सिक्कूरिटीज देने पर ही रुपया उधार मिल सकता था। कर्ज लेनेवालों में दो बड़ी बैंके ऐसी थी, जिनसे लॉर्ड इचकोप और सर फेलिक्स शुस्टर स्वयं सम्बद्ध थे। उस समय ऐसे समालोचनों की कमी नहीं थी, जिन्होंने इन दोनों पर पक्षपात का दोषारोपण करते हुए यह कहा कि इनका एक हाथ कर्ज देता था, और दूसरा लेता था। पर लॉर्ड इचकोप ने अपनी और सर फेलिक्स शुस्टर की सफाई में कहा कि उन्होंने उन बैंकों के साथ जरा भी गियायत नहीं की थी।

इण्डिया आफिस के दलाल मि० होरेस स्कॉट थे। उनसे पहले उनके पिता उस पद पर रह चुके थे। व्याज से जो आमदनी होती उसपर पाँच प्रतिशत के हिसाब से मि० स्कॉट को दलाली मिलती थी। १९१०-११ में उनकी दलाली १६,००० पाउंड अर्थात् २,४०,००० रुपए हुई थी। उस पर टिप्पणी करते हुए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री केन्स ने लिखा था—“जब पहले-पहल यह मालूम हुआ कि नव्वे लाख को छोड़, भारत-सरकार की ओर से मांग अधिक धन या पुरस्कार पानेवाला इण्डिया आफिस का यह दलाल है तो लोग आश्चर्य-चकित हो गए। मजा यह कि इस दलाल को अपना पूरा समय इण्डिया आफिस के काम के लिए नहीं लगाना पड़ता; उगाता अपना भी व्यवसाय है, और वह उसे भी देगता-भाळता है।”

आन्डरसन उठने पर मि० स्कॉट की दलाली घटा दी गई। फिर भी इसमें उसकी श्राव्य आठ हजार पाउंड अर्थात् १,२०,००० रुपए के लगभग थी। भारत-सरकार की आर में स्ट्रांक (ताम्र) की सरीस-बिबी करने में किए उठे १,५०० पाउंड अलग मिलता था। समाजोत्पास का कहना था—और बहुत टीस करता था कि घटा देने पर भी इण्डिया आफिस में दलाल की दशाई बहुत ज्यादा थी। किन्तु इन कराओं का होता था, और वार की दर वारार की तरफ पर निर्भर करती थी। दलाल की कार्यभार में आमदनी से उगाता ज्यादा नहीं नहीं पड़ सकता था कि उसे इस पैसा के पुरस्कार दिया जाय। पर इण्डिया आफिस का माला पर कर दिया देना था ?

भारतवर्ष का जो रुपया लन्दन के व्यापारियों को इस प्रकार उधार दिया जाता वह कभी-कभी २७ करोड़ के करीब पहुँच जाता था। व्याज की दर कभी-कभी इतनी नीची होती कि बैंक ऑफ इंग्लैंड भी हैरान हो जाती। इस बात को सब स्वीकार करते थे कि लन्दन का सराफा और लन्दन का व्यापार, दोनों को इण्डिया ऑफिस की इस महाजनी से बहुत लाभ था।

पर भारतवर्ष का रुपया भारतवर्ष के काम न आ सकता था। यहाँ सरकार की नीति इतनी सकीर्ण थी कि बड़ी-से-बड़ी बैंक के लिए भी उधार लेना लाभप्रद नहीं था। १८९९ और १९०६ के बीच कुल छ बार बैंको ने सरकार से कर्ज लिए—प्रत्येक बार २० से ४० लाख रुपए के बीच। १९०६ और १९१३ के बीच लेन-देन का काम हुआ ही नहीं। व्यापारियों को यहाँ प्रायः उँचे व्याज पर रुपया मिलता। ८ प्रतिशत यहाँ के लिए साधारण दर थी। जब कभी लोग सरकार से कहते कि रुपया सस्ता करके वाणिज्य-व्यापार और उद्योग-धंधों की उन्नति में सहायता पहुँचाइए तब उन्हें उत्तर मिलता कि “यह सहायता पहुँचाना हमारा काम नहीं। बाजार को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, और भारतीय पूँजी ऐसे कामों में लग सके, इसका प्रवन्ध करना चाहिए।” भारतवर्ष का धन लन्दन के लिए था, भारतवर्ष के लिए नहीं।

भारत-सचिव भारत-सरकार पर जो हुण्डी किया करते वह ‘कौंसिल विल’ कहलाती थी। भारतवर्ष में आयात (इम्पोर्ट) की अपेक्षा यहाँ से निर्यात (एक्स्पॉर्ट) अधिक होने के कारण स्टर्लिंग की अपेक्षा रुपए की माँग प्रायः अधिक रहती थी। रुपए चाहनेवाले लोग विलायत में भारत-सचिव को सोना या स्टर्लिंग देकर उससे भारत-सरकार के नाम हुण्डी ले सकते थे और हुण्डी भुना कर उसके रुपए कर सकते थे। इसके लिए कायदा यह था कि रुपए चाहनेवालों को टेण्डर देना पड़ता—अर्थात् यह बताना पड़ता कि वे किस दर से उसे खरीदने को तैयार हैं। फिर भारत-सरकार की ओर से यह सूचित किया जाता कि किसकी दर मंजूर हुई है और किसको कितने की हुण्डी मिलेगी। तार-द्वारा जो हुण्डी की जाती उसके लिए

(१) रुपये के लिए चादी खरीदने की जरूरत इसलिए पड़ती थी कि हमारे शासक हमें वह सच्चा गोल्ड स्टैंडर्ड (सोने का मान) देने को तैयार नहीं थे, जिसकी सिफारिश फौलर-कमेटी ने की थी और जिसे देना स्वयं भारत-सचिव ने स्वीकार कर लिया था। अगर चलन में सोने के सिक्के होने, तो चादी के इन सिक्कों की न ऐसी आवश्यकता होती, न ऐसी बहुतायत।

(२) एक्सचेंज का गिरना बहुत दूर की बात या सम्भावना थी। भारतवर्ष में इम्पोर्ट से एक्सपोर्ट ज्यादा होने के कारण स्टर्लिंग से रुपये की माग ज्यादा रहती है। कभी किसी साल ऐसा संयोग हो जाता है कि एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट बढ़ जाना है और स्टर्लिंग की माग बढ़ जाने के कारण एक्सचेंज की गंगा उलटी बहने लगती है। पर ऐसे अवसर बहुत कम हुए हैं। अधिकारियों को एक्सचेंज के गिरने की फिक्र तो इतनी थी कि उसको रोकने के लिए साल-ब-साल लन्दन में सोना इकट्ठा करते जाते थे। पर महासमर-जैसी परिस्थिति की उन्हें कोई भी चिन्ता नहीं थी, जिसमें न सोना मिल सकता था, न सिक्कूरिटिज या कागज ही बेचे जा सकते थे।

(३) व्याज तो भारतवर्ष में भी उपजाया जा सकता था, बल्कि यहाँ इसकी गुजाइश विलायत से ज्यादा थी। पर जहाँ मुद्रा-प्रणाली की वास्तविक भित्ति या आधार का प्रश्न हो वहाँ तो सब से पहले यह देखना चाहिए कि वह सुरक्षित किस प्रकार रह सकेगी। उसके सुरक्षित रहने से ही हम सुरक्षित बने रहेंगे। थोड़े से व्याज के लिए इतनी बड़ी जोखिम उठाना कहा की बुद्धिमत्ता थी? पर लन्दन में सोना इंग्लैंड की भलाई के खयाल में रखा जा रहा था—भारतवर्ष को व्याज के रूप में कुछ लाभ कराने के उद्देश से नहीं।

लन्दन में चादी खरीदने का कारण लन्दन का पक्षपात था। वहाँ का बाजार बहुत ही छोटा है। चार दलालों के गुट या टोली को लन्दन में चादी का बाजार समझना चाहिए। भारतवर्ष में लोगों की माग थी कि चादी के लिए टेण्डर करा जाय और उनपर विचार होने के बाद चादी बम्बई में खरीदी जाय। सर शापुर्जी भरोचा के कथनानुसार यह नगर सभ-

थी कि अन्तर्राष्ट्रीय समझौता करके इस देश में चादी को उसकी पुरानी जगह फिर दे दी जाय।

सोने में दामों की अपेक्षा रुपए में दाम ज्यादा बढे थे और कुछ विशेषज्ञों का—खास कर श्रीगोखले का—मत यह था कि रुपए चलन में आवश्यकता से अधिक थे। उनका कहना था कि “सोने के सिक्के, आवश्यकता न रहने पर, निकल जाते हैं (जैसे निर्यात के रूप में), पर रुपए निकल नहीं सकते, उन्हें गलाने से लाभ नहीं, भुगतान के लिए उन्हें विदेश भेजना संभव नहीं। या तो वे लौट कर बैंको में या सरकारी खजाने में आ जायेंगे या चलन में बने रहेंगे। पर इस देश में बैंक-व्यवसाय की अभी यथेष्ट उन्नति नहीं हुई है, इसलिए रुपए जन्दी लौटते नहीं, लोगों के ही पास बने रहते हैं और दामों पर अपना असर डालते रहते हैं।” इस विषय का अनुसन्धान करने के लिए १९१० में एक छोटी-सी कमेटी बैठी थी, जिसके अध्यक्ष मि० के० एल० दत्त थे। इसकी राय यह ठहरी कि रूपयों की वृद्धि आवश्यकता के अनुसार ही हुई थी और उनकी कोई ऐसी बहुतायत न थी। हा, बैंको में उधार मिलने में अब बड़ी सहूलियत हो चली थी, और इसका असर दामों पर बेशक पड़ा था।

चेम्बरलेन-कमीशन की सिफारिशों का जिक्र करने से पहले परिस्थिति का सिद्धान्तकन कर लेना आवश्यक है —

(१) इस समय सॉवरेन (गिनी) और रुपया, दोनों ही चलन में थे, और लोग दोनों को ही लेने-देने को बाध्य थे।

(२) सरकार रुपए के बदले सोना देने को कानूनन बाध्य नहीं थी, पर एक हद तक वह सोना देने को तैयार रहती थी।

(३) सरकार सॉवरेन के बदले १६ पेंस की दर से रुपया देने को बाध्य थी, पर धातु के रूप में सोने के बदले नहीं।

(४) भारत-सचिव १६½ पेंस की दर से चाहे जितने की हुडी भारत-सरकार के नाम बेचने को तैयार रहते थे। भारत-सरकार भी भारत-सचिव के नाम उलटी हुडी बेचना स्वीकार कर चुकी थी, पर १५¾ पेंस से नीची दर से नहीं। ऐसी हालत में एक्सचेंज न तो १६½ पेंस से ऊपर जा सकता था, न १५¾ पेंस से नीचे।

पतियो के हाथ की कठपुतली थे। उन्हें वही करना पड़ता था जो इंग्लैण्ड के हित के अनुकूल था, जिससे इंग्लैण्ड की भलाई निश्चित थी।

१७ अप्रैल १९१३ को एक रायल कमीशन भारतीय मुद्रा-प्रणाली के हर पहलू पर विचार करने के लिए नियुक्त हुआ। इसके अध्यक्ष थे मि० ऑस्टेन चेम्बरलेन, जो बाद में भारत-सचिव और परराष्ट्रसचिव हुए थे। कमीशन के दूसरे मेम्बरों में लॉर्ड फैवर, सर शापजोर्ज भरोचा, सर अर्नेस्ट केवल और अध्यापक केन्स थे। इसके सेक्रेटरी थे सर वेसिल ब्लैकेट, जो बाद में भारत के अर्थ-सदस्य हुए।

पिछली कमेटियों की तरह इस कमीशन की भी सारी कार्रवाई लन्दन में ही हुई। इसकी रिपोर्ट २४ फरवरी १९१४ को ब्रिटिश सरकार के पास भेजी गई। इसके एक मेम्बर सर जेम्स वेग्वी ने सोने के प्रचार के सम्बन्ध में औरों से अपना मतभेद प्रकट किया था। रिपोर्ट में अध्यापक (वर्तमान लॉर्ड) केन्स का रिजर्व बैंक जैसी संस्था पर एक नोट था।

कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया कि कितनी ही बातों में वस्तुस्थिति फौज़र-कमेटी द्वारा स्वीकृत स्कीम से भिन्न थी। यहाँ की मुद्रा-प्रणाली का आधार या तो मि० लिण्डसे का प्रस्ताव, जो कमेटी द्वारा अस्वीकृत हो चुका था, पर कमेटी के वास्तविक मार्ग का अवलम्बन न करने के लिए कमीशन ने अधिकारियों की किसी प्रकार की निन्दा नहीं की, बल्कि उसका कहना था कि जो कुछ हुआ था, अच्छा ही हुआ था।

कमीशन की सिफारिशों में कुछ खास बातें ये थी —

(१) यह निश्चित हो जाना चाहिए कि भारतीय मुद्रा-प्रणाली का लक्ष्य क्या है। १८९८ की कमेटी की राय थी कि इस देश में सोने के मान की सफलता के लिए सोने का सिक्का आवश्यक है। पर पिछले १५ वर्षों के इतिहास से इस धारणा की पुष्टि नहीं होती।

(२) चलन में सोने के उपयोग को प्रोत्साहन देना भारतवर्ष के लिए हितकर न होगा।

(३) सोने के सिक्के की यहाँ ढलाई की कोई आवश्यकता नहीं। पर भारतीय जनता सचमुच इसे चाहती है और भारत-सरकार इसका

राशें देने को तैयार है, तो सिद्धांततः कोई आपत्ति नहीं हो सकती। हा, जो सिक्का ढाला जाय वह साँवरेन होना चाहिए।

(४) एमचेंज की पुश्ती के लिए रिजर्व में काफी सोना और स्टैलिम रहना चाहिए।

(५) गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व की अभी कोई हद नहीं बांधी जा सकती।

(६) रुपयों की ढलाई में जो मुनाफा हो वह पूरा-का-पूरा इसी रिजर्व में जमा किया जाय।

(७) इस रिजर्व में इस समय जितना सोना रखा जाना है उससे अधिक रखने की जरूरत है।

(८) गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व लन्दन में ही रहना चाहिए।

(९) सरकार को माफ़ तोर से यह जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेनी चाहिए कि जब कभी स्टैलिम की भारतवर्ष में माँग होगी तब वह भारत-सर्विस के नाम १५३६ पग की दर से हुट्टी बेचने को तैयार रहेगी।

(१०) भारत-सरकार के हाथ में जब कभी वचन का रुपया हो तो उसे प्रेमिस्सी बेना को उधार देने का नियम-मा कर लेना चाहिए। गिन बार्स पर रुपया उधार दिया जाय, यह निश्चित हो जाना चाहिए।

(११) इस समय हम किमी स्टैट या सेण्ट्रल (केन्द्रीय) बैंक की स्थापना के पक्ष या विपक्ष में कुछ भी नहीं कह सकते, पर इतना हम अवश्य कहेंगे कि यह विषय सन्तुष्टपूर्ण है और हमपर विशेषज्ञता की एक छाती-सी कमटी द्वारा विचार होना की आवश्यकता है।

इंडिया ऑफिश की फाइनल कमिटी के दो संयोजक और एक सभ्य लेडी ईला में सम्मेलन हो चुके थे, जिनका इंडिया ऑफिश में लेन-देन का सम्बन्ध रहना था। यह बात समाचार-पत्रों-द्वारा अपानिजनक कलाई जा चुकी थी। हमपर कमीशन ने अपाई राय यह दी कि इस सम्मेलन के कारण इंडिया ऑफिश का पक्षपात हो जायित नहीं शक, पर भारत-सर्विस का चाहिए, कि अगर वह हो सके, ऐसी समाचार-पत्र या जिक्रियन के लिए कोई मोता हो न सके।

इंडिया ऑफिश के दस्तावेजों में नियम उगुद पर दस्तावेजों की जाँच थी,

सका कमीशन समर्थन न कर सका । उसकी सिफारिश थी कि कुछ समय बाद इस प्रश्न पर फिर से विचार किया जाय ।

बैंक ऑफ इंग्लैंड के विषय में उसने दबी जवान इतना ही कहा कि हम लोगो के विचार में, इंडिया ऑफिस और इस बैंक के सम्बन्ध को नई भेत्ति पर रखने का समय आ गया है ।

कमीशन की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन ही थी कि अगस्त १९१४ में प्रथम महाममर छिड़ गया । अब यह निश्चय हुआ कि जब तक शांति स्थापित नहीं होती तब तक कार्रवाई मुलतवी रहे ।

लेने के देने

महागमर के कारण भारतवर्ष को जो आर्थिक लाभ होना चाहिए था नहीं हुआ, बल्कि गहरी हानि हुई। परतन्त्रना के फलस्वरूप उसे लेने के देने पड़ गए।

आरम्भ में हमारे व्यापार का धक्का-सा लगा और काम-काज बढ़ा कम हो चला। पागलेज में कमजोरी आने लगी जिसका रोकने के लिए सरकार ने भारत-गन्धर्व के नाम उल्टी हण्टी बेचना शुरू किया। लाभ बेनाम अपने-अपने गण उठाने लगे। पहले दो महीनों में ही सौंपण बेहिशिष्ट मध्य करों की कमी हो चली। गितम्बर में अक्टूबर १९१४ तक दो लाख की और कमी हुई। बाद में परिस्थिति सुधरी और शिपिंग बढन लगे। सरकार में चक्रवर्त के मारे लोग नोट भी तेजी से भुनाने लगे। ३१ जून १९१४ और ३१ मार्च १९१५ के बीच नोटों का चलन प्रायः उस तरह कम हो चला। पर हमारे बाद अवस्था सुधरने पर नोटों का चलन फिर बढन लगा और बढता ही गया। जुलाई १९१४ में अनाम सार्वजनिक बाजार बढ चली और सरकार ने राज्य में प्रायः १,८००,००० पाउंड का नाना निष्कास किया। ५ अगस्त को सरकार ने माना देना बन्द कर दिया। उसके बाद नोटों के बढते फिरने गण निष्कास करने थे।

भारतवर्ष की स्थिति और समस्या पर महागमर का क्या असर हुआ? उस समय में परतन्त्रना के द्वारा अवस्था के निष्कास में जो सुधार और सुधार लाने का प्रयास हुआ, उसकी सम्मानना जारी रही। इन्टरनेशनल लैबर ऑर्गेनाइजेशन से मदद माँगी, और फिर हम सरकार माना माना कर दे, और सुधार लाने का प्रयास रखा गया।

इंग्लैण्ड तथा अन्य मित्र-देशों को इस समय भारतवर्ष से बहुत कुछ माल मिल सकता था और वह मिलने भी लगा ।

एक्सपोर्ट के मार्ग में कई कठिनाइयाँ थीं । जहाज कम मिलते थे, आर्थिक प्रतिबन्ध के कारण जितना माल जा सकता था, न जा पाता था । फिर भी एक्सपोर्ट में कमी नहीं हुई, बल्कि १९१६-१७ से वृद्धि ही होने लगी । दूसरी ओर बाहर से कम माल आने लगा, क्योंकि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी जैसे देशों से तो कुछ आ ही नहीं सकता था और दूसरे देशों से भी आने में कई तरह की रुकावटें थीं । फिर भी दाम ऊँचे होने के कारण जो कुछ आया उसकी कीमत महासमर के पूर्व जैसी ही बनी रही । १९१४-१५ से १९१८-१९ तक ऐसे माल का जितना इम्पोर्ट हुआ उससे हर साल प्रायः ७६ करोड़ रुपए अधिक का एक्सपोर्ट हुआ । यह कोई असाधारण बात नहीं थी, पर सोना-चादी पहले की अपेक्षा बहुत कम आई, इसलिए और देशों में हमारा पावना पहले में कहीं अधिक हो चला । लड़ाई से पहले पाँच वर्षों में यहाँ १८० करोड़ की सोना-चादी आई थी । पर इन पाँच वर्षों में कुल ५४ करोड़ की आई । सालाना औसत प्रायः ११ करोड़ बैठा ।

भारतवर्ष से ही उस समय ईराक, ईरान और पूर्व अफ्रीका में लड़ाई के खर्च के रुपए भगाए जाते थे । फौज का वेतन-आदि चुकाने, लड़ाई के सामान खरीदने और शासन-सम्बन्धी सारा व्यय चुकाने के लिए इन रुपयों की जरूरत पड़ती थी । इन रुपयों के बदले भारत-सरकार विलायत में ब्रिटिश सरकार से स्टैलिंग पाती थी । १९१४ और १९१९ के बीच इस प्रकार के खर्च का जोड़ २४०,०००,००० पीड़ हो चुका था और खर्च जारी ही था । भारतवर्ष में अमेरिका और ब्रिटिश उपनिवेशों की ओर से उन दिनों करोड़ों के माल खरीदे गए थे, इसके लिए भी खास व्यवस्था करनी पड़ी थी ।

इन सब कारणों से यहाँ करेन्सी की माग बढ़ने लगी और टकसालों में रुपयों की ढलाई जोर-शोर से होने लगी । अप्रैल १९०४ और मार्च १९०९ के बीच जब करेन्सी की माग काफी अच्छी थी, प्रायः १८०,०००,००० स्टैण्डर्ड औंस चादी के रुपए ढले थे । पर अप्रैल १९१६ और मार्च १९१९

माचं और अप्रैल १९१९ में महासमर-सम्बन्धी परिस्थिति कुछ चिन्ता-जनक हो चली जिसका नतीजा यह हुआ कि लोग नोटों को बेतहाशा भुनाने लगे। जून के पहले सप्ताह में रपए कुल प्रायः चार करोड़ रह गए थे। इस बीच में सरकार ने अमेरिका से कुछ चादी लेने की व्यवस्था कर ली थी और वह चादी अब आने भी लगी। इसके फलस्वरूप परिस्थिति में सुधार होने लगा।

सरकार नोटों के बदले रपए देने के लिए सब जगह बाध्य नहीं थी पर आम तौर में दिया करती थी। पर यह सुविधा अब न रही। रेल या स्टीमर-द्वारा सिक्के ले जाने पर प्रतिबन्ध लग गया। डाक-द्वारा भी अब कोई उन्हें कहीं न भेज सकता था। करेन्सी ऑफिसों में सरकार नोटों के बदले रपए देने को अब भी बाध्य थी। पर वहां भी अब यह विधान कर दिया गया कि एक आदमी को एक ही दिन इतने से ज्यादा रपए न मिल सकेंगे। इन प्रतिबन्धों और रुकावटों के कारण चलन में रपयों का स्थान नोट ग्रहण करते गए। पर नोटों पर ऐसी हालत में बढ़ा लगाना स्वाभाविक था। कुछ समय तक तो कहीं-कहीं यह बढ़ा १९ प्रतिशत तक रहा।

हम स्वाधीन होते और दूसरों के हाथ माल बेचते या उनके लिए कुछ खर्च करते तो हम उनसे धेवाकी स्टैलिंग—जैसे कागजी रपए में न कराके चादी या सोने में कराते। घड़ी भर के लिए यह मान ले कि हमारे देनदार चादी या मोना देने में असमर्थ होते और हम फिर भी उनके साथ कारोबार करना चाहते तो हम यह व्यवस्था कर सकते थे कि उन्हें कुछ समय के लिए अपना रपया कर्ज दे। पर हम थे पराधीन और इस पराधीनता के कारण हम दाम या भुगतान अपनी इच्छा या सुविधा नहीं बल्कि इंग्लैंड की इच्छा और सुविधा के अनुसार लेने को विवश थे। वर्षों वहां हमने जो सोना जमा कर रखा था वह तो कागज हो ही गया, अब इंग्लैंड हमसे जो कुछ लेने लगा उसका दाम भी कागज में ही चुकाने लगा। करेन्सी रिजर्व की जो शाखा लन्दन में थी उसमें स्टैलिंग के कागज रख दिए जाते और उनके मद्दे इधर नोट निकाल दिए जाते। दोनों ओर पतगवाजी थी।

महासमर छिड़ते ही प्रायः प्रत्येक देश ने सोने के निर्यात पर प्रति-

बन्ध लगा दिया। सोना बाहर जा सकता था तो उगी हातल में जब सिना सोना दिए किसी देश का काम चलनेवाला न था। १९१७-१८ में भारतार्थ में जापान और अमेरिका से कुछ सोना इस कारण आया था कि उन्हें यहाँ माल गरीबना था और उस समय भारत-सचिव से हुडी मिशन में कठिनाई थी। जब सोना दुर्लभ हो चला तब चादी की माग बढ़ी। पर चादी का उत्पादन १९१४ से ही कम होने लगा था। १९१० में १९१३ तक तमाम दुनिया की गानों में २२८,५५२,००० औंस चादी निकली थी। १९१४ में १९१७ तक तुल चादी १७८,०७५,००० औंस निकली। इस कमी का गाम कारण यह था कि मेक्सिको में राजनीति अस्थिर के कारण चादी का उत्पादन बहुत घट गया। दूसरे ब्रिटिश साम्राज्य और चीन आदि देशों की आर में माग कहीं से-कहीं उठ गई। इसका नतीजा यह हुआ कि चादी महंगी हो गई। १९१५ में जा दाम २७ पेंस था वह अगस्त १९०७ में ४३ पेंस, और एक ही महीना बाद ५५ पेंस हो चला था।

अमेरिका, कनाडा और ग्रेट ब्रिटन में चादी के दाम की घटावही को गारंटी की तुल्य गाम व्याख्या की, जिसमें चादी का दाम कुछ समय तक प्रति औंस प्राय ५५ उठकर बना रहा। मई १९१८ और अप्रैल १९१९ के बीच लन्दन में दाम ४७॥ और ५० पेंस के बीच रहा। मई १९१९ में अमेरिका और ग्रेट ब्रिटन में चादी के बाजार में अपना-अपना नियन्त्रण लगा दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि लन्दन में दाम फौरन ५८ पेंस हो गया। उसी बाद ही दाम बढ़ना ही गया और १७ दिसम्बर को ७८ पेंस तक पहुँच गया था।

बी. ए. ए. ए. में कहा गया है कि जब चादी का दाम लन्दन बाजार में २८ पेंस था तब एक रुपए की चादी की कीमत ९ पेंस में कुछ उपर जाती। इसी प्रकार जब चादी का दाम ४३ पेंस हो गया तब रुपए की चादी की कीमत १८ पेंस में गाम बढ़ गई, अर्थात् चादी उनकी महंगी हो गई तब रुपए की कीमत इसी नतीजे कीमत में गाम पहुँच गई। और इसी बाद ही दाम बढ़ने लगे और १८ पेंस में रुपए बना गया और १८ पेंस में रुपए बना गया।

वचाव के लिए सरकार ने एक्सचेंज को ऊचा करना शुरू कर दिया । २८ अगस्त १९१७ को टी० टी०^४ का दाम १६^१/_{१०} पेंस से १७ पेंस कर दिया गया । उसके कुछ ही दिन बाद यह विज्ञप्ति निकली कि भारत-सरकार के नाम हुडी की दर अब चादी के दाम पर निर्भर करेगी । १२ अप्रैल १९१९ को दर १८ पेंस कर दी गई और १३ मई १९१९ तक यही दर रही । अमेरिका ने चादी के बाजार पर से नियन्त्रण उठा लिया, इस कारण चादी और भी महंगी हो चली और स्पष्ट की एक्सचेंज-दर अब २० पेंस कर दी गई । उसके बाद ज्यों ज्यों चादी तेज होती गई यह दर ऊची होती गई । इसके मरातिव ये थे —

१२ अगस्त १९१९	२२ पेंस
१५ सितम्बर ,,	२४ पेंस
२२ नवम्बर ,,	२६ पेंस
१२ दिसम्बर ,,	२८ पेंस

३ सितम्बर १९१७ को चादी का व्यापारियों-द्वारा इम्पोर्ट बन्द कर दिया गया । एक्सपोर्ट पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया—बिना सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए कोई सोना या चादी के सिक्के इस देश से बाहर नहीं भेज सकता था ।

इम्पोर्ट रोका गया था इस उद्देश से कि जो चादी ससार में उपलब्ध थी उसका कोई हिस्सा भारतवर्ष के व्यापारियों के हाथ लगने न पावे । एक्सपोर्ट इसलिए रोका गया था कि लोग सिक्को को गला कर या यो ही बाहर भेजना न शुरू कर दें । २९ जून १९१७ के बाद तो चादी या सोने के सिक्को को और किसी काम में ले आना भी जुर्म करार दे दिया गया ।

चादी की कमी के कारण सरकार अपना सोने का स्टॉक भी बढ़ाने लगी । २९ जून १९१७ के बाद जो सोना विदेश से आता उसे मगानेवाले को सरकार के हाथ बेच देना पड़ता । अगस्त १९१९ में रॉयल मिण्ट अर्थात् ब्रिटिश टंकाल की एक शाखा बम्बई में खोली गई और वहां माँव-

* Telegraphic Transfers—तार-द्वारा की जानेवाली हुडी ।

रेन ढाँटे जाने लगे। इससे पहले कुछ ऐसी मोहरे गहा की टकसालों में छाड़ी जा चुकी थी जो प्रायः हर बात में सॉवरेन के समान थी। अप्रैल १९१९ में सॉवरेन मिण्ट की यह धारणा उठा दी गई।

ऊपर कहा जा चुका है कि महासमर छिड़ते ही सरकार ने सॉवरेन देना बन्द कर दिया था। बाजार में सॉवरेन की कीमत गढ़ चुकी और (१५) में ऊपर रहने लगी। कानूनन सॉवरेन की कीमत अब भी वही (१५) थी, और सरकार उसके बदले (१५) देने को ही बाध्य थी। सॉवरेन ऐसी ताकत में करनेवाली के काम न आ सकते थे। फिर भी रुपयों की इतनी कमी हो रही थी कि दो बार सरकार को इस देश के कुछ हिस्सों में किसानों में माल गरीबों के लिए कई करोड़ के माने के मिलने (सॉवरेन और देशी माहरे) देने पड़े।

जानि स्थापित हो जाने पर अमेरिका ने ९ जून १९१९ में मोने के एम्पाईर की स्मृत्यन्ता दे दी। दक्षिण अफ्रीका और अस्ट्रेलिया का मोना भी बाहर जाने के लिए स्मृत्यन्त हो गया। इंग्लैंड, इस देश में मोने की आपूर्ति बंद कर दी। भारतवर्ष लन्दन में और अन्यत्र भी सोना गरीबने लगा। १५ मार्च १९१८ के बाद भारत-सरकार इम्पाईर को माने का दावा इस सिद्धांत में दब लगी कि हुंरी की दर की चढ़ा-बढ़ी के अनुसार मोन की आ कीमत हो वह उसे मिल जाया करे।

अगस्त १९१९ के अन्त में भारत सरकार ने यह धारणा किया कि हर एम्पाईर उसी ओर में मोने की बिक्री की जायगी। इस बिक्री का नीति यह हुआ कि बाजार में मान का दावा फिर पड़ा। १५ अगस्त १९१९ को हम का ३२ १२ रुपए भोला। ३३ सितम्बर का दर फिर ३३ रुपए रह गया। फिर नाम में कुछ नेत्री आई और अक्टूबर में अन्त तक वह ३३ १२ रुपए रह गया। फिर कुछ ही दिन बाद वह फिर ३४ ५ रुपए रह गया। अब नाम ३३ १२ रुपए बाहर था और एक माह में ही इन्फ्लेशन ३३ ९ रुपए थी। अब नाम ३४ ५ रुपए बाहर रह गया और इन्फ्लेशन ३४ ९ रुपए हो गई।

अक्टूबर १९१९ के अन्त में भारत सरकार ने यह धारणा किया कि हर

तरह की तदवीर की, पर चादी की कमी बनी ही रही और अन्त में उसे ब्रिटिश सरकार की मार्फत अमेरिका का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अमेरिका के पास रिजर्व में बहुत कुछ चादी पड़ी हुई थी और उसने उसका एक हिस्सा भारत-सरकार को देना स्वीकार कर लिया। २३ अगस्त १९१८ को वहाँ इसके लिए पिटमैन ऐक्ट नामक विधान बना जिसका आशय था कि वहाँ की सरकार दूसरी सरकारों को इस रिजर्व में से ३५०,०००,००० चादी के डॉलर तक चादी बेच सकती है। भारत को इसमें से २००,०००,००० औंस चादी मिली जिम्का दाम प्रति औंस (घालिस चादी) १०१½ सेंट चुकाना पड़ा। यह चादी मिल जाने से भारत-सरकार का बहुत बड़ा सकट टल गया। समय-समय पर वह बाजार में भी चादी खरीदती रही। मब मिला कर उसने ५३८,००५,००० औंस (स्टैण्डर्ड) चादी खरीदी।

३० मई १९१९ को एक करेन्सी कमेटी की नियुक्ति हुई जिसके अध्यक्ष मि० बैबिंगटन स्मिथ थे और जिसके एकमात्र भारतवासी मेम्बर थे मि० दादीवा मेरवान जी दलाल। कमेटी को यह देखना था कि भारतीय प्रणाली पर महासमर का क्या असर हुआ है—उस प्रणाली में कौन से हेरफेर की जरूरत है और किस प्रकार यहाँ के 'गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड' में स्थिरत्व या स्थायित्व लाया जा सकता है। उस समय एक्सचेंज की दर २० पेंस थी।

२२ दिसम्बर १९१९ को कमेटी की रिपोर्ट तैयार हुई और भारत-सचिव के पास भेजी गई। मि० दलाल, कमेटी की रिपोर्ट से सहमत न हो सके और उन्होंने अपने विचार अलग ही एक नोट में प्रकट किए।

कमेटी की खास सिफारिश यह हुई कि रुपए की एक्सचेंज-दर सोने में बाध दी जाय और यह दर २४ पेंस (सोना) हो। इस हिसाब से साँवरेन की कीमत १५) के बजाय १०) होती। १८७३ से पहले एक्सचेंज की जो रेट थी उसे फिर से ले आने के लिए, ऊँचे एक्सचेंज के पक्षपातियों की दृष्टि में, यह अवसर अनुपम था—इसे हाथ से जाने देना परले सिरे की मूर्खता होती।

मि० दत्तगुप्त ने इस धीमाभीमी का जोरो से विरोध किया। उन्होंने आगस्टस युनियन में यह प्रमाणित कर दिया कि एससनेज की दर (१६ पग) में किसी प्रकार का परिवर्तन न होना चाहिए था।

कमेट्री ने जिम दर की सिफारिश की थी वह थी २४ पेम (गोना) । उस समय इंग्लैण्ड में सोने का स्टैंडर्ड का मान नहीं था—नोटों के बदले माना मिलना बन्द हो गया था । सोना और स्टर्लिंग दोनों दो चीज हो रही थी । एक सौ और ग्रांटिंग माना तो तो उसके ४२५ सावरेन बढे जा सकते हैं—ज्यादा यह कहना शीक होगा कि बाले जा सकते थे । पर १७ डिसेम्बर १९१५ को जा मान था उसके अनुसार एक सौ और ग्रांटिंग सोने का दाम प्राय ५४४ पाँउ स्टर्लिंग (कामजी) होता था । एक पाँउ स्टर्लिंग (कामजी) अब एक सावरेन के बराबर न होकर १११ अर्थात् ३८ सावरेन (गोना) के बराबर था । इसीको दूसरी तरफ था यह सकते हैं कि एक सावरेन (माना) अब १११ अर्थात् १.५८ पाँउ स्टर्लिंग (कामजी) के बराबर था । कमेट्री ने स्पष्ट तो स्टर्लिंग में न बाव कर मान में बाधने की सिफारिश की । २४ पेम (गोना) का अर्थ २४ पेम स्टर्लिंग नहीं, बल्कि इसका कल्ला अर्थक था ।

[illegible]

भी जरूरी था कि रुपए की एक्सचेंज-दर काफी ऊँची हो—जिससे भारतवर्ष में महंगी की भीषणता कुछ हद तक कम हो सके।

वास्तव में—जैसा कि मि० दलाल ने अपने वक्तव्य में कहा था—चादी की तेजी ही एक्सचेंज की दर में वृद्धि का एकमात्र कारण नहीं हो सकती थी, क्योंकि अधिकारियों की मंशा थी कि चादी सस्ती हो जाय तो भी एक्सचेंज १६ पैसे से काफी ऊँचा रखा जाय।

पर जो दलील दी गई थी उसका मि० दलाल के गब्दों में जवाब यह था—

“महासमर की समाप्ति हो जाने पर भी चादी के एक्सपोर्ट पर प्रतिबन्ध बना रहा। अगर यह प्रतिबन्ध हटा दिया गया होता तो चादी में इतनी तेजी न आती। भारतवर्ष आसानी से दूसरे देशों के हाथ अपनी चादी का एक हिस्सा बेच सकता था। इसका चादी के दामों पर अच्छा असर पड़ता। चादी का एक्सपोर्ट रक जाने में और जो चादी बेच सकता था उसका चादी का खरीदार बन जाने से ही इस बाजार में आग लग गई।

“अगर यह मान भी लिया जाय कि चादी का एक्सपोर्ट होने लायक न था तो भी लड़ाई के समय उसका दाम बढ़ने के कारण एक्सचेंज को उठाना मुनासिब न था। भारत-सचिव को चाहिए था कि जितने रुपए की उन्हें जरूरत होती उतने की भारत-सरकार के नाम हुण्डी करके इस काम में हाथ मीच लेते—व्यापारी अपना देना, चादी न भेजकर, और जिस तरह चुका सकते, चुकाते।

“जब तक ससार-मात्र में सोने के एक्सपोर्ट पर प्रतिबन्ध था तब तक थोड़े समय के लिए एक्सचेंज में कुछ वृद्धि शायद अनिवार्य-सी थी, पर जब अमेरिका ने ९ जून १९१९ से प्रतिबन्ध हटा लिया और दक्षिण अफ्रीका का सोना भी १८ जुलाई १९१९ से लन्दन के बाजार में बे-रोक-टोक बिकने लगा तब कोई भी कारण न हो सकता था कि एक्सचेंज की दर को २० पैसे से २८ पैसे कर दिया जाय।

“सोने और रुपए के बीच की दर जो कायम थी वह महासमर के समय उठा दी गई। पर महासमर के बाद जो कुछ किया गया वह उससे

भी जरूरी था कि रुपए की एक्सचेंज-दर काफी ऊँची हो—जिससे भारतवर्ष में महंगी की भीषणता कुछ हद तक कम हो सके।

वास्तव में—जैसा कि मि० दलाल ने अपने वक्तव्य में कहा था—चादी की तेजी ही एक्सचेंज की दर में वृद्धि का एकमात्र कारण नहीं हो सकती थी, क्योंकि अधिकारियों की मशा थी कि चादी सस्ती हो जाय तो भी एक्सचेंज १६ पैसे से काफी ऊँचा रखा जाय।

पर जो दलील दी गई थी उसका मि० दलाल के शब्दों में जवाब यह था—

“महासमर की समाप्ति हो जाने पर भी चादी के एक्सपोर्ट पर प्रतिबन्ध बना रहा। अगर यह प्रतिबन्ध हटा दिया गया होता तो चादी में इतनी तेजी न आनी। भारतवर्ष आसानी से दूसरे देशों के हाथ अपनी चादी का एक हिस्सा बेच सकता था। इसका चादी के दामों पर अच्छा असर पड़ता। चादी का एक्सपोर्ट रुक जाने में और जो चादी बेच सकता था उसका चादी का खरीदार बन जाने से ही इस बाजार में आग लग गई।

“अगर यह मान भी लिया जाय कि चादी का एक्सपोर्ट होने लायक न था तो भी लंडन के समय उसका दाम बढ़ने के कारण एक्सचेंज को उठाना मुनासिब न था। भारत-सचिव को चाहिए था कि जितने रुपए की उन्हें जरूरत होती उतने की भारत-सरकार के नाम टुण्डी करके इस काम से हाथ रींच लेते—व्यापारी अपना देना, चादी न भेजकर, और जिस तरह चुका सकते, चुकाते।

‘जब तक ससार-मात्र में सोने के एक्सपोर्ट पर प्रतिबन्ध था तब तक थोड़े समय के लिए एक्सचेंज में कुछ वृद्धि शायद अनिवार्य-सी थी, पर जब अमेरिका ने ९ जून १९१९ से प्रतिबन्ध हटा लिया और दक्षिण अफ्रीका का सोना भी १८ जुलाई १९१९ से लन्दन के बाजार में बे-रोक-टोक विक्रन लगा तब कोई भी कारण न हो सकता था कि एक्सचेंज की दर को २० पैसे से २८ पैसे कर दिया जाय।

“सोने और रुपए के बीच की दर जो कायम थी वह महासमर के समय उठा दी गई। पर महासमर के बाद जो कुछ किया गया वह उसमें

भी अनुक्ति था। शान्ति स्थापित हो जाने पर परिस्थिति बदल गई। लड़ाई के कारण गे पैमाने पर होनेवाले तरह-तरह के राशे की अब कोई जरूरत न रह गई। व्यापार के लिए रूपए की मांग अवश्य थी, पर यह मांग पूरी करने में कहीं अधिक आवश्यक यह था कि यहाँ की जनता के मुद्रा-सम्पत्ती अधिकार की रक्षा की जाय, मूल्य का जो मान या स्टैण्डर्ड कर दिया गया था उसे बरिचाल रहने दिया जाय। हर हालत में—पर चाहे कितनी व्यापार हो जाने पर—चाहिए यह कि व्यापार उस मान या स्टैण्डर्ड के पीछे चले—न कि यह कि मान या स्टैण्डर्ड ही व्यापार का अनुवर्ती बन जाय। अगर उस स्टैण्डर्ड का बदले बिना व्यापार की मांग पूरी नहीं की जा सकती थी तो मनामिच था कि यह मांग पूरी न की जाय, यह हरिज मुनामिच न था कि मांग तो पूरी की जाय और स्टैण्डर्ड का उठा दिया जाय।"

रूपए स्वयं हमारी मुद्रा-प्रणाली में, मूल्य का कोई मान न था। यह मान या स्टैण्डर्ड १६ पैस अर्थात् ७५३२८८ ग्राम सोना था। रूपए सोने की तरह उसका प्रतिनिधित्व-मान था। अगर चांदी मुद्रा हो गई थी तो सरकार को चाहिए था कि मान या माप-दण्ड का जमा-पा-पा

"मान या मापदण्ड के लिए तिन धातु का उपयोग होता था वह सोना ही नहीं थी, इसलिए मान या मापदण्ड ही बदल दिया जाय—यह प्रश्न किन्तना अनुचित था यह नीचे के उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा। तापने के मत को लीजिए। यह १६ गिरह या तीन फुट का होता है। मान लीजिए कि वहीं मत तापने के लिए रेशम का फीका काम में लाया जाय है (सोल्ड पैस के लिए एक रुपए की तरह)। अर्थात् रेशम मिला हो गया और मत के लिए उसका उपयोग असम्भव है। धूर्ती वशा में कोई शर्त क्या करायें? अवश्य ही रेशम की जगह यह और किसी धातु का उपयोग करना पड़ेगा जो रेशम से मजबूत हो। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हम रेशम का निरन्तर उपयोग करनी हैं और उसमें रेशम की जगह धातु के धातु की जगह न देकर यह प्राप्ति दे दी कि १९ पैस के बजाय अब २८ पैस का मत मत समझा जायगा। धूर्ती प्राप्ति

रखते हुए, रुपए में चादी का परिमाण कम कर देती या नए रुपए ढालती ही नहीं। कई व्यक्तियों और सस्थाओं ने उस समय यह प्रस्ताव किया था कि दो या तीन रुपए के ऐसे सिक्के निकाले जाय जिनमें चादी का परिमाण फी रुपया १६५ ग्रेन के हिसाब से न होकर इतना कम हो कि चादी का दाम काफी ऊँचा होते हुए भी रुपयों के चलन से निकल जाने का कोई खतरा न रहे। दरअसल नए रुपए ढालने की कोई ऐसी जरूरत ही न थी। व्यापारियों पर ही यह जिम्मेवारी छोड़ देनी चाहिए थी कि अपना देना चुकाने के लिए उन्हें जो व्यवस्था उत्तम जचती, करते।

पूछा जा सकता है कि व्यापारी आखिर क्या करते ? उत्तर यह है कि इंग्लैण्ड को अगर हमारे माल की जरूरत थी तो वह हम सोना देता—सास कर जब शान्ति स्थापित हो गई और कई देशों में सोने को बाहर जाने की स्वतन्त्रता मिल गई—या इंग्लैण्ड हमसे कर्ज लेता। इसके बजाय किया यह गया कि हमारा स्टैंडर्ड बदल दिया गया—एकमचेज की जो ऊँची-से-ऊँची दर उस समय हो सकती थी, कायम कर दी गई—नोटों की छूट कर दी गई और नोटों की पुष्टी के लिए लन्दन में ब्रिटिश 'ट्रेजरी बिलों' के रूप में स्टैलिंग कागज रखे जाने लगे। इन ट्रेजरी बिलों के द्वारा भी ब्रिटिश सरकार ने हमसे कर्ज लिया, पर यह कर्ज ऐसा न था जिसे हमने अपनी खुशी या रजामन्दी से दिया हो। यह तो हमसे जबरन लिया हुआ कर्ज था—और जिस समय बैबिगटन स्मिथ कमेटी की रिपोर्ट तैयार हुई उस समय यह कर्ज ८३ करोड़ रुपए से ऊपर हो चला था।

या विधान का एक फल यह होगा कि जो किसीको एक गज देने के लिए बाध्य है उसे १६ फी जगह अब २४ अगुल नाप कर देना होगा। एक्सचेंज-रेट बढ़ा देने का नतीजा भी ठीक ऐसा ही हुआ। पहले जो किसीको १) देने को बाध्य था उसे अब ७ ५३३४४ ग्रेन की जगह ११ ३००१६ ग्रेन सोना (या इसी हिसाब से अपने खेत की उपज) देना पड़ा। कारण कि रुपया-रूपी गज अब १६ फी जगह २४ अगुल की नाप या स्टैंडर्ड बन गया था।

भी अनुचित था। जाल्ति स्थापित हो जाने पर परिस्थिति बदल गई। लड़ाई के कारण नये पैमाने पर होनेवाले तरह-तरह के सर्च की अब कोई जरूरत न रह गई। व्यापार के लिए रुपए की मांग आवश्यक थी, पर यह मांग पूरी करने में कहीं अधिक आवश्यक यह था कि यहाँ की जनता के मुद्रा-सम्बन्धी भ्रमों का हटाना हो सके। मूल्य का जो मान या स्टैण्डर्ड कर दिया गया था उसे अविच्छेद रहने दिया जाय। हर हाथत में—पर लाभ कर जाल्ति स्थापित हो जाने पर—चाहिए यह कि व्यापार उस मान या स्टैण्डर्ड के पीछे चले—न कि यह कि मान या स्टैण्डर्ड ही व्यापार का अनुवर्ती बन जाय। अगर उस स्टैण्डर्ड का बदलने बिना व्यापार की मांग पूरी नहीं की जा सकती थी तो मनागिये या कि वह मांग पूरी न की जाय, यह हीमज मुनागिया न या कि मांग तो पूरी की जाय और स्टैण्डर्ड को उठा दिया जाय।*

रुपया रुपए हमारी मुद्रा-प्रणाली में, मूल्य का कोई मान न था। यह मान या स्टैण्डर्ड १६ पग अर्थात् ७५३२४४ ग्रेन मिला था। रुपया कागजी नोट की तरह उसका प्रतिनिधि-मात्र था। अगर चाही महगी हो गई थी तो सरकार या चाहिए था कि मान या माप-दण्ड को उठाया-जाल्या।

* मान या मापदण्ड के लिए जिस धातु का उपयोग होता था वह महगी हो रही थी, इसलिए मान या मापदण्ड ही बदल दिया जाय—यह प्रस्ताव कितना अनुचित था यह नीचे के उदाहरण में स्पष्ट हो जाएगा। नापने के मात्र को खोजिए। यह १६ गिन्ट या तीन फुट का होता है। मान लीजिए कि कहीं मात्र नापने के लिए रेडम का पीला काम में लाया जाता है (माल्टा पत्र के लिए एक रुपए की तरह)। अचानक रेडम महंगा हो गया और मात्र के लिए उसका उपयोग असम्भव है। ऐसी वजह से क्या क्या होगा ? अरुण ही रेडम की जगह पर और किसी धातु की उपयोग करने लगेंगे जो रेडम से महंगा हो। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इस शिष्ट के नियंत्रण सरकार करती है और उसने रेडम की जगह सोने के धातु की जगह न करे यह आज्ञा दे दी है १९ प्रमुख के बजाय अब २६ प्रमुख का एक मात्र सम्भव जायगा। ऐसी वजह

रखते हुए, रुपए में चादी का परिमाण कम कर देती या नए रुपए ढालती ही नहीं। कई व्यक्तियों और संस्थाओं ने उस समय यह प्रस्ताव किया था कि दो या तीन रुपए के ऐसे सिक्के निकाले जाय जिनमें चादी का परिमाण फी रुपया १६५ ग्रेन के हिसाब से न होकर इतना कम हो कि चादी का दाम काफी ऊँचा होते हुए भी रुपयों के चलन से निकल जाने का कोई खतरा न रहे। दरअसल नए रुपए ढालने की कोई ऐसी जरूरत ही न थी। व्यापारियों पर ही यह जिम्मेवारी छोड़ देनी चाहिए थी कि अपना देना चुकाने के लिए उन्हें जो व्यवस्था उत्तम जचती, करते।

पूछा जा सकता है कि व्यापारी आखिर क्या करते ? उत्तर यह है कि इंग्लैण्ड को अगर हमारे माल की जरूरत थी तो वह हमें सोना देता—खास कर जब शान्ति स्थापित हो गई और कई देशों में सोने को बाहर जाने की स्वतन्त्रता मिल गई—या इंग्लैण्ड हमसे कर्ज लेता। इसके वजाय किया यह गया कि हमारा स्टैंडर्ड बदल दिया गया—एक्सचेंज की जो ऊँची-मे-ऊँची दर उस समय हो सकती थी, कायम कर दी गई—नोटों की छूट कर दी गई और नोटों की पुष्टी के लिए लन्दन में ब्रिटिश 'ट्रेजरी बिलो' के रूप में स्टॉर्लिंग कागज रखे जाने लगे। इन ट्रेजरी बिलों के द्वारा भी ब्रिटिश सरकार ने हमसे कर्ज लिया, पर यह कर्ज ऐमा न था जिसे हमने अपनी खुशी या रजामन्दी से दिया हो। यह तो हमसे जबरन लिया हुआ कर्ज था—और जिस समय वैबिगटन स्मिथ कमेटी की रिपोर्ट तैयार हुई उस समय यह कर्ज ८३ करोड़ रुपए से ऊपर हो चला था।

या विधान का एक फल यह होगा कि जो किसीको एक गज देने के लिए बाध्य है उसे १६ की जगह अब २४ अंगुल नाप कर देना होगा। एक्सचेंज-रेट बढ़ा देने का नतीजा भी ठीक ऐसा ही हुआ। पहले जो किसीको १) देने को बाध्य था उसे अब ७ ५३३४४ ग्रेन की जगह ११.३००१६ ग्रेन सोना (या इसी हिसाब से अपने खेत की उपज) देना पड़ा। कारण कि रुपया-रूपी गज अब १६ की जगह २४ अंगुल की नाप या स्टैंडर्ड बन गया था।

साँवरेन (गिनी) ढालने की व्यवस्था की जाय। सरकार यह घोषित कर दे कि जो कोई सोना लावेगा उसे नई एक्मचेज-दर से—अर्थात् एक रुपया = ११.३००१६ ग्रेन खालिस मोना के हिसाब से साँवरेन मिल सकेंगे।

(५) चादी की कमी और महगी के कारण सरकार के लिए अब साँवरेन के बदले रुपए देना आवश्यक न रहे।

(६) साँवरेन की कीमत अब १५) के बजाय १०) होगी, इसलिए सरकार यह घोषित कर दे कि अमुक तिथि तक जो कोई साँवरेन लाकर देगा उसे फी साँवरेन १५) मिल जायगा। यही बात मोहर के सम्बन्ध में भी रहे, और कुछ समय बाद चलन से मोहर उठा दी जाय।

(७) चादी के इम्पोर्ट पर जो प्रतिबन्ध है वह यथासम्भव शीघ्र हटा दिया जाय।

(८) एक्सपोर्ट-सम्बन्धी प्रतिबन्ध अभी कुछ समय के लिए बना रहे।

(९) चादी खरीदने की जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार के हेर-फेर की हम भिफारिण नहीं करते।

(१०) करेन्सी रिजर्व का जो हिस्सा कागज के रूप में रखा जा सकता है वह कुछ समय के लिए १२० करोड़ बना रहे।

(११) करेन्सी रिजर्व में जितना सोना या स्टर्लिंग* है उसकी नई कीमत २४ पेंस की दर से ठहराई जाय। ऐसा करने से रिजर्व में ३८४ करोड़ की कमी होगी। यह कमी धीरे-धीरे पूरी कर दी जायगी।

(१२) करेन्सी रिजर्व की जो सोना-चादी हो वह इसी देश में रखी जाय। बाहर उमी हालत में रह सकती है जब यहाँ आनेवाली हो या आ रही हो।

(१३) नोट भुनाने के लिए जो सुविधाएँ सर्वसाधारण को पहले प्राप्त थी वे स्थिति सुधरते ही फिर से जारी कर दी जाय। सरकार को यह अधिकार हो कि वह नोटों के बदले चादी या सोने के सिक्के दे सके।

(१४) सरकार को जो सोना प्राप्त हो सके वह फिलहाल गोल्ड

* इसके लिए सोना और स्टर्लिंग समान माने गए।

स्टैंडर्ड रिजर्व में न रखा कर पेपर-करेन्सी रिजर्व में रखा जाय। जन ऐसा करना सम्भव हो तब मोन्ट स्टैंडर्ड रिजर्व में भी काफी सोना रखने की आवश्यकता की जाय, पर इस समय तो सब में सन्तोषजनक व्यवस्था नहीं हो पायी है कि उस रिजर्व को ऐसी सिक्कस्टीज के रूप में रखा जाय जिसे भीयाद छोटे ही समय में पूरी होनेवाली हो।

(१५) मोन्ट स्टैंडर्ड रिजर्व के सारे का अतिरिक्त-अधिक आरक्षित भाग्यपूर्ण में रखा जाय, पर सर्वसाधारण को वह सिक्के निर्गता में ही मिल सकें।

कमिटी ने बहुमत में जो सिफारिश की थी उसे भारत-मन्त्रिमण्डल ने मंजूर कर दिया। फरवरी १९२० में सरकारी विज्ञप्ति निकलने से पता चलता है कि दर २८ पस (स्टर्लिंग) से ३०१ पस (स्टर्लिंग) हो चली। यह नई दर २८ पस (गोना) के आसपास थी। पर बाजारवाला ही दरानी जैसी दर के रहने का विज्वाय न हो सका और उसी क्षण में स्टर्लिंग की माग होने लगी। तबसे यह था कि पहले रुपयों के बदले ऐसी ही दर से स्टर्लिंग के दिया जाय, फिर आवश्यक मित्त पर उसी स्टर्लिंग में अतिरिक्त रुपय बना दिए जाय। सरकार स्टर्लिंग की माग पूरी करने के लिए, फरवरी की सिफारिश के अनुसार उल्टी दुकानें खोलने लगी। इससे सब जानते हैं कि सरकारी कीमतें १०) कर ही गई और लागू उस दर से दिन-दिन ही बाध्य कर दिए गए।

स्टर्लिंग की माग जानी गाय थी कि सरकार के लिए उसे पूरा करना असम्भव था। उस नई मलाई की गई कि वह माग पूरी करने में प्रयत्न हो जाय और भारत-मन्त्रिमण्डल का जो मन लक्ष्य में था उसे पूरा कर लिया। पर सरकार ने पूरा न मनी और उल्टी दुकानें खोल दी गई। उस दर से २८ पस (गोना) वाली दर कायम न हो सकी वह बढ़ाया गया ३० पस २८ पस स्टर्लिंग पर पचास के रहने की थी।

३० नवम्बर १९१९ को रिजर्व ३९,६३८,३१३ पौंड स्टर्लिंग का जिसमें ३९,६११,५०६ पौंड स्टर्लिंग सिक्कस्टीज के रूप में था।

करने लगी। यह नीति-परिवर्तन २४ जून १९२० से किया गया। पर इसमें भी उसे सफलता नहीं मिली और अन्त में हार मान कर उसने २८ सितम्बर को उलटी हुण्डी बेचना बन्द कर दिया।

स्टर्लिंग की माग अपरिमित-सी थी, और वह माग पूरी करने की सरकार की शक्ति अत्यन्त परिमित। ऐसी दशा में एक्सचेंज का गिरना स्वाभाविक था। जो दर १ जनवरी १९२० को २७½ पेंस स्टर्लिंग थी वह १ अगस्त १९२० को २२½ पेंस स्टर्लिंग हो चली थी। उसके बाद भी दर क्रमशः गिरती ही गई।

१९१९-२० और १९२०-२१ में सब मिलाकर सरकार ने ५५,५३२,००० पौंड स्टर्लिंग की उलटी हुण्डिया बेची। सरकार को इसके बदले यहाँ ४७ करोड़ १४ लाख रुपए मिले। अगर पुरानी दर १६ पेंस रहती तो इतने रुपयों के बदले सरकार को कुल ३१,४२६,६६६ पौंड स्टर्लिंग बेचना पड़ता। इससे स्पष्ट है कि २४ पेंसवाली दर को कायम करने के प्रयत्न में सरकार ने २४,०००,००० पौंड स्टर्लिंग से अधिक गवा दिया। यह धन भारतवासियों का था, जिसे सरकार ने उनके हानि-लाभ की तनिक भी परवा न कर बात-की-बात में लुटा दिया। पुरानी दर से २४,०००,००० पौंड स्टर्लिंग के ३६ करोड़ रुपए हुए।

स्टर्लिंग के लिए जो इतनी बड़ी माग पैदा हो गई वह इस नई ऊँची दर के कारण ही। इसलिए यद्यपि यह कहा गया है कि उलटी हुण्डियों की बिक्री से प्रायः ३६ करोड़ की हानि हुई तथापि यह भी ध्यान में रखने की बात है कि अगर यह ऊँची दर सरकार-द्वारा स्वीकृत न होती तो स्टर्लिंग के लिए जो कृत्रिम माग पैदा हो गई वह न होती और लन्दन में जो हमारा स्टर्लिंग धन था वह इस प्रकार हवा न हो जाता।

१९१९-२० में यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत ही बड़े पैमाने पर हुआ। सोने-चादी को छोड़ बाकी चीजों के इम्पोर्ट से एक्सपोर्ट प्रायः १२६ करोड़ रुपए अधिक का हुआ। पर स्थिति पलटते देर न लगी। १९२०-२१ में एक्सपोर्ट तो ३२७ करोड़ से २५८ करोड़ और इम्पोर्ट २०१ करोड़ से ३३६ करोड़ हो चला। १९२१-२२ में भी ऐसी ही अवस्था रही। जिस समय एक्सचेंज

की दर २४ पस की जा रही थी उस समय इसके विरोधियों ने कहा था कि इस उन्नी दर का परिणाम यह होगा कि एक्सपोर्ट कम हो जाये और इम्पोर्ट १८ जायग—और सम्भवत एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट का पतन भारी हो जायगा। ठीक यही हुआ। जून १९२० से ही यह पतन भारी दान लगा और दोनों वर्षों के अको को मिला कर एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट का पतन प्रायः ९९ करोड़ रुपय भारी रहा। म्युनि में इस विप्लव की बहुत बड़ी जिम्मेवारी एमचज की नई दर पर थी। सर वेदव्यास शिराड अपनी India (Old and New (भारत—प्राचीन और नवान) नामक पुस्तक में लिखते हैं —

“वैचारिक गम्य कमिटी की सिफारिश का भारत-सचिव ने स्वीकार कर दिया और फरवरी १९२० में नई दूर का कायम करने के लिए उपाय द्या। यद्यपि, हालांकि जनवरी में ही उस नाम का समूह मिल गया था कि जातिगत मान की गति भारतवर्ष के प्रतिष्ठित ज्ञान लगी थी। यद्यपि सामान्य रूप से जातिगत मान ज्ञान जा रही थी। कमिटी में उसके प्रस्ताव विचारों के अन्तर्गत बाजार के पारसी व्यापारी मि० मेरदान जी दशरथ के नेतृत्व में समय का व्यावहारिक ज्ञान शायद कमिटी के सचिव मद्रास में स्वीकृत था। उन्होंने सिफारिश की थी कि पुरानी प्रथा के अनुसार ज्ञान जा रहा हो। यद्यपि यद्यपि प्रमाणित ज्ञानवादी भी हैं जिनका यह कहना उचित नहीं है कि दूरदर्शिता में पूर्ण था।”

[illegible][illegible]

ने देखा कि यह मौदा उसको बेतरह मटगा पड़ने जा रहा था । वम, उमने माल छुडाने मे ही इनकार कर दिया, वयोकि माल छुडाने का अर्थ था उसका सर्वनाश । उससे यह कहना कि व्यापारी को अपना कौल-करार जरूर पूरा करना चाहिए, विलगुल व्यर्थ था, वह इसका उत्तर यह देता कि इस विषय मे सरकार ही अपना उदाहरण मवके सामने रख चुकी थी—उसने भी एक तरह का कौल-करार किया था कि वह स्पष्ट की कीमत दो शिलिंग कर देगी और उसने अपने वचन की रक्षा न हो सकी थी । सरकार की ओर से कहा गया कि उसने कोई कौल-करार नहीं किया था, पर भारतीय व्यापारी की ओर मे इसका जवाब यह दिया गया कि अब तक तो सरकार की बात को लोग इसी प्रकार का महत्व देते आ रहे थे—यहा तो यही समझा जाता था कि उसने जो कुछ कह दिया उमे वह पूरा करके ही रहेगी ।”

सर वैंलण्टाइन शिरोल भारतीय आकाशगो के और भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के विरोधी और निन्दक थे, इसलिए उनका ऐसा लिखना विरोधपूर्ण है ।

उल्टी हुडियो की बिक्री-द्वारा जो परिस्थिति पैदा की गई उसे उस समय 'लूटपाट' कहा गया था । इसकी सार्थकता समझने के लिए कुछ बातें ध्यान मे रखने की है । लन्दन मे हमारा जो धन संचित था वह १६ पेंस या उससे कुछ ऊँची दर के हिसाब मे—अर्थात् जब हमने १५) का माल बेचा तब हमे लन्दन मे एक पीड स्टलिंग या उमने कुछ अधिक स्वीकार करना पडा । पर जब दर २४ पेस (मोना) कर दी गई और उसे ठहराने के लिए उल्टी हुडिया बेची जाने लगी तब एक पीड स्टलिंग ७) मे ही मिलने लगा* । १५) की दर से हमने लन्दन मे जो कुछ जमा किया था उसे

* स्टलिंग में उल्टी हुडियो की दर २७ $\frac{1}{2}$ पेंस से ३४ $\frac{1}{2}$ पेंस तक थी । स्टलिंग सोने की अपेक्षा सस्ता था, इसलिए (२४ पेंस सोना) ३४ $\frac{1}{2}$ पेंस (स्टलिंग) होता था । ३४ $\frac{1}{2}$ पेन्स के हिसाब से एक पीड स्टलिंग प्राय ७) का हुआ ।

७) की दर से हमें छोड़ना पड़ा। यह छूट-गसोट नहीं तो और क्या था ?

इस छूट-गसोट के लिए दोषी कहा तक भारत-सचिव थे और कहां तक भारत-सरकार, इसका स्पष्टीकरण न हो सका। जनता की आर से कई बार यह मांग पेश की गई कि सरकार इस सम्बन्ध में भुगतें हुए पना और तारों को प्रकाशित करें। पर उसने ऐसा नहीं किया। अनुमान—जिसकी पुष्टि उतिहास से होती है—यही है कि जो कुछ हुआ, भारत सचिव की पेरणा और दवाव से।

२८ गिनम्बर १९२० के बाद उल्टी हुईयो की बिन्ती तो मन्द हो गई, पर तानूनन दर २४ पम (गोना) ही बनी रही—अर्थात् एक मार्गरेन के बड़े सरकार के ल १०) देने को बाध्य थी। एम्माचज गिर जाने के कारण मार्गरेन की वास्तविक कीमत उससे कहीं ज्यादा थी, और एसी राज्य म मार्गरेन करन्गी के काम न आ सकत थे।

सरकार स्पष्ट देकर बड़े से स्टन्डिंग दे रही थी। इसका अर्थ यह हुआ कि चक्र में रुपए या नोट निकले जा रहे थे। १ फरवरी और १५ गिनम्बर १९२० के बीच उल्टी हुईया की बिन्ती के फलस्वरूप लोग ता चक्र १८५ करोड़ रुपए में घट कर १५० करोड़ रुपए हो गया था। इसी अर्थ में रुपए के चक्र में भी कमी आई थी। गिनाबला सरकार के लिए मर मरना था कि रुपया की कमी करके पड़ना। तर्क दर का जो चार्टी, कर दिया। पर व्यवहार में एसी कभी करना उस समय सरकार के योग्य नहीं था। नतीजा यह हुआ कि इस दर का न उद्देश्य मिला।

पर १५ नो १९, रुपए बाजार का मय मरी जाता रहा कि रुपए का १८५ करोड़ रुपए की दर मर दिया जाय, और १८५ के लिए अलार्म मर दिया जाय। १८५ करोड़ रुपए के दर के लिए।

हो कि इतनी सिक्कूरिटीज तो स्टर्लिंग में रहे और इतनी रुपए में । इस विधान में दूसरे ऐक्ट द्वारा और भी हेर-फेर किए गए । रिजर्व में जो सिक्कूरिटीज और सोना था उनकी कीमत नई दर से लगाई गई । एक सॉवरेन पहले १५) के नोट की पुष्टी करता था, अब १०) के नोट की पुष्टी करने लगा । इस कारण रिजर्व में कुछ कमी पड़ी, जिसकी पूर्ति भारत-सरकार ने अपने कागज रिजर्व को देकर कर दी ।

१८ पैस का रुपया

जिस समय उल्टी दुजिया की बिभी जर हुई (फरवरी १९२०) पास जमीनसमय में चांदी का भाव गिरना लगा। उस समय दाग ८२ और ८९॥ पास में नीचे था, पर मितम्बर १९२० तक ५५^१ और ६०^१ पास में नीचे आ जाता था। उसके बाद चांदी के दाग भा रहा —

	ऊने-मे-ऊचा	नीचे-मे-नीचा
	पास	पास
जारी १९२०	४२ ^१	३५ ^१
मितम्बर "	३५ ^१	३४ ^१
१९२२	३५ ^१	३० ^१
१९२५	३३ ^१	२० ^१
१९२७	३१ ^१	३१ ^१
१९२९	२९ ^१	३१ ^१

पासों में ही पास गल रहा —

	उरी पास	गाल
	पास	पास
१९२२	१५ ^१	१० ^१
१९२५	१५ ^१	११ ^१
१९२७	१५ ^१	१५ ^१
१९२९	१५ ^१	१५ ^१
१९३०	१८ ^१	१५ ^१

उसके बाद चांदी के दाग भा रहा —

मे फिर सोने के मान या स्टैण्डर्ड की प्रतिष्ठा हो गई। उसके बाद स्टैलिंग और सोने में मन्थ-सम्बन्धी एकता हो चली।

१ अगस्त १९२१ का रुपए की एक्सचेंज-दर स्टैलिंग में १५ $\frac{1}{2}$ पेंस और सोने में ११ $\frac{1}{4}$ पेंस थी। पर कानूनन दर वही २४ पेंस (सोना) थी—अर्थात् सरकार एक साँवरेन के बदले १०) से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। जाहिरा तौर पर वह रुपचाप बैठी हुई थी, कुछ नहीं कर रही थी, पर असलियत में उसने अपनी इस नीति-द्वारा नई करेन्सी की पैदाइश को रोक रखा था। उद्देश था धीरे-धीरे रुपए को महंगा करके उसके मूल्य में मनमानी वृद्धि करना। अनुकूल परिस्थिति का अर्थ था रुपए का ऐसा अभाव कि लोग उसकी कीमत ज्यादा देने को मजबूर हो जाय। कुछ न करके सरकार वास्तव में ऐसे अभाव को प्रकृत या यथार्थ करना चाहती थी।

२४ जनवरी १९२२ को व्यवस्थापिका परिषद् में सर विट्ठलदास ठाकरसी ने इस आणय का एक प्रस्ताव उपस्थित किया कि—

“एक ऐसी कमेटी नियुक्त की जाय जिसके अधिकांश मेम्बर भारत-वासी हो और जो निम्नलिखित विषयों पर विचार करे —

- (१) करेन्सी और एक्सचेंज-सम्बन्धी वर्तमान नीति,
- (२) भारतीय टकसालों में सोने के सिक्कों की अवाधित ढलाई,
- (३) गोल्ड स्टैण्डर्ड रिजर्व को लन्दन से हटा कर भारतवर्ष में रखने की आवश्यकता।”

उस समय तक दाम काफी गिर चुके थे। कपास, पाट, चाय, लोहा, प्रायः सभी चीजों के दाम नीचे हो रहे थे। अगर १९१३ के दाम को १०० मान लें तो फरवरी १९२० में दाम इस प्रकार थे —

ग्रेट ब्रिटेन ३०३

अमेरिका २३२

और ये दाम गिर कर जनवरी १९२२ में क्रमशः १५९ और १३८ हो गए थे।

भारतवर्ष में जुलाई १९१४ का दाम १०० माना जाय तो १९२०

का ओगल २०४ बैठता था और १९२१ का १८१ होता था। जनवरी १९२० मयरा के दाम का 'इण्डेस नम्बर'—अर्थात् 'सूचक अंक' १७८ था।

चादी की बान ऊपर कही जा चुकी है। वैविग्टन स्मिथ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि —

“अगर लाभा के विश्वास के प्रतिकूल, मगार में चीजों के दाम तेजी से गिर पड़े तो यह उल्ट-फेर कर देनेवाली एक नई बान होगी। इस हालत में हो सकता है कि भारतवर्ष में मजूरी आदि इसी हिमाय में न गिरे और भारतवर्ष में एमपाई इतना कम हो कि जिस एमपाई-रर की हम लोग सिफारिश कर रहे हैं उसे लागू रखना असम्भव हो जाय। अगर परिस्थिति सचमुच ऐसी हो जाय तो हम विषय पर नए गिरे से विचार करना और तत्सम्बन्ध कार्य करना आवश्यक होगा।”

मगर रिपोर्ट समझा कहता था कि परिस्थिति इस समय सचमुच ऐसी ही हो रही थी, इसलिए आवश्यक था कि मारे विषय पर फिर से विचार लिया जाय और २६ मयचादी फरजी दर के कारण व्यापारियों का जो दुःख था किना हो रही थी उसका अन्त कर दिया जाय।

पर सरकार की आर में यही उत्तर मिला कि अभी कुछ भी करना ठीक न होगा—अभी कुछ और ठहराए और देखिए कि स्थिति कैसी होगी है।

२० जनवरी १९२० में भारत-मार्ग ने भारत-सरकार पर दृष्टि करना बन्द कर दिया। तीन मास तक उन दृष्टियों की निरी बन्द रही। जब मार्च १-१९२० मय स्ट्रिकिंग हो चली तब फिर दृष्टियाँ बिखरने लगीं। इस बीच में भारत-मार्ग ने अपना काम क्रिस्टिय सरकार में भारत-सरकार का एमपाई मारुद कर और इन्फ्लेक्शन के रजिस्टर चलाये रहे। इस मयचादी बन्द में मार्ग बहुत खराब था। १९१८-१९ और १९२०-२१ के बीच प्रायः ०८ बन्दों का दे दे रहा। हमारे मई नमूने थे—मासिक आय में वृद्धि, १९१९ में २०००० रु० की और मार्च १९२१ २६ मय (माना) कम में २२०००० रु० की। सरकार ने इन्फ्लेक्शन के रजिस्टर में दर्ज करने देना पड़ा, जो उस प्रकार था —

१९२१-२२ में	१७,५००,०००	पौंड	स्टर्लिंग
१९२२-२३ में	३२,५००,०००	"	"
१९२३-२४ में	२०,०००,०००	"	"

सरकारी दर २४ पेंस सोना होने के कारण नई करेन्सी की पैदाइश बन्द थी ही, उधर सरकारी नीति के कारण जो करेन्सी मौजूद थी उसका भी सकोच हो रहा था। यह सकोच कई प्रकार से किया जा सकता था। जब रुपया चलन में जाता है तब करेन्सी का विस्तार होता है, जब रुपया चलन से खिच कर सरकारी खजाने या रिजर्व में पहुँच जाता है तब करेन्सी का सकोच होता है। जब भारत-मन्त्रि भारत-सरकार के नाम हुडिया बेचते और यहाँ उन हुडियो के भुगतान के लिए रुपए दिए जाते तब करेन्सी का विस्तार होता। इसके विपरीत जब भारत-सरकार लोगों से रुपए लेकर उलटी हुडिया बेचती तब करेन्सी का सकोच होता। १ जनवरी १९२० और ३१ अगस्त १९२४ के बीच इस प्रकार प्रायः ४५॥ करोड़ रुपए का सकोच हुआ। इसी तरह जब सरकार कर्ज लेती तो करेन्सी का सकोच होता, और जब कर्ज चुकाती तब करेन्सी का विस्तार।

सरकार की नीति कुछ हद तक सफल हो चली और सितम्बर १९२४ में एक्सचेंज-दर १६ पेंस (सोना) पर आ गई। सरपुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने उस समय व्यवस्थापिका परिषद् में दो बिल पेश कर यह विधान कराना चाहा कि स्थायी रूप से एक्सचेंज १६ पेंस (सोना) कर दिया जाय। पर इन बिलों पर परिषद् में विचार न हो सका। इस समय अर्थ-सदस्य सर बेसिल ब्लैकेट थे। उन्होंने सरकारी नीति का स्पष्टीकरण करते हुए १९ सितम्बर को कहा कि —

“ऐसे समय में जब कि हॉलैण्ड, स्विटजरलैण्ड और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी स्टर्लिंग की गति के विषय में कुछ और निश्चयपूर्वक जाने बिना सोने के मान या स्टैंडर्ड की स्थापना को अपने लिए जोखिम का काम समझते हैं, भारत-सरकार रुपए की एक्सचेंज-दर को सोने में अभी निश्चित कर देना भारतवर्ष के लिए हितकर नहीं समझती।”

वात यह थी कि सरकार की नीयत १६ पेंस (सोना) से ऊँची दर करने

मोने का मान या स्टैंडर्ड फिर स्थापित हो जाय तब रुपए की एक्सचेंज-दर भी बराबर के लिए १८ पेंस मोना हो चले । भारत-सचिव एतने से ही सन्तुष्ट नहीं थे । वह १८ पेंस (मोना) में भी ऊँची दर के इच्छुक थे । पर भारत-सरकार को वस्तुस्थिति का जैसा ज्ञान था वैसा उनको नहीं । सरकार जानती थी कि अगर इससे भी ऊँची दर के लिए प्रयत्न किया गया तो यहाँ ऐसी भय-कर स्थिति पैदा हो जायगी जिसे सभालना संभवन उनके लिए असंभव हो जायगा । ८ अक्टूबर १९२४ को उसने भारत-सचिव को तार दिया—

“अब आम तौर से लोग यह समझने लगे हैं कि बाजार में रुपए की जो तगड़ी है वह सरकार के करेन्सी का संकोच करने या उसके विस्तार को रोक देने का फल है ।”

उसी तार में यह भी कहा गया था कि “अगर हम पेंस जड़ते ही गए और रुपए की तगड़ी बढ़ती ही गई तो आर्थिक संकट उपस्थित होने का खतरा उत्तरा है ।”

फिर भी भारत-सचिव की राय न बदली—वह यही चाहते रहे कि एक्सचेंज की ऊपरी हद न बांधी जाय । हा, वह इतना करने को राजी हुए कि किमी एक हफ्ते में ६ पेंसी से अधिक एक्सचेंज को न उठने दिया जाय ।

११ अक्टूबर को भारत-सरकार ने फिर तार दिया—

“भारत के हित को, और भविष्य में अपनी आर्थिक जिम्मेवारी को, देखते हुए हम समझते हैं कि १८ पेंस से ऊँची दर मनासिव न होगी ।”

उसने जिस नीति का समर्थन किया वह उसीके शब्दों में यह थी —

“अपने मन में हम यह निश्चित कर ले कि रुपए की एक्सचेंज-दर १८ पेंस स्टैलिंग की जायगी, और तब तक कुछ न करे जब तक स्टैलिंग और मोना इन दोनों का मूल्य एक नहीं हो जाता ।”

उस समय सारे विषय पर एक नए करेन्सी कमीशन द्वारा विचार होने जा रहा था । रेट के सम्बन्ध में केवल विचार का अभिनय होनेवाला था, क्योंकि विचार तो सरकार पहले ही कर चुकी थी, और होना बही था जो उसे मजूर था । भारत-सचिव तो और भी ऊँची दर चाहते थे, इसलिए भारत-सरकार की नीति के सम्बन्ध में उन्होंने उसे व्यंग-पूर्वक लिखा

बहुमत ने एक्सचेंज के सम्बन्ध में वही राय दी जिसकी उससे आशा की जा सकती थी—यह कि एक्सचेंज को १८ पेंस पर टिका दिया जाय। उसकी दासदलील यह थी कि इस दर को कायम हुए इतना समय हो चुका—देश में चीजों के दाम और मजूरी का इससे बहुत कुछ मिलान हो चुका है—अब इसको हटाकर दूसरी दर कायम करने से बड़ी गड़बड़ी होगी। पाठकों को याद होगा कि फीलर कमेटी ने १६ पेंस के पक्ष में भी ऐसी ही बातें कही थी। १६ पेंस की तरह १८ पेंस भी कृत्रिम ढंग से पैदा किया गया और कुछ महीनों के लिए टिकाया गया। फिर एक करेन्सी कमीशन ने आकर यह कहा कि जो चीज जमी हुई है उसे उखाड़ने की सलाह हम दे ही कैसे सकते हैं।

मिलानवाली दलील यह है कि एक्सचेंज उठने से दाम गिरते हैं, मजूरी सस्ती हो जाती है—और किसान-जैसे उत्पादक को जहां अपना गल्ला बेचने पर कम रूपया मिलता है वहां साथ ही और चीजें सस्ती होने के कारण उसका खर्च भी कम पड़ता है—इसलिए वह अन्त में न नफे में रहता है, न घाटे में। एक्सचेंज की घटावड़ी थोड़े समय के लिए किसीको लाभ पहुंचा सकती है, और किसीको हानि। पर अन्त में सब चीजों का उससे मिलान हो जाता है और यह मिलान हो जाने पर हानि-लाभ का प्रश्न ही जाता रहता है। लेना-देना समान हो गया, किसीकी स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ा।

बात ठीक-सी जचती है, पर इस सम्बन्ध में कई प्रश्न किए जा सकते हैं। क्या गल्ले का दाम गिरने के साथ सरकार ने या जमींदारों ने किसानों से कम लगान लेना शुरू कर दिया था? क्या महाजन इस बात पर राजी हो गए थे कि व्याज में कमी कर देंगे? क्या मजूरो ने सचमुच खुशी-खुशी अपनी मजूरी में कटौती मजूर कर ली थी, और क्या रेल-भाड़ा अब दाम गिरने से घटा दिया गया था? अगर नहीं, तो कैसे कहा जा सकता था कि मिलान हो चुका था? भारतवर्ष का भीतरी व्यापार उसके विदेशी व्यापार से कई गुना बड़ा है। इस भीतरी व्यापार की सैकड़ों चीजें ऐसी हैं जो कभी एक्सचेंज या इम्पोर्ट की लिस्ट पर नहीं चढ़ती और जिनपर

भी विचार किया और प्रमाणित कर दिया कि प्रत्येक दृष्टि में पुगना चावल ही हमारे लिए पथ्य हो सकता था ।

कमीशन की दूसरी सिफारिशें यह थी —

(१) चलन में नोट और रुपए रहे और सरकार इनके बदले मोना देने को बाध्य हो, पर वह मोना इस रूप में हो कि उसका मूद्रा की तरह उपयोग न हो सके ।

(२) करेन्सी-सम्बन्धी सारी व्यवस्था एक बड़ी बैंक के हवाले कर दी जाय जिगका नाम रिजर्व बैंक हो ।

(३) सॉवरेन अब सिक्का न रहे और उसे लेने-देने को कोई बाध्य न हो ।

(४) कागज के नोटों के बदले जो रुपए देने की व्यवस्था है वह धीरे-धीरे उठा दी जाय । जो पुराने नोट चलन में हैं उनके लिए तो यह व्यवस्था रहे, पर नए नोटों के लिए न रहे । पर कानूनन ऐसी व्यवस्था न होते हुए भी व्यवहार में नोटों के बदले रुपए दिए जाय । एक रुपए के नोट फिर से जारी किए जाय । करेन्सी-विभाग को अधिकार हो कि वह एक रुपए के नोटों को छोड़ बाकी नोटों के बदले या तो कम कीमत के दूसरे नोट दे सके या—अगर वह चाहे तो—रुपए ।

(५) रुपया लेने-देने को लोग बाध्य बने रहे पर नए रुपए तब तक न ढाले जाय जब तक चलन में उनका परिमाण काफी कम न हो जाय ।

(६) पेपर करेन्सी और गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व मिल्य दिए जाय, और उस न्युक्तर रिजर्व में सोना, चादी या गिक्यूरीटिज का परिमाण क्या हो यह कानून-द्वारा निश्चित कर दिया जाय ।

(७) हुडियो और चेको पर जो स्टैम्प-ड्यूटी है वह उठा दी जाय ।

सोने के जिस मान या स्टैंडर्ड की कमीशन ने सिफारिश की थी उसमें सिक्को का कोई स्थान नहीं था । कमीशन की राय सोने के सिक्को के चलन के खिलाफ थी, इसलिए उसने सिफारिश की थी कि करेन्सी-विभाग सोना लेने-देने को बाध्य तो हो पर वह सोना सिक्को के रूप में न होकर सिल या पासे के रूप में हो, और ४९० औंस से कम लेने-देने का किमीको

अतिरिक्त न था। कमीशन ने इस स्टैंडर्ड को गोल्ड युनियन स्टैंडर्ड—अर्थात् माने का भावनात्मक मान बताया। जो गोल्ड एक्स्चेंज स्टैंडर्ड फोल्डर-कमेटी की सिफारिश को ठुकरा कर महा स्थापित किया जा चुका था उसे कागज रखने की कमीशन ने मजबूत नहीं दी। उसने हमें एक दोष तो यह बताया कि एंग्लो मद्रा-प्रणाली में रूपए का चलन अनिवार्य था और चांदी में एक दस में ज्यादा तोड़ी आगे ही रूपए मांगा हो सकता थे। वैसी हालत में इलाज नहीं हो सकता था कि कम कीमत के नोट निकाले जाए—या 'नोट' के निकले जारी किए जाए, या रूपए में चांदी की मात्रा घटा दी जाए। पर कमीशन की राय में इस प्रणाली का साथ दोष यह था कि यह सफल न होकर जाइल थी—इसे समझना मत कि किए आसान नहीं था—अगर हा जिन इस प्रश्न का वाई मलायजनक उत्तर न मिल सकता था कि नोट या रूपए के पीछे पुंजी करनेवादी और उसकी कीमत बढ़ाने वाले आदमी कौन भी चीज है? इंग्लिश जनता का जैसा विश्वास होता था कि, नहीं था, और बहुत सत्याना या यह सत्यात (मजबूत हो गई) था कि उनमें एंग्लो सार्वभौम के किए नहीं मजबूत थी जिनमें भारत का अर्थ हो गया था। कमीशन ने जिन स्टैंडर्ड की सिफारिश की उसके बिना हमें यह पुराना-नया का करना था कि अगर माना भारत में आने से या न रख या उस से माने में कि वह व्यवस्थापिका परिषद् की सिफारिश के, सिद्धि पर ही नहीं न पड़ी जान, या में भी मान के इस भावनात्मक मान को स्टैंडर्ड में पुराना मजबूत।

आज जनता कहीं अधिक जाग्रत थी। १९१९-२० से भी वह बहुत आगे चट गई थी। इसका श्रेय महात्मा गांधी को था। लोग इतने दिनों से चरावर यही देखते आ रहे थे कि सरकार को अपनी मुद्रा-सवधी नीति-रीति वही रत्ननी पटती थी जो इंग्लैण्ड के व्यापारियों या पूंजीपतियों के हक में अच्छी थी, न कि इस देश की जनता के। इस नीति-रीति का उद्देश होता आया था भारतवर्ष का दोहन कर इंग्लैण्ड के मुह में धारोष्ण पहुँचा देना। १६ पेंस की जगह १८ पेंस एक्सचेंज करने की तैयारी भी इसी नीयत में थी। इसमें भारतवर्ष के उत्पादकों की, करोड़ों किसानों की, हानि थी। लाभ था ब्रिटिश व्यवसायियों का—इस देश में ब्रिटिश माल मगानेवालों का, यहाँ के ब्रिटिश कर्मचारियों का।

सरकार ने निश्चय किया कि व्यवस्थापिका सभा-द्वारा सबसे पहले एक्सचेंज की नई दर पास करा ली जाय, फिर और विषयों को हाथ में लिया जाय। यह जानी हुई बात थी कि व्यवस्थापिका सभा में जनता के प्रतिनिधियों की ओर से इस प्रस्ताव का घोर-से-घोर विरोध होगा। इसलिए सरकार ने भी अपनी पूरी शक्ति लगा कर १८ पेंस को पास कराने की तैयारी शुरू कर दी।

२७ और २८ मार्च १९२७ को परिपद् में इस विषय पर वाद-विवाद हुआ। अर्थ-मदस्य सर वेसिल ब्लैकेट ने इसका श्रीगणेश करते हुए उन परिणामों का एक बड़ा ही भयकर चित्र खींचा, जो १८ की जगह १६ पेंस के ग्रहण से उपस्थित होनेवाले थे। उनके कहने का सारांश यह था कि अगर एक्सचेंज की दर १६ पेंस कर दी जायगी तो दाम चढ़ेंगे, और दाम चढ़ने से चारों ओर चड़ी अशांति पैदा हो जायगी। मजूरों के तथा ऐसे लोगों के हक में, जिनकी आमदनी बधी या निश्चित है, इस प्रकार की महंगी बहुत ही बुरी चीज होगी।

वास्तव में दाम बढ़ने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, १८ पेंस के कारण दाम या मजूरी अभी यथेष्ट परिमाण में गिरी नहीं थी। अगर रेट उस समय १६ पेंस कर दी जाती तो अवस्था में विशेष अन्तर पड़ने का कोई कारण नहीं था। गिरने के बजाय दाम जहाँ थे, प्रायः वही बने रहते। उठने की बात तो विभीषिका-मात्र थी, जिसका

उद्देश था कुछ लोगों को डर दिया कर उनकी सहानुभूति प्राप्त कर लेना । मर पुण्योत्तमराज ने इस दलील का जवाब देते हुए अपने वातव्य में बहुत ही ठीक किया था कि —

“हमारे साधियों ने जो दलील पेश की है उसमें देगने की बात तो आसिर गयी है कि जो चीज यहा पैदा या मर्फ होती है उनके वागो में १६ पैग दर के कारण हिलनी वृद्धि होगी । हमारे साधियों का कहना है कि दामा का मिश्रान १८ पैग की दर से बहुत कुछ हा चुका है—अर्थात् दाम उस दर तक मिर चुके है, उसमिन् अगर दर १६ पैग कर दी गई तो दामा में पूरे १२०० प्रीति का की वृद्धि होगी । पर में उसे नहीं मानता । मैं यह दिया चुका हूँ कि दामा का मिश्रान अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि जो दामा चारित्र्य उगाहा अर्थात् राज अभी नहीं हुआ है—यही दाम अभी मिर नहीं, मिरन सके है । एही दामा में अगर दर १६ पैग कर दी गई तो बाकि मिरि म बा उल्ल-प-र दामा वह बहुत ही मुक्त या नगण्य दामा और उसमें हानि भी होगी वा बहुत ही कम लामा की । पर अगर दर २८ पैग हुई तो चार आधे का मिश्रण हुए बिना न रहता । उस मिश्रण का अभी आसिर ही हुआ है, उसके खरे-म दर फल वा फलन ही का है ।”

परिपत्र में उस समय लाक-मश रोज दया का पाठिया में निभाया था । पर वह दरदाम पार्सी थी, जिसके नाना पार्सी मालिकाल नेहरू ने, दमर्ग नेहरू मालिक माली, जिसने नाना पार्सी मालिकाल मालिक मालिक, और मालिक

की विस्मृति-सी दिखाते हैं कि हम लोगो ने १९२४ में ही एक्सचेंज को स्थिर कर देने का आग्रह किया था। हम लोगो का प्रस्ताव था कि एक्सचेंज १६ पेंस कर दिया जाय—यह उन्हें स्वीकार क्यों न हुआ? उस समय तो उन्हें इतना भी स्वीकार न हुआ कि रायल (शाही) कमीशन-द्वारा इस विषय पर विचार कराया जाय। बाद में उन्होंने इसे स्वीकार भी किया तो लोकमत का निरादर-सा करते हुए। कमीशन के मेम्बरो की नामावली प्रकाशित होते ही हम लोग समझ गए थे कि फैसला वही होनेवाला है जो सरकार को मजूर है। हम लोगो को इस बात का निश्चय हो गया था कि उसका निर्णय १८ पेंस के ही पक्ष में होनेवाला है।”

इसके बाद जो बहस हुई उसमें खास हिस्सा लेनेवाले सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, श्रीयुत घनश्यामदास बिडला, मि० जिन्ना, मि० जमनादास मेहता और सर विक्टर सैसून थे—जो सब-के-सब १६ पेंस के पक्षपाती थे। दो-एक अगरेज मेम्बरो ने भी इसी पक्ष का समर्थन किया। बड़ी सरगर्मी से बहस हुई और १८ पेंस के पक्ष में जो दलीले दी गई थी उनकी बड़ी छीछालेदर की गई। बोटो के लिए काफी खीचातानी रही और सरकार ने सचमुच अपनी पूरी ताकत लगा दी। अन्त में जब बोट लिए गए तब सरकार के पक्ष में आए ६८ और विपक्ष में ६५—अर्थात् तीन बोटो से सरकार की जीत रही, और १८ पेंस कायम रह गया।

जो विधान पास हुआ उसके द्वारा व्यवस्था यह हुई कि सरकार को कोई जितना सोना चाहे २१ $\frac{1}{2}$) १० तोले के हिसाब से बेच सकता था। सोने को बम्बई टकसाल में पहुँचाना पड़ता और कोई भी पासा ४० तोले से कम का न हो सकता था। नोटो या रुपयो के बदले सरकार उसी दर से बम्बई में सोना—या वह चाहती तो लन्दन में स्टर्लिंग—दे सकती थी। पर १,०६५ तोले से कम सोना न मिल सकता था। स्टर्लिंग देने के लिए सरकार की ओर से १७ $\frac{1}{2}$ पेंस की दर मुकर्रर हुई—बम्बई से लन्दन सोना भेजने में जो खर्च पड़ता उसे १८ पेंस से काट कर। सॉवरेन लेने-देने को कोई बाध्य न रहा, पर सरकार २१ $\frac{1}{2}$) १० तोला के हिसाब से (अर्थात् १३।-४ फी सॉवरेन) उन्हें लेने को बाध्य कर दी गई।

सरकार ने अपनी जीत की नयी राशियाँ मनाईं। पर १६ पैसे के पक्ष में पचासवाँ वोट प्रजा-द्वारा निर्वाचित मेम्बरों के थे, और १८ पैसे के पक्ष में पचासवाँ वोट प्रायः सारे वोट ऐसे मेम्बरों के थे जो सरकार-द्वारा मनोनीत और परिशुद्ध में आए थे। अगर परिशुद्ध में सिर्फ़ प्रजा के प्रतिनिधि होते तो १६ पैसे जीती होती। इसलिए सरकार की जीत जीत नहीं, हार थी।

सरकार की ओर से प्रजापक्ष को हराव के लिए कैबी चाल चलती गई थी। अक्सर १६ मतदाता नए नए परिशुद्ध में कुछ प्रत्यक्ष आया था --

जैसे कि एक दोना और सौ कैबीसम हर्ष दे उसके समान में बढ़ा १६ पैसे मंगा दे। मगर नहीं कहता कि कैबीसम दोनी ही नहीं पाएँ, पर दोना में अक्सर हर्षा १६ कैबीसम दो प्रकार की हो सकती है -- आम की और बाँस की, और बाँसवा १६ कैबीसम है। इस प्रकार की कैबीसम हुई

इतिहास की पुनरावृत्ति

रेट कायम कर देना एक बात है, उसे टिकाना और १ इस देश में जब से स्वयसिद्ध मुद्रा नाम की कोई चीज नहीं रही और करेन्सी की मिकदार सरकार की मर्जी पर रह गई, तब से—जैसा कि पहले कहा जा चुका है—सरकार के लिए कोई भी दर कायम करना और उसे टिकाना सम्भव हो गया। पर यह सिद्धान्त की बात है। व्यवहार में सरकार की शक्ति और उसके साधन परिमित हैं, इसलिए सब कुछ उसीकी मर्जी से नहीं हो सकता। पहले-पहल जब उसने १६ पेंस की दर चलानी चाही थी तब उसे इसके लिए कई साल ठहरना पड़ा था। करेन्सी की माना कम करते-करते वह सफलता के पाम पहुँची थी। फिर जब वह उसी दर को बराबर के लिए २ शिलिंग करने चली तब उसे इस देश के करोड़ों रुपए लुटा देने पर भी कामयाबी नहीं हुई और अन्त में उसे यह प्रयास छोड़ देना पड़ा। अब दर १८ पेंस कायम कर दी गई, पर इसका यह अर्थ नहीं कि विधान बनते ही इस दर में आप-ही-आप स्थायित्व आ गया। जब आर्थिक स्थिति इसके अनुकूल नहीं थी—अर्थात् जब रुपए की असली कीमत बाजार में १६ पेंस के लगभग थी तब उमके बदले १८ पेंस आसानी से कैसे मिल सकता था? हा, उसी पुराने अस्त्र का फिर उपयोग करके—करेन्सी का सकोच करके—सरकार ऐसी स्थिति अवश्य पैदा कर सकती थी कि बाजार को रुपए की नई कीमत स्वीकार करनी पड़े। और इस अध्याय में हम देखेंगे कि उसने सचमुच यही किया। १८ पेंस दर को टिकाने के लिए सरकार ने फिर उन्हीं कृत्रिम उपायों का अवलम्बन किया और जहाँ तक करेन्सी का सम्बन्ध है, देश को भूखो मार कर उससे रुपए की नई कीमत मजूर करा ली। जो कुछ हुआ वह, और ही पैमाने पर सही, इस देश में पहले भी हो चुका था।

नई दर के विरोधियों ने सरकार को काफी चेतावनी दे दी थी कि

इसके परिणाम भयकर होनेवाले थे। देश की दुष्टि से यह बहुत अच्छा होना, अगर ये सच्चे भाषियारत्ता न निकलते और नई दर से इतना अनर्थ न होता। पर उनके भाग्य में कुछ और ही बदा था, इस कारण नई दर का भाषियार आसानी से स्थापित न हो सका और भारतवासियों को इसकी बेसी पर अपने दिल का काफी बख्तिदान करना पड़ा। विरोधियों की भाषियारणी सखी साजित हुई, और यह दर अत्यन्त हासिक। १९२८ को हार्ड प्राय हर साल एममेंज की कमजोरी बनी रही और इसमें वर लान के लिए सरकार ने हमारा क्या-क्या अभिप्रेत नहीं किया? हमारा जो घन सात के रूप में मिलता था वह उठा दिया गया— हमारे ऊपर जो कर का भाल था वह और भी भारी कर दिया गया— हमारे एममेंजों का नाम और हमारे उद्योग-धन्दा का प्रचल आपत्त पटुनाया गया और हमारे कर्मचारी कर्मियों का दया और भी खीन होना कर दी गई।

दर ११ कमजोरी साल १-साल बनी रहने के कारण सरकार के लिए भारी सर्जिट का काम पूरा करना, दुष्टि के अर्थ में उनके पास २ पाउंड केवल एममेंज का ही गया, क्योंकि जिस तरह तक स्ट्रिकिंग की माग नहीं थी उस तरह तक एममेंज की भी माग नहीं थी—अर्थात् एममेंज और भी नीचे जा जाता। इसी कारण सरकार में जाकर या तो सरकार ने भारत में निवास करने वाले विदेशी एममेंज उठा लेना दिया, या भारत में निवास करने वाले एममेंज में कटौत करके एममेंज का काम बढ़ाया। भारत में निवास के माग में विलेज में रहने वाले एममेंज और निवास वाले एममेंज की माग में जो जो माग, वह एममेंज में अंतर में जाकर देना —

* एममेंज में भारत में निवास करने वाले भारत में निवास के नाम दुष्टियों का काम पूरा करना — अर्थात् स्ट्रिकिंग के कारण भारत में निवास के माग में विलेज में रहने वाले एममेंज और निवास वाले एममेंज में अंतर में जाकर देना — अर्थात् स्ट्रिकिंग के कारण भारत में निवास के माग में विलेज में रहने वाले एममेंज और निवास वाले एममेंज में अंतर में जाकर देना —

लाख पीड स्टर्लिंग

वजट के अनुसार जो रकम भेजी जा सकी

१९२७—२८	३५५	२८३
१९२८—२९	३६०	३०८
१९२९—३०	३५२	१५२
१९३०—३१	३४५	५४
	<u>१,४१२</u>	<u>७९७</u>

पिछले दोनो साल हालत बड़ी ही नाजुक रही। १९३०-३१ में कुल ५,३९५,००० पीड स्टर्लिंग खरीदा जा सका। प्राय ५७ लाख पीड स्टर्लिंग सरकार को बेचना भी पडा। १९ नवम्बर १९३० को सरकार के पास स्टर्लिंग बेचनेवालों की ओर से कोई टेण्डर आया ही नहीं, जिसका नतीजा यह हुआ कि कुछ समय के लिए सरकार बाजार से ही हट गई। १९३१-३२ में एक्सचेंज की कमजोरी इतनी बनी रही कि सरकार कुछ भी स्टर्लिंग न खरीद सकी। उसके रुपए को दबाकर बैठ जाने पर भी रुपए की कीमत जैसी-की-तैसी ही रही।

जब उलटी हुण्डिया बेची गई थी तब भारतवर्ष के सचिव सुवर्ण तथा स्टर्लिंग धन को लुटा देने में सरकार को तनिक भी सकोच नहीं हुआ था। ३१ मार्च १९१९ को जितने नोट चलन में थे उनके सैकड़े ६५९ भाग की पुश्ती रिजर्व में ऐसे सुवर्ण तथा स्टर्लिंग धन-द्वारा होती थी। एक साल बाद यह परिमाण घट कर १९.६ रह गया था—क्योंकि पहले जहा प्राय ११५ करोड़ (१६ पैसे की रेट से) था वहा अब कुल ३२ करोड़ (२४ पैसे की दर से) रह गया था। उलटी हुण्डियों की बिक्री के प्रारम्भ और अन्त के बीच प्राय ७७ करोड़ का सोना और स्टर्लिंग हवा हो गया। इसके बाद जो समय आया उसमें फिर कुछ सचय हुआ और ३१ मार्च १९२६ को नोटों का सैकड़े २६.५ भाग रिजर्व में सोने-स्टर्लिंग के रूप में था। यह रकम थी प्राय ५१ करोड़ (२४ पैसे की रेट से) अर्थात् प्राय २२ करोड़ (१८ पैसे की रेट से प्राय ३० करोड़) सोना और प्राय: २९ करोड़ (१८ पैसे की रेट से प्राय ३८॥ करोड़), स्टर्लिंग।

पास जनवरी के अन्त में प्राय ८८ करोड़ का सोना या सोने की सिक्कूरिटीज थी। चलन में जितने नोट हैं उनका यह प्राय आधा होता है। बैंक ऑफ इंग्लैण्ड के पास तो सोने का परिमाण ८ जनवरी को इससे कम ही था—अर्थात् नोटों के सैकड़ें ३६ भाग की ही पुष्टी होने में होती थी।”

हमारे अर्थ-सदस्य ने जानबूझ कर ऐसी बात कही जो असत्य थी। जनवरी १९३० के अन्त में पेपर करेन्सी रिजर्व में सोना और सोने की सिक्कूरिटीज मिलाकर कुल प्राय ३५ करोड़ था। इसमें स्पष्ट है कि गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व के सोने को शामिल करके ही उन्होंने सोना ८८ करोड़ रुपए का बताया था। पर गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व कागज के नोटों की पुष्टी के लिए तो था नहीं। वह तो चादी के नोटों अर्थात् रुपयों की पुष्टी के लिए था। असलियत यह थी कि गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व रुपयों की दृष्टि में ही काफी नहीं था। उस समय करेन्सी रिजर्व के रुपयों की छोट चलन में बाकी रुपए प्राय २०० करोड़ थे। सोने में इनकी कीमत प्राय ५० करोड़ थी। गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व का मोना बेचने पर भी रुपयों की पुष्टी के लिए प्राय १०० करोड़ की कमी थी। इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान में रखने की बात है कि चादी की जो कीमत यहाँ ली गई है वह उस समय की बाजार-दर के अनुसार है। अगर इतनी चादी कभी बाजार में बिकने को आती तो दर और भी गिरती और उसकी कीमत कम हो जाती। कुछ भी हो, कागज के नोटों के प्रसंग में गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व के सोने की बात करना लोगो को भ्रमान्व करने की चेष्टामात्र थी।

भारत-सचिव को अपना काम चलाने के लिए न सिर्फ करेन्सी रिजर्व के धन पर हाथ फेरना पड़ा, बल्कि उन्हें लन्दन में कर्ज भी काफी लेना पड़ा। मई १९२३ से १९२७ के अन्त तक स्टर्लिंग में हमें कोई कर्ज लेना नहीं पड़ा था। पर इसके बाद तो स्थिति इतनी बिगड़ी कि सरकार के लिए लन्दन में कर्ज लेना अनिवार्य-सा हो गया। वजट में व्यवस्था न होते हुए भी कर्ज लेना पड़ता, या सरकार का तखमीना कुछ होता, और असलियत कुछ और ही होती।

मरिच में कर्ज—आम पीड़

	अमर के अनुसार	असहिमत
११२१ - २१	कुछ नहीं	७५
११२१ - २१	"	१००
११२१ - ३०	५२३	१०५
११३० - ३१	६०	३१०
	११२३	५१०

मायाया भाग के अमर शीघ्र ही निकला और ने १८ मिनट पराम लीने
 ने पराम परियेद म मर भाग ली पराम की भी कि निना रन्दन म इस प्रकार
 यों कि इस समय पराम ली निना अमर नव होमा और उल्लोच पूरा था कि --

'इस सा ११ मा मायाया हो गली है कि १८ मिनट की दर का लहाने
 ने किया सरफार हा इस समय म बहुत बड़ा कर्जदार न कना म था ?
 और अगर इस न कर्ज कि ली तो व्याज का देना सर कोन होमा ? मायाया
 म मा ११ कि ली जाय ली मा मा न लहान के कि ली इस समय के कर सा ११
 म माया रन्दन ने किया जायमा, और माया इस कारण उनका खोज कही म
 ली माया ने ही रमा ?'

इस सा ११ म सरफार की लहाने कि ली प्रकार सही मर नी के
 ली ली म ली ली होमा --

करोड़ रुपए

३१ मार्च १९२४—३१ मार्च १९२७—३१ मार्च १९३१

इंग्लैंड में —

कर्ज और दूसरी देनदारी १८ पैंस की रेट से	४३२.०४	४५२.४८	५१७.०१
भारतवर्ष और इंग्लैंड की मिलाकर	९१९.००	१,००६.१९	१,१७१.९६

ऊपर ट्रेजरी बिलों का जिक्र है। १९३०-३१ में सरकार की इस रूप में देनदारी ५५ करोड़ से ऊपर थी। इन बिलों के द्वारा कुछ महीनों के लिए कर्ज लेना और इस प्रकार बाजार से रुपए को यथासम्भव खींच लेना अब सरकार की मुद्रा-नीति का एक मुख्य भाग बन गया। जुलाई १९२७ में सरकार ने कुछ कर्ज लेना चाहा, पर उसे यथेष्ट सफलता नहीं हुई। अगस्त में उसने ट्रेजरी बिल निकाल कर ऊँचे व्याज पर रुपया लेना शुरू किया। साख गिर जाने के कारण सरकार को यह ऊँचा व्याज देना पड़ता था। बैंको को डिपॉजिट के लिए जो व्याज देना पड़ता उससे प्रायः १ प्रतिशत अधिक सरकार को ऐसे कर्ज के लिए देना पड़ता था। पर एक्सचेंज-दर को ठिकाने के लिए करेन्सी का सकोच करना सरकार के लिए इतना आवश्यक था कि वह इन ट्रेजरी बिलों के जरिए बाजार से रुपया खींचती ही गई। इधर करेन्सी का कब कितना विस्तार या सकोच हुआ यह नीचे की तालिका से स्पष्ट होगा। इसमें + विस्तार का और — सकोच का सूचक है।

	लाख रुपए
१ जनवरी १९२० से ३१ मार्च १९२१ तक	— ३८,४८
१९२१—२२	— ३,८०
१९२२—२३	— ९,६०
१९२३—२४	+ १८,१५
१९२४—२५	+ १,६०
१९२५—२६	+ १,००

करोड़ रुपए

३१ मार्च १९२४—३१ मार्च १९२७—३१ मार्च १९३१

इंग्लैंड में —

कर्ज और दूसरी देनदारी १८ पैसे की रेट से	४३२.०४	४५२.४८	५१३.०१
भारतवर्ष और इंग्लैंड की मिलाकर	९१९.००	१,००६.१९	१,१३१.९६

ऊपर ट्रेजरी बिलों का जिक्र है। १९३०-३१ में सरकार की इंग्लैंड में देनदारी ५५ करोड़ से ऊपर थी। इन बिलों के द्वारा कुछ मतानों के लिए कर्ज लेना और इस प्रकार बाजार से रुपए का यथासम्भव गोचर लेना अब सरकार की मुद्रा-नीति का एक मुख्य भाग बन गया। जुलाई १९२७ में सरकार ने कुछ कर्ज लेना चाहा, पर उसे यथेष्ट सफलता नहीं हुई। अगस्त में उसने ट्रेजरी बिल निकाल कर ऊँचे व्याज पर रुपया लेना शुरू किया। साख गिर जाने के कारण सरकार को यह ऊँचा व्याज देना पड़ता था। बैंकों को डिपॉजिट के लिए जो व्याज देना पड़ता उससे प्रायः १ प्रतिशत अधिक सरकार को ऐसे कर्ज के लिए देना पड़ता था। पर एक्मचेंज-दर को ठिकाने के लिए करेन्सी का सकोच करना सरकार के लिए इतना आवश्यक था कि वह इन ट्रेजरी बिलों के जरिए बाजार से रुपया खींचती ही गई। इधर करेन्सी का कद कितना विस्तार या सकोच हुआ यह नीचे की तालिका से स्पष्ट होगा। इसमें + विस्तार का और - सकोच का सूचक है।

	लाख रुपए
१ जनवरी १९२० से ३१ मार्च १९२१ तक	- ३८,४८
१९२१—२२	- ३,८०
१९२२—२३	- ९,६०
१९२३—२४	+ १८,१५
१९२४—२५	+ १,६०
१९२५—२६	+ १,००

वर्न	२१	२१	२१	२१
कलकत्ता	७	७	७	६

२० जून १९३१ को दरे इस प्रकार थी —

लन्दन	२१	फीसदी
न्यूयार्क	११	"
एम्स्टर्म्	२	"
वर्न	२	"
कलकत्ता	६	"

१९२९ में इम्पीरियल बैंक के विरोध करने पर भी सरकारी आदेश से बैंक-रेट ७ में ८ प्रतिशत कर दी गई थी। परिपद् में इस विषय पर प्रश्न किए गए तो अर्थ-मदस्य ने कहा कि सरकार ने जो कुछ किया, सोच-समझ कर किया और उमरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है।

१८९३ के बाद भी सरकारी नीति ने इस देश में ऐसी ही स्थिति पैदा कर दी थी। उस नीति का उद्देश था रुपए की तगी करके उसका मूल्य १६ पेंस कर देना। जो तगी इस बार पैदा की गई थी उसका उद्देश था रुपए के मूल्य को १८ पेंस पर ठहराना। फौलर कमेटी के सामने सरकारी नीति के समर्थकों ने कहा था कि इधर एक्सचेंज में स्थिरता का अभाव रहा है, इसलिए विलायतवालों ने अपनी बहुत कुछ रकम यहाँ से उठा ली है — बैंकों के पास उधार देने के लिए अब उतना रुपया-पैसा नहीं रहा है और इसी कारण बाजार में ऐसी तगी है—अर्थात् इस तगी का सरकार के रुपए न ढालने से कोई सम्बन्ध नहीं था। दूसरे गवाहों ने इस तर्क का खण्डन करते हुए कहा था कि “वात ऐसी नहीं है। एक्सचेंज की स्थिरता से ही किसी देश में बाहर से पूँजी नहीं आ सकती। पूँजी तो तब आती है जब उसका लाभदायक उपयोग हो सकता है, और जहाँ ऐसी स्थिति होती है वहाँ एक्सचेंज की अस्थिरता भी पूँजी के आने को नहीं रोक सकती। एक्सचेंज-दर गिरते रहने पर भी बाहर से करोड़ों रुपए आकर यहाँ के वाणिज्य-व्यवसाय और उद्योग-धंधों में लग चुके थे। उधर इंग्लैण्ड और आयरलैण्ड के बीच का एक्सचेंज स्थिर होते हुए भी इंग्लैण्ड से आयरलैण्ड में जाकर बहुत

रहो थी उसकी तह में फिर सरकार की बही गिरावट-नीति थी। फर्क था तो इतना ही कि इस बार उस नीति का रूप कहीं उग्र था—और करेन्सी की वृद्धि ही नहीं रोक दी गई थी, बल्कि चलन से करेन्सी बहुत निकदार में उठा ली गई थी।

१९२३-२४ से १९२५-२६ तक हर साल इम्पोर्ट से एक्सपोर्ट प्रायः ८८ करोड़ अधिक हुआ, पर बाद के तीनों साल इतने अच्छे न रह सके और एक्सपोर्ट हर साल ४७ करोड़ ही अधिक रहा। १९२९-३० में यह आधिक्य बढ़ कर प्रायः ५३ करोड़ हो गया था, पर एक्सपोर्ट को कम होते देर न लगी और १९३०-३१ में वह इम्पोर्ट ने प्रायः ३७॥ करोड़ ही अधिक रहा।

जिस समय एक्सचेंज-दर २४ पेंस की गई थी उस समय उसके पक्ष-पातियों ने जोर देकर कहा था कि ससार में दाम गिरनेवाले नहीं, बल्कि और ऊपर चढ़नेवाले हैं। बात कुछ और ही हुई, और दाम काफी नीचे गिर पड़े। १९२७ में जब दर १८ पेंस की जा रही थी तब उसके विरोधियों ने कहा था कि ससार में दाम चढ़ने की तो कोई आशा की नहीं जा सकती, पर दाम गिरने की आशका जरूर की जा सकती है। और अगर सचमुच ऐसा हुआ—अर्थात् चीजों के सोने में दाम गिरे—और रुपए की एक्सचेंज-दर १८ पेंस रही, तो यहां के किसानों को इन दोनों पाटों की चक्की में पिसना पड़ेगा। पर सरकार की ओर से उनका मजाक उड़ाया गया और कहा गया कि ससार में दाम गिरने का कोई कारण नजर नहीं आता—हमें यह मान ही लेना होगा कि दाम स्थिर बने रहेंगे। काश कि ऐसा ही होता।

श्री बिडला जी बराबर यह कहते जाते थे कि सरकार को अपना घर सभालना चाहिए—अर्थात् अपने खर्च को घटा कर दिवालिया-पन से बचना चाहिए। ७ मार्च १९२८ को उनके एक भाषण में हम यह चेतावनी पाते हैं —

“जो आफत हमारे ऊपर आ पहुंची है उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पांच साल से लगातार फसल अच्छी होती आई है। इसने मुल्क में खुशहाली होनी चाहिए थी। पर हम देखते क्या हैं? परिपक्व के बहुत से मेम्बरो को मालूम होगा कि देश की क्रय-शक्ति बहुत ही कम हो गई

३० मे १ करोड ५६ लाख टोटा रहा। १९३०-३१ मे हालत ज्यादा धिगड़ी और पाच करोड से ऊपर नए टैस लगने पर भी जहा ८६ लाख वचत की आशा की गई थी वहा प्राय १३॥ करोड टोटा रहा।

सरकार ने अपने खर्च को कुछ हद तक घटाया। कर्मचारियों के वेतन मे १० प्रतिशत की कटौती* भी की, पर परिस्थिति काबू में लाई गई विशेषत करदाताओं का बोझ भारी करके। तीन साल में पाय' ४२ करोड की कर-वृद्धि हुई—१९३०-३१ के बजट-द्वारा पाच करोड, १९३१-३२ के बजट-द्वारा १५ करोड, और बाद के सप्लीमेंटरी बजट-द्वारा २२ करोड की।

आरम्भ मे ही निराशावादियों की चेतावनी पर ध्यान दिया जाता तो यह नौवत न आती। निराशावादी ही यथार्थवादी थे।

* १९३३-३४ के बजट-द्वारा यह कटौती १० से ५ प्रतिशत कर दी गई और १९३५-३६ के बजट-द्वारा बिलकुल उठा दी गई।

उधर अमेरिका में बाहर से इतना सोना आया कि १९१४ में वहाँ जो स्टॉक था वह १९१९ में दूना हो चला। वहाँ सोने का चलन भी बना रहा। सोने का उत्पादन कम होते हुए भी दामों के उस ऊँचे सतह पर कायम रहने का रहस्य यही है कि अमेरिका में तो सोने की यो ही बहुतायत हो चली, और दूसरे देशों में सोना चलन से निकल कर रिजर्व बैंकों की तिजोरियों में भर गया। सोने और नोटों के बीच जो अनुपात पहले था वह अब न रहा—अर्थात् नोटों की पुष्टी के लिए अब पहले की अपेक्षा कम सोना आवश्यक हो चला। सोना केन्द्रीभूत हो गया, अनुपात में हेर-फेर कर दिए गए—नोटों का प्रसार बढ़ गया, दामों की सतह ऊँची हो चली।

लार्ड की मुसीबत ने इंग्लैण्ड तथा कई अन्य देशों को गोल्ड स्टैंडर्ड से अलग कर दिया था। अब जरा अच्छे दिन आए और लोगों को यह देखने लगा कि सोने की ओर से कोई खतरा नहीं है, तब उन देशों में लोकमत का झुकाव गोल्ड स्टैंडर्ड को फिर अपना लेने के पक्ष में होने लगा। अमेरिका में गोल्ड स्टैंडर्ड बना हुआ था—वहाँ का डॉलर एक निर्दिष्ट मात्रा के सोने का प्रतिनिधि था, नोट देकर कोई भी उसके बदले उतना सोना पा सकता था और उसका जैसा उपयोग चाहता, कर सकता था। ऐसी हालत में इंग्लैण्ड-जैसे देश के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड पर वापिस आने का व्यावहारिक अर्थ था पौण्ड को डॉलर के साथ बाध देना—अर्थात् डॉलर या सोने में पौण्ड की कीमत को तरल या चंचल न छोड़ कर उसे स्थिर, निश्चित, निश्चल कर देना।

पर कीमत बाधी जाय तो किस दर से ? निर्र्व पुराना हो या नया ? जब पहले इंग्लैण्ड और अमेरिका दोनों गोल्ड स्टैंडर्ड पर थे तब एक पौण्ड ४ ८६ डॉलर की बराबरी करता था। वहाँ १९२५ में सरकार ने यह निर्णय किया कि अब आगे से पौण्ड के बदले बे-रोक-टोक सोना मिल सकेगा और निर्र्व वही पुराना (अर्थात् १ पौण्ड = ४ ८६ डॉलर) होगा। पर इस निर्णय के विरोधी भी थे जिनका कहना था कि पौण्ड का मूल्य इतना ऊँचा नहीं होना चाहिए—इससे निर्यात (एक्सपोर्ट) व्यापार को घबका लगेगा और उद्योग-धंधों की गहरी हानि होगी।

१९२२ में पौड और डॉलर के बीच एक्सचेंज की दर १ पौड = ४.२५ डॉलर थी। उस समय इंग्लैण्ड में थोक दाम अमेरिका में प्रायः १५ प्रतिशत ऊंचे थे। अगर यह मान लेने का यथेष्ट कारण होता कि अब आगे दोनों देशों में दामों की गति समान रहेगी तो एक्सचेंज की इसी रेट को स्थायी कर देना उपयुक्त होता। पर इसके खिलाफ यह दलील थी कि आदर्श तो यही हो सकता है कि पौड फिर अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर ले—अर्थात् ४.८६ डॉलर तक पहुँच जाय। कारण कि जब तक पौड वहाँ तक नहीं पहुँच जाना तब तक लन्दन की साख फिर पूरी तरह नहीं जम सकती और वह फिर एक बार मसार का आर्थिक केन्द्र नहीं बन सकता। लुप्त गौरव को फिर से प्राप्त करने के उद्देश से ही वहाँ की सरकार ने १९२५ में पौड को ४.८६ डॉलर पर पहुँचा कर उसका यही मूल्य स्थिर कर दिया, यद्यपि इंग्लैण्ड को इसके बाद यह अनुभव होने लगा कि यह जल्दबाजी हो गई—उसे पौड को इस तरह सोने की जजीर में जकड़वन्द नहीं करना चाहिए था।

१९२५ में लक्षणों से यह प्रतीत होता था कि अमेरिका में दाम उठने-वाले हैं, पर वहाँ उसके बाद दाम उठने के बजाय गिरने लगे। बाकी दुनिया में भी दामों का झुकाव गिरने की ही ओर था।

इंग्लैण्ड अगर औरो की तरह अपने दामों को गिरा सकता तो उसके लिए चिन्ता की कोई बात नहीं थी, पर वह ऐसा करने में असमर्थ था। कारण यह कि वहाँ मजदूरी में कमी करना जरा टेढ़ी खीर थी। कल-कारखानेवालों का कहना था कि विदेशों में दाम गिर रहे हैं, हमारे सामने उस प्रतियोगिता का मुकाबिला करने के दो ही उपाय हैं—या तो एक्सचेंज-रेट नीची कर दी जाय या हमें भी उसी हद तक दाम गिराने दिया जाय। पर दोनों में एक भी सभव न हो सका। न तो सरकार ने रेट गिराई, न मजदूरों ने अपनी औसत मजदूरी में कोई खास कमी होने दी। कल-कारखानेवाले चीखते-चिल्लाते रहे—लाखों आदमी बेकार बने रहे।

जो सोना अमेरिका जाता वह वहाँ तिजोरियों में बन्द कर प्रायः निष्क्रिय

उसमे माल मे भुगतान लेने को तैयार नहीं था। अमेरिका की तरह फ्रांस भी साहकार बन गया था, पर उसकी भी नीति यही हो रही थी कि कर्जदागो से जहा तक हो सके सोने मे ही भुगतान लिया जाय, बल्कि उसने अपनी मुद्रा की कीमत घटाकर अपने निर्यात-व्यापार को उत्तेजन देना और दूसरो के क्षेत्र पर आक्रमण करना भी शुरु कर दिया था। प्रायः सबकी नीति यही हो रही थी— अपना माल अधिक-से-अधिक बेचना, दूसरो का माल कम-से-कम खरीदना। ऐसी स्थिति मे यह तारनम्य कैसे हो सकता था जिस पर समार का आर्थिक स्वास्थ्य निर्भर था ?

बला जव तक टाली जा सकती थी, टाली गई। अमेरिका और फ्रांस ने दूसरे देशो को कर्ज दे-देकर परिस्थिति को सम्हालने की चेष्टा की। इससे प्रायः दो साल—१९२६ से १९२८ तक—सुकाल-सा बना रहा। उत्पादन की वृद्धि हुई, सुख-शान्ति विराजमान् रही। पर यह अवस्था स्थायी नहीं थी। रोग जड मे तो गया नहीं था, केवल उसका जमडना कुछ समय के लिए रुक गया था।

कुछ ही समय बाद न्यूयार्क के शेयर-बाजार मे सट्टा ऐसे जोर-शोर से चला कि अमेरिका के व्याज उपजानेवालो के लिए, दूसरे देशो को देने के बजाय अपने घर के सटोरियो को कर्ज देना कहीं अधिक लाभदायक प्रतीत होने लगा। फ्रांस ने भी दूसरे देशो को कर्ज देने से हाथ खींच लिया। इससे इन देशो की भूसीवन और भी बढ़ गई। वहा दाम तेजी मे गिरने लगे। उन देशो की दशा विशेष शोचनीय हो चली जो बच्चा माल—मसलन चीनी, रबर, कहवा—पैदा करनेवाले थे। १९२९ मे अमेरिका में शेयरो के सट्टे ने और भी जोर पकड़ा। इसका नतीजा यह हुआ कि बाहर से आकर्षित होकर बहुत कुछ पैसा अमेरिका पहुँचने लगा। दूसरे देश अपने-अपने बचाव के लिए तरह-तरह की तरकीबे करने लगे। इंग्लैण्ड ने अपनी बैंक-रेट अर्थात् न्याज की दर ६½ प्रतिशत कर दी। इसके फलस्वरूप गहा दाम और भी नीचे गिरे। आखिर अमेरिका भी मन्दी वी हवा के झोके से कब तक बच सकता था ? वहा के शेयर-बाजार मे जो बेहद तेजी आ गई थी वह कुछ ही समय बाद जाती रही और प्रतिक्रियास्वरूप दामो का गिरना शुरू

उससे माल में भुगतान लेने को तैयार नहीं था। अमेरिका की तरह फ्रांस भी साहकार बन गया था, पर उसकी भी नीति यही हो रही थी कि कर्जदाने से जहाँ तक हो सके सोने में ही भुगतान लिया जाय, वल्कि उसने अपनी मुद्रा की कीमत घटाकर अपने निर्यात-व्यापार को उत्तेजन देना और दूसरों के क्षेत्र पर आक्रमण करना भी शुरू कर दिया था। प्रायः सबकी नीति यही हो रही थी— अपना माल अधिक-से-अधिक बेचना, दूसरों का माल कम-से-कम खरीदना। ऐसी स्थिति में वह तारतम्य कैसे हो सकता था जिस पर मसार का आर्थिक स्वास्थ्य निर्भर था ?

बला जब तक टाली जा सकती थी, टाली गई। अमेरिका और फ्रांस ने दूसरे देशों को कर्ज दे-देकर परिस्थिति को सम्हालने की चेष्टा की। इसने प्रायः दो साल—१९२६ से १९२८ तक—सुकाल-सा बना रखा। उत्पादन की वृद्धि हुई, मुख-शान्ति विराजमान रही। पर यह अवस्था स्थायी नहीं थी। रोग जड़ में तो गया नहीं था, केवल उसका उभड़ना कुछ समय के लिए रुक गया था।

कुछ ही समय बाद न्यूयार्क के शेयर-बाजार में सट्टा ऐसे जोर-शोर से चला कि अमेरिका के व्याज उपजानेवालों के लिए, दूसरे देशों को देने के बजाय अपने घर के सटोरियों को कर्ज देना कहीं अधिक लाभदायक प्रतीत होने लगा। फ्रांस ने भी दूसरे देशों को कर्ज देने से हाथ खींच लिया। इससे इन देशों की मुसीबत और भी बढ़ गई। वहाँ दाम तेजी में गिरने लगे। उन देशों की दशा विशेष शोचनीय हो चली जो बच्चा माल—मसलन चीनी, रबर, कहवा—बँदा करनेवाले थे। १९२९ में अमेरिका में शेयरों के सट्टे ने और भी जोर पकड़ा। इसका नतीजा यह हुआ कि बाहर से आकर्षित होकर बहुत कुछ पैसा अमेरिका पहुँचने लगा। दूसरे देश अपने-अपने बचाव के लिए तरह-तरह की तरकीबें करने लगे। इंग्लैंड ने अपनी बैंक-रेट अर्थात् -याज की दर ६½ प्रतिशत कर दी। इसके फलस्वरूप वहाँ दाम और भी नीचे गिरे। आखिर अमेरिका भी मन्दी की हवा के झोंके से कब तक बच सकता था ? वहाँ के शेयर-बाजार में जो बेहद तेजी आ गई थी वह कुछ ही समय बाद जाती रही और प्रतिक्रियाम्बु रूप दामों का गिरना शुरू

यो तो यह मन्दी सब को तबाह करनेवाली थी, मगर खास कर उन देशों को, जो कृषि-प्रधान थे। कल-पुरजों में बननेवाली चीजों के दाम उस हद तक नहीं गिरे जिग हद तक खेतों की उपज के। एक तो खेती-वारी करने-वाले, कल-कारखानेवालों की अपेक्षा, कहीं कम चुस्त-चालाक होते हैं। फिर, यह धधा ऐसा है कि उनकी नीति-रीति में समयानुकूल परिवर्तन या तो होता ही नहीं, या थोड़ा-बहुत होता भी है तो बड़ी देर और मुश्किल से। अन्न की माग कम हो जाने पर भी किसान करे तो क्या ? न तो वह अन्न उपजाना छोड़कर दूसरे धधे में लग सकता है, न वह कोई मगइन या समझौता करके उत्पादन को ही कम कर सकता है। इधर दुनिया में काश्तकारी बहुत बढ़ गई है। अर्जेंटाइन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया—जैसे देशों में खेती बहुत बड़े पैमाने पर होने लगी है और अन्न का निर्यात उनके आर्थिक अस्तित्व का मुख्य आधार बन गया है। खेती का विस्तार ही नहीं बढ़ा है, उसकी गहराई भी बढ़ गई है—अर्थात् अग्रगामी देशों में खेती वैज्ञानिक ढग से होने लगी है और इस कारण भूमि की उत्पादन-शक्ति कहीं-से-कहीं बढ़ चली है। भारतवर्ष—जैसे देश में लोगों को भरपेट मोटा अन्न भी नहीं मिलता, इसलिए यहा वह दिल्ली दर है जहा पहुँच जाने पर अन्न की माग तृप्त हो सकती है। पर समृद्धिवाली देशों में और बात है। वहा लोगों को भरपेट अन्न मिल रहा है। इसलिए अन्न की माग परिमित हो गई है, वल्कि भोजन में अन्न का स्थान कुछ हद तक मास-मछली, फल-मूल इत्यादि ने ले लिया है, इसलिए अन्न की खपत कम हो गई है। अमेरिका का उदाहरण देते हैं। वहा १८८९ में फी शरस पीछे २४४ पौण्ड गेहूँ का आटा लगा था। पर १९२९ में यह मात्रा घट कर १५५ पौण्ड रह गई थी। ऐसी स्थिति में दाम गिरने के कारण, कृषि-जीवी लोगों को उन लोगों की अपेक्षा विशेष क्षतिग्रस्त होना पडा जो तैयार माल बनानेवाले थे या अपनी जीविका के लिए उसपर निर्भर थे। एक ओर अन्न की पैदावार बढ़ रही थी, दूसरी ओर उसकी खपत कम हो रही थी। भारतवर्ष—जैसे देशों में अन्न की वास्तविक कमी थी, पर वहा के लोग इतने दीन-हीन थे कि ऐसी सस्ती में भी उन्हें पेट भर अन्न मिलना असम्भव था।

शाली है। ऐसी स्थिति में उन्होंने जिस तरह अपनी रक्षा कर ली उस तरह दूसरों के लिए करना असम्भव था। चाय के व्यवसायियों और भारत-सरकार के सहयोग से उसका उत्पादन परिमित कर दिया गया, जिससे दामों का गिरना रुक गया और कुछ समय बाद दाम चढ़ने भी लगे। १९१४ (=१००) के आधार पर १९२९ सितम्बर में चाय के दाम १२९ थे, मई १९३३ में ७४ और मई १९३४ में १४७ थे। पर यह खुशनमीवी उन चीजों को हासिल नहीं हो सकती थी जिन्हें उपजाने में यहाँ के किसानों का हाथ है और जिनपर उनका अस्तित्व निर्भर है। नीचे के सूचक अकों से यह स्पष्ट है—

जुलाई १९१४ = १००

	सितम्बर	मई	मई
	१९२९	१९३३	१९३४
चावल	१०४	६०	६५
गेहूँ	१३५	८९	७२
तेलहन	१७५	७२	९२
पाट	९०	५०	३७
कपास	१४६	८४	७१

दामों के गिरने के कारण किसानों की आय कहीं-से-कहीं कम हो गई। नीचे दिए गए अकों से इसपर प्रकाश पड़ता है। तालिका में, किसानों को मिलनेवाले दामों के आधार पर, यह दिखाया गया है कि प्रत्येक प्रान्त की खेती की खास पैदावार की कीमत पर मन्दी का क्या असर पड़ा—

(लाख रुपए)

	१९२८—२९	१९३२—३३
मद्रास	१,८०,७८	९९,३३
बम्बई	१,२०,५२	८३,८६
बंगाल	२,३२,५९	९०,५४
संयुक्त प्रान्त	१,४०,५२	९१,०१
पंजाब	७६,७८	४८,५३

मन्दी के कारण दाम कहा तक गिरे यह नीचे के सूचक अंको में जाहिर होगा —

(थोक दाम)

कलकत्ता		इंग्लैण्ड
जुलाई १९१४ = १००		१९१३ = १००
१९२९	सितम्बर १४३	१३५ ८
१९३०	„ १११	११५ ५
१९३१	„ ९१	९९ २
१९३२	„ ९१	१०२.१
१९३३	„ ८८	१०३ ०

पर जिन वस्तुओं के दाम ऊपर लिए गए हैं उनमें निर्यात और आयात दोनों ही शामिल हैं। अगर इनका पृथक्करण किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायगा कि जिस हद तक निर्यात (अर्थात् यहाँ से बाहर जानेवाली) वस्तुओं के दाम गिरे उस हद तक आयात (अर्थात् बाहर से यहाँ आनेवाली) वस्तुओं के नहीं। इन सूचक अंकों को देखिए —

कलकत्ता (१९१४ = १००)

निर्यात वस्तुओं के दाम		आयात वस्तुओं के दाम
१९२९	सितम्बर १३३	१५०
१९३१	दिसम्बर ८१	१२४
१९३२	„ ६९	११५
१९३३	„ ७३	११२

पर इन अंकों से भी परिस्थिति की भीषणता का पूरा पता नहीं चलता। निर्यात वस्तुओं में कुछ ऐसी हैं जिनके उत्पादन का व्यवसाय विशेष रूप से सगठित है। मन्दी की मार इनपर वैसी नहीं पड़ी जैसी साधारण कृषि-व्यवसाय पर। चाय का उदाहरण देते हैं। यो तो इस देश की पैदावार में यह भी शामिल है और करोड़ों रुपए की चाय यहाँ से बाहर जाती है, पर यह व्यवसाय प्रधानतः विदेशियों के हाथ में है और चाय उपजानेवाले धान या पाट उपजानेवालों से कहीं अधिक शिक्षित, सगठित और शक्ति-

शाली है। ऐसी स्थिति में उन्होंने जिस तरह अपनी रक्षा कर ली उस तरह दूसरों के लिए करना असम्भव था। चाय के व्यवसायियों और भारत-सरकार के सहयोग से उसका उत्पादन परिमित कर दिया गया, जिससे दामों का गिरना रुक गया और कुछ समय बाद दाम चढ़ने भी लगे। १९१४ (=१००) के आधार पर १९२९ सितम्बर में चाय के दाम १२९ थे, मई १९३३ में ७४ और मई १९३४ में १४७ थे। पर यह खुशानीवी उन चीजों को शामिल नहीं हो सकती थी जिन्हें उपजाने में यहाँ के किसानों का हाथ है और जिनपर उनका अस्तित्व निर्भर है। नीचे के सूचक अकों में यह स्पष्ट है —

जुलाई १९१४ = १००

	सितम्बर	मई	मई
	१९२९	१९३३	१९३४
चावल	१२४	६०	६५
गेहूँ	१३५	८९	७२
तेलहन	१७५	७२	९२
पाट	९०	५०	३७
कपास	१४६	८४	७१

दामों के गिरने के कारण किसानों की आय कहीं-से-कहीं कम हो गई। नीचे दिए गए अकों से इसपर प्रकाश पड़ता है। तालिका में, किसानों को मिलनेवाले दामों के आधार पर, यह दिखाया गया है कि प्रत्येक प्रान्त की खेती की खास पैदावार की कीमत पर मन्दी का क्या असर पड़ा —

(लाख रुपए)

	१९२८—२९	१९३२—३३
मद्रास	१,८०,७८	९९,३३
बम्बई	१,२०,५२	८३,८६
बंगाल	२,३२,५९	९०,५४
संयुक्त प्रान्त	१,४०,५२	९१,०१
पंजाब	७६,७८	४८,५३

स्टर्लिंग से गंठबन्धन

पाठको को स्मरण होगा कि हिल्टन यंग कमीशन ने रुपए को सोने का प्रतीक बनाने का प्रस्ताव किया था। सरकारी विधान ने रुपए को सोने और स्टर्लिंग का प्रतीक बना दिया। १९२७ में जो ऐक्ट पार हुआ उसमें यह व्यवस्था थी कि सरकार सोने के बदले रुपया दे, और रुपए के बदले सोना अथवा स्टर्लिंग। व्यवहार में वह सोने के बदले रुपए देती थी, और रुपए के बदले स्टर्लिंग। इंग्लैण्ड में उन दिनों स्टर्लिंग के नोट सोने के प्रतीक थे। इसलिए स्टर्लिंग के रास्ते भी रुपया सोने पर ही पहुँच जाता था।

१८९३ में चांदी की टकसाल बन्द करने के समय कहा गया था कि रुपया सोने का प्रतीक होगा। हमको बताना दिया गया था कि यहाँ विशुद्ध गोल्ड स्टैंडर्ड (सुवर्ण-मान) की स्थापना होगी। पर गोल्ड स्टैंडर्ड की जगह गोल्ड एक्स्चेंज स्टैंडर्ड स्थापित किया गया। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश हुई कि गोल्ड एक्स्चेंज की जगह गोल्ड बुलियन (धातुवात्मक) स्टैंडर्ड की प्रतिष्ठा की जाय, पर जो विधान बना उसने इस देश को कुछ और ही स्टैंडर्ड दिया। यह एक गंगा-जमुनी चीज थी जिसमें सोने से स्टर्लिंग की प्रधानता थी और स्टर्लिंग सोने का प्रतीक था, इसलिए कहना चाहिए कि यहाँ वही पुराना गोल्ड एक्स्चेंज स्टैंडर्ड, कुछ हेरफेर के साथ, काम कर रहा था। हा, लक्ष्य यही था कि धातु के रूप में ही सही, यहाँ विशुद्ध गोल्ड स्टैंडर्ड की स्थापना की जाय।

१९२७ में यहाँ मुद्रा-समस्या की गई वह १ अप्रैल (१९२७) से १९ सितम्बर १९३१ तक चली। २० सितम्बर को यह घोषित किया गया कि इंग्लैण्ड में मृत्यु का मान अब सोना न रह गया था—अर्थात् वहाँ से गोल्ड स्टैंडर्ड उठ चुका था। २१ दिसम्बर को यहाँ बड़े लाट में एक

फर्मान निकाल कर रुपये के बदले सरकार के सोना या स्टर्लिंग देने की व्यवस्था उठा दी। इसका अर्थ यही हो सकता था कि सरकार रुपये को न सोने से सम्बद्ध रखना चाहती थी, न स्टर्लिंग से—वह रुपये के मूल्य को हर तरह के बन्धन से मुक्त कर देना चाहती थी। पर उसी दिन लन्दन में भारत-सचिव ने यह ऐलान किया कि रुपये का मूल्य १८ पैसे स्टर्लिंग रहेगा। श्रीयुत बनश्यामदास जी बिडला, जो उस समय लन्दन में थे, अपनी एक पुस्तक* में लिखते हैं—“इंग्लैण्ड ने आग्विर गोल्ड स्टैण्डर्ड छोड़ दिया। भारतवर्ष सोने से तो हट गया पर स्टर्लिंग से वह अभी तक बंधा हुआ है। गुस्टर ने शिमले में कुछ कहा, और होर ने फेडरल कमेटी में कुछ। जान-बूझ कर यहावालो ने पीछे बेईमानी की है।”

इस पुस्तक के पूर्वार्द्ध में लिखा है कि प्रतीक और स्वयंसिद्ध मुद्रा का तलाक हो जाने पर “प्रतीक की कीमत कटी पतंग की तरह हो जाती है और जैसे हवा के झोके के बल पर पतंग गिरती है या उठती है उसी तरह प्रतीक की कीमत भी चलन की फुलावट की कमी-वेशी के आधार पर झिलोरे खाती रहती है।” मान लीजिए कि रुपये का तलाक जहा सोने से हो गया था वहा स्टर्लिंग से भी हो जाता। उस हालत में रुपये की गति उसी कटी पतंग-सी होती। उसका विनिमय-मूल्य इस बात पर निर्भर करता कि चलन में उसकी मिकदार क्या थी—उसके लिए माग कैसी थी—यहा इस देश में वह कितनी त्रय-शक्ति अथवा मूल्य रखता था। कटी पतंग पर आदमी का कोई बस नहीं रह जाता, क्योंकि हवा आदमी का हुक्म माननेवाली नहीं है, पर चलन में फुलावट या गिरावट करके—या यो कहिए कि उसका विस्तार या सकोच करके—रुपये की कीमत घटाई-बढ़ाई जा सकती थी। सोने या स्टर्लिंग का प्रतीक न रहने पर भी रुपये की अपनी कीमत हो सकती थी और उस कीमत का रुपये की चादी की कीमत से ऊपर रहना भी संभव था।

पर जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अधिकारियों ने एक बार रुपये को स्वतंत्र कर फिर कुछ ही घंटों बाद अपना विचार बदल दिया और उसका

स्टर्लिंग से गठबन्धन कर दिया। २४ सितम्बर को बड़े लाट ने एक नया फर्मान निकाल कर २१ सितम्बर के फर्मान को मन्सूख कर दिया—कानूनन परिस्थिति फिर वही हो चली जो २१ सितम्बर से पहले थी। हा, रुपए के बदले स्टर्लिंग मिलना पहले से ज़रूर मुश्किल कर दिया गया। अब स्टर्लिंग सर्वसाधारण को नहीं, बल्कि कुछ खास बैंको को ही मिल सकता था। रेट वही पुरानी रही—एक रुपए के १७½ पेस। इस बात की भी व्यवस्था कर दी गई कि किस प्रकार का देना चुकाने के लिए स्टर्लिंग मिल सकता था। रुपया अब स्टर्लिंग का प्रतीक हो गया, इसलिए सोने में उसकी कीमत वही हो सकती थी जो स्टर्लिंग की। अगस्त १९३१ के अन्त में यहाँ सोने का दाम २१।।।-)। तोला था—यह दिसम्बर १९३१ में २९=) हो चला था। आने वाले दिनों में यह दाम और भी ऊँचा होने वाला था। रुपया अब स्टर्लिंग से बंधा हुआ था, इसलिए सोने के मुकाबले जिस हद तक स्टर्लिंग गिरता उसी हद तक रुपए को भी गिरना पड़ता। उसकी अपनी कोई हस्ती नहीं थी।

भारतवर्ष में इस समय लोगों की आर्थिक अवस्था शोचनीय थी। इधर सरकार की जो मुद्रा-नीति चली आ रही थी उसके भयंकर फल अब प्रत्यक्ष होने लगे थे। मन्दी के कारण दाम यो ही नीचे थे, पर इस देश में ऊँचे एक्सचेंज ने दामों को और भी नीचे गिरा दिया था और गाँव में रुपए का भीषण दुष्काल उपस्थित कर दिया था। ऐसे समय में जब सोने की कीमत (रुपयों में) ऊँची हो चली तब लोगों को इसका सहारा-सा मिल गया और वे सुनारों के हाथ अपना जेवर इत्यादि बेच कर अपना काम चलाने लगे। पर यह सोना उन सुनारों के पास कब तक टिक सकता था? थोड़े ही समय में इस देश से सोना विदेश जाने लगा और कुछ ही महीनों के अन्दर प्रायः ५० करोड़ का सोना विदेश चला गया। इस सोने के बदले मिलनेवाले स्टर्लिंग की बहुतायत हो जाने में स्टर्लिंग की बिन्ती पर किसी प्रकार का नियन्त्रण रखना अब अनावश्यक हो गया और ३१ जनवरी १९३२ के बाद उसकी बिन्ती बे-रोक-टोक होने लगी।

रुपए का स्टर्लिंग से गठबन्धन भारत-सचिव के दबाव से किया गया।

लन्दन में उस समय गोलमेज परिषद् के सिलसिले में जो थोड़े से भारतीय नेता या प्रतिनिधि मौजूद थे उन्होंने वहाँ सरकारी नीति का घोर विरोध किया और भारत-सचिव को महात्मा गांधी के सन्तोष के लिए इस विषय पर कुछ कहने-सुनने को मजबूर किया ।

श्री विडला जी अपनी "डायरी"* में प्रसंगवश लिखते हैं —

"आज (६ अक्टूबर १९३१) शाम को इण्डिया ऑफिस में सर हेनरी स्ट्रॉकोश के साथ दगल हुआ । सभापति का आसन पहले तो भारत-सचिव सर सैमुएल होर ने ग्रहण किया, पर मन्त्रिमण्डल की मीटिंग थी, इसलिए सर रेजिनल्ड मॅण्ट को अपना पद देकर कुछ ही मिनट बाद चलता बना । और बहुत मे लोग उपस्थित थे—गांधीजी, सर पुरुषोत्तमदास, मि० जिन्ना, सर मानिकजी, सर फिरोजशाह सेठना, के० टी० शाह, प्रो० जोशी, रंगास्वामी अयंगर इत्यादि । गांधीजी प्रायः ७ बजे कार्यवश उठकर चले गए । ५॥ बजे मे कार्रवाई आरम्भ हुई । सरकार की ओर से सर हेनरी स्ट्रॉकोश ने वक्ता का काम किया, और अपनी ओर से मैंने। ब्लैकट भी मौजूद था, पर कुछ बोला नहीं ।

"स्ट्रॉकोश ने पहले तो सत्तार की परिस्थिति का दिग्दर्शन कराया, फिर भारतवर्ष की बाते करने लगा । उसकी सबसे बड़ी दलील यही थी कि अगर एक्सचेंज १-६ स्टर्लिंग पर न बाध दिया गया होता तो न जाने लुटकते-लुटकते कहा जाकर दम लेता और न जाने सरकार को कहा तक नोट छपाकर अपना काम चलाना पड़ता । मैंने जब पूछा कि आखिर ठहराने के लिए तुम्हारे पाम साधन क्या हैं ? तब उससे कोई उत्तर न बन पड़ा । उसने अधिकांश समय मेरी उन दलीलों का जवाब देने में लगाया जो मैंने Monetary Reform (मद्रा-सम्बन्धी सुधार) नाम की पुस्तिका में पेश की हैं । मैंने कहा कि मैं बात-बात पर वहस करने को तैयार हूँ, पर मैं यह कह देना आवश्यक समझता हूँ कि उस पुस्तिका में मैंने जो मत प्रकट किया है वह मेरा अपना है, भारतीय व्यापारीवर्ग का नहीं । यहाँ जो लोग आए हैं

* "डायरी के कुछ पन्ने", पृष्ठ ६७ और ६९ ।

वे भारत-सरकार की नीति के विषय में कुछ कहने उस विषय को छोड़ कर मेरी * पुस्तिका की समाप्ति उनके साथ अन्याय करना है। फिर भी स्ट्रॉकोश ने अ.

“खैर, अच्छी बहस हुई। मैंने लिखा था कि . . . वास्तविक उद्देश अंग्रेज सिविलियन और व्यवसायी को यह बात इन लोगों को खूब चुभी और स्ट्रॉकोश कहने लगे प्रमाणित कर सकने हों ? सर पुष्पोत्तमदाम ने तो लम्बा-चौड़ा हैं और इसे सुनने-सुनाने के लिए सम पीने का वस्तु हो रहा था, लोगों को अपने-अपने काम इसलिए चर्चा म्यगित की गई।

* इस पुस्तिका का विषय है दामों की घटा-बढ़ी को क्रयशक्ति को बराबर समान रखने की वाछनीयता और रुपए के दो प्रकार के मूल्य हैं—एक तो देश के भी देश के बाहर का। देश के भीतर के मूल्य का अर्थ है इसकी सम्बन्धी क्रय-शक्ति। देश के बाहर के मूल्य का अर्थ है जैसे पौंड, स्टर्लिंग से विनिमय की दर या भाव। अब तक का लक्ष्य इसके बाहरी मूल्य को स्थिर रखने की ओर रहा है या १८ पैसे, जब जो ठीक जचा इसका मूल्य कर दिया और वहीं टिका दिया। पर इसके बाहरी मूल्य के प्रश्न से कहीं जनि पूर्ण प्रश्न है इसके देशान्तर्गत मूल्य का। यह मूल्य अब तक अ घटता-बढ़ता रहा है—जब रुपए का मूल्य घटा तब दाम चढ़ १८९६ और १९१४ के बीच) और जब रुपए का मूल्य बढ़ा गिर गए (जैसे कुछ दिन पहले की मन्दी के जमाने में)। लेखक घटा-बढ़ी को रोकने की वाछनीयता पर भारतवर्ष की दृष्टि से। किया है और दिखाया है कि इस विषय में Irving Fisher विद्वानों के सिद्धान्तों को, हेर-फेर के साथ, कैसे व्यावहारिक रूप दे सकता है। इस सम्बन्ध में, भीमासा-भाग का अन्तिम अध्याय द्रष्टव्य

“मुझे ऐसा जान पड़ा कि स्ट्रॉकोश अपने विषय का बड़ा पंडित है, पर बेईमान नहीं है। इसलिए सम्भव है या तो इसकी चर्चा ही न हो, या ब्लैंकेट* जैसे आदमी को सरकारी पक्ष के समर्थन का काम सौंपा जाय। स्ट्रॉकोश अच्छी तरह जानता है कि सरकार की ओर से पेश करने लायक कोई जोरदार दलील नहीं है। वह करे तो क्या? बोला कि तुमने बार-बार कहा है कि हमारा सोना उड़ा दिया। वास्तव में सरकार ने उड़ाया नहीं; हिन्दुस्तान की जो जिम्मेदारी थी उसे पूरा किया। मैंने पूछा, इंग्लैंड की भी तो जिम्मेदारी थी—यहां क्या किया? उसने कहा—मगर इंग्लैंड हिन्दुस्तान-जैसा दूसरा का देनदार नहीं है। मैंने उत्तर दिया—मैं इसे मानता हूँ, पर दो बातें हैं। इंग्लैंड वैसे देनदार न हो, पर यहां एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट ज्यादा है। हमारा देश देनदार है, पर वह इम्पोर्ट से एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, यह तुम्हें न भूलना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान में रखने की बात है कि हम अपने उद्योग-धन्यो की उन्नति कर, अपनी उत्पादन-शक्ति बढ़ा कर ही अपना देना चुका सकते हैं। फिर

* वास्तव में ब्लैंकेट के इस विषय पर अपने स्वतंत्र विचार थे जो उसने अपनी Planned Money (व्यवस्थित मुद्रा) नामक पुस्तक में प्रकट किए हैं। पुस्तक-लेखक के विचार में मन्दी के कारण भारतवर्ष-जैसे देशों के सामने बड़ी गहन समस्या उपस्थित हो गई थी और साधारणतः सबकी, पर विशेषतः उनकी दृष्टि से, दामों का उठना बहुत जरूरी था। वह लिखता है :—

“भारतवर्ष की परिस्थिति इस देश से भी खराब है। वहां की पैदावार के दाम गिर जाने से, फर्ज का बोझ—चाहे फर्ज देश के भीतर लिया गया हो चाहे बाहर—देहव भारी हो चला है। भारतवर्ष अधिक काल तक उस बोझ को टेकर न चल सकेगा। अगर दाम न बढ़ें तो फर्ज, लगान, मजदूरी, किराया, महसूल-जैसी निर्दिष्ट रकमों में कमी किए बिना काम चलने का नहीं। पर जो भारतवर्ष की स्थिति से परिचित हैं उन्हें इस प्रकार की कमी होने की संभावना हास्यास्पद जचेगी। सबकी

जुटाना पड़ता। समस्या हल करने के लिए उसे नोट छापने पड़ते। पर इसका नतीजा यह होता कि दाम और भी बढ़ते—अर्थात् रुपए की कीमत और भी गिरती, और ज्यो-ज्यो दवा की जाती त्यो-त्यो मर्ज बढ़ता ही जाता। इसलिए भारत-सरकार को यहाँ से यही सलाह देना मुनासिब समझा गया कि वह रुपए को स्टर्लिंग से सम्बद्ध कर दे। पूछा जा सकता है कि जब इंग्लैण्ड ने स्टर्लिंग को स्वतन्त्र छोड़ दिया है तब भारतवर्ष रुपए को क्यों न स्वतन्त्र छोड़ दे? इसका उत्तर यह है कि इंग्लैण्ड, भारतवर्ष की तरह देनदार मुल्क नहीं। वह पावनेदार है—इसलिए यहाँ स्टर्लिंग को स्वतन्त्र छोड़ देने से वह खतरा नहीं जो भारतवर्ष में रुपए को स्वतन्त्र छोड़ देने से हो सकता है। भारतवर्ष ने इंग्लैण्ड से बहुत कुछ कर्ज ले रखा है, उसे हर साल यहाँ करीब ३॥ करोड़ स्टर्लिंग खर्च करना पड़ता है, उसके विदेशी व्यापार का बहुत बड़ा अंश ब्रिटिश साम्राज्य के साथ है—ऐसी अवस्था में, उसके हित की दृष्टि से, स्टर्लिंग से सम्बद्ध रहना ही उसके लिए वाछनीय है।”

श्रीधनश्यामदास विडला —

“यह सच है कि भारतवर्ष के लिए रुपए को सोने से सम्बद्ध रखना असम्भव था। आखिर सम्बद्ध रखने का अर्थ तो यही है कि अगर कोई रुपए के बदले सोना मागे तो सरकार उसे दे सके। पर यहाँ तो सरकार अपना सोना खो चुकी थी—सोने में रुपए की कीमत ऊँची रखने की नीति को सफल बनाने के लिए वह रिजर्व के सोने से ही हाथ धो चुकी थी—फिर जब सोना पास न हो तब रुपए को उससे सम्बद्ध रखने का अर्थ ही क्या? पर हम लोगो का कहना है कि जब रुपया सोने का प्रतीक न रहा तब उसे स्टर्लिंग का भी प्रतीक न रहना चाहिए था। आज रिजर्व में सरकार के पास स्टर्लिंग भी कहा है? जहाँ किसी समय प्रायः ६८ करोड़ रुपए का सोना (या स्टर्लिंग) था वहाँ इस समय सिर्फ ४ या ५ करोड़ का सोना बच गया है, और स्टर्लिंग नहीं के बराबर है। फलतः १८ पैसे स्टर्लिंग पर रुपए का विनिमय-मूल्य टिकाने के लिए सरकार को या तो रुपए गला-गला कर बाजार में चादी बेचनी पड़ेगी—जिससे चादी बेहद सस्ती हो

जायगी—या इंग्लैण्ड में कर्ज लेना पड़ेगा, जिससे हमारी देनदारी और भी बढ़ जायगी। सर हेनरी स्ट्रॉकोश को भय है कि अगर रुपया स्वतन्त्र छोड़ दिया गया तो उसकी कीमत गिरते-गिरते उसकी चादी की कीमत (प्रायः ६ या ७ पैसे) के आस-पास पहुँच जायगी। मैं नहीं समझता कि रुपए की कीमत यहाँ तक गिर सकती है, पर अगर रुपए की असली कीमत सचमुच ६ पैसे है तो कृत्रिम रीति से वह १८ पैसे पर कब तक टिकाई जा सकती है? लोग सरकार को रुपए देना शुरू कर देंगे और बदले में स्टर्लिंग मागेगे। सरकार कुछ हद तक यह माग पूरी करेगी और फिर कह देगी कि “अब हम और स्टर्लिंग नहीं दे सकते।” पर तब तक हमारा बचा-खुचा स्टर्लिंग-धन स्वाहा हो जायगा और हमारे नोट बिना किसी प्रकार की पुष्टी के रह जायेंगे। इंग्लैण्ड के पास १६०,०००,००० पौण्ड स्टर्लिंग सोना था। ज्योंही यह घट कर १३३,०००,००० पौण्ड स्टर्लिंग हो चला, इंग्लैण्ड ने सुवर्णमान—गोल्ड स्टैण्डर्ड का परित्याग कर दिया और स्टर्लिंग को बिल्कुल स्वतन्त्र कर दिया। पर भारतवर्ष में सर्वस्व खोकर भी सरकार उसका अनुकरण करना अनुचित समझती है और रुपए का स्टर्लिंग से गठबन्धन कर देती है—और कहा जाता है कि अगर रुपया इस प्रकार आवद्ध न रहा तो भारतवर्ष रसातल में पहुँच जायगा। सर हेनरी स्ट्रॉकोश ने भारतवर्ष की देनदारी का जिक्र करते हुए फरमाया कि इंग्लैण्ड के लिए जो वस्तु अमृत है वही भारतवर्ष के लिए विष हो सकती है। हम भारतवासी इस विषय में उनके कथन की सत्यता स्वीकार नहीं कर सकते। भारतवर्ष देनदार है तो उसकी आर्थिक नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे उसकी देनदारी घटे। देनदारी तभी घट सकती है जब उसकी उत्पादन-शक्ति और उसका निर्यात-व्यापार बढ़े। पर इसके लिए यह आवश्यक है कि वहाँ चीजों के दाम उँचे हों—और दाम उठाने को, मौजूदा हालत में, एकमात्र उपाय है एक्सचेंज को गिरा देना। कहा गया है कि रुपया जब गिरने लगेगा तब अपनी चादी की कीमत के पास पहुँच कर ही रुकेगा। इस सम्बन्ध में मेरे दो निवेदन हैं। एक तो यह कि भारतवर्ष देनदार भले ही हो पर साधारणतः वह इम्पोर्ट (आयात) से एक्सपोर्ट (निर्यात)

जुटाना पड़ता। समस्या हल करने के लिए उसे नोट छापने पड़ते। पर इसका नतीजा यह होता कि दाम और भी बढ़ते—अर्थात् रुपए की कीमत और भी गिरती, और ज्यो-ज्यो दवा की जाती त्यो-त्यो मर्ज बढ़ता ही जाता। इसलिए भारत-सरकार को यहाँ से यही सलाह देना मृनासिव समझा गया कि वह रुपए को स्टर्लिंग से सम्बद्ध कर दे। पूछा जा सकता है कि जब इंग्लैण्ड ने स्टर्लिंग को स्वतन्त्र छोड़ दिया है तब भारतवर्ष रुपए को क्यों न स्वतन्त्र छोड़ दे? इसका उत्तर यह है कि इंग्लैण्ड, भारतवर्ष की तरह देनदार मुल्क नहीं। वह पावनेदार है—इसलिए यहाँ स्टर्लिंग को स्वतन्त्र छोड़ देने से वह खतरा नहीं जो भारतवर्ष में रुपए को स्वतन्त्र छोड़ देने से हो सकता है। भारतवर्ष ने इंग्लैण्ड से बहुत कुछ कर्ज ले रखा है, उसे हर साल यहाँ करीब ३॥ करोड़ स्टर्लिंग खर्च करना पड़ता है, उसके विदेशी व्यापार का बहुत बड़ा अंश ब्रिटिश साम्राज्य के साथ है—ऐसी अवस्था में, उसके हित की दृष्टि से, स्टर्लिंग से सम्बद्ध रहना ही उसके लिए वाछनीय है।”

श्रीधनश्यामदास बिडला —

“यह सच है कि भारतवर्ष के लिए रुपए को सोने से सम्बद्ध रखना असम्भव था। आखिर सम्बद्ध रखने का अर्थ तो यही है कि अगर कोई रुपए के बदले सोना मागे तो सरकार उसे दे सके। पर यहाँ तो सरकार अपना सोना खो चुकी थी—सोने में रुपए की कीमत ऊँची रखने की नीति को सफल बनाने के लिए वह रिजर्व के सोने से ही हाथ धो चुकी थी—फिर जब सोना पास न हो तब रुपए को उससे सम्बद्ध रखने का अर्थ ही क्या? पर हम लोगो का कहना है कि जब रुपया सोने का प्रतीक न रहा तब उसे स्टर्लिंग का भी प्रतीक न रहना चाहिए था। आज रिजर्व में सरकार के पास स्टर्लिंग भी कहा है? जहाँ किसी समय प्रायः ६८ करोड़ रुपए का सोना (या स्टर्लिंग) था वहाँ इस समय सिर्फ ४ या ५ करोड़ का सोना बच गया है, और स्टर्लिंग नहीं के बराबर है। फलतः १८ पेंस स्टर्लिंग पर रुपए का विनिमय-मूल्य ठिकाने के लिए सरकार को या तो रुपए गला-गला कर बाजार में चादी बेचनी पड़ेगी—जिससे चादी बेहद सस्ती हो

जायगी—या इंग्लैण्ड में कर्ज लेना पड़ेगा, जिससे हमारी देनदारी और भी बढ़ जायगी। सर हेनरी स्ट्रॉकोश को भय है कि अगर रुपया स्वतन्त्र छोड़ दिया गया तो उसकी कीमत गिरते-गिरते उसकी चादी की कीमत (प्रायः ६ या ७ पैसे) के आस-पास पहुँच जायगी। मैं नहीं समझता कि रुपए की कीमत यहाँ तक गिर सकती है, पर अगर रुपए की असली कीमत सचमुच ६ पैसे हैं तो कृत्रिम रीति से वह १८ पैसे पर कब तक ठिकाई जा सकती है? लोग सरकार को रुपए देना शुरू कर देंगे और बदले में स्टर्लिंग मांगेंगे। सरकार कुछ हद तक यह मांग पूरी करेगी और फिर कह देगी कि “अब हम और स्टर्लिंग नहीं दे सकेंगे।” पर तब तक हमारा बचा-बूचा स्टर्लिंग-घन स्वाहा हो जायगा और हमारे नोट बिना किसी प्रकार की पुष्टी के रह जायेंगे। इंग्लैण्ड के पास १६०,०००,००० पौण्ड स्टर्लिंग सोना था। ज्योंही यह घट कर १३३,०००,००० पौण्ड स्टर्लिंग हो चला, इंग्लैण्ड ने सुवर्णमान—गोल्ड स्टैंडर्ड का परित्याग कर दिया और स्टर्लिंग को बिलकुल स्वतन्त्र कर दिया। पर भारतवर्ष में सर्वस्व खोकर भी सरकार उसका अनुकरण करना अनुचित समझती है और रुपए का स्टर्लिंग से गठबन्धन कर देती है—और कहा जाता है कि अगर रुपया इस प्रकार आवद्ध न रहा तो भारतवर्ष रसातल में पहुँच जायगा। सर हेनरी स्ट्रॉकोश ने भारतवर्ष की देनदारी का जिन करते हुए फरमाया कि इंग्लैण्ड के लिए जो वस्तु अमृत है वही भारतवर्ष के लिए विष हो सकती है। हम भारतवासी इस विषय में उनके कथन की सत्यता स्वीकार नहीं कर सकते। भारतवर्ष देनदार है तो उसकी आर्थिक नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे उसकी देनदारी घटे। देनदारी तभी घट सकती है जब उसकी उत्पादन-शक्ति और उसका निर्यात-व्यापार बढ़े। पर इसके लिए यह आवश्यक है कि वहाँ चीजों के दाम ऊँचे हों—और दाम उठाने की, मौजूदा हालात में, एकमात्र उपाय है एक्सचेंज को गिरा देना। कहा गया है कि रुपया जब गिरने लगेगा तब अपनी चादी की कीमत के पास पहुँच कर ही रुकेगा। इस सम्बन्ध में मेरे दो निवेदन हैं। एक तो यह कि भारतवर्ष देनदार भले ही हो पर साधारणतः वह इम्पोर्ट (आयात) से एक्सपोर्ट (निर्यात)

ज्यादा करता है। दूसरा यह कि चलन में जितने सिक्के या नोट हैं सब-के-सब, विनिमय के लिए, कभी उपस्थित नहीं किए जा सकते। अगर रुपए के सिक्को की तादाद दो अरब मान ली जाय और नोटों की डेढ़ अरब, तो सब मिला कर साढ़े तीन अरब हुए। इनमें से अगर डेढ़ अरब भी स्टर्लिंग से विनिमय के लिए उपस्थित किए जाय तो देश में रुपए की बेहद तंगी हो जायगी—जिसका अर्थ यह हुआ कि रुपए की कीमत बढ़ जायगी। इन दो कारणों से, मैं नहीं समझता कि किसी भी हालत में रुपया ११ पैसे या १२ पैसे (सोना) से नीचे गिर सकता है। पर दाम बढ़ाने के लिए—जिससे किसानों और दूसरे उत्पादकों का भला हो और जो मन्दी चली आ रही है उससे उनका दम घुटने न पाए—रुपए की कीमत का गिरना जरूरी है। कहा गया है कि दामों की स्थिरता वांछनीय है। पर कौन-से दामों की? इतना तो सभी स्वीकार करते हैं कि आज के दाम बहुत नीचे हैं और अगर हम इन्हें ज्यों-के-त्यों रहने देते हैं तो हम करोड़ों किसानों के हित की हत्या करते हैं। भारतवर्ष में न्याय का तकाजा यह है कि दाम १०० से उठा कर १५० कर दिए जाय—और उस हद तक एक्सचेंज को गिरने दिया जाय। इसीलिए हम लोगों का कहना है कि रुपए को स्टर्लिंग में बाध कर, और दामों का उस हद तक उठना असम्भव कर, सरकार ने हमारे देश के साथ घोर अन्याय किया है।”

सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास —

“रुपए को स्टर्लिंग का प्रतीक कर दिया गया, पर केवल इसी अर्थ में कि उसकी कीमत १८ पैसे से नीचे नहीं जा सकती। ऊपर के लिए कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि सरकार ने यह जिम्मेवारी नहीं ली है कि १८ पैसे स्टर्लिंग बेचनेवाले को वह एक रुपया दे दे। १९२७ वाले विधान में सरकार पर यह जिम्मेवारी रखी गई थी कि अगर कोई सोना बेचना चाहे तो सरकार उसे १८ पैसे = १ रुपए की दर से खरीदने को बाध्य होगी। उस परिस्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ा है, जिसका अर्थ यह होता है कि अगर कोई सरकार के हाथ अपना सोना बेचना चाहता है तो उसे उसी पुराने भाव से बेचना पड़ेगा। पुराना भाव था प्रायः २१।।।—) तोला। आज का बाजार-

भाव २५) से भी अधिक है। इस समय बम्बई में गावों से काफी सोना आ रहा है। लोग इतने विपन्न हैं कि उनके पास जो कुछ सोना है उसे देचकर अपना काम चला रहे हैं। पर सरकार इस सोने का दाम इतना कम देने को तैयार है कि व्यापारी इसे उसके पास नहीं ले जा सकते। लेहाजा सारा सोना भारतवर्ष से बाहर जा रहा है। सरकार की इस नीति से जनता का असन्तुष्ट होना स्वाभाविक है। कहा जाता है कि भारतवर्ष ऋणी देश है, उसने इंग्लैण्ड में बहुत कुछ कर्ज ले रखा है, इसलिए एक्सचेंज गिराना उसके लिए हितकर नहीं हो सकता। पर ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण हम लोगों के सामने है। भारतवर्ष की अपेक्षा बड़ा ऋणी होते हुए भी उसने अपना एक्सचेंज गिरा दिया। किसानों की दृष्टि में भारतवर्ष की दशा ऑस्ट्रेलिया ने कहीं खराब है। गेहूँ का १।-) मन बिकना एक ऐसी बात है जिसे पिछले ८० साल के इतिहास में हम अभूतपूर्व कह सकते हैं। सरकार को इसमें क्या आपत्ति हो सकती है कि बत्तीर एक प्रयोग के, कुछ महीनों के लिए ही सही, रुपए को इस बन्धन से मुक्त कर दे और देखे कि इससे दाम चढ़ते हैं या नहीं और किसानों का कुछ भला होता है या नहीं? इस समय तो उन्हें बाजार या मंडी में जो दाम मिलता है वह बैलगाड़ी का भाड़ा चुकाने के लिए भी काफी नहीं होता। एक घटना की खुद मुझे जानकारी है, जहाँ किसान बाजार में गन्ना बेचने लाए और दाम सुनकर इतने निराश हुए कि गन्ने को बेचने के बजाय गायों और भैसों को समर्पित कर अपने घर लौट गए।”

पर इस शास्त्रार्थ में परिस्थिति में तनिक भी अन्तर न पड़ा और रुपए—स्टलिंग का गठबन्धन ज्यों-का-त्यों बना रहा।

यह तो हुई लन्दन की बात। यहाँ भारतवर्ष में उस समय व्यवस्थापिका परिषद् का अधिवेशन हो रहा था। वहाँ सदस्यों ने २१ सितम्बर को एक बात सुनी, २२ को दूसरी। भारत-सचिव द्वारा किए जानेवाले हस्तक्षेप और स्टलिंग-गठबन्धन का प्रतिवाद करने के लिए सर कावसजी जहागीर ने परिषद् में “काम स्थगित करानेवाला” प्रस्ताव लाना चाहा, पर बड़े लाट ने एक खाम आदेश से इसे रोक दिया। २६ सितम्बर

को मि० (अब सर) पण्मुखम् चेद्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया —

“चूकि इस बात का डर है कि मौजूदा हालत में रुपए का स्टर्लिंग से गठबन्धन कर देना भारत के लिए अत्यन्त अहितकर होगा,

“और चूकि भारत-सरकार के रुपए का विनिमय-मूल्य १८ पैसे रखने के कारण इस देश की कृषि और उद्योग-धन्धों की गहरी हानि हुई है और करेन्सी-कोप में जो सोना या सोने के तुल्य समझे जाने लायक धन था वह प्रायः साफ हो चुका है,

“और चूकि इस बात का भी डर है कि भारत-सरकार के रुपए का स्टर्लिंग से गठजोड़ा कर देने और इस सम्बन्ध में कुछ खास जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेने के कारण उस सोने या धन की और भी बरबादी होगी, और इससे इस देश की विशेष आर्थिक क्षति होगी;

“इस परिषद् की राय है कि भारत-सरकार को फौरन इस उद्देश से कुछ खास कार्रवाई करनी चाहिए कि हमारे करेन्सी तथा गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्वों या कोषों में जो सोना या स्टर्लिंग जमा है वह किसी भी हालत में आज की अपेक्षा कम न होने पावे,

“और इस परिषद् की यह भी राय है कि इस देश की भलाई के लिए भारत-सरकार को चाहिए कि वह रुपए के बदले सोना या स्टर्लिंग देने की कोई जिम्मेवारी अपने ऊपर न रहने दे और एतद्विषयक विधान में जो संशोधन आवश्यक हो, कर दे। अगर सरकार को यह मजूर न हो तो वह तब तक कोई जिम्मेवारी अपने ऊपर न ले जब तक ब्रिटिश सरकार से उसे लम्बी मुद्दत के लिए, मुनासिब शर्तों पर, काफी बड़ी रकम लन्दन में तत्काल कर्ज नहीं मिल जाती।

“अर्थ-सदस्य ने उस दिन यह सूचित किया कि वह अतिरिक्त कर लगाने के लिए परिषद् में दूसरा राजस्व बिल पेश करनेवाले हैं। इस सम्बन्ध में परिषद् का कहना है कि इसके सदस्यों को काफी नोटिस दिए बिना कर-सम्बन्धी कोई नया प्रस्ताव यहाँ पेश नहीं होना चाहिए और इस अधिवेशन में तो ऐसा प्रस्ताव हर्गिज नहीं होना चाहिए।”

प्रस्ताव के पक्ष में आए ६४ वोट, और विपक्ष में ४० । पर बहुमत से पास होने पर भी प्रस्ताव स्थिति में कोई अन्तर डालनेवाला न था । उस समय के भारत-सचिव ने ही एक अवसर पर कहा था कि कुत्ते भूकते रहते हैं, कारवा आगे बढ़ता जाता है । प्रजा पर इधर करो का बोझ काफी भारी हो चला था । वह और भी भारी कर दिया गया । इसी अधिवेशन में नए प्रस्ताव-द्वारा प्राय २५ करोड़ रुपए की कर-वृद्धि कर, हमारे शासकों का कारवा अपने मार्ग पर अग्रसर हुआ ।

गंठबन्धन के बाद

इंगलैंड के बाद और कई देशों ने भी गोल्ड स्टैंडर्ड का परित्याग कर दिया। वास्तव में यह कोई अन्ध अनुकरण नहीं था—सब मजबूर होकर सोने को तलाक देने लगे थे। सोने से बंधे रहते हैं तो दाम ऊँचे हो नहीं सकते, और जो देश अपनी मुद्रा की कीमत सोने के मुकाबिले गिरा देता है वह प्रतियोगिता में अपना माल सस्ता बेचने की क्षमता पा जाता है—यह विचार कर कई देशों ने अपने-अपने प्रतीक को सोने के बन्धन से मुक्त कर दिया। अमेरिका भी १९३३ में सोने से हट गया, यद्यपि कुछ समय बाद वह अपने डॉलर की कीमत घटाकर गोल्ड स्टैंडर्ड पर वापस आ गया। सोने में डॉलर की कीमत जहाँ १०० थी वहाँ अब घटाकर ६० कर दी गई।

सोने के बन्धन से प्रतीक-मुद्राओं को मुक्त करने और इनका मूल्य गिराने का रहस्य क्या था, यह इस प्रकार समझाया जा सकता है—

मान लीजिए, इंगलैंड और अमेरिका दोनों गोल्ड स्टैंडर्ड पर हैं और १ पौंड = ४८६ डॉलर—यह एक्सचेंज-रेट है। यह भी मान लीजिए कि किसी चीज का पड़ता इंगलैंड में १ पौंड है और अमेरिका में ४८६ डॉलर।

इंगलैंड ने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया और सोने के मुकाबिले पौंड की कीमत घट गई। अमेरिका गोल्ड स्टैंडर्ड पर कायम है, इसलिए एक्सचेंज-रेट में फर्क पड़ गया और जहाँ पहले १ पौंड के ४८६ डॉलर होते थे वहाँ अब (उदाहरणार्थ) ३७४ ही होने लगे।

अमेरिका में उस वस्तु का दाम वही ४८६ डॉलर है जो पहले था। इसलिए इंगलैंड का व्यवसायी अगर अपना माल अमेरिका भेजता है

तो वहा उसका दाम ४८६ डॉलर उठता है। नई एक्सचेंज-रेट (३७४ डॉलर = १ पौंड) से यह रकम इंग्लैण्ड में २६ शिलिंग होती है।

वहा पहले पड़ता था २० शिलिंग का। अब यह कुछ ऊंचा हो चला होगा। पर स्पष्ट है कि जब तक पड़ता २६ शिलिंग नहीं हो जाता तब तक इंग्लैण्ड के व्यवसायी को नई एक्सचेंज-रेट के कारण विशेष लाभ रहेगा और वह प्रतियोगिता में अमेरिका के व्यवसायी को पछाड़ता जायगा।

मान लीजिए इंग्लैण्ड में अब पड़ता २३ शिलिंग हो चला है। अगर अमेरिका का माल वहा जाकर बिकता है तो उसका दाम २३ शिलिंग उठता है और नई एक्सचेंज-रेट से २३ शिलिंग के प्राय ४३० डॉलर होते हैं। चूँकि अमेरिका का पड़ता ४८६ डॉलर का है, वहा का माल इंग्लैण्ड जाकर न बिक सकेगा। प्रत्युत इंग्लैण्ड का माल अब विशेष रूप से अमेरिका जाने लगेगा। वहा का पड़ता २३ शिलिंग है। अमेरिका में दाम ४८६ डॉलर है, जिसके २६ शिलिंग होते हैं। ऐसी अवस्था में इंग्लैण्डवाले वहा अपना माल ४८६ डॉलर से कम में बेच कर भी नफे में ही रहेंगे। अगर उन्होंने ४६८ डॉलर में ही बेचा तो भी उन्हें तो प्राय २५ शिलिंग मिल गए और अमेरिका के कल-कारखानेवालों का व्यवसाय चौपट हो गया।

पर ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका भी गोल्ड स्टैंडर्ड का परित्याग कर दे और सोने के मुकाबिले अपनी मूद्रा की कीमत उसी हद तक गिरा दे (जिस हद तक इंग्लैण्ड गिरा चुका है) तो (और सब बातें समान होते हुए) एक्सचेंज-रेट फिर वही १ पौंड = ४८६ डॉलर हो चलेगी और ऐसी साम्यावस्था होने पर विशेष लाभ या हानि का प्रश्न ही न रहेगा। हा, अगर अमेरिका सोने के मुकाबिले अपने प्रतीक की कीमत, इंग्लैण्ड से भी अधिक गिरा दे, तो साम्य की जगह फिर वैपम्य उपस्थित हो जायगा और गंगा उलटी दिशा में बहने लगेगी—अर्थात् प्रतियोगिता में अब अमेरिका इंग्लैण्ड को दवाने लगेगा।

इन्ने-गिने देशों को छोड़ प्राय सभी गोल्ड स्टैंडर्ड से अलग हो गए। १९३४ में केवल आधे दर्जन देश गोल्ड स्टैंडर्ड पर रह गए थे। इन्हे विदेशी

प्रतियोगिता-रूपी आक्रमण में अपने-आपको बचाने के लिए तरह-तरह के उपायों का अवलम्बन करना पड़ा। जकात या टैरिफ की दीवारें और भी ऊंची कर दी गईं—विनिमय के व्यवसाय को इस प्रकार में नियंत्रित कर दिया गया कि बाहर में कम-से-कम माल आ सके। जो देश गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ चुके थे वे इनका जवाब दिए बिना कब रह सकते थे ? नतीजा यह हुआ कि व्यापार के क्षेत्र में प्रायः सभी देश ऐसी लड़ाई लड़ने लग गए जैसी इसमें पहले कभी देखी या सुनी नहीं गई थी। प्रत्येक देश अपनी रण-नीति को सफल बनाने के लिए विभिन्न अस्त्र-धन्यों का प्रयोग करने लगा। इंग्लैंड बहुत बड़े अरम में इस सिद्धांत का प्रतिपादक बन आ रहा था कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग में किसी भी देश को किसी भी हालत में जकात या शुल्क-रूपी अवरोध खड़ा करना नहीं चाहिए। पर अब कावे में ही 'कुफ्र' मुनाई देने लगा। अपने उद्योग-धन्यों की जान बचतरे में देख इंग्लैंड ने उस पुराने सिद्धान्त को ताक पर रख दिया और अब "स्वतन्त्र व्यापार" (Free Trade) से "संरक्षण" (Protection) का हिमायती बन गया। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में स्वतन्त्रता या स्वच्छन्दता नाम की अब कोई चीज ही नहीं रह गई—कदम-कदम पर प्रतिबन्ध, नियन्त्रण, अटकाव नजर आने लगे। बार-प्रहार, घात-प्रतिघात करने-करते जब दो देश थक जाते तब आपस में समझौता या इकरार-नामा करके यह तय कर लेते कि कौन किसमें कितना माल लिया करेगा। पर इस प्रकार का समझौता भी व्यापार के क्षेत्र को संकुचित ही करने-वाला होता। आश्चर्य नहीं कि सारे मसार के व्यापार की मालियत जहाँ १९२९ में १०० थी वहाँ १९३३ में प्रायः ३३ ही रह गई थी।

तुलनात्मक दृष्टि में कहा जा सकता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड पर रह जाने-वाले देशों की अपेक्षा उसमें अलग हो जानेवाले देश अच्छे रहे। इन देशों में दामों की अधोगति कुछ समय के बाद रुक गई और वे ऊपर चढ़ने लगे। १९२९ से १९३२ तक के अध्याय का नाम अगर 'अन्धकार' रखा जाय तो १९३३ से १९३७ तक के अध्याय को 'अरण्योदय' कहा जा सकता है। पर यह इंग्लैंड और अमेरिका-जैसे देशों के ही सम्बन्ध

में। यहा भारतवर्ष में तो अन्धकार बना ही रहा— कहना चाहिए कि १९३२ के बाद वह और भी घनघोर हो चला। नीचे के 'सूचक अंक' यही जाहिर करते हैं।

जिन्सों के धोक दाम			
	भारतवर्ष (कलकत्ता)	इंग्लैण्ड	अमेरिका
१९२९	१००	१००	१००
१९३०	८२	८८	९१
१९३१	६८	७७	७७
१९३२	६५	७५	६८
१९३३	६२	७५	६९
१९३४	६३	७७	७९
१९३५	६५	७८	८४
१९३६	६५	८३	८५
१९३७	७२	९५	९१
१९३८	६८	८९	८२

१९३७ में जो सुधार दिखाई देता है वह अमेरिका में तेजी की एक लहर के आने का नतीजा था। पर वह स्थायी न हो सका और दाम फिर गिर पड़े। खासकर भारतवर्ष का यह हाल हुआ कि 'चार दिना की चादनी, फिर अन्धियारी रात।' १९३८ में हम फिर वही जा पहुँचे जहा १९३१ में थे।

जब इंग्लैण्ड गोल्ड स्टैण्डर्ड पर था तब वहा एक औंस खालिस सोने का दाम प्राय ८५ शिलिंग होता था। पर स्टर्लिंग और सोने का सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने पर वह दाम ऊँचा हो चला अर्थात् सोना स्टर्लिंग में पहले की अपेक्षा महंगा बिकने लगा। कई साल तक यह दाम १४० शिलिंग के आस-पास या उससे भी ऊपर रहा। इसके दो खास नतीजे हुए। नोट-प्रसारक बैंको के पास जो सोना था उसकी कीमत बढ़ जाने से, उनके लिए उसके आधार पर और भी नोट जारी कर देना सम्भव हो गया। इससे चीजों के दाम ऊपर उठाने में सहायता मिली। उधर सोने की खानों के

मालिकों का मुनाफा बढ़ गया और इसके फलस्वरूप सोने का उत्पादन अधिकाधिक होने लगा । १९२९ से १९३७ तक ससार में सोने का उत्पादन इस प्रकार हुआ —

	टन
१९२९	६००
१९३०	६३९
१९३१	६२५
१९३२	६७८
१९३३	७०७
१९३४	७५६
१९३५	८२४
१९३६	९२१
१९३७	९९०

चूँकि रुपया स्टर्लिंग से सम्बद्ध था, यहाँ भी सोना पहले से महंगा रहने लगा । अगस्त १९३१ के अन्त में—जब भारतवर्ष गोल्ड स्टैंडर्ड पर था—यहाँ सोने का दाम २१॥१—) था । उसके बाद इस दाम में जो वृद्धि हुई वह नीचे की तालिका में दिखाई गई है । साथ ही स्टर्लिंग में भी सोने की कीमत दे दी गई है —

सोने का ऊँचे से ऊँचा दाम

लन्दन में (प्रति औंस) *		वम्बई में (प्रति तोला)		
	पौ०	शि०	पै०	रु० आ० पा०
अप्रैल १९३३	६	२	६	३०—०—०
„ १९३४	७	५	८॥	३६—१२—०
„ १९३८	७	०	१॥	३५—०—०
„ १९३९	७	८	६॥	३७—१—३

पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि १९३१ में एक असाधारण बात यह हुई कि यहाँ से सोने की रपतनी होने लगी । आन्तरिकता का

* १ औंस = ४८० ग्रेन, १ तोला = १८० ग्रेन, अर्थात् ३ औंस = ८ तोला

और कोई उपाय न देख कर विपन्न भारतवर्ष ने अपना सोना बेचना आरम्भ कर दिया और चूँकि भारत-सरकार इस सोने की खरीदार नहीं थी, यह सोना विदेश जाने लगा। भारतवर्ष से इधर कब कितना सोना बाहर गया है यह नीचे के अंको से स्पष्ट होगा —

साल	रुपए (लाख)
१९३१-३२	५७,९७
१९३२-३३	६५,५२
१९३३-३४	५७,०५
१९३४-३५	५२,५४
१९३५-३६	३७,३५
१९३६-३७	२७,८४
१९३७-३८	१६,३३
१९३८-३९	२३,२६
१९३९-४०	४४,६४

३,८२,५० लाख रुपए

आम तौर से यह देश बराबर सोने का खरीदार रहा है। इस बीसवीं सदी के आरम्भ के ३० वर्षों में यहाँ प्रायः ७ अरब रुपए का सोना बाहर से आया था। इन ९ वर्षों में उसमें से प्रायः ४ अरब का सोना बाहर चला गया। किसीने ठीक ही कहा था कि जितना सोना हमने इन वर्षों में खो दिया उतना तैमूरलंग और नादिरशाह भी यहाँ से लूट कर न ले गए होंगे।

इस बात के लिए हमारे नेताओं और प्रजा-प्रतिनिधियों की ओर से काफी कोशिश की गई कि सोने की इतने बड़े पैमाने पर रफ्तानी न हो और सरकार या रिजर्व बैंक इस सोने को खरीदकर नोटों की पुष्टी के लिए यही रखती जाय, पर कुछ भी नतीजा न निकला। सरकार की ओर से बराबर यही जवाब दिया गया कि खरीद-विक्री या व्यापार की दृष्टि से जैसी और चीजे हैं, वैसा सोना है, फिर जब दूसरी चीजों के लिए कोई रुकावट नहीं है तब सोने के लिए ही क्यों हो? हमारे देश में अगर राष्ट्रीय

सरकार होती तो ऐसी बात मुह से न निकालती और सोना सचित्त का जो यह सुअवसर उपस्थित हुआ था उसे हाथ से न जाने देती।

सोने के सम्बन्ध में हमारे शासक हमको तो अनासक्ति और त्याग का उपदेश देते जाते थे और स्वयं अपने देश में सोने में चिपटे जाते थे बल्कि यथासंभव उसका परिमाण बढ़ाते जाते थे। बैंक ऑफ़ इंग्लैंड के पास जहाँ १९३१ में सब मिलाकर १२५,४०१,६२८ पाँड का सोना था वहाँ १९३७ में वह रकम ३२६,४०६,६२५ पाँड हो चली थी। 'हमको लिखि-लिखि योग पठावत आपु करत रजधानी'।

सोने की इस रफतनी की असलियत क्या थी, यह दिखाने के लिए हम परिपद् में किए हुए एक अंगरेज सदस्य के भाषण से कुछ अंश उद्धृत करते हैं।

मार्च १९३३ को व्यवस्थापिका परिपद् में वजट की आलोचना करते हुए सर लेस्ली हडसन ने कहा था —

“पूरव बंगाल के किसानों की अवस्था अत्यन्त दयनीय है। १९३१ में नदियों की बाढ़ के कारण उनकी कर्जदारी बेहद बढ़ गई। १९३२ में फसल अच्छी जरूर हुई, पर दाम इतने नीचे थे कि किसान अपने कर्ज न चुका सके। जीवन-निर्वाह के लिए उन्हें अपने पीतल के बर्तन और मकानों में लगी हुई लोहे की चादरे-जैसी चीजें भी बेच देनी पड़ी। पहले तो उन्होंने अपने मोने-चादी के जेवर बेच डाले, फिर जब इसमें भी पूरा न पड़ा तब उन्होंने और मालमता बेचना शुरू कर दिया। पीतल और अरमूमीनियम के बर्तन विक गए, उनकी जगह मिट्टी के बर्तनों ने ले ली। पर किसानों की मुसीबत की कहानी यही समाप्त नहीं होती। अब वे अपनी झोपड़ियों की भी आहुति देने लग गए हैं। और तो उनके पास कुछ है नहीं—उन झोपड़ियों में लगी हुई लकड़ी या लोहे की जो कीमत उन्हें मिल सकती है वही अब उनका एकमात्र अवलम्ब रह गई है।

“हमारे अर्थ-सदस्य ने मोने के निर्यात के सम्बन्ध में जो यह कहा है कि उसीकी बदौलत हमारी रक्षा हो सकती है—हम इस बवडर में उड़ जाने से बच गए हैं, यह सच है, पर मोना क्यों बिका या बिकता जा रहा है, इसका जो उत्तर हमारे अर्थ-सदस्य ने दिया है मैं उसे ठीक नहीं मानता।

उनका कहना है कि लोगों का जो पू जी-पल्ला सोने के रूप में था अब वे उसे दूसरा रूप देने लगे हैं। असलियत कुछ और ही है। कम-से-कम इस बात में उतनी सचाई नहीं जितनी हमारे अर्थ-सदस्य समझते हैं। बाहर जाने वाले सोने का बहुत बड़ा हिस्सा सुख या समृद्धि नहीं बल्कि दुःख या दारिद्र्य का सूचक है—अर्थात् उसे बेचनेवाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने धन या पू जी को दूसरा रूप देने के लिए ऐसा नहीं किया है, बल्कि जिन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए—चावल, आटा, दाल, नमक खरीदने के लिए—अपना संचित सुवर्ण बेच देना पड़ा है।”

यहां कुछ चादी के भी सम्बन्ध में कहने की जरूरत है।

अगस्त १९३१ में—जब इंग्लैंड गोल्ड स्टैंडर्ड पर था—लन्दन में चादी का दाम (फी स्टैंडर्ड औंस) १३ पेंस के आसपास था। सितम्बर में, इंग्लैंड के गोल्ड स्टैंडर्ड से हट जाने पर, यह दाम प्रायः १९ पेंस हो चला। भारतवर्ष में इधर दाम इस प्रकार रहा—

			१०० तोले का
			६० आ०
मार्च	१९३१-३२	(औंसत)	५६-२१ ^१ / _२
"	१९३२-३३	"	५६-२३ ^१ / _२
"	१९३३-३४	"	५६-३३ ^१ / _२
"	१९३४-३५	"	६५-२
"	१९३५-३६	"	४९-३३ ^१ / _२
"	१९३६-३७	"	५३-०३ ^१ / _२
"	१९३७-३८	"	५०-१५ ^३ / _४
"	१९३८-३९	"	५२-१५ ^३ / _४

लन्दन में १२ जून १९३३ को आर्थिक विषयों पर अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के लिए एक कांफ्रेंस बैठी। इसमें ६४ राष्ट्र सम्मिलित हुए। पर कोई समझौता न हो सका। सबसे गहरा मतभेद मुद्रा-सम्बन्धी प्रश्न पर हुआ और कांफ्रेंस निष्फल साबित हुई। हा, उसमें चादी के सम्बन्ध में एक समझौता ऐसे

देशों के बीच जट्टर हुआ जो या तो चादी के उत्पादक थे या जिनके पास काफी परिमाण में चादी इकट्ठी थी।

पर चादी के बाजार पर इस समझौते का कोई ग्रास असर नहीं पड़ा। लोग पहले से ही यह धारणा किए बैठे थे कि इस प्रकार का कोई समझौता होकर ही रहेगा। इसलिए दाम जहाँ तक उठ सके थे पहले ही उठ चुके थे।

इस समझौते या इकरारनामे की मीयाद १९३७ के अन्त में पूरा हो गई।

भारत-सरकार ने डबल भी बराबर चादी बेचना जारी रखा। १९३१-३२ से रुपए खींच कर गला दिए जाते और उनकी चादी बेच दी जाती। १९३१-३२ और १९३९-४० के बीच सरकार-द्वारा बाहर में जानेवाली चादी २० करोड़ औंस से ऊपर थी। चलन में चादी के रुपए का स्थान या तो नोटों ने ले लिया या वह खाली रहा।

१९३१-३२ और १९३८-३९ के बीच, चलन में जानेवाले रुपयों का जोड़ ५७,४५ लाख बैठता है, और चलन से निकलनेवाले रुपयों का जोड़ ५४,४४ लाख। प्यासे को किस हद तक पानी मिल सका, इस सम्बन्ध में और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं।

इस देश में जिन्सों के आयात से निर्यात अधिक होता रहा है। वास्तव में हम उसी आधिक्य के रूप में अपनी देनदारी* चुकाते आए हैं। १९२४-२५ से १९२८-२९ तक उस आधिक्य का औसत ११० करोड़

* “भारतवर्ष अपनी जिन्सों के निर्यात से जिन्सों के आयात का ही दाम नहीं चुकाता, कुछ ऐसे आयात का भी दाम चुकाता है जो अदृश्य रूप से हुआ करता है। इस अदृश्य आयात में इंग्लैंड को Home Charges तथा अन्य रूप में जानेवाली रकमें शामिल हैं। इनका जोड़ हर साल प्रायः ८० करोड़ रुपए बैठता है।”—

भारतीय व्यापारी महासभा (फेडरेशन) के दशम अधिवेशन के अध्यक्ष श्रीमंत देवीप्रसाद खतान का भाषण (अप्रैल, १९३७)।

रुपए से अधिक पड़ा था। पर १९३२-३३ में वह घटकर केवल ३ करोड़ रुपए के लगभग रह गया था। उसके बाद स्थिति कुछ सुधरी, पर यथेष्ट रूप से नहीं। अगर इन वर्षों में सोने का निर्यात सहायक न होता तो अदृश्य रूप से होनेवाले आयात का दाम हमसे न चुकता और हमारी देनदारी और भी बढ़ जाती।

अपने देश के किसानों की दीनता-हीनता का कर्जंदारी से रास सम्बन्ध है। १९२८-२९ में कुछ विशेषज्ञ जाच-पड़ताल के बाद इस नतीजे पर पहुँचे थे कि सारे भारतवर्ष के किसानों का कुल कर्ज ९ अरब रुपए के करीब था। भिन्न-भिन्न प्रांतों में यह इस प्रकार विभक्त था —

सारा कर्ज
(करोड़ रुपए)

मद्रास	१५०
बम्बई	८१
बंगाल	१००
संयुक्त प्रांत	१२४
मध्य प्रांत	३६
पंजाब	१३५
विहार-उड़ीसा	१५५
आसाम	२२
केन्द्रीय इलाका	१८
बर्मा	६०

ब्रिटिश भारत

८८१ करोड़

देशी रियासतों के किसानों का कर्ज इसके अलावा था।

अब देखिए मन्दी का इस कर्जंदारी पर क्या असर पड़ा। गल्ले के दामों में प्रायः ५० प्रतिशत कमी हो जाने से कर्जंदारों का बोझ यों ही दूना हो गया। कारण यह कि जो १० मन अनाज बेचकर कर्जंदारी से छुटकारा पा सकता था उसे अब २० मन जुटाना पड़ता था। अगर यह मान लिया जाय कि ऐसी

मन्दी के समय में किसान न तो असल अदा कर सकते थे, न सूद, तो हमारे अर्थशास्त्रियों का यह तख्तीना सही समझा जा सकता है कि जो बोझ १९२९ में ९ अरब रुपए था वह १९३३ में २२ अरब रुपए के बराबर हो चला था।

दामो को बढ़ाना और उसके द्वारा किसानों या कर्जदारों की रक्षा करना भारत-सरकार की नीति के प्रतिकूल था। उधर असन्तोष और अशांति की वृद्धि के कारण परिस्थिति भयंकर होती जा रही थी। इस कारण प्रांतीय सरकारों के लिए चुपचाप बैठे रहना भी असंभव था। उन्होंने इधर कुछ ऐसे कानून बनाए जिनका उद्देश था साहूकार के पावने की रकम को कम कराके कर्जदार को डमदाद पहुंचाना। कुछ हद तक सरकारी लगान में भी छूट दी गई। पर इन उपायों से किसानों का कष्ट कहा तक दूर हो सकता था? उनकी वास्तविक सहायता या रक्षा का उपाय था ऐसी नीति का अवलम्बन जो दामो को ऊपर चढ़ा सके या कम-से-कम उन्हें नीचे गिरने से रोक सके। पर हमारी सरकार की नीति तो उन्हें नीचे की ही दिशा में ढकेलनेवाली थी—उससे यहाँ के किसानों की भलाई की आशा कैसे की जा सकती थी? दामो की मन्दी और हमारी सरकार की एक्सचेंज-नीति, चक्की के इन दोनों पाटों के बीच पड़कर हमारे किसान तग-तबाह हो गए।

दिसम्बर १९३३ में जब रिजर्व बैंक से सम्बन्ध रखनेवाला विल परिषद् में विचाराधीन था, वहाँ इस बात की चेष्टा की गई कि एक्सचेंज-रेट को स्थायी रूप से १८ पैसे न करके इस प्रश्न पर पुनर्विचार की गुंजाइश रहने दी जाय। विल में यह व्यवस्था थी कि जब रिजर्व बैंक स्थापित हो जाय—और इसमें अभी कुछ देर थी—वह प्रायः १८ पैसे की रेट से स्टर्लिंग खरीदने और बेचने को बाध्य हो।

१९२७ के विधान में स्टर्लिंग खरीदने की सरकार पर कोई जिम्मेवारी नहीं थी—जिम्मेवारी २१½) १० तोला के भाव से (सालिस) सोना खरीदने की थी। बाजार में १९३१ के बाद सोने का भाव इससे कहीं ऊँचा हो रहा था, इसलिए सरकार की वह जिम्मेवारी अब कोई अर्थ नहीं रखती थी। अब सरकार अपने ऊपर स्थायी रूप से सोने की

जगह स्टलिंग खरीदने की जिम्मेवारी लेने जा रही थी। उमरी ओर से यह कहा जा चुका था कि कानूनन जा स्थिति इस समय, उमम विनी प्रकार का परिवर्तन करना हमें अभीष्ट नहीं। परिपद में पूछा गया कि अगर बात ऐसी ही है तो स्टलिंग खरीदने की जिम्मेवारी आप अपने ऊपर क्यों लेने जा रहे हैं? गैर यह तो एक विधि-विषयक छाटी-सी बात हुई। विशेष आपत्तिजनक बात तो यह थी कि सरकार भविष्य के लिए स्टलिंग खरीदने या बेचने की दर अभी मुकर्रर करने जा रही थी। गैर-सरकारी मेम्बरो ने सरकार की इस कार्रवाई का घोर विरोध किया और उनकी ओर से इस विषय में सम्बन्ध रखनेवाले कई सशोधन पेश किए गए। उनमें एक सशोधन इस आशय का था कि एक्सचेंज-रेट अभी निश्चित न की जाय—सारे प्रश्न का निर्णय भविष्य के लिए छोड़ दिया जाय। रिजर्व बैंक की स्थापना में अभी देर थी, इसलिए उसके द्वारा सोने या स्टलिंग की खरीद-बिक्री का प्रश्न अभी कुछ काल तक उठनेवाला नहीं था। फिर भी सरकार इसी समय दर को निश्चित कर देने पर तुली हुई थी और उसने जो चाहा, कर दिया। इस प्रश्न से सम्बन्ध रखनेवाला एक भी सशोधन परिपद-द्वारा स्वीकृत न हो सका, और रिजर्व बैंक-द्वारा स्टलिंग की खरीद-बिक्री के लिए १८ पैसे की रेट निर्धारित हो गई।

दिसम्बर १९३८ में श्रीसुभाषचन्द्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया—

“जब से रुपए की दर १८ पैसे मुकर्रर कर दी गई तब से यहाँ व्यवसायी-वर्ग और यहाँ की सार्वजनिक सस्थाएँ इसका विरोध करती रही हैं। उनकी मांग यह रही है कि चूँकि हुण्डी की यह दर, आर्थिक से, भारतवर्ष के लिए अहितकर है, इसमें रद्दोदल होना जरूरी है। सरकार इस लोकमत की उपेक्षा करती आई है। ६ जून (१९३८) उसने इस विषय पर एक वक्तव्य निकाल कर कहा कि वह हुण्डी की कोई भी हेर-फेर करना नहीं चाहती और दलील यह पेश की कि करने से परिस्थिति इतनी डवाडोल और अनिश्चित हो जायगी कि को लाभ के बदले हानि उठानी पड़ेगी।

“समिति की राय में १८ पेंस की दर से यहा के किसानों की गहरी हानि हुई है। इसने उनकी पैदावार की कीमत गिरा दी है और बाहर से आनेवाले माल को नाजायज फायदा पहुंचाया है।

“कार्यकारिणी समिति का विश्वास है कि अगर व्यापार की यही हालत बनी रही तो यह दर आगे टिकनेवाली नहीं है। पिछले ७ वर्षों में यह सिर्फ सोने के बड़े पैमाने पर निर्यात के कारण ही टिक सकी है। उस निर्यात से देश की बड़ी क्षति हुई है। अब इसको आगे टिकाने के लिए गिरावट के सिवा और कोई रास्ता नजर नहीं आता। भारतवर्ष के पास सोने और स्टर्लिंग के रूप में जो सम्पत्ति बच गई है उसको बरबाद करके ही हुण्डी की यह दर कायम रखी जा सकती है। जो स्टर्लिंग था वह पहले भी बहुत कुछ स्वाहा हो चुका है, अगर भारत-सरकार ने इस दर को टिकाने के प्रयत्न से मुंह न मोड़ा तो बचा-खुचा स्टर्लिंग भी जाता रहेगा। कार्यकारिणी की दृष्टि में ऐसी सम्भावना अत्यन्त चिन्ताजनक है।

“परिस्थिति को देखते हुए कार्यकारिणी इस नतीजे पर पहुंची है कि देश की भलाई इसी में है कि हुण्डी की दर को टिकाने का प्रयत्न छोड़ दिया जाय और सरकार इसे शीघ्रातिशीघ्र १६ पेंस कर देने की दिशा में अग्रसर हो।”

पर सरकार का उस दिशा में अग्रसर होना एक असंभव-सी बात थी। ऊंची दर कायम की गई थी इंग्लैण्ड के हित की दृष्टिसे, और जब तक इंग्लैण्ड का यहा आधिपत्य था तब तक यहा की सरकार की नीति में वैसे परिवर्तन की आशा दुराशा-मात्र थी। कार्यकारिणी के प्रस्ताव का उसकी ओर से जो उत्तर दिया गया उसमें एक बार फिर वही पुराना झूठ दोहराया गया कि हुण्डी की दर गिरने से किसानों का लाभ नहीं बल्कि हानि है।

बड़े पैमाने पर सोने की रफ्तानी से इतना जरूर हुआ कि १८ पेंस की दर टिकाने में सरकार को किमी कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ा। हमारा सोना गया, रेट अपनी जगह बनी रही।

रिजर्व बैंक की स्थापना

१९३१ के बाद की घटनाओं में यहाँ रिजर्व बैंक की स्थापना महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

इस प्रकार की बैंक से सम्बन्ध रखनेवाला प्रस्ताव प्रायः सौ व. पुराना बताया जाता है। १८३६ में कुछ अंगरेज व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के संचालकों के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि भारत में एक ऐसी बड़ी बैंक स्थापित की जाय जिसमें साधन और शक्ति के रूप से केन्द्रीभूत हो और जिसका यहाँ के सराफा-बाजार पर पूरा जाल पड़्य हो। पर यह प्रस्ताव ही रहा। १८६७ में फिर इस विषय की चर्चा हुई—तीनों प्रेमियेसी बैंकों को सम्मिलित कर एक अविलम्ब बैंक कर देने की सलाह सरकार को दी गई, पर कुछ नतीजा न मिला। इसके बाद भी दो-एक मौकों पर यह प्रश्न सरकार के सामने लाया पर इससे परिस्थिति में कुछ भी अन्तर न पड़ा। चेम्बरलेन-कमिटी सदस्य अध्यापक (वर्तमान लॉर्ड) केन्स ने, दूसरे सदस्य सर अर्नेस्ट के सहयोग से, इस सम्बन्ध में एक स्कीम तैयार की, पर महासमर १८ के कारण इसपर विचार भी न हो सका। शान्ति स्थापित हो फिर ऐसी केन्द्रीय बैंक के प्रश्न की ओर लोगों का ध्यान गया और यह दीखने लगा कि कुछ-न-कुछ होके ही रहेगा। सफलता की इस समय सबसे व्यावहारिक उपाय यही समझा गया कि तीनों प्रेमियेसी का एकीकरण कर दिया जाय। अन्त में इसी एकीकरण से स्मिथि. तृप्ति हुई। इससे सम्बन्ध रखनेवाला विधान सितम्बर १९२० हुआ और २७ जनवरी १९२१ से अमल में लाया गया।

पर अभीष्ट-सिद्धि न हो सकी। इम्पीरियल बैंक में उन सब बातों का समावेश न था जो किसी देश या राष्ट्र की नीति को त्रियात्मक रूप देनेवाली सबसे प्रधान बैंक में होनी चाहिए। उसमें कई दोष नजर आने लगे। इम्पीरियल बैंक न तो सरकारी बैंक थी, न यथार्थतः सार्वजनिक। वह कुछ शेयरहोल्डरों के हाथ की चीज थी जिसमें अगरेजों का प्राधान्य था—जिसकी नीति-रीति भारतीय वाणिज्य-व्यवसाय की दृष्टि से पूर्णतः सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती थी। जो बैंक सर्वोपरि हो—जो वास्तव में इस व्यवसाय-चक्र की धुरी का काम करे—उसे ऐसा काम-काज नहीं करना चाहिए जिससे और बैंकों की प्रतिगोहिता हो। पर इम्पीरियल बैंक पर इस प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था—व्यवसाय के क्षेत्र में वह प्रायः और बैंकों के ही समान थी, जिसका अर्थ होता है कि जो उनसे प्रतियोगिता करती थी उसी पर उनके संरक्षण की जिम्मेवारी थी। सेण्ट्रल अर्थात् केन्द्रीय बैंक को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह कुल सरकारी रोकड़ रखे और नोटों के प्रसार का प्रबन्ध करे। इम्पीरियल बैंक को कुल रोकड़ रखने का अधिकार प्राप्त नहीं था—उदाहरणार्थ, गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व सरकार अपने हाथ में ही रखती थी। नोटों के प्रसार का काम भी उसे नहीं सौंपा गया था, इसलिए पेपर करेंसी रिजर्व भी उसके दायरे से बाहर था। कुछ ही समय बाद यह सिफारिश की जाने लगी कि भारतवर्ष में एक ऐसी नई बैंक स्थापित की जाय जो विशुद्ध सेण्ट्रल या रिजर्व (निधि) बैंक का काम करे—जिमपर करेंसी और एक्सचेंज-सम्बन्धी पूरी जिम्मेवारी हो—और जिसे यह जिम्मेवारी पूरी करने के लिए सरकार से विशेष अधिकार प्राप्त हो। हिट्टन यंग कमीशन की यह एक ग्रास सिफारिश थी—यद्यपि १९३४ से पहले रिजर्व बैंक-सम्बन्धी विधान न बन सका।

सरकार की ओर से जो भ्रमविदा १९२७ में पेश किया गया वह व्यवस्थापिका परिपद् को आपत्तिजनक जचा—ग्रास कर इसलिए कि उसके अनुसार रिजर्व बैंक सरकारी बैंक न हो कर, शेयर-होल्डरों की बैंक होती और उसके टाइरेक्टरों अथवा सचालकों की नियुक्ति उस प्रकार न होती जो भारतीय हित की दृष्टि से वाछनीय कहा जा सकता था। सरकार अन्त

में इस यानपर राजी हो गई कि रिजर्व बैंक शेयर-होल्डरो की बैंक न होकर सरकारी बैंक हो, पर डाइरेक्टरो की नियुक्ति के प्रश्न पर एक राय न हो सकी। अर्थ-सदस्य ने एक दूसरा मसविदा परिषद् के सामने रखा और कुछ लोगो को ऐसा दीखने लगा कि इसके आचार पर समझौता हो जायगा। पर भारत-सचिव को समझौते की बात मजूर नहीं थी, और उन्होने भारत-सरकार को उस दिशा में आगे बढ़ने से रोक दिया। अर्थ-सदस्य को परिषद् में यह कहना पड़ा कि डाइरेक्टरो के प्रश्न पर घोर मतभेद होने के कारण सरकार इस अधिवेशन में प्रस्तुत बिल पर और कुछ विचार करना-कराना मुनासिब नहीं समझती।

कुछ ही समय बाद उसकी ओर से दूसरा बिल प्रकाशित किया गया। इसमें कितनी ही नई बातें थी, पर बैंक को सरकारी बैंक बनाने की व्यवस्था नहीं थी। इस विषय में सरकार को उसी पुराने पहलू पर लौट जाना पड़ा था कि बैंक शेयर-होल्डरो की हो। साथ ही, यह भी व्यवस्था थी कि व्यवस्थापिका परिषद् या सभा के सदस्य इस बैंक के डाइरेक्टर न हो सकेंगे। पर परिषद् के अध्यक्ष ने अर्थ-सदस्य को यह बिल विचारार्थ उपस्थित करने की अनुमति नहीं दी। कारण यह था कि न तो इन्होंने पुराने बिल को बाकायदा वापस लिया था, न अभी इतना समय बीत पाया था कि वह बिल निरस्त या निर्जीव समझा जाय। विवश होकर अर्थ-सदस्य को सरकार की ओर से फिर उसी पुराने बिल को विचारार्थ उपस्थित करना पड़ा। पर ऐसा करते ही पुराना विरोध फिर जोर-शोर के साथ उठ खड़ा हुआ और सरकार को प्रत्यक्ष हो चला कि जो वह चाहती थी वह न हो सकेगा। लेहाजा १० फरवरी १९२८ को उसकी ओर से यह कहकर कि परिषद् के रख को देखते हुए इस दिशा में और आगे बढ़ने से कोई लाभ नजर नहीं आता—इस विषय की चर्चा यही समाप्त कर दी गई।

१९३१ में सेण्ट्रल बैंकिंग इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि रिजर्व बैंक यथाशीघ्र स्थापित की जाय। फिर लन्दन की राउण्ड टेबल कान्फरेस (गोलमेज परिषद्) की फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी ने भी प्रायः यही सिफारिश दोहराई। १९३३

मे राजनैतिक सुधारों के सम्बन्ध में, सरकारी की ओर से एक वयान निकला। उसमें कहा गया था कि केन्द्र में अर्थ-विभाग-सम्बन्धी जिम्मेवारी भारत-वासियों को सौंप देने की दृष्टि से रिजर्व बैंक का होना अनिवार्य है—और वह रिजर्व बैंक ऐसी होनी चाहिए जिसपर किसी प्रकार का राजनैतिक दबाव न पड़ सके। इस विषय पर फिर से विचार करने के लिए एक कमेटी बैठी। इसकी रिपोर्ट अगस्त १९३३ में निकली और इसकी सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक-सम्बन्धी तीसरा बिल ८ सितम्बर को दोनों व्यवस्थापिका सभाओं में पेश किया गया। इसपर विचार होता गया और इतिहास की पुनरावृत्ति की नीबट नहीं पहुँची। कुछ हेर-फेर के साथ इस बिल ने अन्त में विधान का रूप धारण किया और ६ मार्च १९३४ को इसे बड़े लाट की स्वीकृति मिल गई। १ अप्रैल १९३५ को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई।

रिजर्व बैंक शेयर-होल्डरों की बैंक है। इसकी पूंजी है पाच करोड़ रुपए, और प्रत्येक शेयर मी रुपए का है। कुछ शेयर भारत-सरकार इसलिए अपने हाथ में रखती है कि अगर कोई गरस सेण्ट्रल बोर्ड का डाइरेक्टर चुना जाय और उसके पास कम-से-कम उतने शेयर न हो जितने डाइरेक्टर के पास होने चाहिए, तो सरकार इन शेयरों में से कुछ उसके हाथ बेच कर उसकी कमी पूरी कर दे। शेयर-होल्डर अलग-अलग प्रांतों या प्रदेशों में विभक्त हैं। और प्रत्येक प्रांत या प्रदेश का अपना खास रजिस्टर है। ये रजिस्टर बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में रक्के जाते हैं। इस बात के लिए खास विधान है कि रिजर्व बैंक के शेयर-होल्डर वही हो सकते हैं जो भारतवर्ष (या बर्मा*) के निवासी हैं या जो ब्रिटिश प्रजा की परिभाषा के अन्तर्गत हैं। व्यक्तियों के साथ कम्पनियों को भी शेयर-होल्डर होने का हक हासिल है।

* १ली अप्रैल १९३७ से बर्मा भारतवर्ष से अलग कर दिया गया। इसके क्या कारण थे यह बताना यहाँ अप्रासंगिक होगा। पर राजनैतिक पृथक्करण के बावजूद भी रुपए का स्थान वहाँ पूर्ववत् हो बना रहा। निर्णय यह हुआ कि मुद्रा-सम्बन्धी व्यवस्था की दृष्टि से दोनों देश एक

मूल-विधान में सङ्गोघन करके अब यह व्यवस्था कर दी गई है कि बीस हजार रुपए ने अधिक का कोई भी शेयर-होल्डर नहीं माना जा सकता । बैंक की पूँजी, सेण्ट्रल बोर्ड की सिफारिश और व्यवस्थापिका सभाओं की सिफारिश ने घटाई-बटाई जा सकती है । सेण्ट्रल बोर्ड के लिए जरूरी है कि सिफारिश करने से पहले भारत-सरकार की अनुमति प्राप्त कर ले । पूँजी के अलावा बैंक के पास पाँच करोड़ का रिजर्व भी है । शेयर-होल्डरों को जो डिविडेंड या मुनाफा मिल सकता है वह सरकार द्वारा ३॥ प्रतिशत नियत है । उतना दे देने पर बचत होने की सूरत में उसका एक हिस्सा शेयर-होल्डरों को मिलेगा और बाकी सरकार ले लेगी ।

बैंक का संचालन और प्रबन्ध डाइरेक्टरों के सेण्ट्रल बोर्ड-द्वारा होता है । इसके १६ सदस्य होते हैं; यथा (क) एक गवर्नर और दो डिप्टी गवर्नर, जो भारत-सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, (ख) चार डाइरेक्टर, जिन्हें भारत-सरकार मनोनीत करती है, (ग) आठ डाइरेक्टर, जो शेयर-होल्डरों का प्रतिनिधित्व करते हैं—बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली की ओर से छ और मद्रास तथा रंगून की ओर से दो, (घ) एक सरकारी अपसर, जिसे भारत-सरकार मनोनीत करती है । सेण्ट्रल बोर्ड के अलावा पाँच लोकल बोर्ड हैं—प्रत्येक प्रांत या प्रदेश के लिए एक । इन लोकल बोर्डों के कुछ सदस्य शेयर-होल्डरों द्वारा निर्वाचित होते हैं, और कुछ सेण्ट्रल बोर्ड-द्वारा मनोनीत । लोकल बोर्डों का काम है सेण्ट्रल बोर्ड को सलाह देना और जो जिम्मेवारी उसके द्वारा सौंपी जाय उसे पूरा करना ।

बैंक का सर्वोच्च पदाधिकारी या कर्मचारी उसका गवर्नर है जो सेंट्रल बोर्ड का अध्यक्ष भी है । गवर्नर और डिप्टी गवर्नर भारत-सरकार-द्वारा

ही क्षेत्र समझे जायेंगे और व्यवस्थापक का पद भारतवर्ष की रिजर्व बैंक को प्राप्त होगा ।

वर्मा पर जापान का आधिपत्य हो जाने से पहले एक रजिस्टर रंगून में भी रखा जाता था । इस समय वर्मा की मुद्राप्रणाली जापान के अधीनस्थ और देशों की-सी हो चली है ।

स्टॉलिंग में अदा होनेवाली

सिक्कूरिटीज या सरकारी कागज	७३४,८३,९६,०००
	<u>७७९,२५,३९,०००</u>

(ख) रुपए

१२,८१,८४,०००

रुपए में अदा होनेवाली

सिक्कूरिटीज या सरकारी कागज	५८,३२,६५,०००
जोड़	<u>८५०,३९,८८,०००</u>

बैंकिंग विभाग

देनदारी—

पूजी	५,००,००,०००
------	-------------

रिजर्व फण्ड	५,००,००,०००
-------------	-------------

डिपॉजिट

(क) सरकारी

(१) भारत-सरकार	१३,८७,४०,०००
----------------	--------------

(२) बर्मा-सरकार	५०,७८,०००
-----------------	-----------

(३) दूसरी सरकारी रकमें	९,८९,८२,०००
------------------------	-------------

(ख) बैंको के	९०,१७,३९,०००
--------------	--------------

(ग) दूसरों के	७,१६,५७,०००
---------------	-------------

चुकनेवाले बिल	३,३७,८७,०००
---------------	-------------

दूसरी देनदारी	६,८१,२८,०००
---------------	-------------

जोड़	<u>१४१,८१,११,०००</u>
------	----------------------

सम्पत्ति—

नोट	९,५९,७२,०००
-----	-------------

रुपए	१७,९३,०००
------	-----------

रेजगारी	१,६०,०००
---------	----------

ट्रुडिया—जो खरीदी या डिस्कूट की गई

(क) देशी

.....

(ख) विदेशी
(ग) सरकारी ट्रेजरी बिल	३,२५,०००
रोकड जो विदेशों में है	१२०,६०,००,०००
सरकार को दिया गया कर्ज	२६,००,०००
दूसरों को दिए गए कर्ज	१८,७५,०००
जो रकम शेयरों में या और चीजों में लगी हुई है	७,६८,५३,०००
दूसरी सम्पत्ति	३,२५,३३,०००
	<hr/>
	१४१,८१,११,०००

नोट-प्रसार का जो काम पहले सरकार खुद किया करती थी वह अब रिजर्व बैंक के जिम्मे है। हा, बैंक-द्वारा निकाले गए नोटों के भुगतान की गारण्टी सरकार ने दे रखी है। इस काम के सुचारु रूप से सम्पादन के लिए भारतवर्ष छ सर्कलो में विभक्त है, यथा—कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, बम्बई, कराची और मद्रास।

ऊपर नोट-प्रसार विभाग का जो तलपट दिया गया है उसमें नोट-सम्बन्धी देनदारी ८ अरब ५० करोड ३९ लाख ८८ हजार रुपए की दिखाई गई है—अर्थात् उस तारीख को इतने रुपए के नोट खड़े थे और इनमें से प्रायः साठे नौ करोड के नोट बैंक के अपने बैंकिंग-विभाग में थे। जब चलन में नोटों का परिमाण बताया जाता है तब ऐसे नोटों को छोड़ कर। हा, सरकारी मजाने में या दूसरी बैंकों के पास जो नोट होते हैं वे शामिल कर लिए जाते हैं।

नोटों की पुष्टी के लिए बैंक के रिजर्व या कोष में जो धन है उसमें सबसे पहली चीज है सोना। इस समय जो कुछ सोना है वह इसी देश में है, अन्यत्र नहीं। पुष्टी के लिए जहा सोना प्राय ४४॥ करोड का था वहा स्टर्लिंग सिम्युस्टिटीज थी प्राय ७३५ करोड की। इधर लड़ाई छिड़ने के बाद भारत-सरकार ने एक रुपए के नोट जारी किए हैं। ये नोट भी तलपट के "रुपए" में शामिल हैं —अर्थात् कुछ हद तक नोटों की पुष्टी नोटों से ही की जा रही है।

वर्तमान अवस्था में मुद्रा-सम्बन्धी विस्तार या सकोच करने का उपाय है नोटों का परिमाण बढ़ा या घटा देना—और यह इस प्रकार किया जा सकता है—

अगर पुष्टी के लिए रुपए (जिनमें एक रुपए के नोट भी शामिल हैं), सोना या किसी प्रकार की सिक्यूरिटीज (कागज) बढ़ा दी जायें और दूसरी ओर उतने नोट जारी कर दिए जायें, तो यह मुद्रा-सम्बन्धी विस्तार होगा। जब रिजर्व बैंक को ऐसा विस्तार करना होता है तब वह अपने बैंकिंग-विभाग से सिक्यूरिटीज को उठा कर नोट-प्रसार-विभाग में डाल देती है और उसके मद्दे नोट जारी करके बैंकिंग-विभाग को दे देती है। इसके लिए यह भी किया जा सकता है कि नए ट्रेजरी बिल निकाल दिए जायें और उनके मद्दे नोट जारी कर दिए जायें। ये ट्रेजरी बिल बैंक की तिजोरियों में पड़े रहेंगे और जो नोट जारी होंगे उनकी पुष्टी करेंगे। जब मुद्रा-सम्बन्धी सकोच करना होता है तब बैंक नोट-प्रसार-विभाग से सिक्यूरिटीज को उठाकर बैंकिंग-विभाग में डाल देती है और उस विभाग से जो नोट मिलते हैं उन्हें रद्द कर देती है—क्योंकि नोट-प्रसार-विभाग में सिक्यूरिटीज की जगह नोट नहीं रखे जा सकते। यह भी हो सकता है कि सरकार ट्रेजरी बिलों का भुगतान कर दे और इस प्रकार नोट-प्रसार-विभाग में जो नोट आवे वे रद्द कर दिए जायें—अर्थात् मुद्रा-सम्बन्धी सकोच या कमी पैदा कर दी जाय। पहले करेन्सी और बैंकिंग-सम्बन्धी सूत्र अलग-अलग हाथों में थे। करेन्सी का काम स्वयं सरकार देखा करती और जहाँ तक बैंकिंग का सरोकार है वह इम्पीरियल बैंक से अपने साधन का काम लेती। अब परिस्थिति भिन्न है। सारे सूत्र रिजर्व बैंक के हाथ में आ गए हैं। करेन्सी, एक्सचेंज, बैंकिंग—इन सबसे सम्बन्ध रखनेवाली सरकारी नीति को त्रियात्मक रूप उसीके द्वारा मिलता है। प्रबन्ध-सम्बन्धी जहाँ पहले अनेकता थी वहाँ अब एकता है, और इस एकता के कारण अब वह समन्वय हो चला है जिसका पहले अभाव-सा था।

ऊपर संक्षेप में बताया जा चुका है कि करेन्सी के क्षेत्र में रिजर्व बैंक के कर्तव्य क्या हैं। यहाँ बैंकिंग के क्षेत्र में उसके कर्तव्य का दिग्दर्शन कराना है।

रिजर्व बैंक वास्तव में बैंको की बैंक है—इस सारे व्यवसाय की उमे धुरी या मेरुदण्ड समझिए। देश में जितनी ऐसी बैंके हैं जो कुछ महत्व रखती हैं और जो रिजर्व बैंक की मूची या शेडूल में दाखिल हो चुकी हैं—उन सबको एक निश्चित रकम इसके पास रखनी पड़ती है। वह रकम क्या होगी, यह पत्येक बैंक की अपनी देनदारी पर निर्भर है। अगर देनदारी ऐसी है कि पावनेदार के तलब करते ही चुका देनी चाहिए तो उसे उस देनदारी का कम-से-कम ५ प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास जमा रखना होगा। और अगर देनदारी चुकाने के लिए समय या मद्दत मिलने की गुंजाइश है तो उस बैंक को पांच की जगह दो प्रतिशत ही जमा कराना होगा। रिजर्व बैंक का जो तलपट ऊपर दिया गया है उसमें “बैंको के डिपॉजिट” प्रायः ९० करोड़ हैं। इसमें खास कर वह रकमें शामिल हैं जो शेडूल बैंको को—अपनी-अपनी देनदारी के अनुसार—रिजर्व बैंक के पास जमा करानी पड़ती हैं। और बैंको की तरह रिजर्व बैंक व्याज पर डिपॉजिट नहीं ले सकती। उस प्रतिबन्ध का उद्देश्य है उसे दूसरी बैंको की प्रति-योगिता करने से रोकना। इस प्रकार रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट रखना इन बैंको के लिए अपनी हिफाजत का बीमा है। गाढ़े समय में किसी भी बैंक को कर्ज के रूप में मदद के लिए रिजर्व बैंक के पास दौटना पड़ेगा और उसके पास डिपॉजिट के रूप में जितना अधिक धन जमा होगा उतना ही अधिक वह सहायतायियों की सहायता कर सकेगी।

यहां ‘शेडूल’ या तालिकान्तर्गत बैंको के विषय में कुछ और कहने की आवश्यकता है।

जब से रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, यहाँ की बैंके दो श्रेणियों में विभक्त हो चली हैं—एक तो वे, जो रिजर्व बैंक की तालिका के अन्तर्गत हैं, दूसरी वे जो उसके बाहर हैं। कोई भी बैंक—गुठ खाम शर्तें पूरी करने पर—तालिका में दाखिल हो सकती है। एक शर्त यह है कि वह ब्रिटिश भारत में काम-काज करनेवाली कम्पनी हो, दूसरी शर्त यह कि उसके पास कम-से-कम पांच लाख रूपए की पूंजी और रिजर्व हो। ऐसी बैंको की गणना ३१ मार्च १९४१ को ६४ थी। इनमें ५ वर्गों में काम करनेवाली बैंक थीं।

नवसे बड़ी शेड्यूल बैंक इम्पीरियल बैंक है। बैंकिंग क्षेत्र में इसका खास अपना स्थान है। कभी यह इस देश की सेण्ट्रल बैंक होने का हौसला रखती थी। आज भी यह कई कामों में एजेंट की हैसियत से रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करती है। इसके बाद विदेशी 'एक्सचेंज बैंको' का नम्बर है। इनकी संख्या २० है, और ये मुख्यतः विदेशी हुडियो के लेन-देन का काम करती हैं। उनके बाद आती हैं इस देश की पांच बड़ी बैंकों, जिनके नाम हैं—सेण्ट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया, बैंक ऑफ़ इण्डिया, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ोदा, और पंजाब नेशनल बैंक। इनमें प्रत्येक की जगह-जगह शाखाएँ हैं और प्रत्येक के पास पाँच करोड़ से अधिक डिपॉजिट हैं। बाकी बैंकों का नम्बर इन सबके बाद आता है और इनमें कुछ तो बड़ी हैं, पर कुछ बहुत ही छोटी या साधारण।

अब रिजर्व बैंक और शेड्यूल बैंकों के बीच के सम्बन्ध पर एक नजर डालनी है।

प्रत्येक शेड्यूल बैंक को रिजर्व बैंक के पास अपनी देनदारी के हिसाब से डिपॉजिट रखना पड़ता है, यह बात ऊपर बताई जा चुकी है। इसका असली उद्देश्य यह नहीं कि सर्वसाधारण का जो रुपया शेड्यूल बैंकों के पास जमा है उसे सुरक्षित किया जाय, क्योंकि दो या पाँच प्रतिशत के हिसाब से डिपॉजिट लेने से वह उद्देश्य पूरा होने का नहीं। उद्देश्य दरअसल यह है कि रिजर्व बैंक को इस देश की बैंकिंग प्रणाली या बैंकिंग व्यवसाय पर कुछ नियंत्रण रखने का अधिकार दिया जाय। प्रत्येक शेड्यूल बैंक के लिए यह जरूरी है कि वह भारत-सरकार को तथा रिजर्व बैंक को अपनी स्थिति से अभिज्ञ रखे। इसके लिए उसे प्रति सप्ताह (और अवस्था-विशेष में प्रतिमास) निर्दिष्ट प्रकार से तैयार करके अपना एक तलपट भेजना पड़ना है। न भेजने पर रिजर्व बैंक को अधिकार है कि वह उस बैंक के और उसके संचालकों के विरुद्ध मुतासिब कार्रवाई करे।

पर रिजर्व बैंक शासक होने के साथ सहायक भी है। शेड्यूल बैंकों के लिए कानून ने यह सुविधा कर दी है कि जरूरत पड़ने पर वे रिजर्व बैंक से कर्ज ले सकती हैं। यह कर्ज उन्हें कुछ खास तरह की सिक्यूरिटीज और

देने के लिए बाध्य नहीं जो उसके पास जमा रहता है । पर सार्वजनिक कर्ज-सम्बन्धी काम करने के लिए उसे सरकार से पुरस्कार या कमीशन मिलता है ।

विभिन्न आर्थिक विषयों पर—खास कर सार्वजनिक कर्ज लेते समय—भारत-सरकार और प्रांतीय सरकारें रिजर्व बैंक से सलाह मांगा करती हैं, और सलाह देने से पहले रिजर्व बैंक प्रत्येक विषय पर व्यापक दृष्टि से विचार कर लेती हैं ।

रिजर्व बैंक का एक ग्रास विभाग किसानों के कर्ज से सम्बन्ध रखने वाली समस्या के हल के लिए है । इस देश के लिए यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है यह बनाने की आवश्यकता नहीं । रिजर्व बैंक-द्वारा सारे विषयों की समीक्षा-परीक्षा की गई है और यह ऐलान किया गया है कि अगर सहकारी या कोऑपरेटिव बैंक हमारी शर्तें पूरी कर सकती हैं तो हम उन्हें उधार देने को तैयार हैं ।

रिजर्व बैंक की जिम्मेदारियों में एक का सम्बन्ध एक्सचेंज को १८ पैसे के करीब टिकाए रखने से है । इसके लिए वह कुछ निर्दिष्ट सीमा के भीतर स्टॉक की खरीद-विक्री करने को बाध्य है । जब स्टॉक बेचेगी तब १७ $\frac{1}{4}$ पैसे से नीची रेट से नहीं—अर्थात् एक्सचेंज इससे नीचे नहीं जा सकता । जब स्टॉक खरीदेगी तब १८ $\frac{1}{4}$ पैसे से ऊंची रेट से नहीं—अर्थात् एक्सचेंज इससे ऊपर नहीं जा सकता ।

साधन-सम्पन्न होते हुए भी रिजर्व बैंक को कानूनी मर्यादा के भीतर चलना पड़ता है और वह अपने साधनों का उपयोग केवल कमाई की दृष्टि से नहीं कर सकती । उसे अपने धन को बराबर ऐसे रूप में रखना पड़ता है कि आवश्यकता पड़ने पर उसे शीघ्र-से-शीघ्र, बिना नुकसान उठाए, मुद्रा में परिणत कर सके । जो औरों की हिफाजत के लिए है उसे अपनी हिफाजत का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है ।

साहूकार की समस्या

३ सितम्बर १९३९ को—प्रथम महासमर छिड़ने के प्राय २५ वर्ष बाद—द्वितीय महासमर की आग धधक उठी और उसकी लपट में इस देश को फिर आ जाना पड़ा। उस आग में भारतीय धन-जन की काफी बड़ी आहुति पड़ चुकी है, और अभी पता नहीं कि हमें इस आहुति को कब तक जारी रखना पड़ेगा। कहा गया है कि हमारा यह त्याग यज्ञ-कुंड में होम-द्रव्य डालने के समान फल-प्रद होगा। इसमें कहा तक सचाई है, यह भविष्य ही बता सकता है।

अभी तक हमारे त्याग का सबसे बड़ा नतीजा यह हुआ है कि जहाँ हम इंग्लैण्ड के कर्जदार थे वहाँ अब साहूकार बन गए हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं कि हमारी सुख-समृद्धि बढ़ गई है या हमारी दीनता-हीनता कम हो गई है। साहूकार होते हुए भी हमें खाने-पीने को—पहनने को पहले में कम मिल रहा है। इस अभाव के प्रश्न ने इधर कहीं-कहीं बड़ा ही भीषण रूप धारण कर लिया है। कागजी जमान्धर्व में हम साहूकार जन्म सावित होते हैं, पर इस साहूकारी की बुनियाद हमारी फाकाकशी है—अर्थात् स्टर्लिंग के रूप में हम जो धन जमा कर मके हैं वह पेट काट कर। उस स्टर्लिंग के सम्बन्ध में तरह-तरह के प्रश्न उठ रहे हैं—तरह-तरह की आशंकाएँ हो रही हैं। पर उनकी आलोचना में पहले कुछ और घटनाओं का उल्लेख आवश्यक है।

महाममर छिड़ते ही सोने के मुकाबिले स्टर्लिंग का विनिमय-मन्थ नीचे गिर पड़ा। अगस्त में हुडी की दर ४६८ डालर के आसपास थी। सितम्बर में सरकार को यह दर ४०३ के आसपास बाध देनी पड़ी। नूदन में सोने का बाजार २ से ४ सितम्बर और दम्बई में ८ से ९ सितम्बर तक

बन्द रहा। ५ सितम्बर को इंग्लैण्ड में सोने की खरीद-विक्री की मनाही कर दी गई। भारतवर्ष में यह नियम कर दिया गया कि बिना रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त किए कोई भी सोने को न तो बाहर से यहाँ मंगा सकेगा और न यहाँ से बाहर भेज सकेगा। देश के भीतर सोने की खरीद-विक्री पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं किया गया। तब से यहाँ सोने के दाम पर सामरिक घटनाओं के (जिनमें आशाएँ और आशकाएँ भी शामिल हैं) असर पड़ते रहे हैं और उनके अनुसार वह घटता-बढ़ता रहा है। मुख्य बात यह है कि आयात और निर्यात-सम्बन्धी नियन्त्रण के कारण यहाँ का बाजार बाहर के बाजार से पृथक्-सा हो गया है। अब यह आवश्यक नहीं कि बम्बई में सोने का दाम लन्दन या न्यूयार्क के दाम का अनुसरण करे। एक औसत खालिस सोने का दाम लन्दन में १९८ शिलिंग और न्यूयार्क में ३५ डॉलर चला आ रहा है। पर यहाँ भारतवर्ष में दाम उत्तरोत्तर बढ़ता* हो गया है। बम्बई में इधर ऊँचे-से-ऊँचा दाम इस प्रकार रहा है —

फी तोला

६० आ० पा०

१९३८—३९

३७—१०—६

१९३९—४०

४३—८—०

१९४०—४१

४८—८—०

१९४१—४२

५८—४—०

१९४२—४३

७२—०—०

चादी का दाम भी बढ़ता ही गया है। उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि इस प्रकार हुई है —

*पुस्तक छपते-छपते (दिसंबर, १९४३) बाजार में कुछ मन्दी आ गई है और सोने-चादी के दाम गिरने लगे हैं। २३ दिसंबर को दाम थे— सोना ७०॥) और चादी ११३॥)। इसका एक कारण तो रिजर्व बैंक की बिकवाली है, दूसरा लोगो की यह धारणा है कि महासमर का अन्त अब दूर नहीं है।

१९४२ में फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्बर (भारतीय व्यापारी-महासभा) ने इस प्रकार की बिन्नी का विरोध करते हुए सरकार को एक आवेदन-पत्र भेजा था, जिसमें लिखा था कि —

“फेडरेशन की कमेटी को यह मालूम नहीं कि चादी की बिन्नी के बारे में भारत-सरकार और ब्रिटिश-सरकार के बीच क्या समझौता हो चुका है। इस विषय में सर्वसाधारण को कुछ भी बताया नहीं जाता और सारी कार्रवाई गुप्त रखी जाती है। कमेटी को इस बात का भी पता नहीं कि भारत-सरकार लन्दन में जो चादी बेचती है वह २३। पेंस की दर से हो या उससे नीचे दाम में भी। अच्छा होता अगर सरकार स्पष्ट और प्रामाणिक रूप से यह बता देनी कि कितनी चादी इंग्लैण्ड को बेची जा चुकी है, और किम दाम में।

“युद्ध-सम्बन्धी उद्योग-धन्धों में चादी का उपयोग अनिवार्य-सा हो गया है, इसलिए इंग्लैण्ड तथा दूसरे मित्र-राष्ट्रों को इसकी जो सरत जरूरत है उसे महसूस करते हुए भी हम यह कह देना चाहते हैं कि जब उस चादी का दाम और भी ऊँचा मिल सकता है तब उसे इतने नीचे दाम में बेच देना इस देश की सम्पत्ति को लुटा देना है।

“हमारी मुद्रा-प्रणाली में चादी का विशेष स्थान रहा है। इधर सरकार ने रुपए में चादी की मात्रा $\frac{1}{4}$ से घटा कर $\frac{1}{8}$ कर दी है। रुपए में अब तक जनता का जो विश्वास चला आया है उसको इस कार्रवाई से आघात पहुँचने की सम्भावना है। आज नहीं तो कल सरकार को इस विषय पर पुनर्विचार करना पड़ेगा और रुपए में चादी की मात्रा बढ़ाकर फिर वही $\frac{1}{4}$ कर देनी पड़ेगी। इस दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि सरकार के पास जो कुछ भी चादी हो उसे वह बचाकर रखे, या किसी मित्र-राष्ट्र के हाथ बेचना आवश्यक भी हो तो ऐसे दाम में बेचे कि लडाई के बाद जब बाजार में चादी खरीदनी पड़े तब उसे किसी तरह का घाटा न हो।”

अमेरिका में चादी का दाम १० जुलाई १९३९ से प्रायः ३५ सेण्ट (फी औंस खालिस चादी) चला आ रहा था। १९४२ में अमेरिका का मेक्सिको से चादी के दाम के बारे में नया समझौता हुआ। इसके फल-

है। पर मुद्राओं के विनिमय की दर निर्धारित कर देने के बाद सरकार या रिजर्व बैंक इस विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती और मुद्राओं की बदला-बदली या गरीद-विक्री अनियंत्रित तथा अवाधित रूप में हुआ करती है।

पर असाधारण समय में—विशेषतः ऐसे महासमर के समय में—यह स्थिति नहीं रह सकती। कई कारणों से सरकार के लिए इस विनिमय को नियन्त्रित करना—दमपर प्रतिबन्ध लगाना—आवश्यक हो जाता है। आधुनिक लड़ाई जिन उपायों में लड़ी जाती है उनमें आर्थिक व्यवस्था या योजना का बहुत ऊँचा स्थान है। इस व्यवस्था या योजना के लिए बड़ी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं—बड़ी वृद्धि बाधनी पड़ती है। सामान जुटाने में जो पिछड़ गया, समझ लीजिए, उसकी हार हो चुकी। और इतने बड़े पैमाने पर सामान जुटाना कोई आसान काम नहीं। यथासंभव एक देश को दूसरे से महायुता लेनी ही पड़ती है—जिसका अर्थ है कि उनके बीच लेन-देन के भुगतान के लिए मुद्राओं का विनिमय अनिवार्य हो जाता है।

पर यह विनिमय पहले की तरह अनियंत्रित रूप से होता रहे तो कोई भी देश अपनी आर्थिक स्थिति को अपने काबू में नहीं ला सकता। इंग्लैण्ड का उदाहरण देते हैं। उसे अमेरिका में तरह-तरह के सामान खरीदने के लिए डॉलर चाहिए। ऋण लेने की बात छोड़ दी जाय तो डॉलर प्राप्त करने का प्रधान उपाय यही हो सकता है कि जिन लोगों ने वहाँ फाल बेच रखा है और जिन्हें वहाँ की मुद्रा में भुगतान मिला है उन्हें अपने डॉलर सरकार के हवाले कर देने को मजबूर किया जाय। अगर ऐसा नहीं होता तो वे अपने डॉलर बाजार में बेच देंगे और इनका संभवतः ऐसा उपयोग होगा जिसे राष्ट्रीय दृष्टि से दुर्प्रयोग कहा जा सकता है। हो सकता है कि कोई पैसावाला अपना पैसा इंग्लैण्ड से उठा कर अमेरिका ले जाना चाहता था और उसने स्टर्लिंग देकर इन डॉलरों को खरीद लिया। हो सकता है कि किसी व्यापारी ने अमेरिका में कुछ ऐसा माल मगा रखा था जो अमीरों के ठाटवाट को और भी बढ़ाने वाला था और उसने इन डॉलरों को खरीद कर अपना देना चुका दिया। हो सकता है, कोई गरस सैर-सपाटे के लिए अमेरिका जाना चाहता था या

करना पड़ता है। जबतक वह निर्दिष्ट रीति से यह आश्वासन नहीं देता कि वह नियमों की पूरी पाबन्दी कर चुका है या करने जा रहा है तबतक उसे बाहर माल भेजने की इजाजत ही नहीं मिल सकती। अगर आश्वासन देने के बाद वह किसी नियम का उल्लंघन करता है तो कठोर दण्ड का भागी बन जाता है। उसे आरम्भ में ही यह बताना पड़ता है कि दाम के भुगतान के बारे में क्या तय पाया है और यह भुगतान कौन-सी बैंक के द्वारा हुआ है या होनेवाला है। फिर उसे विदेश में माल मगानेवाले के पास सारे कागजात किसी निर्दिष्ट बैंक की मार्फत ही भेजने पड़ते हैं। माल मगानेवाला जब भुगतान कर देगा तब बैंक सारे कागजात उसके हवाले कर देगी और वह जहाज से माल छोड़ा सकेगा। वह बैंक फिर रिजर्व बैंक को यह सूचित कर देगी कि भुगतान मिल चुका और उस विदेशी मुद्रा का रिजर्व बैंक जो उपयोग मुनासिब समझेगी, करेगी। ऐसे नियन्त्रण के कारण न तो कोई यहाँ से माल के रूप में अपना पूँजीपल्ला ही बाहर भेज सकता है, न भुगतान में मिली हुई विदेशी मुद्रा का मनमाना उपयोग ही कर सकता है।

यह नियन्त्रण दो-तरफा है, अर्थात् माल भेजनेवाले को ही नहीं, माल मगानेवाले को भी अब रिजर्व बैंक-द्वारा अनुशासित होना पड़ता है। माल भेजनेवाला तो सरकार को विदेशी मुद्रा दिलाता है, पर माल मगानेवाला उससे विदेशी मुद्रा मागता है— इसलिए आयात-सम्बन्धी नियन्त्रण को निर्यात-सम्बन्धी नियन्त्रण से भी कठोर समझना चाहिए। १९४० में ही यह नियम कर दिया गया कि बिना सरकार से अनुमति प्राप्त किए कोई भी व्यापारी अमुक-अमक वस्तु को विदेश से यहाँ न मगा सकेगा। व्यापार के अलावा और कामों के लिए पैसा बाहर भेजने पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिए गए। १९४२-४३ में आयात-सम्बन्धी नियन्त्रण और भी सख्त कर दिया गया। अब सरकार जिस चीज को मौजूदा हालत में जरूरी समझती उसीको मगाने की अनुमति मिल सकती थी। इसका उद्देश्य केवल इतना ही नहीं था कि विदेश में जो धन प्राप्त हो उसका अनावश्यक वस्तुओं के दाम चुकाने में दुरुपयोग न होने पावे। और प्रकार के दुरुपयोगों को रोकने के उद्देश्य से भी आयात-सम्बन्धी नियन्त्रण कठोर

कर दिया गया। अनावश्यक वस्तुओं के निर्माण में अमेरिका की उत्पादन-शक्ति का दुरुपयोग सम्भव था। फिर, यह भी सम्भव था कि ऐसी वस्तुओं को वहाँ से वहाँ लाने में उम स्यान का दुरुपयोग हो जो जहाजों में मिल सकता था। वास्तव में जहाजों की बड़ी कमी हो रही थी, जितने जहाजों की जरूरत थी उतने मिल नहीं रहे थे। ऐसी स्थिति में आयात को उन्हीं वस्तुओं तक परिमित कर देने का नियम हो गया जो सरकार की दृष्टि में आवश्यक थे—बल्कि इस आवश्यकता का भी श्रेणी-विभाजन कर दिया गया और जिस वस्तु की आवश्यकता ऊँचे दर्जे की न हो, उसका आना असम्भवप्राय हो गया।

बैंक ऑफ इंग्लैंड ने डॉलर तथा कुछ दूसरी मुद्राओं में पौड का विनिमय-मूल्य बाध दिया था। पर यह विनिमय-मूल्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही मान्य हो सकता था। साम्राज्य के बाहर पौड का मूल्य इन बातों पर निर्भर था कि उसकी मांग के मुकाबिले उसकी 'बिकवाली' कमी थी और लंडॉन के नतीजे के बारे में बाहरी दुनिया का क्याल क्या था। इसलिए पौड की दो दरें रहने लगी—एक तो बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा नियंत्रित या निर्धारित दर, दूसरी वह दर जो न्यूयार्क—जैसे अनिगत्रिन या स्वतन्त्र बाजार में प्रचलित थी। उस स्वतन्त्र बाजार में पौड की दर नियन्त्रित दर में नीची या मम्नी रहने लगी—ममलन, जिस समय बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा निर्धारित दर ४०३॥ डॉलर थी उस समय न्यूयार्क की बाजार-दर सिर्फ ३०२ डॉलर थी। इसका एक नतीजा यह हुआ कि भारतवर्ष में अमेरिका जानेवाले माल का दाम डॉलर-मुद्रा में न चुक कर स्टैलिंग में चुकने लगा। मान लीजिए किसीने वहाँ में (१३१-॥) अर्थात् १ पौड का माल अमेरिका भेजा। वहाँ अगर सरकारी दर में भुगतान होता है तो माल मगानेवाले को ४०३॥ डॉलर देने पड़ते हैं। उस हालत में डॉलर

*यह दूसरी बात है कि क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक, इस सम्बन्ध में सरकार का निर्णय कभी-कभी वास्तविकता में दूर—यहूँ दूर रहता है।

तो सरकार ले लेगी और यहाँ से माल भेजनेवाले को रुपए मिल जायेंगे। पर चूँकि न्यूयार्क में बाजार-दर से पौंड ३.०२ डॉलर में ही मिल रहा है, इसलिए वहाँ माल भेजनेवाला उतने में एक पौंड खरीद कर इंग्लैण्ड में दाम चुका देता है और यहाँ के व्यापारी को (१३।-) मिल जाता है। इस तरीके से भुगतान होने पर सरकार को डॉलर नहीं मिलते और उस हद तक उसकी भुगतान-मध्यस्थी अपनी कठिनाई बढ़ जाती है। यही कारण है कि कुछ समय बाद सरकार ने विभिन्न उपायों का अवलम्बन कर उन ठिठ्ठों को प्रायः बन्द कर दिया जिनके द्वारा डॉलर-मुद्रा उसकी पहुँच से बाहर निकलनी जा रही थी।

• ब्रिटिश भारत की प्रजा की जो रकम डॉलर के रूप में जमा थी उसे सरकार ने दिसम्बर १९४० में स्वायत्त कर ली। जिनके डॉलर ले लिए गए उन्हें बदले में यहाँ रिजर्व बैंक में रुपए दिला दिए गए। निरर्थक था १०० डॉलर = ३३० रुपए। १० मार्च १९४१ को सरकार इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ी। जिन लोगों ने अमेरिका में कुछ खास सिक्यूरिटीज खरीद रखी थी उनके लिए भी यह लाजिमी कर दिया गया कि वे अपने कागज सरकार के हवाले कर दें और बदले में उसी निरर्थक से रुपए ले लें। पिछले दिन के बाजार-भाव से उन सिक्यूरिटीज की जॉलरो में जो कीमत हुई उसका यहाँ रुपयों में भुगतान कर दिया गया।

रुपए के विनिमय-मूल्य में सरकार ने किमी प्रकार का हेर-फेर नहीं किया है और हुडी की दर प्रायः १८ पैसे रहती आई है। चादी का दाम काफी ऊँचा होते हुए भी एक्सचेंज बढ़ा कर इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं की गई है। पाठकों को याद होगा कि पिछली लड़ाई में चादी की तेजी का नाम लगाकर रुपए के विनिमय-मूल्य को १६ से २४ पैसे (सोना) कर दिया गया था। कहा गया था कि जब रुपए की चादी की कीमत बढ़ रही है, तब उसका विनिमय-मूल्य बढ़ाए बिना वह चलन में किम प्रकार रखा जा सकता है? वास्तव में रुपया प्रतीक-मुद्रा का काम करता था, इसलिए चादी चाहे जितनी महँगी हो रुपए की कीमत में हेर-फेर नहीं होना चाहिए था। जैसा कि उस समय भी सरकारी नीति के आलोचकों ने कहा था—

अगर चादी महगी हो चली है तो कुछ समय के लिए या तो रुपए में चादी की मात्रा घटा दीजिए या कागजी रुपए से ही काम चलाइए। अगर गज लोहे के छड का हो और लोहा महंगा हो जाय तो गज किमी और सस्ती चीज का काम में लाया जायगा या समस्या हल करने के नाम पर गज की नाप ही सोलह में बत्तीस गिरह कर दी जायगी? मगर उस समय सरकार पर उस दलील का कुछ भी असर नहीं हुआ और वह अपने मनकी ही करके रही। इस बार भी चादी का वही हाल है, पर रुपए के विनिमय-मूल्य ने उससे बाजी ले जाने की कोशिश नहीं की है। पहले रुपए में १६५ ग्रेन लालिस चादी होती थी। अब वह ९० ग्रेन कर दी गई है—अर्थात् लम्बाई नापनेवाला गज कुछ हद तक लोहे का बना रहा, पर लोहा महंगा होने के कारण उसकी चौड़ाई या मुटाई आधी कर दी गई*। किसी भी हालत में चादी के दाम के घटने-बढ़ने का कोई असर हमारे प्रतीक के विनिमय-मूल्य पर नहीं पड़ना चाहिए। गनीमत है कि इस बार वह मूल्य बढ़ाया नहीं गया है।

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इस महासमर में हमारी आर्थिक स्थिति की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि विदेश में हमने अपना ऋण चुकाकर अब कुछ पूजी-पटला इकट्ठा कर लिया है।

पहले हम इंग्लैण्ड के कर्जदार थे—अब इंग्लैण्ड हमारा कर्जदार है। यह परिवर्तन इस कारण हुआ है कि इंग्लैण्ड हमसे जो कुछ ले रहा है उसकी पूरी कीमत चुकाने में असमर्थ है, लेहाजा उसने हमसे उधार लेना शुरू किया है। हमने इस सिलसिले में पहले अपना कर्ज उतारा, फिर उसे उधार देने गए। यों इस लड़ाई के जमाने में हम कर्जदार में साहूकार बन गए।

स्टलिंग में हमारा कर्ज या देना कब कितना था यह नीचे की तालिका से स्पष्ट हो जायगा। इसमें १८ पेंस के हिमाव में पौंड स्टलिंग के रुपए कर दिए गए हैं —

मार्च के अन्त में—	करोड़ रुपए
१९१४	२६५ ८१
१९१९	३०४ ०८
१९२४	३९७ ७६
१९२९	४७२ ७८
१९३४	५१२ १५
१९३९	४६९ १०
१९४३	५७ ४१

अर्थात् लडाई छिड़ने से पहले जहा लन्दन में हमारा देना प्राय ४६९ करोड़ था वहा मार्च १९४३ के अन्त में प्राय ५७॥ करोड़ ही रह गया था । बाकी देना या कर्ज हम अपने सिर से उतार चुके थे । और इसके बाद लन्दन में हमारा जो पावना हां चला था उसके भी, उसी १८ पैसे की दर से, मार्च १९४३ के अन्त में प्राय ५११ करोड़ रुपए होते थे । जबसे लडाई छिड़ी तबसे ३१ मार्च १९४३ तक का हिसाब इस प्रकार था —

जमा	करोड़ रुपए
१—अगस्त १९३९ में रिजर्व बैंक के पास स्टर्लिंग	६४
२—समय-समय पर रिजर्व बैंक ने जो स्टर्लिंग बाजार में खरीदा	३८७
३—ब्रिटिश सरकार से जो भुगतान स्टर्लिंग में मिला	५७१
	<hr/> १,०२२

* खर्च

१—मार्च १९४३ के अन्त तक भारतवर्ष का कर्ज चुकाने में स्टर्लिंग लगा	३८०
२—दूसरी देनदारी चुकाने में स्टर्लिंग लगा	१३१
	<hr/> ५११

बाकी ५११ करोड़ रुपए का स्टॉकिंग मार्च १९८३ के अन्त में रिजर्व बैंक के पास उन्दन में जमा था।

ऊपर के जमा-वर्च में रिजर्व बैंक-द्वारा स्टॉकिंग की गरीब ३८७ करोड़ रुपए दिखाई गई हैं। बाजार में स्टॉकिंग बेचनेवाले वे ही हो सकते हैं जो अपना माल या थम बेच कर इंग्लैण्ड में उसे हासिल किया है। साधारणतः यहाँ जितने रुपए का माल बाहर में जाता है उसमें अधिक का माल यहाँ से बाहर जाता है। ऐसी स्थिति में जिस हद तक वह आधिन्य होता है उस हद तक दूसरे देश हमारे देनदार बन जाते हैं। अगर बात उतनी ही होती तो हम आरम्भ से ही माहूँकार होते और कभी हमारे इंग्लैण्ड के कर्जदार बनने की नीयत न आती। पर होता यह रहा कि व्यापार में हमारा जो कुछ पावना निकला उसे तो इंग्लैण्ड ने ले ही लिया, जमा-वर्च के मुताबिक हम उलटा देनदार बना दिया।

ईस्ट इंडिया कम्पनी की अपनी पूँजी उसके कारोबार के लिए काफी नहीं थी, इसलिए बंगाल में उसे बराबर जगन्मोह की फाँटी में कर्ज लेना पड़ता था। अन्त में जगन्मोह के लागो रुपए डूब भी गए, क्योंकि प्रभुता हो जाने पर कम्पनी के संचालकों ने अपना देना चुकाने में उनकार कर दिया। अब उस देश का वाफायदा दोहन होने लगा—हमारे विदेशी शासक हमारी पराधीनता में जहाँ तक फायदा उठा सकते थे उठाने लगे। फिर एक दिन कम्पनी का रगमच में हटना पड़ा और शासन की बागडोर ब्रिटिश सरकार ने खुद अपने हाथ में ले ली। पर अब हमारा नोश और भी भारी हो चला। कम्पनी को जो हर्जाना दिया गया, उस देशके आपत्तियों को जो कामत चुकाई गई और परिस्थिति का काबू में लाने के लिए इंग्लैण्ड का जो खर्च करना पड़ा उस भारी रकम के देनदार हम ठहराए गए। और फिर नोश बढ़ मिल-मिठा चला कि हम माल-ब-माद इंग्लैण्ड में लेने की अपेक्षा करीब जितना माल इंग्लैण्ड का देने गए, और फिर भी व्रण में हमारा पिण्ड न छड़ा, बल्कि हम देनदारी के दलदल में फगने ही गए।

ब्रीटिशलार्जी ने इस विषय का विवेचन करने हुए एक जगह दिखाया है कि १८६८ और १९२० के बीच हमने बाहर में जितना

रुपए का माल लिया उसने प्राय २८ अरब रुपए अधिक का माल बाहर भेजा। इस माल में मोना-चादी शामिल नहीं है। इतने समय में बाहर में प्राय १४ अरब की मोना-चादी यहाँ आई। तो इस हिसाब से हमारा १४ अरब पावना रहा। पर असलियत में हम इस रकम में हाथ धो चुके थे और इंग्लैण्ड के काफी बड़े देनदार बन चुके थे। १९२९ में हमारी इस देनदारी का तखमीना प्राय १० अरब रुपया किया गया था। यह देनदारी स्टर्लिंग-ऋण के ही रूप में नहीं रही है। अगरेजों ने हमें यहाँ भी जो कुछ उधार दे रखा है या यहाँ वाणिज्य-व्यवसाय में जो कुछ लगा रखा है उस सबको इस देनदारी के अन्तर्गत समझिए।

जब मैं यह सिलसिला चला हूँ उस स्टर्लिंग को जो, आयात से निर्यात अधिक होने के कारण, हमें भुगतान में मिलता गया है, भारत-सचिव को यह कह कर अर्पित करते आए हैं कि—

“लीजिए—अपनी दरिद्रता को बरकरार रखते हुए हम जो कुछ बचा सके हैं उसे स्वायत्त कीजिए। हमारे देश में जितनी सरकारी नौकरियाँ अपने भाईबन्द को दे सकते हैं देते जाइए और इस रकम से उनकी पेन्शनें चुकाइए—उन्हें ऊँचे से ऊँचा भत्ता दीजिए। यह जरूरी नहीं कि सरहद्दी लडाइयों का ही खर्च हमसे वसूल किया जाय, क्योंकि हमारे देश की सरहद्द वही है जहाँ इंग्लैण्ड को लडाई लडनी हो। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार या हित-रक्षा के लिए भारतवर्ष के बाहर लड़ी हुई कितनी ही लडाइयों का खर्च हमसे वसूल किया जा चुका है—आगे भी ऐसे सिलसिले में आप जो चाहे हमारे नाम लिख कर वसूल कर सकते हैं। वेतन, पेन्शन, पुरस्कार, भत्ता, लडाई-खर्च—इनके अलावा और भी जिस मद में चाहे इस स्टर्लिंग का उपयोग कर सकते हैं। लाल-समुद्र या भारत-समुद्र में काम करनेवाली किसी ब्रिटिश कम्पनी को हर्जाना देना है? इंग्लैण्ड में किसी पागलखाने को इम-दाद पहुँचाना है? लन्दन में आए हुए तुर्की के सुल्तान के मनोरंजन के लिए नाच-रंग का आयोजन करना है? आपके बस की बात है कि जो बोझ चाहे हम पर लाद दे, जिस रकम के लिए चाहे हमें देनदार बना दे और सूद लगा कर उसे हमसे पाई-पाई वसूल कर ले।”

आज भारतवर्ष लडाई से पहले की अपेक्षा अधिक दीन और दुखी है। अपने को भूखा रखकर हमने मित्र-राष्ट्रों को अन्न दिया है—अपने को नग्न रखकर हमने उनके लिए वस्त्र जुटाया है। यही बात और दिशाओं में भी समझनी चाहिए। हमारे कारखाने बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करते हुए चल रहे हैं। विशेषज्ञों की कमी है। जो कच्चा माल मिलता भी है उसे कारखाने तक पहुँचाने में सौ-सौ दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। कल-पुरजों की घिसाई का कोई ठिकाना नहीं। और नियंत्रण के नाम पर तरह-तरह की अट्चने अलग डाली जाती हैं। फिर इतनी कठिनाइयों के होते हुए भी कारखानेवाले जो माल तैयार कर पाते हैं उसका काफी बड़ा अंश सरकार ले लेती है। ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है कि हमें स्वयं उपवास कर अपने भोजन की सामग्री दूसरों को दे देनी पड़ती है।

उस सामग्री की कीमत हमें न तो जित्नी में मिली है, न सोने-चादी में। उलटा हमारी ही चादी इंग्लैंड को बेच दी गई है। हमें जो डॉलर प्राप्त होते हैं वे भी हमसे ले लिए जाते हैं। हमें कीमत चुकाई जाती है स्टर्लिंग में, क्योंकि इंग्लैंड उसे किसी भी दूसरे रूप में चुकाने में असमर्थ है। ३१ मार्च १९४३ तक हमें ५७१ करोड़ २० का भुगतान मिल चुका था। इधर और भुगतान मिला है। सब ले-देकर ३१ दिसम्बर १९४३ को रिजर्व बैंक के नोट-प्रसार-विभाग में प्रायः ७३५ करोड़ रुपए का स्टर्लिंग जमा था। इसके अलावा उसके बैंकिंग विभाग में, इस देश के बाहर, प्रायः १२० करोड़ रुपए रोकड़ और सिक्यूरिटीज के रूप में थे। याद रखने की बात है कि हमने अपना प्रायः सारा स्टर्लिंग-ऋण चुका दिया है, और अब हम इंग्लैंड के कर्जदार नहीं बल्कि साहकार हैं। जब तक लडाई जारी रहेगी, इंग्लैंड का उधार लेना जारी रहेगा और हमारे पावने की रकम बढ़ती ही जावेगी।

अब हमारे सामने प्रश्न यह उपस्थित है कि हमने वहाँ जो कुछ जमा किया है या करते जायेंगे उसे कब और किस रूप में वहाँ ला सकेंगे ?

जब हम इंग्लैंड के कर्जदार थे तब उसे यह चिन्ता रहती थी कि कहीं शक्तिशाली होने पर भारतवासी अपना देना चुकाने से इनकार न कर दे, और उसकी ओर से बराबर इस बात पर जोर दिया जाता था कि स्वराज्य-सम्बन्धी विधान या सघटन में उसके हित के संरक्षण के लिए खास व्यवस्था होनी चाहिए। अब वह तो निश्चिन्त हो गया और तरह-तरह की चिन्ताएँ हमको होने लगी हैं। आर्थिक क्षेत्र में इंग्लैंड की आज तक की करतूतों को देखते हुए, हमारा यों चिन्तित होना स्वाभाविक ही है। पर इस विषय के विवेचन में हम यह मानकर ही आगे बढ़ सकते हैं कि इंग्लैंड न तो जोर-जबर्दस्ती करेगा न टाट उलटेगा—वर्तिक हमसे जो कुछ ले चुका है या लेता जा रहा है उसे एक दिन पाई-पाई वापस कर देगा।

श्रीबिडला जी ने 'कर्जदार से साहूकार' नामक पुस्तिका* में बताया है कि इस सिलसिले में हमारी मांग क्या होनी चाहिए। वह लिखते हैं—

“ब्रिटिश सरकार से हमारी पहली मांग यह होनी चाहिए कि हमारी स्टिलिंग की वचत रकम, जो अभी है या बाद को इकट्ठी होगी, किसी तरह नष्ट न की जायगी, इसका वह हमें आश्वासन दे।

“पिछली लड़ाई का अनुभव इस सिलसिले में सर्वथा सुखद नहीं कहा जा सकता। यह बात छिपी नहीं है कि पिछली लड़ाई के वृत्त से रार्च, जो ब्रिटिश सरकार को देने चाहिए थे वे हिन्दुस्तान के मत्थे मढ़े गए। अगर हिन्दुस्तान अपने भाग्य का निर्णय स्वयं कर सकता, तो जितनी रकम उसे लड़ाई के रार्च के हिमाय में मिली थी उससे कहीं ज्यादा रकम मिलती। परन्तु जो मिला था वह भी बाद में योही बन्दर-काट में गायब हो गया।

“... अगर हिन्दुस्तान मावधान न रहा तो इतिहास की पुनरावृत्ति हो सकती है। अतः हम बराबर मावधान रहना चाहिए और यह मांग करना चाहिए कि जिस रार्च में हमारी अपनी सीमाओं की रक्षा का मीघा

सम्बन्ध नहीं है वह हिन्दुस्तान के नाम न लिया जाय, न नो भविष्य में पेशन चुकाने के लिए आज ही ब्रिटिश सरकार को एक मोटी रकम दे दी जाय और न युद्धोपरान्त पुनर्निर्माण के लिए कोई रकम अलग कर दी जाय। हमारी रकम पर हमारा पूरा कब्जा रहे, क्योंकि हमारी रकम हमारी अपनी है। किसीको हमसे यह कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि अपने धन का हम क्या उपयोग करें, और क्या न करें। इस मामले में इससे कम कुछ भी हमको स्वीकार नहीं हो सकता।

‘परन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात इस बात की सावधानी रखना है कि भविष्य में हमारे बचे हुए स्टैलिंग की कीमत कम न हो जाय।’

इस विषयको कुछ विस्तार से समझाने की आवश्यकता है।

मान लिया कि स्टैलिंग के बदले हमें स्टैलिंग ही मिलेगा, पर हो सकता है कि अग्रेज स्टैलिंग की जो क्रय-शक्ति है वह कल न रहे—आज स्टैलिंग से जितना माल खरीदा जा सकता है कल उतना न खरीदा जा सके। उस हालत में हमको बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। जब हमने इंग्लैंड को कर्ज दिया उस समय स्टैलिंग की जिन्सों के रूप में जो कीमत थी वह कीमत बनी रही तब तो चिन्ता की कोई बात नहीं, पर अगर वह कीमत गिर गई—अर्थात् स्टैलिंग के बदले जिन्से कम मिलने लगी—तो हमको क्षतिग्रस्त होना पड़ा। श्रीविडलाजी का कहना है कि उस अवस्था में ब्रिटिश सरकार को हमारी क्षतिपूर्ति करने को तैयार रहना चाहिए। इसकी व्यवस्था यो हो सकती है कि हमारा जो स्टैलिंग जमा हो उसकी मालियत जिन्सों में मुकर्रर कर दी जाय और कर्ज चुकाने के समय अगर वह मालियत कम हो तो हमें और रकम देकर वह कमी पूरी कर दी जाय ताकि हमें कोई घाटा उठाना न पड़े। स्टैलिंग की क्रय-शक्ति में क्या कमी हुई है यह ‘इण्डेक्स नम्बर’ अर्थात् ‘सूचक अंक’ से जाना जा सकता है और तदनुसार क्षति-पूर्ति की जा सकती है। मान लीजिए, जिस समय इंग्लैंड को हमने कर्ज दिया उस समय वहाँ जिन्सों के दामों का ‘इण्डेक्स नम्बर’ १२५ था, और जिस समय वह कर्ज चुका उस समय ‘इण्डेक्स नम्बर’ था २५०। तो इसके माने हुए कि इस बीच में

होगी। यथादि-जैसे साधनों के दाम ऊँचे रहने की तो और भी अधिक संभावना है, क्योंकि ऐसी चीजें इंग्लैण्ड से विशेषतः बाहर जानेवाली हैं। और भारतवर्ष को अपनी उत्पादन-शक्ति बढ़ाने के लिए—नए कल-कारखाने खोलने के लिए इंग्लैण्ड से प्रायः ऐसी ही चीजें चाहिए।

पर हम मालियत की ऐसी घटा-बढ़ी के झमेले में पड़े ही क्यों? राष्ट्र की ओर से ज़ुआ खेलने या दाव लगाने का किसीको अधिकार नहीं है। हमारी मांग तो यही होनी चाहिए कि हमने मालियत के रूप में जो कुछ दिया है हमें वह वापस मिलना चाहिए—न कम, न ज्यादा। जहाँ आग लगने या जहाज डूबने की संभावना कम—बहुत कम—होती है वहाँ भी कुशल व्यवसायी या व्यापारी बीमा कराए बिना नहीं रहते। वे कभी ऐसा तर्क नहीं करते कि जब संभावना इतनी कम है तब बीमा कराने के खर्च का बोझ क्यों उठाया जाय? फिर हमारी मांग यह क्यों न हो कि इंग्लैण्ड में जमा होनेवाली हमारी रकम का ब्रिटिश सरकार बीमा कर दे—अर्थात् स्टर्लिंग की मालियत घटने की सूरत में हमारी क्षति-पूर्ति करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले। कौन कह सकता है कि यह प्रस्ताव किसी भी अंश में अनुचित या अनुपयुक्त है?

इंग्लैण्ड का स्टर्लिंग ऋण तो हमने चुका दिया। पर इस देश में उसने अपना जो धन वाणिज्य-व्यवसाय में लगा रखा है—और इस प्रकार हमें कर्ज दे रखा है—वह अभी तक हम नहीं चुका पाए हैं। कनाडा, दक्षिण अफ्रीका जैसे साम्राज्यान्तर्गत दूसरे देशों ने, ऐसी ही परिस्थिति से लाभ उठाकर, अपने इस प्रकार के ऋण को बहुत बड़ी हद तक चुका दिया है। पर वहाँ की तरह यहाँ भी यह तभी हो सकता है जब कि सरकार ब्रिटिश व्यवसायियों या पूँजीपतियों को अपना-अपना भुगतान लेकर हमारा बोझ हलका करने को बाध्य करे।

मुक्त बात यह है कि सारा ऋण चुका देने के बाद हमारा जो पावना निकले वह हमें जिनसों के—अर्थात् उत्पादन-सम्बन्धी साधनों के—रूप में अनतिविलम्ब चुका दिया जाय। इसमें न कोई अड़चन डाली जाय, न कोई आनाकानी हो।

(१) हमारी मुद्रा-नीति का प्रधान लक्ष्य यहा के किसानों को तथा अन्य उत्पादकों को अधिक-से-अधिक लाभ पहुंचाना होता—न कि ब्रिटिश व्यवसायियों या कर्मचारियों को ।

(२) १८९३ में चांदी की टकसाल बन्द न की जाती ।

(३) कभी सोने का मान या स्टैंडर्ड ग्रहण भी किया जाता तो दूसरे देश को लाभ पहुंचाने के उद्देश से किसी विकृत रूप में नहीं ।

(४) सोना भारतवर्ष में मचित किया जाता, सात समुद्र-पार इंग्लैण्ड में नहीं । और इस बात का बराबर ध्यान रखा जाता कि हमारे नोटों की पुष्टी के लिए हमारे पास अधिक-से-अधिक सोना हो ।

(५) भारतवर्ष में ब्रिटिश माल की खपत बढ़ाने तथा ब्रिटिश कर्मचारियों को लाभान्वित करने के उद्देश से रुपए का विनिमय-मूल्य कृत्रिम उपायों से ऊंचा न किया जाता । और इन प्रयत्नों की सफलता के लिए वह भयानक गिरावटी नीति काम में न लाई जाती जिससे समय-समय पर हमारी अमित हानि हुई है ।

(६) १९०१ का विनिमय-मूल्य १८९३ में १६ पेंस (सोना) न किया जाता, पर एक बार कर देने पर उसमें ये हेरफेर हर्गिज न किए जाते —

१९१९ में २४ पेंस (सोना)

१९२७ में १८ पेंस (सोना)

(७) २४ पेंसवाली दर को टिकाने के लिए उन दामों उलटी छुटिया न बेची जाती और गिरते हुए को उठाने के प्रयत्न में हमारे करोड़ रुपए बरबाद न किए जाते ।

(८) १९३१ में जब रुपए का सोने से पल्ला छूट गया तब उसका स्टैलिम से गठबन्धन न किया जाता ।

(९) मन्दी का दीर-दीरा होने पर ऐसी मुद्रा-नीति बरती जाती जो दामों को ऊपर उठाने में सहायक होती—न कि वैसी जिसने उन्हें और भी नीचे गिरा दिया ।

(१०) अरबों रुपए का सोना इस देश से बाहर न जाने दिया जाता ।

सोल देने के पक्ष में कैसे हूँ ? मैं उत्तर देता हूँ कि यह प्रश्न एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट का नहीं, यह तो देश की भलाई का प्रश्न है। देश की उत्पादन-शक्ति बढ़ जाय तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही फायदे में रहेंगे। फर्क इतना ही है कि एक्सपोर्ट और फौरन फायदा उठा लेगा और इम्पोर्ट को—अर्थात् मुझको कुछ देर ठहरना पड़ेगा।”* पर मि० ग्राहम-जैसे विचार रखनेवाले ब्रिटिश व्यापारी या पदाधिकारी विरले ही हुए हैं। कलकत्ते से लन्दन तक उदारता अथवा दूरदर्शिता का नितान्त अभाव-सा रहा है। इंग्लैण्ड के दृष्टिकोण में ऐसी सकीर्णता न होती तो वह, इस देश में, छोटे स्वार्थ के सामने अपने बड़े स्वार्थ को देखने में असमर्थ न होता और भारतवर्ष को खुशहाल बना कर अपनी खुशहाली की नींव को आज से कहीं ज्यादा मजबूत बना लेता।

असलियत यह है कि उसने इस देश में ऐसी नीति से काम लिया जो हमारी खुशहाली को आगे न बढ़ाकर पीछे धकेलनेवाली थी। सासकर यहाँ की मुद्रा-नीति ऐसी रखी गई जो इंग्लैण्ड की अपनी दृष्टि से श्रेयस्कर थी, न कि भारतवर्ष की।

अगर भारतवासी अपनी उत्पादन-शक्ति बढ़ा लेते हैं तो यह इंग्लैण्ड के हक में आर्थिक ही नहीं, राजनैतिक दृष्टि से भी बुरा होता है—इस कुविचार ने यहाँ की मुद्रा-नीति वैसी न होने दी जिससे यहाँ के उत्पादक-वर्ग को यथेष्ट सहायता मिल सकती थी—जो उद्योग-धंधों का मुद्रा-सम्बन्धी अभाव दूर कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर सकती थी, जिससे मरुभूमि में भागीरथी बहाई जा सकती थी और बालू को मोने में परिणत किया जा सकता था। पर यह सब न होकर हुआ कुछ और ही, कारण कि “रोपे पेड बबूल को, आम कहा ते होय ?”

उम मुद्रा-नीति का उद्देश्य हो गया रुपए की मालियत—चाहे जैसे हो—ऊंची-से-ऊंची रखना, जिससे यहाँ रुपए कमानेवाले ब्रिटिश कर्मचारी या व्यापारी अपनी-अपनी कमाई को अधिक-से-अधिक स्टैलिंग में तबदील

कर सक—जिससे ब्रिटिश माल यहाँ सस्ता बिक सके अधिक-से-अधिक खपत हो सके।

पर इंग्लैण्ड के लाभ का अर्थ था भारतवर्ष की हुई की मालियत बढ़ती है तब यहाँ दाम गिरते हैं। यह स मुकसान से बचने के लिए हम अपने दाम बढ़ा सकें।,। नहीं बढ़ी है या हमारे प्रतियोगी पुराने दामों में ही मान तो हमें ऊँचे दाम मिल ही कैसे सकते हैं ? तो बाहर ही बने रहे और हमारे प्रतीक की कीमत या मालियत बढ़ उत्पादकों को कम रुपए मिलने लगे। उनकी लागत भी उन्हीं जो पहले थी। लगान वही देना पड़ता है, कर वही देना महाजन को सूद वही देना पड़ता है। और सबसे बड़ी मजदूरी भी वही देनी पड़ती है। अगर उत्पादक मजदूरों में कि रुपए का विनिमय-मूल्य बढ़ने के कारण बढ़ गए हैं, अब आप लोग अपनी मजदूरी में कटौती मजदूरों की मानते नहीं। अगर बढ़ता है तो हड़ताल होती है, कल-कारण हो जाते हैं। यों भी उत्पादक ऐसी अवस्था में एक हद तक काम-काज जारी रग सकेंगे। जब वे देखेंगे कि बाजार बेहद गया तब वे उसे जमीन पर पटक देंगे और उत्पादन के धंधे में लगे। उद्योग-धंधों के बन्द होने में बेकारी बढ़ेगी, जन-धान्य की घटेगी, लोग और भी दीन-हीन-विपन्न हो जायेंगे। सरकार की मुद्रा के कारण यहाँ ऐसी स्थिति एक नहीं, अनेक बार उत्पन्न हो चुकी।

जब-जब यहाँ सरकार ने मुद्रा की मालियत—या यों कहिए कि दर—ऊँची बांधी है तब-तब उसे अभीष्ट-मिष्टि के लिए गिरावट-नीति अवलम्बन करना पड़ा है। किसी चीज की बाजार-दर १० पैसे है, सरकार चाहती है कि वह १६ पैसे हो जाय, या वह १५ पैसे हो जाय। स्पष्ट है कि अगर उस चीज की पैदाइश सरकार के अपने हाथ में है वह उसमें कमी करके—उस वस्तु को दुर्लभ बनाके—बाजार में ही ऊँची दर चला सकती है।

बरसो से रुपए के सम्बन्ध में सरकार यही करती आई है। १८९३ में चांदी की टंकसाल का दरवाजा सर्व-साधारण के लिए बन्द कर दिया गया। अब मुद्रा का प्रसार सरकार की अपनी मर्जी पर रह गया। जब चाहे जितना करे, न करे। रुपए की वह जो कीमत मांगती है, अगर लोग उसे देने को तैयार नहीं हैं तो उन्हें अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रुपए मिलने के नहीं। हा, मुद्रा-प्रसार रोक कर ही सरकार सन्तुष्ट नहीं हुई। जब उसने देखा कि हाथ खींच लेने से ही काम नहीं चलता तब उसने, गिरावट की दिशा में और आगे बढ़कर, तरह-तरह की कारसाजियां शुरू कर दी। उद्देश था मुद्रा के प्रसार को समेट लेना—चलन से जहां तक हो सके रुपयों को खींच लेना। ऊंचे-से-ऊंचे व्याज पर कर्ज लेकर, बाजार में रुपए की भीषण टान या तंगी पैदा कर दी गई। जो रुपए नोटों के रूप में आए वे जला दिए गए—जो चांदी के रूप में आए वे गला दिए गए।

मुद्रा के अभाव के कारण दाम गिरे, और दाम गिरने से तरह-तरह के सकट उपस्थित हो गए। उत्पादन की गति या तो बन्द हो गई या बिलकुल रुक गई, किसानों की मुसीबत खास तौर से बढ़ गई। आय कम हो जाने के कारण लोगों की त्रय-शक्ति क्षीण हो गई और देश भर में दुख-दारिद्र्य का विस्तार हो गया। ऐसी स्थिति में सरकार की अपनी आय कम हुए बिना कब रह सकती थी? पर जब उसकी आय घटी तब करो के रूप में प्रजा का बोझ और भी भारी कर दिया गया। इस प्रकार हर ओर से वही तंग-तबाह की गई।

पर इस गिरावट-नीति के अवलम्बन का एक कुफल और हुआ। जब रुपए की दर ऊंची कर दी जाती है अर्थात् स्टर्लिंग सस्ता कर दिया जाता है तब स्वभावतः स्टर्लिंग की मांग बढ़ जाती है। यह मांग उस हालत में और भी अधिक होती है जब लोग समझते हैं कि इतनी ऊंची दर को टिकाने में सरकार कभी सफल न होगी।

मान लीजिए, आज १ रुपए के बदले सरकार ३० पैसे स्टर्लिंग देने को तैयार है और बाजार का विश्वास है कि यह दर ठहरनेवाली नहीं

फिर एक बार लडाई छिड़ी और इंग्लैण्ड भारतवर्ष में धन-जन-सम्बन्धी जितनी सहायता ले सकता था, लेने लगा। इंग्लैण्ड हम से जो कुछ लेता है उसकी कीमत सोने-चादी या डॉलर-जैसी मुद्रा में चुकाने में असमर्थ है, इसलिए वह सारा भुगतान कागजी स्टर्लिंग में करता है। भारत-सचिव को ब्रिटिश सरकार से जो स्टर्लिंग प्राप्त होता है वह उसे रिजर्व बैंक को देकर उससे यहाँ सरकार को रुपए दिला देते हैं। उस स्टर्लिंग से सिव्वायरीटीज खरीद कर रिजर्व बैंक की लन्दन-शाखा में रख दी जाती है और यहाँ उनके मद्दे नोट निकाल कर चलन में डाल दिए जाते हैं। लन्दन में प्राप्त होनेवाले स्टर्लिंग का एक हिस्सा भारतवर्ष के ऋण को चुकाने में खर्च कर दिया गया है, फिर भी इस समय वहाँ प्रायः ८५० करोड़ का स्टर्लिंग जमा है। यों भारतवर्ष कर्जदार से साहूकार बन गया है, और इस समय हमें चिन्ता है तो इस बात की, कि इंग्लैण्ड से हमारा यह पावना कब और किस रूप में वसूल हो सकेगा।

ऊपर कहा जा चुका है कि उस स्टर्लिंग के मद्दे यहाँ नोटों के रूप में रुपए जारी कर दिए गए हैं। इस समय नोट-प्रसार प्रायः ८५० करोड़ है। लडाई से पहले यह प्रायः २१७ करोड़ था। मुद्रा के परिमाण में यह वृद्धि 'फुलावट' कही जा सकती है या नहीं ?

इसके उत्तर के लिए मीमांसा-भाग का तृतीय अध्याय देखना चाहिए। वहाँ फुलावट की परिभाषा यह दी गई है—“आवश्यकता से अधिक हृद से बाहर नोटों का चलण”, और बताया गया है कि “यह तरीका तभी काम में लाया जाता है जब कि सरकार आर्थिक कठिनाइयों में फँसी हुई होती है या दिवालिया बनने की राह पर होती है।”

भारत-सरकार की स्थिति ऐसी नहीं कही जा सकती। न तो वह आर्थिक कठिनाइयों में फँसी हुई है, न दिवालिया बनने की राह पर है। यहाँ जो नोट-प्रसार हुआ है उसे मीमांसा-भाग के लेखक के शब्दों में “स्वाभाविक विस्तार” कहना ही उपयुक्त होगा। यहाँ भारत-सरकार को आर्थिक संकट से उबारने के लिए नोट नहीं छापे गए हैं। यहाँ तो इतना ही हुआ है कि इस देश की उत्पादन-शक्ति बढ़ी है, दाम बढ़े हैं,

परिशिष्ट

१

जिन्सों का आयात और निर्यात*

साल	आयात	निर्यात	आयात से निर्यात अधिक
१९०९-१० से १९१३-१४ तक का सालाना औसत	१४५,८५	२२४,१२	७८,२७
१९१४-१५ से १९१८-१९ तक का सालाना औसत	१४७,८०	२२४,११	७६,३१
१९१९-२० से १९२३-२४ तक का सालाना औसत	२५४,०५	३००,९६	४६,९१
१९२४-२५ से १९२८-२९ तक का सालाना औसत	२४१,४३	३५१,९२	११०,४९
१९२९—३०	२४०,८०	३१७,९३	७७,१३
१९३०—३१	१६४,८०	२२५,६४	६०,८४
१९३१—३२	१२६,३७	१६०,५५	३४,१८
१९३२—३३	१३२,५९	१३५,४९	२,९०
१९३३—३४	११५,३६	१५०,६७	३५,३१
१९३४—३५	१३२,२९	१५५,२२	२२,९३
१९३५—३६	१३४,४२	१६४,२९	२९,८७
१९३६—३७	१२५,२४	२०२,३७	७७,१३

*जो माल भारत-सरकार ने मंगाया था बाहर भेजा वह इस तालिका के बाहर है।

१९३७—३८ से बर्मा ब्रिटिश भारतवर्ष का अंग नहीं है।

१९२५-२६	+ ६,१३५,५८१	+ ३४,८५,४५,७९९
१९२६-२७	+ ३,३८५,५२९	+ १९,४०,०५,४४८
१९२७-२८	+ ३,१८१,७५९	+ १८,१०,००,०२३
१९२८-२९	+ ३,७८५,४४१	+ २१,१९,८६,९७८
१९२९-३०	+ २,५२३,५६२	+ १४,२२,०८,३९६
१९३०-३१	+ २,२४२,६५३	+ १२,७५,१८,११५
१९३१-३२	- ७,६२९,३७७	- ५७,९७,२७,८४२
१९३२-३३	- ८,३५३,८२९	- ६५,५२,२७,९५६
१९३३-३४	- ६,६९५,२९८	- ५७,०५,३५,९६१
१९३४-३५	- ५,६९४,८२०	- ५२,५३,७४,६०७
१९३५-३६	- ४,०१९,२६२	- ३७,३५,५९,९५५
१९३६-३७	- ३,०११,०३६	- २७,८४,६१,१२९
१९३७-३८	- १,७६६,८१७	- १६,३३,१८,१२९
१९३८-३९	- २,३८७,६४७	- २३,२६,०२,०६८
१९३९-४०	- ४,१५५,३४३	- ४४,६४,३०,४२२

१९००-०१ से १९३०-३१ ।

तक ३१ वर्षों का जोड़ + ८९,२४४,५९२ + ५,४७,७५,४७,८२९
 १९३१-३२ से १९३९-४०

तक ९ वर्षों का जोड़ - ४३,७१३,४२९ - ३,८२,५२,३८,०६९

३

चांदी का आयात (+) या निर्यात* (-)

साल औंस में वजन रुपयो में कीमत

१९००-०१ से १९०४-०५

तक का सालाना औसत + ५७,०४९,२७८ + १०,११,४१,९१४

* देखिए फुटनोट, तालिका २ (परिशिष्ट)

१९०५-०६ में १९०९-१०		
तक का सालाना औसत	+ ८७,०३७,३७२	+ १५,८५,४४,०३०
१९१०-११ में १९१८-१५		
तक का सालाना औसत	+ ६१,०११,३०१	+ १०,६१,४१,३२३
१९१५-१६ में १९१९-२०		
तक का सालाना औसत	+ १०६,७२५,६१५	+ २७,९६,३८,६२५
१९२०-२१ में १९२८-२५		
तक का सालाना औसत	+ ७३,६०८,६०३	+ १५,७४,१३,८२७
१९२५-२६	+ ९३,३६३,७५८	+ १७,१०,४१,१५०
१९२६-२७	+ १२८,२८०,३६५	+ १९,८६,८०,३३५
१९२७-२८	+ ९०,८२१,८१३	+ १३,८३,६४,६२७
१९२८-२९	+ ६३,८२०,९०९	+ ९,७७,०६,९२६
१९२९-३०	+ ६२,५२०,५६८	+ ८,६०,१२,१९८
१९३०-३१	+ ८०,५३५,९३५	+ १०,०७,९३,०५६
१९३१-३२	- ११,१६१,२८१	- ६२,१७,०८८
१९३२-३३	- २८,५१७,२००	- २,०१,३०,९५१
१९३३-३४	- ५०,९८९,०९०	- ६,३५,७१,४२६
१९३४-३५	- ३८,६८३,८९८	- ५,८०,६६,८००
१९३५-३६	+ १,५१६,०७८	- ५७,३४,७१०
१९३६-३७	+ ११०,१११,८६५	+ १३,५९,१७,००८
१९३७-३८	+ ११,९८५,२२३	+ १,५०,८२,८३५
भारतवर्ष	+ १५,७७८,९८८	+ १,५७,०८,०००
बर्मा	- ६,०३१,०९०	- ८८,५९,५८९
१९३८-३९	+ ८,०३६,५७८	+ ५७,९१,६०६
भारतवर्ष	+ ११,८९९,९६०	+ १,६८,५०,७८०
बर्मा	- ८,३०३,०७५	- १,०७,९८,०६३
१९३९-४०	+ १३,८२०,००६	+ १,८८,८८,०८७
भारतवर्ष	+ १८,८०६,१११	+ ८५,६०,९७१
बर्मा	- ८०८,३६२	+ ८१,८०,९८६

४

नोट-प्रसार

लाख रुपए

(साल के अन्त में)	कुल नोट	सार्वजनिक चलन में
१८९९-१९००	२८,७४	२२,१०
१९००-१०	५४,४१	३९,९९
१९१३-१४	६६,१२	४९,९७
१९१८-१९	१,५३,४६	१,३३,५८
१९१९-२०	१,७४,५२	१,५३,७८
१९२०-२१	१,६६,१६	१,४७,८८
१९२१-२२	१,७४,७६	१,५७,२३
१९२२-२३	१,७४,७०	१,६१,१०
१९२३-२४	१,८५,८५	१,६९,०६
१९२४-२५	१,८४,१९	१,६६,५५
१९२५-२६	१,९३,३४	१,६७,७१
१९२६-२७	१,८४,१३	१,६४,३१
१९२७-२८	१,८४,८७	१,७४,५३
१९२८-२९	१,८८,०३	१,७८,१०
१९२९-३०	१,७७,२३	१,५९,३०
१९३०-३१	१,६०,८४	१,४७,९३
१९३१-३२	१,७८,१४	१,६५,१७
१९३२-३३	१,७६,९०	१,५०,३४
१९३३-३४	१,७७,२२	१,६३,८८
१९३४-३५	१,८६,१०	१,६३,५६
१९३५-३६	१,९५,५८	१,६८,८२
१९३६-३७	२,०४,००	१,९४,३७

१९३७-३८ भारतवर्ष	{ २०६,२०	१७८,२०
बर्मा	{ ७,८३	७,८३
१९३८-३९ भारतवर्ष	{ १९६,४७	१७८,३६
बर्मा	{ १०,७६	१०,७४
१९३९-४० भारतवर्ष	{ २३८,४३	२२५,१०
बर्मा	{ १३,७८	१३,४५
१९४०-४१ भारतवर्ष	{ २५१,८१	२४०,५५
बर्मा	{ १७,४४	१७,११
१९४१-४२ भारतवर्ष	{ ३९२,७१	३८१,७३
बर्मा	{ २८,३५	२८,३३
१९४२-४३ भारतवर्ष	६५५,११	६४३,५८

५

टकसालों में कब कितने (पूरे) रुपए ढले

	रुपए
चतुर्थ विलियम १८३५	१६,३९,७८,५७२
विक्टोरिया, १८४०, पहली बार	३१,१६,७०,९२४
" १८४०, दूसरी बार	७६,६५,६०,९३७
" १८६२	७०,६९,१२,१७९
" १८७४	४,३५,२२,४००
" १८७५	३,०९,९१,५४८
" १८७६	४,०९,५०,३०१
" १८७७	१३,४८,०६,०१२
" १८७८	९,६५,८५,०३३
" १८७९	८,८७,२८,२२९
" १८८०	७,२१,८५,५१८
" १८८१	५५,९७,५७७

"	१८८२	७,१४,८७,५६७
"	१८८३	२,३१,४६,१६१
"	१८८४	४,८४,८८,३२७
"	१८८५	९,९०,३०,२०३
"	१८८६	५,२०,२४,५३२
"	१८८७	८,८६,००,१४८
"	१८८८	७,०७,६८,०००
"	१८८९	७,४६,६८,३१०
"	१८९०	११,७६,४१,८६५
"	१८९१	६,४१,६९,९०३
"	१८९२	१०,४६,५५,१२०
"	१८९३	७,८७,३०,३१०
"	१८९७	१५,२४,७७७
"	१८९८	७५,१९,४१३
"	१९००	११,८१,३९,४९९
"	१९०१	१०,९१,३५,९६१
"	१९०१ (१९०२ में ढले)	९,३१,३९,३८४
सप्तम एडवर्ड	१९०३	२५,०००
"	१९०३	१०,२३,४७,५०६
"	१९०४	१६,०२,७८,९०८
"	१९०५	१२,७४,६०,१०६
"	१९०६	२६,३७,५०,४३३
"	१९०७	२५,२२,४९,८१६
"	१९०८	३,०९,३२,४९८
"	१९०९	२,२२,९७,३२६
"	१९१०	१,७६,८८,६७३
"	१९१० (१९११ में ढले)	५८,२३,२८६
पचम जॉर्ज	१९११	९४,४३,०४९

"	१९१२	१२,४१,८९,२०६
"	१९१३	१६,३२,६५,९५१
"	१९१४	४,८३,७०,१५०
"	१९१५	१,५२,७२,११८
"	१९१६	२१,२९,००,२१०
"	१९१७	२६,४७,८२,८७६
"	१९१७ (१९१८ में ढले)	१७,७४,०२५
"	१९१८	४१,१८,७६,६०३
"	१९१८ (१९१९ में ढले)	४०,९४,००६
"	१९१९	४२,३५,१२,२७८
"	१९१९ (१९२० में ढले)	१,४४,००,०३१
"	१९२०	९,४५,३६,६२९
"	१९२० (१९२१ में ढले)	६४,००,०६४
"	१९२० (१९२२ में ढले)	५,६४,०००
"	१९२० (१९२३ में ढले)	४९,३६,०५०
"	१९२१	५१,१५,१२१
"	१९२२	२०,५१,१५०
षष्ठ जॉर्ज	१९३८ (१९४० में ढले)	९८,०२,१७८
"	१९४०	२,३५,००,००२
"	१९४१	२४,११,००,००१
"	१९४२	२३,७१,००,००१
जोड़		६९८,७५,९७,९६१

१९२२ और १९४० के बीच नए रुपयो की ढलाई नहीं हुई।

ढलाई के जो आकड़े ऊपर दिए गए हैं उनमें ऐसे मिनके भी शामिल हैं जो समय-समय पर देशी रियासतों के लिए ठांके गए हैं।

६

चलन की घटा-बढ़ी

हर साल के अन्त में यह हिसाब किया जाता है कि कितने नोट या रुपए चलन में गए (Absorption of currency) और कितने चलन से निकल आए (Return of currency)। चलन से यहाँ मतलब सार्वजनिक चलन से है। रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले इसे निश्चित करने का यह तरीका था —

(१) नोटों के सम्बन्ध में यह देखा जाता था कि कितने नोट जारी किए जा चुके थे और साल के अन्त में कितने सरकारी खजाने (Treasuries) और इम्पीरियल बैंक की प्रधान शाखाओं में रह गए थे। जो बाकी बचता वह (सार्वजनिक) चलन में समझा जाता।

उदाहरण—१९२८-२९ के आरम्भ में (सार्वजनिक) चलन में १,७४,५३ लाख रुपए के नोट थे। उसके अन्त में चलन में थे १,७८,१० लाख रुपए के नोट। तो इसके माने यह हुए कि उस साल और ३,५७ लाख रुपए के नोट चलन में गए।

१९३४-३५ के आरम्भ में (सार्वजनिक) चलन में १,६३,८८ लाख के नोट थे। उसके अन्त में चलन में १,६३,५६ लाख के नोट थे। तो इसके माने यह हुए कि उस साल चलन से ३२ लाख के नोट वापस आ गए।

नोट ज्यादा जारी किए गए—उनका प्रसार बढ़ा—लेकिन नए नोट सरकार के अपने खजाने में ही पड़े रहे तो (सार्वजनिक) चलन में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसी प्रकार अगर चलन से नोट वापस आए और करेन्सी रिजर्व में न जाकर सरकारी खजाने में पड़े रहे तो नोट जितने जारी किए जा चुके थे उतने ही खड़े रहे—उनके प्रसार में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई।

(२) रुपयों के सम्बन्ध में यह देखा जाता था कि कितना सरकारी खजाने (Treasuries) और करेन्सी रिजर्व में बच रहा, कितना टकसाल

से ढल कर आया और कितना गलाने या फिर में ढालने के लिए टकसाल भेजा गया। इस जोड़-बाकी हिमाव से यह पता चल जाता कि चलन में कितना गया या चलन में कितना वापस आया। (इम्पीरियल बैंक की प्रधान शाखाओं में जो रुपया रहता वह इस हिमाव में नहीं लिया जाता था, क्योंकि उसका परिमाण बहुत कम होता था।)

उदाहरण—१९३२-३३ के आरम्भ में रोकड़ इस प्रकार थी—

सरकारी गजाने में	१,०० लाख रुपए
करेन्सी रिजर्व में	१,०१,९६ " "

जोड़ १,०२,९६ " "

साल के अन्त में रोकड़ इस प्रकार थी —

सरकारी गजाने में	९३ लाख रुपए
करेन्सी रिजर्व में	९६,३४ " "

जोड़ ९७,२७ " "

अर्थात् ५,६९ लाख रुपए (सार्वजनिक) चलन में गए। पर उसी साल १३,२५ लाख रुपए टकसाल में गलाने या फिर से ढालने के लिए भेजे गए। तो निष्कर्ष यह निकला कि उस साल (१३,२५—५,६९) अर्थात् ७,५६ लाख रुपए चलन में निकल आए।

रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद से यह हिमाव इस प्रकार होने लगा है —

अब सरकारी गजाने (Treasuries) के नोट सार्वजनिक चलन के अन्तर्गत माने जाते हैं। कितने नोट चलन में गए या कितने वापस आए, यह पता लगाने के लिए सिर्फ रिजर्व बैंक के प्रसार-विभाग (Issue Department) के नोटों की घटा-बढ़ी पर ध्यान दिया जाता है। इसी प्रकार, कितने रुपए चलन में गए या कितने वापस आए—उसका पता अब रिजर्व बैंक के प्रसार-विभाग की रोकड़ की घटा-बढ़ी में ही चलता है।

कब सिवनी करेन्सी चलन में गई और कब सिवनी उमम में वापस आ गई (—) उसका लेखा नीचे दिया जाता है —

	रुपए*	लाख रुपए नोट	जोड़
१९१४-१५ से १९१८-१९ तक			
५ वर्षों का औसत	२२,०८	१६,७२.	३८,८०
१९१९-२०	२०,०९	२०,२०	४०,२९
१९२०-२१	२५,६८	-५,९०	-३१,५८
१९२१-२२	-१०,४६	९,३५	-१,११
१९२२-२३	-९,५६	३,८७	-५,६९
१९२३-२४	७,६२	७,९६	१५,५८
१९२४-२५	३,६५	-२,५१	१,१४
१९२५-२६	-८,१७	१,१६	-७,०१
१९२६-२७	-१९,७६	-३,४०	-२३,१६
१९२७-२८	-३,७५	१०,२२	६,४७
१९२८-२९	-३,०३	३,५७	५४
१९२९-३०	-२१,७१	-१८,८०	-४०,५१
१९३०-३१	-७१,५८	-११,३७	-८२,९५
१९३१-३२	३,९३	१७,२४	२१,१७
१९३२-३३	-७,५६.	-१४,८३	-२२,३९
१९३३-३४	-३०	१३,५४	१३,२४
१९३४-३५	-३,२१	-३२	-३,५३
१९३५-३६	-९,४१	५,२६	-४,१५
१९३६-३७	-२,४९	२५,५३	२३,०४
१९३७-३८	-६,५२	-८,२३	-१४,७५
१९३८-३९	-१२,६०	२,९८	-९,६२
१९३९-४०	१०,०८	४९,४५	५९,५३

*इसमें रेजगारी शामिल नहीं है। पर इधर भारत-सरकार-द्वारा जारी किए गए एक रुपए के नोट शामिल हैं।

१९४०-४१	३३,२३	१९,११	
१९४१-४२	७,१८	१५२,४०	१
१९४२-४३	४४,९७	२६१,८५	३
(केवल भारतवर्ष)			
१९१९-२० से १९३८-३९			
तक २० वर्षों का जोड़—	१,३०,५५	५२,०८	—
१९१९-२० से १९३८-३९			
तक २० वर्षों का औसत —	६,५३	२,६०	

